अल्पमोली संस्करण

भारत-विभाजन की कहानी

भारत के बटवारे तथा सत्ता-हस्तातरण की आतरिक कहानी

लेखक
एलन कैम्पबेल जान्सन

अनुवादक
रनवीर सक्सेना
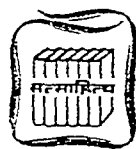
सस्ता साहित्य मण्डल-प्रकाशन
१९६०

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मत्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली-१

दूसरी बार १९६०
अल्पमोली-सस्करण
मूल्य डेढ रुपया

मुद्रक
श्री जैनेन्द्र प्रेस,
दिल्ली-६

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक श्री एलन कैम्पबेल जान्सन की 'मिशन विद माउण्टबेटन' नामक सुविख्यात पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। इसमे लार्ड माउन्ट ेटन के एक महान् मिशन को लेकर भारत मे आने, भारतीय स्वतन्त्रता का व्यावहारिक एव सर्वमान्य हल उपलब्ध कराने, शासन-सत्ता को भारतीयो के हाथ मे सौपने, भारत के टुकडे होने और दो स्वतन्त्र राष्ट्रो के बनने की बडी ही सूक्ष्म, रोचक तथा आतरिक कहानी है। लेखक लार्ड माउन्टबेटन के प्रेस अटेची थे। इस नाते त्येक घटना से उनकी जानकारी रहना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, लार्ड माउन्टबेटन हर मुलाकात के बाद पन्द्रह मिनट मे उसके नोट लिखा देते थे। साथ ही विचार-परिवर्तन करने की दृष्टि से अपने उच्च कर्मचारियो की वह प्रतिदिन नियमित रूप से बैठक भी किया करते थे। इसके परिणामस्वरूप लेखक हर घटना से न केवल अवगत ही रहते थे, अपितु उसकी आवश्यक एव प्रामाणिक सामग्री भी उन्हे प्राप्त होती रहती थी।

बडे हर्ष की बात है कि इस विषय की इतनी ऐतिहासिक एव उपादेय सामग्री लेखक के परिश्रम तथा दूरदर्शिता के कारण प्राप्त हो सकी। उन्होने प्रत्येक दिन की घटनाओ का वर्णन तिथि-क्रम से किया है और छोटे-बडे सभी विवरण प्रस्तुत किये है। उन्हे पढ पर पता चलता है कि भारत के हाथ मे सत्ता सौपने की पृष्ठ-भूमि क्या थी, ब्रिटिश सरकार को किन-किन परिस्थितियो का मुकाबला करना पडा, भारतीयो को किस लाचारी की अवस्था मे विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा, मुस्लिम लीग ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए रास्ते मे क्या-क्या अडचने पैदा की, पाकिस्तान स्वीकार होने पर किस प्रकार भारत का अग-भग हुआ, विभाजन से क्या-क्या समस्याए उत्पन्न हुई, किस तरह दो पृथक् राष्ट्रो का निर्माण हुआ और किस प्रकार भारत से अपनी सत्ता हटा लेने पर भी भारत और ब्रिटेन के सबध मधुर बन रहे।

पुस्तक की सबसे बडी विशेषता यह है कि लेखक ने उसे निष्पक्ष भाव से लिखा है। दैनिक घटनाओ को ज्यो-का-त्यो उन्होने उपस्थित कर दिया है। जहा कही अपनी बात कहने का अवसर आया है, वहा उन्होने किसी के साथ भी पक्षपात से काम नही लिया। भारत-विभाजन व सत्ता-हस्तातरण-सबधी साहित्य मे, जो कि पुस्तक के रूप मे बहुत ही कम उपलब्ध है, इस ऐतिहासिक पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है।

पुस्तक की कुछ घटनाए तो इतनी मनोरजक है कि पाठक पढकर आनन्द-

विभोर हो उठता है। १५ अगस्त की रात को सत्ता-हस्तातरण की विधि के पश्चात् विधान-सभा के अध्यक्ष राजेन्द्रबाबू जब लार्ड माउन्टबेटन से स्वतत्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल बनने का अनुरोध करने जाते है तो उन्हे जो कहना चाहिए, कहना भूल जाते है और उनके मुह से शब्द ही नही निकल पाते। उसी अवसर पर नेहरूजी अपने मत्रिमडल के नामो की सूची एक बद लिफाफे मे माउन्टबेटन को देकर चले जाते है, पर जब माउन्टबेटन उसे खोलते है तो देखते क्या है कि अन्दर कुछ भी नही है। पहली मुलाकात होने के समय जिन्ना, लार्ड और लेडी माउन्टबेटन का फोटो खिचता है। अपनी बहादुरी की डीग मारने के लिए विनोद भरे स्वर मे जिन्ना लेडी माउन्ट-बेटन से कहते है कि दो काटो के बीच एक गुलाब है, पर मजे की बात यह कि माउन्टबेटन-दपति के बीच वह स्वय खडे थे। ऐसी मनोरजक घटनाए बहुत-सी मिलती है, जो पुस्तक को बडी सरसता और सजीवता प्रदान करती है।

मूल पुस्तक काफी बडी है और उसमे विभाजन तथा सत्ता-हस्तातरण के अतिरिक्त और बहुत-सी बाते आ गई है। भारतीय पाठको की दृष्टि से मूलभूत घटनाओ को लक्ष्य मे रख कर पुस्तक का सक्षिप्तीकरण एव सम्पादन कर दिया गया है।

हमे पूर्ण विश्वास है कि यह सग्रहणीय पुस्तक पाठको के लिए बडी उपयोगी सिद्ध होगी।

दूसरा संस्करण

हमे प्रसन्नता है कि पुस्तक का दूसरा सस्करण पाठको के हाथो मे पहुच रहा है। पुस्तक की उपयोगिता को देखकर इसे अपनी 'अल्पमोली प्रकाशन'-माला मे निकाला जा रहा है और सामग्री को ज्यो-का-त्यो रख कर भी इसका मूल्य बेहद कम कर दिया गया है।

—मत्री

दो शब्द

जुलाई १९४२ में मुझे माउन्टबेटन के कर्मचारी-मंडल में संयुक्त कमाण्ड हेडक्वार्टर्स में एयर पब्लिक रिलेशंस आफीसर का स्थान सौंपा गया था। १५ महीने के बाद माउन्टबेटन को दक्षिण-पूर्व एशिया की मित्र-राष्ट्र सेनाओं के सर्वोच्च कमाण्डर के पद पर नियुक्त किया गया तो उन्होंने मुझे केवल सरकारी आधारों से सूचना प्राप्त कर लेने का काम नहीं सौंपा, बल्कि वह मुझे अपनी साप्ताहिक मुलाकातों एवं महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल कर लेते थे। अतः वाइसराय के रूप में जब उन्हें भारत जाने के लिए आमंत्रित किया गया तबतक मैं माउन्टबेटन-तन्त्र का इतना अभिन्न अंग बन चुका था कि मुझे प्रेस अटेची के रूप में उनके साथ भारत आना पड़ा। उनके पूर्व के वाइसरायों के समय में यह पद नहीं होता था।

इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य अपने निजी नोटों, पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर, जोकि मैंने उस समय लिये थे, इस कहानी को कहना है। अधिकांशतः मैंने इतिहास देने की अपेक्षा इतिहास की साधन-सामग्री इस पुस्तक में उपस्थित की है। इसकी घटनाओं और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मेरा संपर्क इतना घनिष्ठ था कि मैं उनके विश्लेषण का प्रयत्न नहीं कर सका।

यदि इस पुस्तक का घटना-क्रम तीव्र है तो इसका कारण यह है कि हम सबको बड़ी तेजी और रफ्तार से काम करना पड़ा और हम लोगों के सामने बेहद जल्दी थी। यदि ये विवरण कुछ असम्बद्ध से प्रतीत होते हैं, तो इसका कारण यह है कि समय-समय पर अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती थीं और उनके तात्कालिक समाधान भी करने पड़ते थे, जिनसे हमारी दिनचर्या का तारतम्य टूट जाता था।

तेजी और बाधाओं के बावजूद विभाजन द्वारा सत्ता-हस्तांतरण निश्चित क्रम के अनुरूप चला। हमारे भारत में आने के ७३ दिन में विभाजन-योजना का ऐलान कर दिया गया और उसके ७२ दिन के बाद स्वतः वाइसराय पद का अंत हो गया। माउन्टबेटन के गवर्नर-जनरल पद के १० महीनों में घटनाओं की रफ्तार कभी भी मंद नहीं पड़ी।

विषय-सूची

भारत-विभाजन की कहानी

: १ :

नये वाइसराय की नियुक्ति

लदन, बृहस्पतिवार, १९ दिसम्बर १९४६

मै सवेरे ही चेस्टर स्ट्रीट मे माउटबेटन के घर पहुचा। नाश्ते का समय था। माउटबेटन ने मुझे आदेश दिया कि मै जाऊ और पश्चिमी-पूर्वी एशिया की कमान-सबधी आदेशो के बारे मे उनसे मिलू। प्रधान सेनापति की हैसियत से उन्होने जो भ्रमण किया था, उस सारे भ्रमण मे मै उनको युद्ध की डायरी लिखता और रखता था, इस नाते उन आदेशो मे पदेन-सदस्य के तौर पर मेरी रुचि थी। इस काम मे कुछ भारी कठिनाइया भी थी और सबसे बडी कठिनाई उनके व्यस्त कार्य-क्रम के साथ इस काम का मेल बिठाना था। हम लोगो का काम पूरा नही हुआ था और समय की कमी थी, इसलिए अगले कार्यक्रम के लिए उनके साथ जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। अगला कार्यक्रम था अपना सरकारी चित्र बनवाने के लिए आस्वाल्ड बर्ले चित्रकार के यहा जाना।

जब हम कार मे बैठ गए तो माउटबेटन ने सब खिडकिया बद कर दी, एकदम गुप्त रखने की मुझे सौगध दिलाई और धीरे से कहा, "जो बात मै आपसे कहने जा रहा हू, वह मेरे निजी परिवार के बाहर किसी को भी मालूम नही।" उन्होने बताया कि मि एटली ने मुझे कल शाम बुलाया था और लार्ड वेवल की जगह भारत का वाइसराय बनने को आमत्रण दिया। यद्यपि मै उनकी अचरज-भरी बातो मे शामिल होने का आदी हो गया हू, तथापि जो रहस्य उन्होने प्रकट किया, उसकी मुझे बिल्कुल आशा न थी। अपने जीवन की चिरकालीन असफल आकाक्षा को पूरा करने के लिए वह फिर नौसेना मे जानेवाले थे और बडे जोरो से उनका अभ्यास भी चल रहा था। उन्हे प्रथम क्रूजर स्क्वेड्रन की कमान के लिए रियर एडमिरल बनना था। इसके अलावा, भारतीय नेताओ, लार्ड वेवल और ब्रिटिश सरकार के बीच अभी-अभी लदन मे जो बातचीत हुई थी, उसमे सहज आशा की कोई झलक न होते हुए भी, लगता था कि मत्रिमडल-मिशन योजना अभी जीवित है।

लेकिन अब जो मैने सुना, उससे जान पडा कि प्रधानमत्री भारत और माउटबेटन दोनो के भविष्य के बारे मे कुछ और ही सोच रहे है। मि एटली ने

माउटबेटन से जो मुलाकात की थी उसकी शुरुआत यह पूछते हुए की थी कि क्या दरअमल उनका दिल नौसेना मे जाने को करता है ? उन्होने जवाब दिया कि निश्चय ही यह बात सही है ।

एटली ने इसके बाद भारतीय सकट की बात छेड दी । उन्होने कहा कि वेवल तो सेनाए हटाने की योजना से अधिक कुछ भी नही कर पाए । इसपर सरकार उन राजनैतिक विचारधाराओ से बहुत ही ज्यादा असतुष्ट है, जो काग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो पर असर कर रही है । अगर हम सावधान न रहे तो हम भारत को न केवल घरेलू युद्ध मे ही, बल्कि तानाशाही राजनैतिक दलो के हाथो मे सौपने को लाचार हो जायगे । प्रस्तुत गतिरोध का अत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, और मत्रिमडल के प्रमुख सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि नये सिरे से व्यक्तिगत सपर्क से ही सभवत आशाजनक परिणाम निकल सकता है। इस काम को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त आदमी की तलाश मे उन्होने चारो ओर नजर दौडाई और सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुचे कि ऐसा व्यक्तित्व और आवश्यक योग्यता केवल माउटबेटन मे ही थी ।

लंदन, बुधवार, १५ जनवरी १९४७

आखिर माउटबेटन ने वाइसराय पद सभालने की स्वीकृति दे ही दी । प्रधान-मत्री के साथ उनकी पहले की बातचीत अपूर्ण रही थी । सरकारी नीति मे समय-अवधि के सिद्धान्त को मान लिया गया, लेकिन बिल्कुल निश्चित तारीख अभी तय नही हो पाई । १९४८ की बाद की छमाही की तजवीज की गई थी, लेकिन माउटबेटन का दृढ मत था कि राजनैतिक सफलता इस बात पर निर्भर है कि सरकार अग्रेजो के भारत छोडने के लिए निकटतम तारीख मजूर करने को तैयार है या नही, और तुरत ही उन्होने सुझाव दिया कि छमाही का अर्थ दिसबर नही, जून होना चाहिए । बडे दिन के सप्ताह के निकट होने के कारण आखिरी निर्णय स्थगित कर दिये गए और माउटबेटन थोडे दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार को लेकर डेवोस चले गए। वहा गये अभी अडतालीस घंटे ही हुए होगे कि लदन से उनके लिए जरूरी बुलावा आ गया और एक खास हवाई जहाज उन्हे लाने को भेजा गया । इस घटना से अखबारो मे बडे-बडे अनुमान लगाये जाने लगे, लेकिन असली मतलब कोई नही समझ पाया । मिसाल के तोर पर 'डेलीमेल' के सपादक फ्रैंक ओवन ने मुझे अपना निजी अनुमान बताया कि माउटबेटन फिलस्तीन भेजे जा रहे है ।

माउटबेटन को इस तरह वापस बुलाने का कारण यह था कि भारत से आने-समाचार अधिकाधिक गभीर थे । साप्रदायिक गतिरोध और हिसा का दौर

जारी था। सरकार जितना जल्दी हो सके, नई नीति और नये वाइसराय की घोषणा करना चाहती थी। इस घोषणा के मसविदे की शर्तों पर गभीरतापूर्वक विचार करने के बाद माउटबेटन ने अतत सिद्धान्त रूप मे इस पद को ग्रहण करना स्वीकार किया। सरकार के साथ उनका जो विचार-विनिमय हुआ, उसमे उन्होने सरकार को इस आशय का कोई भाव प्रकट करने के खतरे से सावधान कर दिया कि उनकी नियुक्ति वाइसराय-प्रथा को स्थिर रखने या ब्रिटिश मध्यस्थता लागू करने के लिए की गई है। इसीलिए शुरू की चर्चा मे उन्होने यह शर्त रखी कि वह वाइसराय-पद तभी स्वीकार करेंगे जब भारतीय दल स्वत अपनी शर्तों के साथ उन्हे भारत आने का निमत्रण दे। जो हो, मि एटली ने विस्तार के साथ समझाया कि यह आखिरी शर्त मुनासिब नही है, लेकिन इस सिद्धात को पूरी तरह स्वीकार किया कि अगर भारतीय दल एक सविधान और एक सरकार के रूप पर एकमत हो जाय तो समझौते के बावजूद वह किसी निश्चित तारीख अथवा उससे पहले भी ब्रिटिश राज्य की समाप्ति कर देंगे।

माउटबेटन को राजी करने के लिए सरकार अधिक-से-अधिक सीमा तक बढने को तैयार थी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा कि भारतीय नेताओ और नये वाइसराय के बीच वह पहले से ही आवश्यक सपर्क की व्यवस्था कर देंगे, और सरकारी घोषणा से पूर्व ही इस नियुक्ति के बारे मे वह उनकी सहमति प्राप्त कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रिप्स ने तो यहा तक कह डाला कि वह माउटबेटन के साथ भारत भी जाने को तैयार है। इस सुझाव को दबा देना स्वाभाविक था, क्योकि भारतीय मामलो मे क्रिप्स की स्थिति और अनुभवो से माउटबेटन की स्थिति बिगड जाती और नये वाइसराय के लिए आवश्यक अधिकार या प्रतिष्ठा के साथ बातचीत करना प्राय असभव हो जाता।

लंदन, सोमवार, १७ फरवरी १९४७

माउटबेटन ने आग्रह किया कि उन्हे वाइसराय के सामान्य कर्मचारी-मडल मे वृद्धि करने की अनुमति दी जाय। उनका कहना था कि उनको पूर्व वाइसरायो को दिये जानेवाले चार्याई मे भी कम समय मे अभूतपूर्व राजनैतिक और सैनिक महत्व के निर्णय लेने का भार सौपा गया है। लार्ड वेवल के सामान्य सिविल सर्विस स्टाफ के लोग हालाकि बहुत प्रतिभाशाली और अनुभवी थे, फिर भी उनसे बिना अन्य सहायता के काम पूरा कर ले जाने की उम्मीद करना असभव था। मि एटली ने तुरन्त वादा किया कि माउटबेटन जिन कर्मचारियो की नियुक्ति चाहेगे सरकार उसे पूरा करेगी।

माउटबेटन चार नये पदो का निर्माण कर रहे थे, जो वाइसराय-भवन के

इतिहास मे नये थे। वाइसराय के नीचे एक चीफ ऑव स्टाफ, एक प्रमुख सेक्रेटरी, एक कान्फ्रेस सेक्रेटरी और एक प्रेस अटची। इनके अलावा उनका व्यक्तिगत मत्रालय भी होगा, जिसके प्रमुख होगे दो वयस्क नौसेना अधिकारी। अपनी पटाने की योग्यता के बल पर, जो माउटवेटन के व्यक्तित्व की एक खासियत है, उन्होंने अपने दो पुराने मित्रो को, अपने कामो को छोड कर, उनके दल को अपने महान् अनुभव का लाभ देने के लिए राजी कर लिया।

यही कारण है कि लार्ड इस्मे ने अपनी समाधि भग करना स्वीकार कर लिया था और वह चीफ ऑव स्टाफ का पद सभाल रहे थे। सर एरिक मिएविल नगर मे महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्तरदायित्व को छोड कर प्रमुख सेक्रेटरी बने थे।

माउटवेटन के विशेष दल के अन्य सदस्य केप्टेन रोनाल्ड ब्रोकमेन (शाही नौसेना), कमाडर जार्ज निकोल्स (शाही नौसेना), लेफ्टिनेट कर्नल वरनोन अर्सकिन क्रम (स्काट्स गार्डस) और मै—हम सब लोग कही-न-कही पहले भी माउटवेटन के नीचे काम कर चुके थे।

: २ :

महत्त्वपूर्ण बहस और सलाह-मशविरे

लंदन, बुधवार, २६ फरवरी १९४७

लार्ड सभा मे गत दो दिन से सरकार की २० फरवरी वाली घोषणा पर जो सनसनीपूर्ण वहस चल रही थी, वह लार्ड टैम्पलवुड के अपने निदा-प्रस्ताव को वापस लेने के साथ समाप्त हो गई। यह एक ऐसा मौका था, जब बहुत से लोगो का यह मानना गलत नही था कि लार्ड सभा के मत कामन्स सभा की अपेक्षा अधिक राजनैतिक वजन वाले है। पहली बात तो यह कि लार्ड सभा वाले नई परिस्थिति पर कामन्स सभा से पूर्व ही से विचार कर रहे थे। इसलिए यह खयाल किया जाता था कि अनुदार विरोधी दल का अन्तिम रुख सभवत लार्डो द्वारा अपनाये गए स्वर पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा, ये वयोवृद्ध राजनीतिज्ञो और विशेषज्ञो के रूप मे अपनी वशगत क्षमता के आधार पर वहस नही कर रहे थे।

भारतीय शासन के इतिहास मे जिनके नाम चौथाई सदी से भी अधिक समय तक चमक चुके थे, ऐसे वहुत से लोगो ने लार्ड टैम्पलवुड के कडे मत पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि समय-अवधि का निश्चय वचन-भग है, जिससे भारत की शाति और समृद्धि खतरे मे पड जायगी।

महत्वपूर्ण बहस और सलाह-मशविरे

जब लार्ड टैम्पलवुड भारत-सचिव के पद पर आसीन थे और सर सेमुअल होर के नाम से प्रख्यात थे, तब उन्होने लगभग सात वर्ष भारत सरकार के १९३५ के विधान को मि० चर्चिल और अनुदार दल के दक्षिणपथियो के तीव्र और सतत विरोध के विपरीत स्वीकार करवाने मे लगाए थे। इसलिए उनके द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव सरकार के लिए निश्चय ही बडी भारी चुनौती थी। यदि इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो जाता तो भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर पूरे राष्ट्र द्वारा कोई सयुक्त प्रयास करना असभव हो जाता। जब लार्ड लिस्टोवेल ने सरकार की ओर से पहले दिन की बहस का जवाब दिया, उस समय तक इस बात की बहुत कम सभावना थी कि इस प्रश्न पर मतदान और पराजय को टाला जा सकेगा।

यह खतरा आज और भी बढ गया जब साइमन कमीशन ख्यातिवाले लार्ड साइमन[1] ने विरोधी दल की तरफ से बोलना शुरू किया। वह एक घटे से जरा ही ऊपर बोले। उनका भाषण तर्कपूर्ण नकारात्मकता और निषेधो का आदर्श नमूना था।

इसके बाद लार्ड ट्रेन्चार्ड ने बहुत ही तीखी आलोचना करते हुए भाषण दिया और फिर लार्ड हैलीफेक्स भारतीय मामलो मे आखिरी बार निर्णायक हस्तक्षेप करने खडे हुए। बहस मे भाग लेने वाले एकमात्र भूतपूर्व वाइसराय वही थे। पार्टी की मान्यताओ और अनुशासन को छोड कर उन्होने कहा

"अपनी जानकारी के आधार पर मै यह कहने को तैयार नही हू कि और कोई चीज चाहे गलत रही हो या सही, लेकिन यह कदम तो हर हालत मे गलत है ही। . क्योकि सच तो यह है कि भारत की समस्या का कोई ऐसा हल नही है जो गभीरतम आपत्ति और गहनतम खतरे से भरा न हो। और मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हू—इसके दोषो के बावजूद—कि मै तबतक सम्राट् की सरकार के निर्णयो की निन्दा करने को तैयार नही हू जबतक कि मै ईमानदारी और विश्वास के साथ इससे अच्छा हल न सुझा सकूं। मुझे खेद होगा यदि इस क्षण इस सभा की ओर से भारत को जो सन्देशा भेजा जा रहा है, उसमे केवल निन्दा ही भरी हो; हालाकि मै अच्छी तरह समझता हू कि यह निन्दा असफलता, निराशा और आशकाओ की स्वाभाविक भावनाओ पर आधारित है।"

लार्ड सेमुअल ने बाद मे मुझसे कहा कि लार्ड सभा मे उन्होने जितने भाषण सुने, उनमे यह सबसे अधिक प्रभावशाली था और इसका इतना अधिक असर पडा कि बहुत से अनुदारदली लार्डो ने, जिन्होने उनके खडे होने से पूर्व सरकार के खिलाफ मत देने का फैसला कर लिया था, उनके भाषण के दौरान मे अपने विचार बदल

---

[1] जिनका ८० वर्ष की अवस्था मे हाल ही मे देहांत हो गया।

डाले। वे टैम्पलवुड से की गई उनकी इस अपील से सहमत हो गए कि "सभा को मतदान लेने की आवश्यकता से बचाए।" शेष बहस मे दम नही था। जनमत का ज्वार पलट गया था। लार्ड टैम्पलवुड ने अपनी आलोचना कायम रखते हुए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

लंदन, बुधवार, ५ मार्च १९४७

हालाकि कामन्स सभा मे दो दिन की वहस का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण ससदीय अवसर था, फिर भी जव मैने क्रिप्स को अपने स्वाभाविक सयम ओर सुस्पष्टता के साथ सरकारी पक्ष की वकालत करने खडे होते देखा, तो मै यह सोचे बिना न रह सका कि नई नीति की मुख्य लडाई तो पहले ही लार्ड सभा मे जीती जा चुकी है। क्रिप्स के भापण हमेशा इतने तर्कयुक्त और इतने सुयोजित होते है कि जब वह बोलते है तो भावनाओ का पारा तुरन्त गिर जाता है। आपके दिमाग को अनुकूल करने का प्रयास करने के पहले वह आपके दिल को अपील करने की कल्पना तक नही कर सकते। लेकिन इस बार उनके भाषण मे मुझे हमेशा से अधिक गहरे आत्मविश्वास का आभास मिला।

भारत की भावी स्वाधीनता मे क्रिप्स ने जो योग दिया, उसका स्थान पहले ही इतिहास मे सुरक्षित हो चुका था। जैसा कि लार्ड हैलीफेक्स ने कहा था, १९४२ की क्रिप्स-मिशन योजना एक ऐसा निर्णायक कदम था, जिससे वापस नही लौटा जा सकता था। १९४६ के मत्रिमडलीय मिशन की वह सबसे बडी हस्ती थे। दोनो बार की चर्चाओ मे वह पूरी सहमति और निर्दोष सफलता के बहुत नजदीक पहुच चुके थे, लेकिन आखिरी क्षण मे उनके प्रयासो को निष्फल होना पडा था।

वह यह समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि प्रशासकीय और सैनिक दृष्टि से १९४८ के वाद भारत मे रुके रहना असभव है। इसके अलावा उन्होने समय की मर्यादा पर कोई विशेप जोर नही दिया ओर न लार्ड वेवल की ही कोई चर्चा की। लार्ड वेवल के सम्वन्ध मे कुछ न कहना नि सदेह एक खेदजनक वात थी, जिससे इन दुर्भावनापूर्ण अफवाहो को वल मिला कि सरकार और लौटनेवाले वाइसराय के वीच गभीर मतभेद है। क्रिप्स ने सारे भापण मे सशोधित मत्रिमडलीय मिशन-योजना के लिए दरवाजा खुला छोडने मे कोई कसर उठा नही रखी। अपने भापण के अत मे उन्होने कहा, "अव समय आ गया है, जब सारे भारत के, जिसमे दोनो सम्प्रदायवाले सव जगह फैले हुए है, व्यापक हितो को अलग-अलग सम्प्रदायो, अथवा उस महादेश के इस या उस भाग के सकीर्ण हितो के ऊपर प्राथमिकता दी जाय।"

लार्ड वेवल को क्यो एक तरफ हटा फेका गया है। उन्होने जोर दिया कि जब वह वापस आवे तो उनसे व्यक्तिगत वक्तव्य देने को कहा जाय।

जहा तक नये वाइसराय का सम्बन्ध है, "क्या वह परिस्थिति को सभालने का नया प्रयत्न करेगे, या उन्हे तथा दूसरे प्रतिष्ठित अधिकारियो को डेरा-डडा उठाने के लिए भेजा जा रहा है? मुझे कहना पडता है कि सारी कार्यवाही ऐसी दिखलाई देती है कि सरकार एक विपादपूर्ण और विनाशकारी सौदे को छिपाने के लिए युद्धकाल के हमारे तेजस्वी नेताओ का उपयोग कर रही है।"

इसके पश्चात् चर्चिल भविष्यवाणी के क्षेत्र मे उतर आये. "भारत का न केवल विभाजन किया जायगा, वरन् उसको अनेक खडो और वह भी बेतरतीब खडो मे बाट दिया जायगा। समय की मर्यादा बाधने से भारतीय दल होश मे न आयगे, वरन् अपनी मागे बढा देगे। इन दलो के भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने के दावे झूठे है। इन तथाकथित राजनैतिक वर्गो के हाथ मे भारत का शासन सौप कर हम मिट्टी की मूरतो के हाथ मे सत्ता सौप रहे है। कुछ ही वर्षो के बाद इनका नाम-निशान भी न रहेगा। सरकार अपने नये काम से यह पन्द्रह महीने की मर्यादा बाध कर नये वाइसराय को अपाहिज किये दे रही है।"

भारत के लिए समय की मर्यादा का निश्चित किया जाना उन्हे अनावश्यक लगा, जबकि फिलस्तीन के लिए उसका अभाव उन्हे खटक रहा था। क्या सभा विश्वास करेगी कि आज विशाल भारत मे जितनी ब्रिटिश सेना है, उससे तीन या चार गुना नन्हे से फिलस्तीन मे है? हमारी सेना के इस बटवारे मे उन्हे कोई तर्क नजर नही आता था। उनका एकमात्र रचनात्मक सुझाव यह था कि सेना के बटवारे का यह अनुपात उलटा कर दिया जाय-और बिल्कुल चर्चिलवादी ढग से उन्होने यह चकित करनेवाला सुझाव रक्खा कि जिलियाकस के सुझाव को स्वीकार कर मुस्लिम अल्पसख्यको की समस्या को सयुक्त राष्ट्र-सघ के सामने रख दिया जाय। अन्त मे वह इस दुखद निष्कर्ष पर पहुचे, "ब्रिटेन को उसके शत्रुओ से तो वहुतो ने बचाया है, लेकिन खुद के खिलाफ उसे कोई नही बचा सकता, किन्तु कम-से-कम एक बात तो हम जरूर कर सकते है। ऐसी शर्मनाक भागदौड मचाकर और ऐसी जल्दबाजी के साथ कुसमय अपना डेरा-डडा उखाडकर अपने दुख के चुभते शूलो पर शर्म की कालिख तो न पोते।"

जब एटली सरकारी पक्ष की ओर से बोलने को खडे हुए उस समय वायुमडल मे प्रतीक्षा व्याप्त थी, जो पहले दिखलाई नही पडती थी, बल्कि कल जब क्रिप्स बोल रहे थे, उस समय मजदूर दल के सदस्यो की कमी से मुझे आश्चर्य हुआ था। प्रश्नो के बाद वे सभी उठ कर बाहर चल दिये थे और तबतक सामूहिक रूप मे नही लौटे जबतक कि दूसरे दिन शाम को प्रधान मत्री ने बहस का अन्त नही किया।

एटली ने लोगो को निराश नही किया। मैने विविध विषयो पर एटली के

अनेक भाषण सुने है, परन्तु भारत पर, जो उनका विशेष विषय है, उनका भाषण सुनने का मेरे लिए यह पहला ही अवसर था। साइमन कमीशन के सदस्य के रूप मे उनका दो वर्ष काम करना स्पष्टत उनके जीवन का बहुत ही प्रभावकारी अनुभव था। इतिहास की दृष्टि से साइमन कमीशन के बारे मे यही सबसे खास बात थी। जो लोग चर्चिल तथा एटली के बीच का अन्तर समझने मे दिलचस्पी रखते है, उन्हे भारतीय पहलू की प्रधानता को नही भूलना चाहिए।

इस अवसर पर एटली ने अपने मशहूर प्रतिद्वन्द्वी पर तर्क के इतने शक्तिशाली शस्त्र चलाए, जिनकी मै उनसे अपेक्षा नही कर सकता था। उन्होने अपने नोट अलग रख दिए और सीधे हृदय से बोलना आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप प्रभावशाली शब्दो का प्रवाह फूट पडा। इससे उनकी शैली मे तो अन्तर नही पडा, किन्तु उनका भाषण असाधारण हो गया। इस व्यक्ति के अन्तस मे एक आग छिपी हुई थी और एक आध्यात्मिक ईमानदारी इसको बल पहुचाती थी। जब कभी कोई महान अवसर आ उपस्थित होता, वही ईमानदारी इसे ऊचे उठने मे सहायक होती।

चर्चिल को उन्होने नाजुक व्यग्यो से भेद डाला। यह एक ऐसी भिडन्त थी, जिसे कभी-कभी साधारण जनता नही समझ पाती, परन्तु जो निर्णायको की दृष्टि मे विजय सूचक होती है और ससद के अखाडे मे बाजी मार लेती है।

एटली ने इस सिद्धात का प्रतिवाद किया कि वेवल के व्यक्तिगत वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता है। उन्होने कहा, "यदि गेद फेकनेवाले को बदलना हो तो सदैव लम्बे-चौडे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नही होती।" जहा तक इस बात की आलोचना का सवाल था कि भारतीय नेताओ को सरकार मे शामिल क्यो किया गया और कामचलाऊ शासन क्यो चालू रक्खा जाता है, उन्होने कहा, "भारतीय समस्या का सार ही यह है कि वहा के राजनीतिज्ञो को यह समझने दिया जाय कि वे समस्याए क्या है, जिनका सामना उन्हे आगे चलकर करना पडेगा। बीते जमाने मे हमने जो सुधार किये उनमे सबसे बडा दोष यही था कि हमने जिम्मेदारी की बजाय गैर-जिम्मेदारी सिखाई है। सारे भारतीय नेता विरोधी पक्ष मे रहते चले आ रहे थे। अपने लबे अनुभव के आधार पर मै कह सकता हू कि हमेशा विरोध मे बने रहना कोई अच्छी चीज नही है।" इसके बाद उन्होने अल्प सख्यको के प्रति हमारी जिम्मेदारी का विषय छेडा। इस बारे मे उन्होने एक बडी पते की बात कही। उन्होने कहा कि चूकि परिगणित जातिया हिन्दू समाज-व्यवस्था का अग है, इसलिए ब्रिटिश राज इच्छा रहते हुए भी उनका उत्थान नही कर सका। एक-दो अपवादो को छोडकर हमारी नीति मौजूदा आर्थिक और सामाजिक ढाचे को स्वीकार कर लेने की थी।

"फिर अब, जब कि हम अपनी सत्ता समेट रहे है, हमसे यह क्यो कहा जाता है कि हम इन सब बुराइयो को साफ करके जायँ, नही तो हम जिम्मेदारी से भागने

के अपराधी होंगे? यदि कोई जिम्मेदारी थी तो उसे बहुत पहले पूर्ण किया जाना चाहिए था। मल बात यह है कि विलम्ब करने और लटके रहन मे उतना ही बडा खतरा है, जितना कि आग बढते जान मे।'' उन्होन यह कह कर अपने भाषण को समाप्त किया,। मुझे विश्वास है, समस्त सभा नय वाइसराय और उनके मिशन के प्रति शुभकामना प्रकट करेगी। यह विश्वासघात का नही, बल्कि उद्देश्य-पूर्ति का मिशन है।''

प्रधानमंत्री के भापण और खासकर उसके आखिरी भाग ने मौन रहनेवाले उनके समर्थको को जगा दिया। भारत के प्रति सकीर्ण और निष्क्रिय दृष्टिकोण रखनेवाले ये सदस्य उत्साह से उफन उठ। जब मत लिये गए तो ३३७ सरकार के पक्ष मे और १८५ विपक्ष मे आये।

हालाकि श्री एटली की यह अपील कि सभा की ओर से भारत के नेताओ और जनता को सद्भाव का सयुक्त सन्देश भेजा जाय, दलो के आधार पर मतदान होना नही रोक सकी थी, फिर भी इस ऐतिहासिक बहस से यही धारणा दृढ़ होती थी कि चर्चिल की सजीदा दलीलो के बावजूद सरकार और विरोधी पक्ष के बीच की खाई बहुत ही सकरी है।

लंदन, सोमवार, १० मार्च १९४७

आमतौर पर कहा जा सकता है कि अपने-आपको आगे आनेवाले राजनैतिक काम के लिए तैयार करने मे माउन्टबेटन ने बिल्कुल सिरे से शुरुआत की थी। वह भारत जा चुके है। पहली बार प्रिस ऑव वेल्स की १९२१ की यात्रा के समय उनके ए डी सा के रूप मे गये थे, फिर, अक्टूबर १९४३ और अप्रैल १९४४ के बीच सर्वोच्च मित्रराष्ट्रीय कमाडर के रूप मे नई दिल्ली उनका प्रधान कार्यालय रहा था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनो मे जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली मुलाकात हुई। लार्ड वेवल के सुझाव पर नेहरू प्रवासी भारतीयो को देखने मलाया गये थे। यह बहुत ही सफल और सुखद भेंट थी। मैं इस मौके पर मौजूद था और स्पष्ट था कि दोनो व्यक्तियो ने एक-दूसरे पर गहरा असर डाला था।

अपनी नियुक्ति की घोपणा होते ही माउन्टबेटन मुलाकातो और बैठको के ताते मे पड गये। वह सम्राट से मिल चुके थे, जिनकी वैधानिक स्थिति पर गहरा असर पडा था। मंत्रिमडल की भारत-वर्मा-कमेटी से भी वह लगातार चर्चा कर रहे थे। इस कमेटी मे एटली, क्रिप्स, अलेक्जेन्डर और पेथिक लारेंस सम्मिलित थे और सरकार की भारत-सम्बन्धी नीति निश्चय करने और उसके नियत्रण का

काम इसी के जिम्मे था। सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुखों और इंडिया आफिस के विशेषज्ञों में भी विस्तार से चर्चाएं हो चुकी थीं।

सबसे अधिक ध्यान दिया गया था गवर्नर जनरल को दिये जानेवाले आदेश-पत्र के संशोधन के प्रश्न पर। यह आदेश-पत्र सरकारी निर्देशों का लेखा होता था, जिनपर अमल करना गवर्नर-जनरल का कर्तव्य था। अपने लिए नया आदेश-पत्र जारी करवाने में माउन्टबेटन का काफी हाथ था। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री एटली की ओर से उनको लिखे गये एक पत्र के रूप में यह आदेश-पत्र दिया जाय।

यह स्वीकार हो जाने पर उसका मसविदा तैयार करने में भी उनका काफी हाथ रहा। आदेश-पत्र में नीति-सम्बन्धी निम्नलिखित लक्ष्य उनके पथ-प्रदर्शन के लिए शामिल किये गए

१ ब्रिटिश सरकार का निश्चित उद्देश्य ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक एकात्मक सरकार की स्थापना करना है। इस सरकार की स्थापना मंत्रिमंडल-मिशन योजना के अनुसार विधान सभा द्वारा की जायगी और जहां तक संभव होगा यह सरकार "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत" रहेगी। ये शब्द "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत" माउन्टबेटन के विशेष आग्रह पर जोड़े गए। उनकी धारणा थी कि उन्हें ऐसा हल निकालने का प्रयास करना चाहिए जिससे इतनी सद्भावना पैदा हो कि भारतीय दल राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत रहना पसन्द करें।

२ चूंकि मंत्रिमंडल-मिशन-योजना दोनों बड़े दलों की रजामन्दी से ही ब्रिटिश भारत में लागू होगी, इसलिए किसी भी दल पर उसके स्वीकार करने के लिए जोर डाले जाने का सवाल नहीं उठता। यदि १ अक्तूबर तक माउन्टबेटन को ऐसा लगे कि एक सरकार के आधार पर समझौता होने की कोई संभावना नहीं है तो वह ब्रिटिश सरकार के सामने सुझाव रक्खें कि निश्चित तिथि पर सत्ता हस्तान्तरण किये जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

एटली के पत्र मे जितने महत्त्वपूर्ण आदेशो का उल्लेख है उतने महत्त्वपूर्ण आदेश शायद ही पहले कभी किसी सरकार द्वारा किसी वाइसराय को दिये गए हो।

लंदन, मगलवार, ११ मार्च, १९४७

मुलाकातो के नाते मे माउन्टबेटन ने विरोधी नेताओ को सम्मिलित करने का विशेष ध्यान रक्खा है। इसमे से कुछ चर्चाए बिल्कुल खानगी और अनौपचारिक रही। आज रात को वह लार्ड सेमुअल से पहली भेट करने के लिए मेरे निवास-स्थान पर आये। लार्ड सेमुअल कुछ मिनट पहले आ गये, माउन्टबेटन बिल्कुल समय पर आये।

उन्होने जोर देकर लार्ड सेमुअल को यह समझाने का प्रयत्न किया, कि जहा तक उनकी नियुक्ति का सवाल है, उसे बादशाह की हार्दिक स्वीकृति प्राप्त है। बादशाह ने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि वह राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर इसे स्वीकार कर ले। एटली ने इस विषय मे सारी आवश्यक औपचारिकता पूरी की थी और विरोधी दल का कहना बिल्कुल गलत था कि यह नियुक्ति केवल प्रधानमत्री ने ही की थी। उन्होने कहा कि मेरी समझ मे नही आता कि समय की मर्यादा का विकल्प क्या था ? जून, १९४८ भले ही लम्बी अवधि न हो, परन्तु इसकी सिफारिश स्वय वेवल ने की थी। अपना व्यक्तिगत मत देते हुए उन्होने कहा कि उस समय सत्ता ग्रहण करना सबसे अच्छा होगा, जबकि देश मे उत्तेजना सबसे कम हो। बगाल और बिहार हाल के उपद्रवो के बाद लगभग शान्त हो गये है, किन्तु पजाब मे सकट अनिवार्य प्रतीत होता था।

कुछ समय से पजाब की स्थिति मे बहुत तनाव था। मिली-जुली सरकार के मुस्लिम प्रधानमत्री मुस्लिम लीगियो के हाथो हत्या से बचने के लिए पाच महीनो से रात को इस घर से उस घर मे छिपते फिरते थे। माउन्टबेटन को लगता था कि शायद सीमाप्रान्त मे भी सकट पैदा होगा।

उन्होने वह चेतावनी दुहराई, जो उन्होने सर ह्यूबर्ट रेन्स को बर्मा के गवर्नर का पद सभालने के पूर्व दी थी। उन्होने कहा था कि रेन्स को तबतक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबतक कि रगून की स्थिति भयानकतम रूप धारण नही कर लेती। परन्तु यह कर्तव्य की भावना से जल्दी चले गए। फलत रगून की हडताल के कुछ दिन पूर्व वहा पहुचे। इससे हडताल का कुछ दोष उनके सिर पर भी मढा गया। माउन्टबेटन ने कहा, "जहा तक मेरा सम्बन्ध है, कोई भी मुझे भारत के वर्तमान उपद्रवो के लिए जिम्मेदार नही समझेगा। यह मेरे लिए अगली चर्चाओ की दृष्टि से एक बडी सुविधा की बात है।"

उन्होंने सलाह मागी कि उन्हे भविष्य मे किस दिशा का आन्दोलन करना चाहिए। बाद मे अपने प्रश्न का उत्तर स्वय ही देते हुए और मन-ही-मन सोची बात को शब्दो मे व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "मै खास-खास नेताओ के साथ शिमला मे एक सप्ताह तक व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना पसन्द करूगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट और बेलाग विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा।" सेमुअल अधिकतर सुनते रहे, परन्तु उन्होंने सत्ता-हस्तातरण के बाद सम्राट् की सरकार के साथ वैधानिक सबध कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाइसराय के पद को कायम रखकर भी शायद ऐसा करना अनुचित न होगा।

मुझे इस भेट की व्यवस्था करने मे बडी खुशी हुई, क्योकि उम्र और दृष्टि-कोण के स्पष्ट अन्तर के बावजूद इन दोनो व्यक्तियो मे बहुत-कुछ साम्य था। लार्ड सभा मे सेमुअल का प्रभाव बहुत अधिक है और आगे आनेवाले महीनो मे उनकी सद्भावना लार्ड सभा मे उदार दल की शक्ति की तुलना मे कही अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी।

लदन, बृहस्पतिवार, १३ मार्च, १९४७

शायद माउन्टबेटन की सबसे जटिल प्रारम्भिक कठिनाई यह है कि भारत के लिए रवाना होने से पहले भारतीय सिविल और सैनिक कर्मचारियो के (जिन्हे सेक्रेटरी ऑव स्टेट की सर्विस भी कहते है) मुआवजे के प्रश्न पर एक ऐसी नीति कैसे तय करे, जिसे सबका समर्थन प्राप्त हो। इस प्रश्न पर शुरू मे ही उन्होंने अपने विचार अपने विशिष्ट उत्साह और दृढता के साथ जाहिर किये थे। जिस हल पर वह आग्रह कर रहे थे, वह आज आखिरी तौर से स्वीकार कर लिया गया था।

जहा तक सेक्रेटरी ऑव स्टेट की सर्विसो (कर्मचारियो) का प्रश्न है, शुरू-शुरू मे उनसे तीन खास वादे किये गए थे। पहला यह कि वैधानिक परिवर्तनो के कारण उनकी नौकरी खत्म होने पर उन्हे एकमुश्त मुआवजा दिया जायगा, जिसकी दरे युद्धकालीन नौकरियो के मुआवजे से किसी हालत मे कम न होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हे एकमुश्त उससे कही बडी रकम मिलेगी, जितनी उन्हे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होती। दूसरा यह कि वे नई भारत सरकार के अन्तर्गत काम करना चाहे या न चाहे, सेक्रेटरी ऑव स्टेट के साथ उनके सबध खत्म हो जायगे। इसलिए मुआवजा उन्हे हर हालत मे मिलेगा। तीसरा यह कि नई सरकार के अन्तर्गत काम करने के लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव नही डाला जायगा और यदि नई भारत सरकार इस दृष्टि से उनके लिए नीची दरे तय करने की कोशिश करेगी तो उसका हर प्रकार से विरोध किया जायगा। इसमे यूरोपीय और भारतीय कर्मचारियो के बीच किसी प्रकार का भेद नही किया जायगा।

भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने जल्दी ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुआवजा देने के सिद्धांत और शर्तें दोनों के ही बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को अपनी पूर्वगामी सरकार के वादों से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि पूर्वगामी सरकार ब्रिटिश पार्लमेंट और सेक्रेटरी आव् स्टेट के नियंत्रण में काम करनेवाली सरकार थी। उन्होंने कहा कि यदि मुआवजे की दर इस आधार पर ठहराई गई कि वह युद्धकालीन नौकरियों के मुआवजे से कम न होगी तो ब्रिटिश सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय मामलों के पार्लमेंटरी अण्डर-सेक्रेटरी आर्थर हेण्डरसन जनवरी में सरदार पटेल को समझाने और इस योजना के लिए राजी करने का निष्फल प्रयास करने दिल्ली गये। इस असफलता से माउन्टबेटन ने अपना विचार नहीं बदला। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मूल योजना को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि वह सिर्फ अंग्रेजों पर लागू होगी। अगर भारत सरकार भुगतान न करे तो उन्हें यह कहने का अधिकार दिया जाय कि उसे देने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार लेगी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि अकेले ब्रिटिश सरकार को यह बोझा उठाना पड़ा तो भारतीय पौंडपावने की रकम को तय करते समय इस खर्चे को ध्यान में रक्खा जायगा।

: ३ :

भारत में पहला सप्ताह

वाइसराय-भवन, नई दिल्ली,
शनिवार, २२ मार्च, १९४७

ठीक १२-३० बजे दोपहर हम पालम के हवाई अड्डे पर उतरे। प्रधान सेनापति फील्ड मार्शल आचिन्लेक हमारा स्वागत करने हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह उनका सौजन्य था, क्योंकि दो घंटे बाद ही माउन्टबेटन का स्वागत करने उन्हें फिर हवाई अड्डे पर आना था। अपने सामान की चिन्ता किये बिना हम वाइसराय-भवन की विशाल मोटरों में सवार होकर चल पड़े।

वाइसराय-भवन में पहुंचते ही हमें बतलाया गया कि हमें वेवल-परिवार के साथ भोजन करना है। वाइसराय के नाते यह उनकी अन्तिम दावत है। यह विश्वास करना कठिन है कि कल सवेरे ही वह यहां से प्रस्थान करनेवाले हैं। कैसा अजीब संयोग है कि पहली बार मैं १९ अक्टूबर, १९४३ को दिल्ली आया था— वेवल द्वारा लिनलिथगो से पद का भार लेने के ठीक एक दिन बाद।

तीसरे पहर मुख्य सहन और वाइसराय-भवन के दरबार हाल को जानेवाली सीढियो पर बडी चहल-पहल थी। गर्वनर जनरल के सवारो और रक्षको के साथ माउन्टबेटन खुली बग्घी मे बैठकर पौने चार बजे वहा पहुच गये। लाल मखमल बिछी हुई सीढिया चढते हुए वे ऊपर पहुचे, जहा वेवल-दम्पती ने उनका स्वागत किया। काफी देर तक वह वहा खडे बाते करते रहे, जिससे फोटोग्राफर उनके चित्र खीच सके।

रात के भोजन के पहले और बाद मे वेवल और माउन्टबेटन के बीच विचार-विमर्श जारी रहा। माउन्टबेटन ने वेवल से भारतीय समस्या के बारे मे सारी जानकारी प्राप्त करने मे कोई कसर नही छोडी।

बिना जरा भी समय नष्ट किये माउन्टबेटन ने गाधीजी और जिन्ना को दो सीधे-सादे पत्र भेजकर आशा प्रकट की कि दोनो नेता जल्दी ही उनसे मिलने आ सकेगे। जहा तक गाधीजी का सम्बन्ध था वह उनके बिहार मे रहने का मूल्य समझते थे। गाधीजी बिहार के दगाग्रस्त इलाको का दौरा कर रहे थे। गाधीजी इतने व्यस्त थे कि इस बात मे भी शक था कि सोमवार को लाल किले की छाया मे प्रारम्भ होनेवाले एशियाई सम्मेलन मे भाग लेने दिल्ली आयगे।

नई दिल्ली, रविवार, २३ मार्च, १९४७

सवेरे ठीक सवा आठ बजे वेवल-दम्पती ने प्रस्थान किया। आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए चैन का दिन नही था। कल के शपथ विधि-समारोह के प्रचार के विषय मे काफी प्रशासकीय घबराहट दृष्टिगोचर हो रही थी। माउन्टबेटन के निवास मे जाकर मैंने मनोनीत वाइसराय से कल के समारोह के बारे मे चर्चा की।

माउन्टबेटन को नई बात सूझी है—शपथ-विधि के समय उनका छोटा-सा भाषण। जार्ज एबेल का तैयार किया पहला मसविदा उन्होने मुझे पढकर सुनाया। मेरा खयाल था कि भाषण का विचार और मौका दोनो उपयुक्त है। शाम के भोजन के समय स्वय माउन्टबेटन द्वारा सुधारा गया मसविदा मेरे सामने आया। इसके एक वाक्य से मुझे चिन्ता हुई। ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय पर टीका करने के बाद कि सत्ता हस्तातरण का काम जून,१९४८ तक पूरा हो जायगा, उन्होने कहा, "अगर छ -महीने के पूर्व कोई हल नही निकलता तो उसे कार्यरूप मे परिणत करने के लिए काफी समय नही रह जायगा।" मुझे लगा कि इन शब्दो को गलत समझा जा सकता था और इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता था कि समय-मर्यादा से बचाव का यह एक तरीका है। माउन्टबेटन की पहली प्रतिक्रिया तो यह हुई कि चूंकि सरकार ने उन्हे अक्तूबर तक प्रगति की रिपोर्ट देने का अधिकार सौपा था, इसलिए इसे अभी से कह देने मे क्या हर्ज था ?

अभी दिन का ठीक एक वजा था और एक ए डी सी ने आकर खबर दी कि वाइसराय महोदय ने अपना भाषण दोहरा लिया है और उसे पत्रो को देने के लिए उन्हे क्या करना होगा ? मुझे यह देख कर राहत मिली कि वह खतरनाक वाक्य उसमे से गायव था ।

नई दिल्ली, सोमवार, २४ मार्च, १९४७

शपथ-विधि के लिए तडके ही उठ बैठा । इसका स्वरूप वेवल की शपथ-विधि के समान था, जो मै १९४३ मे दरबार हाल मे देख चुका था। छत से वजने-वाली वही तुरही, जो समारोह की सूचक थी, इकट्ठे ए डी सी लोगो का वही जलूस, जिसके साथ चलकर 'हिज एक्सेलेसी' अपने सिहासनो के पास पहुचे । इस सब शान-शौकत के वीच माउन्टबेटन ऐसे फबते थे मानो इसीके लिए पैदा हुए हो । 'नाइट ऑव गार्टर' का गहरा नीले रग का फीता और सीने पर सम्मान के अन्य तमगे और पट्टिया पहने लार्ड माउन्टवेटन वहुत प्रभावशाली लग रहे थे ।

लेडी माउन्टवेटन सुकुमारता की साकार प्रतिमा प्रतीत हो रही थी । नये ताज के अलावा वह अपने सब युद्धकालीन तमगे और अन्य सम्मानीय फीते सफेद जरी की पोशाक के ऊपर लगाये हुए थी। कीमती लाल मखमल के पर्दो के अन्दर छिपी हुई बत्तियो के हलके प्रकाश मे लाल और सुनहला काम किये हुए सिहासन वडे भले प्रतीत हो रहे थे ।

भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने माउन्टवेटन को शपथ दिलाना शुरू किया । माउन्टबेटन उनके कहे को दोहराते गए और अपने लम्बे नाम को वोलने मे एकबार भी नही अटके ।

पूरा समारोह चौथाई घटे मे समाप्त हो गया । माउन्टबेटन के भाषण मे केवल चार मिनट लगे। सिहासनो के दोनो ओर नये भारत के नेता खडे थे, जिनके कन्धो पर आनेवाले सप्ताहो मे इतनी भारी जिम्मेदारी पडनेवाली थी । मैने देखा कि नेहरु और लियाकतअली दोनो ने भाषण को वडे गौर से सुना । इस भाषण से उन्हे वडा आश्चर्य हुआ ।

दो महत्त्वपूर्ण लोग इस समारोह से गैरहाजिर थे--और शायद बिना कोई वजह वतलाये। ये थे नवाव भोपाल और महाराजा वीकानेर। नवाव भोपाल और महाराजा वीकानेर दोनो माउन्टवेटन के पुराने दोस्त थे। राजा लोग समारोहो से सम्वन्धित शिष्टाचार को, और खासकर वाइसराय से सम्वन्धित समारोह को वहुत महत्व देते थे । यह वात ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता था कि उनकी अनुपस्थिति उनके वीच पैदा हुई फूट और सघर्ष का अच्छा-खासा सकेत था ।

माउन्टवेटन ने आज तीसरे पहर तीन घटे नेहरू और दो घटे लियाकतअली के

साथ बिताए। उन्होने लियाकत के बजट पर चर्चा की, जो इस समय दोनो दलो के बीच झगडे का कारण बना हुआ था। वेवल ने माउन्टबेटन को चेतावनी दी थी कि जब वह अपनी कार्यकारिणी कौसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता करेगे तो उन्हे इस पेचीदा समस्या से निबटना पडेगा। अन्तरिम सरकार के वित्तमत्री के नाते सब बडी आमदनियो पर भारी कर लगाने का प्रस्ताव कर लियाकत ने काग्रेस को बडी मुसीबत मे डाल दिया था। अपने धनी समर्थको को बचाने के लिए अब उसे अपनी प्रगतिशील और समतावादी घोषणाओ के प्रतिकूल उनके लिए राहत की माग करनी पडेगी। आम भावना यह थी कि कोई समझोते का रास्ता निकल आयगा, क्योकि अपने धनी समर्थको पर कर लगाने मे मुस्लिम लीग और काग्रेस, दोनो ही एक सीमा के आगे नही जा सकेगी।

नई दिल्ली, मंगलवार, २५ मार्च, १९४७

मेने माउन्टबेटन के कर्मचारी-मडल की पहली बैठक मे भाग लिया, जिसमे इस्मे, मिएविल, जार्ज एब्रेल, ब्रोकमेन, अर्सकिन क्रम और मे सम्मिलित हुए। माउन्टबेटन का इरादा था कि प्रतिदिन ऐसी अनौपचारिक बैठक हुआ करेगी, जिससे वह अपने विचारो को बिना किसी छिपाव के सबके सामने रख सकेगे। माउन्टबेटन ने कल नेहरू और लियाकत से हुई मुलाकातो का मजेदार विवरण सुनाया। महाराज बीकानेर और नवाब भोपाल से हुई मुलाकात की बात भी उन्होने बतलाई, जो शपथ-समारोह के समय अपनी गैरहाजिरी की सफाई देने आये थे।

नवाब भोपाल और महाराज बीकानेर की मुलाकातो से राजाओ मे फैली फूट की गम्भीरता का पता चला। इससे नवाब भोपाल बहुत दुखी थे। उन्हे लगता था कि महाराज बीकानेर तथा उनके समान अन्य विद्रोही विधान सभा मे भाग लेकर काग्रेस की कठपुतली बन रहे थे और रियासतो की सोदा करने की ताकत को क्षीण किये दे रहे थे। नवाब भोपाल का विचार था कि समय की मर्यादा का पालन करना असभव होगा और यदि इसपर अमल किया गया तो खून-खराबी और अव्यवस्था फैलेगी। उन्होने बडी चिता से माउन्टबेटन से पूछा कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। माउन्टबेटन ने कहा कि इससे बचने का एक, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह यह कि सारे भारतीय दल हमसे यही बने रहने को कहे, जिसकी बहुत ही कम आशा की जा सकती थी। नवाब भोपाल का खयाल था, जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, ऐसा निमत्रण आ भी सकता है।

माउन्टबेटन ने महाराज बीकानेर से भी इस बारे मे चर्चा की। महाराज बीकानेर का खयाल ऐसा नही था। उन्होने तथाकथित 'विद्रोही' राजाओ का समर्थन

किया। उन्होने फूट को दुर्भाग्यपूर्ण वतलाते हुए इस बात पर जोर दिया कि नवाव भोपाल ने ही अन्तरिम सरकार के प्रति अपने रुख से राजाओ के बीच साम्प्रदायिकता को उभाडा है। 'विद्रोही' राजा विधान सभा मे भाग लेकर नये केन्द्रीय शासन को अपार बल पहुचायगे और यह प्रयास करेगे कि वह पूर्णत काग्रेसी शासन न वन जाय।

नेहरू के साथ माउन्टवेटन की पहली मुलाकात वहुत महत्त्वपूर्ण थी। नेहरू ने मत्रिमडल-मिशन के बाद की सब बडी घटनाओ पर अपनी राय दी। माउन्टवेटन का खयाल था कि नेहरू का दिया व्यौरा काफी सही था और उस जानकारी से मेल खाता था, जो उन्होने लन्दन मे प्राप्त की थी। नेहरू की राय मे लार्ड वेवल ने एक भारी भूल की थी। उन्हे मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार मे शामिल होने का वुलावा न देकर थोडा इन्तजार करना चाहिए था। मुस्लिम लीग शामिल किये जाने की खुद माग करती। उन्होने मुस्लिम लीग की एक खानगी बैठक का जिक्र किया, जिसमे जिन्ना पहले ही इस प्रश्न पर घुटने टेक चुके थे।

माउन्टवेटन ने नेहरू से पूछा कि जिन्ना के बारे मे उनकी क्या राय है। नेहरू ने याद दिलाई कि अपनी नई पुस्तक मे वह इस पर प्रकाश डाल चुके है। फिर भी उन्होने जिन्ना के व्यक्तित्व के बारे मे अपना मार्मिक विश्लेषण उपस्थित किया। नेहरू ने कहा कि जिन्ना के बारे मे समझने की खास वात यह है कि वह एक ऐसे इसान है, जिन्हे जीवन मे वहुत देर मे सफलता मिली—६० वर्ष के वाद। इसके पहले वह भारतीय राजनीति की कोई बडी हस्ती न थे। वह सफल वकील थे, लेकिन कोई खास अच्छे नही। उनको जो सफलता मिली थी, वह मुख्यत उत्तेजनाजन्य थी और काफी वडी थी। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उनमे स्थायी रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण पर जमे रहने की क्षमता थी। यही वात वह वडे एकागी दिमाग से १९३५ से करते आ रहे है। वह वखूवी जानते थे कि पाकिस्तान रचनात्मक आलोचना के सामने ठहर नही सकता और उन्होने यह व्यवस्था कर ली थी कि उसे रचनात्मक आलोचना का सामना नही करना पडेगा।

फिर माउन्टवेटन ने नेहरु से पूछा कि उनकी राय मे आज भारत की सवसे वडी समस्या क्या है। नेहरू ने तुरन्त उत्तर दिया—आर्थिक। इस पर माउन्टवेटन ने पूछा कि जिस ढग से अन्तरिम सरकार इस समस्या से निवट रही है, क्या वह उससे सन्तुष्ट है? नेहरू ने कहा, "नही।" लेकिन स्थिति मुस्लिम लीग ने असभव वना रखी थी, जो केन्द्र की ओर से की जाने वाली आर्थिक योजना की हर कोशिश को नाकाम करने पर तुली हुई थी। अगर ये योजनाए सफल हो गई तो वास्तव मे पजाव के वारे मे पाकिस्तान का दावा कमजोर पड जायगा। नेहरू ने सुझाव रक्खा, जो वह पहले भी रख चुके थे कि पजाव का शासन साम्प्रदायिक आधार पर तीन भागो मे वाट दिया जाय। इनकी एक केन्द्रीय कमेटी भी रहे,

जो बडे और असाम्प्रदायिक मसलो की देखरेख करे। वेवल द्वारा इस महीने के आरम्भ मे पजाब पर लागू धारा ९३[1] के अन्तर्गत उत्पन्न गति-अवरोध को मिटाने का उनकी राय मे यही एकमात्र ढग है।

सत्ता-हस्तातरण के बाद भारतीय सिविल सर्विस के कर्मचारियो को दिये जानेवाले मुआवजे का पेचीदा सवाल भी इस मुलाकात मे उठाया गया। नेहरू का विचार था कि जिन कर्मचारियो को अपने पदो पर बने रहने का न्यौता दिया जा रहा था, उन्हे मुआवजा देने की इच्छा करना पागलपन था। नई सरकार उन्हे पहले की ही शर्तो पर काम पर रखने का वचन देगी। माउन्टबेटन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने वादो मे कैसे मुकरेगी ? नेहरू ने कहा कि जहा तक ब्रिटिश लोगो का सवाल था, वह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी, उन्हे इतने भारी मुआवजे क्यो दिये जाने चाहिए। इससे उनको अपनी नौकरिया छोडने का ही प्रोत्साहन मिलेगा। और भारतीयो के बारे मे नेहरू ने कहा कि यह स्थिति यह है कि वे अपने देशवासियो की सेवा ही करते रहेग। अभी जो योजना थी, वह वास्तव मे प्रमादपूर्ण थी। फिर भी, माउन्टबेटन ने दृढता से इस पर उनके समर्थन की माग की। उन्होने कहा कि शायद नेहरू ने ब्रिटिश जनता की मन-स्थिति को गलत समझा है। मुआवजे की दर जितनी ऊची होगी और शर्ते जितनी स्पष्ट, ब्रिटिश सिविल सर्विस कर्मचारियो द्वारा अपने पदो पर काम करते रहने की सभावना भी उतनी ही अधिक होगी।

माउन्टबेटन की राय थी कि नेहरू ने बहुत ही स्पष्टवादिता और न्याय की भावना दिखलाई, बल्कि उन्होने एक जगह यह सुझाव देकर माउन्टबेटन को चकित कर दिया कि एक ऐसे आग्ल-भारतीय सघ की स्थापना हो, जिसमे नागरिक समता हो। यह सम्बन्ध वास्तव मे राष्ट्रमडल के दर्जे से कही निकट का था। और राष्ट्र-मडल के दर्जे को नेहरू मनोविज्ञान और भावना की दृष्टि से अमान्य समझते थे।

मुलाकात की समाप्ति पर जब नेहरू चलने को हुए तो माउन्टबेटन ने उनसे कहा, "मि नेहरू, आप मुझे ब्रिटिश-राज का बोरिया-बिस्तर समेटनेवाला अन्तिम वाइसराय न समझकर नये भारत का मार्ग प्रशस्त करनेवाला पहला वाइसराय समझे।" नेहरू ने बडी भावुकता के साथ पलटकर देखा और फिर मुस्कराते हुए बोले, "अब मैं समझा कि आपके जादू को लोग इतना खतरनाक क्यों बतलाते है।"

---

[1] यहा इशारा भारत सरकार के १९३५ के विधान की धारा ९३ से है, जिसके अन्तर्गत वाइसराय और प्रान्तो के गवर्नरो को यह अधिकार था कि किसी प्रकार की सार्वजनिक गडबड होने पर वे विशेषाधिकारो का उपयोग कर स्वयं शासन की बागडोर संभाल सकेंगे।

लियाकतअली ने चर्चा के समय माउन्टबेटन के शपथ-विधि के समय दिये गए भाषण के बारे मे प्रश्न पूछा। वह जानना चाहते थे कि यह किसकी सूझ थी। माउन्टबेटन ने कहा कि इसका उत्तर तो वह तत्काल दे सकते है। यह बिल्कुल उनकी सूझ थी और इसके पीछे किसी का हाथ नही था, बल्कि मेरे स्टाफ के कुछ लोग इसके खिलाफ ही थे। लियाकत ने कहा, "यह सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योकि कम-से-कम तीन बडे ओहदेवाले और जानकार क्षेत्रो ने मुझे विश्वास दिलाया था कि आपने यह भाषण कांग्रेस के अनुरोध पर दिया था।" जिस साम्प्रदायिक सन्देह का वातावरण फैला हुआ था, यह छोटी-सी घटना उसका अच्छा उदाहरण थी। कोई भी पक्ष अपने विरोधी पक्ष को नीचे गिराने के किसी मौके को हाथ से नही जाने दे रहा था।

नेहरू के पजाब से सम्बन्धित सुझावो के बारे मे सबसे मजेदार प्रकाश पडा पजाब के गवर्नर सर ईवान जेनकिन्स के तार से। जेनकिन्स ने सूचित किया था कि एक प्रभावशाली सिख नेता ज्ञानी करतारसिह ने कहा है कि अगर कांग्रेस और लीग के बीच ऐसा समझौता नही हुआ, जो सिखो को मजूर हो, तो सिख लोग पजाब के विभाजन की माग करेगे। इस बीच वे अपनी सारी शक्ति लगाकर वहा मुस्लिम लीग का मत्रिमडल बनाये जाने की हर कोशिश का विरोध करेगे। इस भाषण का महत्त्व इस बात से और भी बढ जाता था कि सिखो ने पजाब के विभाजन के बारे मे एक प्रस्ताव पेश करने के लिए कांग्रेस को राजी कर लिया था। इसे वेवल ने माउन्टबेटन के आने के एक सप्ताह पहले स्वीकार भी कर लिया था।

नई दिल्ली, बुधवार, २६ मार्च, १९४७

माउन्टबेटन ने कल रेलवे मत्री डा जान मथाई, राजनैतिक विभाग के सेक्रेटरी कोरफील्ड और सरदार पटेल से भेट की। मथाई ईसाई है और किसी भी अर्थ मे किसी दल के आदमी नही है। मथाई का कहना था कि आज की परिस्थिति की सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे है, धीरे-धीरे उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और दोनो दलो मे उनके प्रति अविश्वास और नापसन्दगी बढती जा रही है। मथाई ने कहा कि उदाहरण के लिए मैंने लियाकत के बजट का भरसक समर्थन किया, पर देखता क्या हू कि 'डान' मेरे ऊपर बुरी तरह से बरस पडा है।

वाइसराय यहा ताज के प्रतिनिधि है। इस नाते कोरफील्ड का काम उन्हे देशी राज्यो के बारे मे हर प्रश्न पर वैधानिक सलाह देना था। कोरफील्ड ने किंचित् कटुता के साथ कहा कि महाराज बीकानेर ने विधानसभा मे प्रवेश कर राजाओ की सौदा करने की ताकत बुरी तरह कमजोर कर दी है। इस विवाद मे कोरफील्ड

साफ तौर से नवाब भोपाल के हामी थे । सत्ता-हस्तातरण मे वह राजाओ को एक भावी तीसरी शक्ति के रूप मे देखते थे ।

सरदार पटेल से अपनी मुलाकात के बारे मे माउन्टबेटन जरा शकित थे। सरदार पटेल काग्रेस हाई कमाण्ड के लौह पुरुष के रूप मे विख्यात थे । लेकिन सरदार पटेल की आखो मे हँसी की चमक देखने मे उन्हे देर नही लगी। सारी समस्या के बारे मे उनका दृष्टिकोण साफ और अटल था । भारत को मुस्लिम लीग से पीछा छुडाना ही पडेगा। लीग वास्तव मे पजाब की घटनाओ के बारे मे घमण्ड से छाती फुलाये घम रही थी । जरूर उसका दिमाग खराब था। जबतक उन्होने मुआवजे की समस्या पर हाथ नही रखा तबतक तो शान्ति रही, लेकिन इसकी चर्चा छिडते ही पटेल ने हाथ ऊचाकर कसम खाई कि यदि किसी भारतीय ने मुआवजा लेना मजूर किया तो उसे फिर कभी नौकर नही रखा जायगा।

भारतीय सिविल सर्विस के मारिस जिनकिन के यहा रात के खाने पर के एम पणिक्कर भी मौजूद थे ।

मने उनसे पूछा, "अगर आप माउन्टबेटन की जगह होते तो क्या करते ?" उन्होने तुरन्त उत्तर दिया कि नौसेना की युद्ध-नीति मे निपुण माउन्टबेटन को समझना चाहिए कि ब्रिटेन का हित एक ठोस केन्द्रीय राज्य का निर्माण करने मे ही है । यह भारत के विशाल समुद्रतट, तीस करोड से अधिक आबादी और भौगोलिक एव धार्मिक एकता पर आधारित होना चाहिए । उन्होने कहा कि भारत हाथी है और पाकिस्तान उसके दो कान है। हाथी अपने कानो के बिना भी काम चला सकता है। बिना लाग-लगाव के उन्होने स्वीकार किया कि जिन्ना की माग मूलत तर्क-सगत है। चार कमरो वाले घर मे से वे केवल एक कमरा ही माग रहे है। लेकिन वह चाहते सिर्फ यही है कि इस कमरे मे किसी और का दखल न रहे। स्थानीय मुस्लिम बहुमत को वह एक केन्द्रित और मजबूत हिन्दू सरकार के हाथो नही सौपना चाहते । पणिक्कर का विचार यही था कि भारत बुनियादी तौर से जितनी एकता चाहता है उससे बडी एकता हमे उसपर नही लादनी चाहिए। पजाब के बारे मे नेहरू के त्रि-दली सुझाव काग्रेस द्वारा हिन्दुस्तान-पाकिस्तान विभाजन स्वीकार किये जाने का पहला सकेत है। सिखो के साथ उन्हे जो अनुभव हुआ था उससे जिन्ना समझ गये होगे कि पजाब की एकता बिलकुल असभव थी।

फिर उन्होने राजाओ की समस्या की चर्चा छेडी। बीकानेर के दीवान और प्रमुख सलाहकार के नाते पणिक्कर का पद बडे महत्त्व का था। उन्होने और जयपुर के दीवान सर वी टी कृष्णमाचारी ने राजपूताने के राजाओ की तरफ से पहल की थी। पणिक्कर मानते थे कि नरेन्द्रमडल के वर्तमान चासलर नवाब भोपाल हिन्दू रियासत के मुसलमान शासक होने के नाते बडी मुश्किल मे पड गये है। उनका कहना था कि किसी रियासत को व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नही उठाना

चाहिए । जो कुछ भी किया जाय, वह सामूहिक रूप से और चासलर की सलाह से, किन्तु यह कहकर चासलर के नाते वह सार्वभौमता के एक नये सिद्वात का प्रतिपादन कर रहे थे । पणिक्कर ने कहा कि सार्वभौमता की उनकी जो कल्पना है, इसमे चासलर को इस बात मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही था कि कोई राजा विधानसभा मे जाना चाहता है या नही । यह बात तो उस राज्य-विशेष और ब्रिटेन से सम्बन्ध रखती थी ओर इस पर सीधे ताज के प्रतिनिधि की ओर से आये आदेश का भी असर पड सकता था ।

सोलह बडी रियासतो मे से लगभग दस ने विधानसभा मे अपने स्थान ग्रहण कर लिये थे । राजाओ के बारे मे ब्रिटेन द्वारा युद्धोत्तर-काल की परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाना भी जरूरी था । जबतक राजा लोग ब्रिटेन की "फूट डालो और राज करो" नीति के मोहरे रहे, तबतक वे राज के शक्तिशाली स्तम्भ बने रहे । लेकिन ब्रिटिश राज के ढीला पडते ही राजाओ की शक्ति अपने-आप घटने लगी । लाचार उन्हे अब उस राजनैतिक ढाचे के नीचे शरण लेनी पडेगी जो ब्रिटिश राज की जगह लेगा । उत्तरी भाग के राजाओ—जोधपुर, जयपुर, बडौदा, पटियाला ओर बीकानेर—की स्थिति ऐसी ही थी । पटियाला दिल्ली से केवल एक सौ चालीस मील है ।

हालाकि राजाओ के साथ फरवरी मे अपनी सात दिन की चर्चाओ मे नेहरू कम-से-कम पाच बार यह बात दोहरा चुके थे कि काग्रेस के साथ वे जो भी समझौता करेगे वह बिल्कुल अपनी इच्छा से होगा । काग्रेस किसी राजा को जोर या दबाव से समझौते के लिए मजबूर नही करेगी । फिर भी राजाओ के सामने विकल्प यही था कि या तो शामिल हो या खत्म हो जाय । निजाम की ही बात लीजिए । उन्हे अपने साथ शामिल करना और उनके साथ दृढता का व्यवहार करना श्रेयस्कर होगा । किन्तु पणिक्कर ने दबाव डालने की सिफारिश नही की । वहा की ८६ प्रतिशत आबादी हिन्दू है । उसका बाहर रहना असभव था । क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बडी रियासत काश्मीर की स्थिति बडी कठिन थी, और इसमे कोई शक नही कि वहा के महाराज जिन्ना के साथ अपने भाग्य का गठबन्धन करने को लालायित होगे । पणिक्कर ने कहा कि विधान-सभा मे शामिल होने के पीछे राजाओ का खास उद्देश्य यह था कि वहा जाकर काग्रेस के दक्षिण पक्ष को मजबूत बनावे ।

अन्त मे मैने पणिक्कर से दोनो दलो के सामाजिक ढाचे के बारे मे उनकी राय पूछी । उन्होने माउन्टबेटन के इस मत की पुष्टि की कि आगे चल कर काग्रेस के कई टुकडे हो जायगे । उनकी धारणा थी कि मुस्लिम लीग ज्यादा सगठित है, क्योकि उसमे औद्योगिक अमीरी और गरीबी के चरम सिरो का अभाव था । जो इने-गिने धनी मुसलमान थे भी, वे मुख्यत जमीदार थे । मुसलमानो का शोषण मुख्यत हिन्दू पूजीपतियो के हाथो होता था ।

सुविधा प्राप्त थी, क्योकि गाधीजी उन्हे एक ईमानदार व्यक्ति मानते थे। परन्तु उन्होने चेतावनी दी कि महात्मा गाधी के साथ बातचीत का अनुमान पहले से नहीं किया जा सकता। उसमे सदैव यह खतरा बना रहता था कि कही गाधीजी किसी विपय-विशेप को पकड कर विचाराधीन विपय को एक ओर न कर दे।"

वापस लौटा तो १० बज रहे थे और कर्मचारी-मडल की बैठक का समय हो गया था। बैठक मे माउन्टबेटन की गाधीजी के साथ तीसरे पहर होने वाली बातचीत की योजना पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया गया। इस भेट मे स्वभावत पत्रो को बहुत दिलचस्पी थी। ३ बजे गाधीजी आये। उस समय इस महादेश का शायद प्रत्येक मान्यता-प्राप्त फोटोग्राफर 'मुगल उद्यान' मे मौजूद था।

प्रारभिक अभिवादन के पश्चात् माउन्टबेटन-दम्पती उन्हे इस 'तोपखाने' का सामना करने के लिए ले गए। गाधीजी ने माउन्टबेटन-दम्पती से विनोद करते हुए अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यह अग्नि-परीक्षा दी। कैमरावाले इस प्रयत्न मे थे कि बहुत बढिया चित्र लिया जा सके और गाधीजी ने उनकी परस्पर-विरोधी मागो को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया।

सबसे बढिया चित्र अमरीकी असोसिएटेड प्रेस के कुशल फोटोग्राफर मैक्स डेस्फर को मिला। वह उस समय तक प्रतीक्षा करता रहा, जबतक कि आयोजित चित्रो की धूम-धाम मिट नही गई। बाद मे उसने सच्चे कलाकार की दृष्टि से देखा कि गाधीजी ने माउन्टबेटन के शीतल बैठकखाने मे जाते समय लेडी माउन्टबेटन के कधे पर अपना हाथ रख लिया था। यही चित्र उसने लिया। गाधीजी ने अपने इस कार्य से लेडी माउन्टबेटन के साथ ठीक वही व्यवहार किया, जो वह प्रार्थना-सभाओ मे जाते समय अपनी पौत्रियो के साथ करते थे। गाधीजी के प्रत्येक सकेत मे जाने-अनजाने, कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होता था और आज तीसरे पहर की यह घटना हार्दिक मित्रता की प्रतीक थी।

आज बातचीत सवा दो घटे चली। उसके अत मे माउन्टबेटन ने मुझे बुलाया और तुरत प्रेस-विज्ञप्ति निकालने पर विचार-विनिमय करने के लिए गाधीजी से मेरा परिचय कराया। गाधीजी ने, जो बहुत मद और किंचित् अस्पष्ट स्वर मे बोल रहे थे, कहा कि उन्हे विज्ञप्ति के मसविदे को वाइसराय पर छोड देने मे प्रसन्नता होगी।

गाधीजी के जाने के बाद माउन्टबेटन ने मुझे बताया कि सारी भेट जानबूझ कर सस्मरणो मे बताई गई। पहले सवा घटे लेडी माउन्टबेटन भी उपस्थित थी और वह मैत्री का वातावरण उत्पन्न करने मे मदद कर रही थी। बाद का एक घटा हम दोनो ही के बीच मे व्यतीत हुआ। माउन्टबेटन ने मैत्रीभाव बढाने की दृष्टि मे तात्कालिक राजनैतिक स्थिति पर कोई चर्चा नही छेडी।

गाधीजी ने इग्लैड तथा दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रारभिक जीवन तथा अन्य

वाइसरायो के साथ अपनी भेटो की चर्चा की । माउन्टबेटन के कथनानुसार, वार्ताए गाधीजी के दिल्ली-वास के शेष एक सप्ताह तक चलती रहेगी । वह उनके साथ ज़ल्दबाजी न करने का पक्का सकल्प कर चुके है ।

यह सब वैसे तो बडा अच्छा होता है, किन्तु सवाददाताओ को समझाना उतना सरल नही । उनके लिए विश्वास करना कठिन होगा कि बातचीत मे महत्त्वपूर्ण फैसले नही किये गए ।

जितनी जल्दी हो सका, मैने एक विज्ञप्ति तैयार की और उसपर माउन्टबेटन की स्वीकृति लेकर बाहर गया, जहा सवाददाताओ की भारी भीड उसकी प्रतीक्षा कर रही थी ।

मैने पढना आरम्भ किया, "वाइसराय तथा लेडी माउन्टबेटन ने आज सायकाल गाधीजी से भेट की और उनके बीच ७५ मिनट तक अत्यन्त मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई।"

मेरे दम लेने के पहले ही एक उत्सुक सवाददाता ने विरोध किया कि यह सच नही हो सकता। वह जानता था कि महात्माजी वहा दो घटे से अधिक रहे थे। शेप सवाददाताओ मे भी कुछ कानाफूसी होने लगी। मैने आगे के शब्द पढे, "इसके बाद वाइसराय तथा गाधीजी ने आत्मीयता के उसी भाव से एक घटे तक अलग बातचीत की।" अब तो सबको मानना पडा कि इस विज्ञप्ति का सत्य के साथ थोडा सम्बन्ध होना असभव नही है ।

नई दिल्ली, मंगलवार, १ अप्रैल, १९४७

गाधीजी के साथ माउन्टबेटन ने आज दूसरी बार बातचीत की । वह दो घटे तक चलती रही, लेकिन उसमे ठोस काम की बात केवल पन्द्रह मिनट ही हुई। इस बार भी काफी समय महात्माजी की जीवन-कथा मे लग गया । फिर उन्होने सम्पूर्ण समस्या को हल करने के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा । वह यह था कि वर्तमान मत्रि-मडल को भग कर जिन्ना को पूर्णत मुस्लिम मत्रि-मडल बनाने के लिए आमत्रित किया जाय।

माउन्टबेटन ने पूछा, "जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया होगी ?"

गाधीजी ने उत्तर दिया, "जिन्ना कहेगे—यह धूर्त गाधी की चाल है।"

माउन्टबेटन ने मुस्करा कर प्रश्न किया, "और क्या उनका यह कहना सही न होगा ?"

"नही", गाधीजी ने कहा, "मै बिल्कुल दिल से कह रहा हू।"

उन्होने माउन्टबेटन से कहा कि आपको दृढता के साथ अपने पूर्वगामियो के पापो के परिणामो का सामना करना होगा । "फूट डालो और राज्य करो"

की ब्रिटिश नीति ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसमे कानून और व्यवस्था कायम रखने के यही विकल्प शेष रह गये है कि या तो ब्रिटिश शासन जारी रहे या भारत मे खून की होली खेली जाय। हमे खून की होली स्वीकार करके उसी का सामना करना पडेगा।

इन भेटो मे लगनेवाले समय से वेवल चिढ गये थे, परन्तु माउन्टबेटन ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो मै गाधीजी के लिए दस घटे भी दे सकता हू। गाधीजी की उनपर गहरी छाप पडी थी और वह मानते थे कि अब भी उनका महत्त्व सर्वोपरि है।

नई दिल्ली, शुक्रवार, ४ अप्रैल, १९४७

समाचारपत्रो का ध्यान अब भी सीमाप्रान्त पर ही केन्द्रित था। इस्मे ने आज की कर्मचारी-मडल की बैठक मे वहा की स्थिति का, जिसे वह 'दोगली स्थिति' कहते थे, वर्णन किया। वहा ९७ प्रतिशत आबादी मुसलमान थी, किन्तु मत्रि-मडल काग्रेसी था।

त्रावणकोर का भी प्रश्न उठा। भारतीय राज्यो मे केवल यही राज्य ऐसा था, जिसके पास पर्याप्त समुद्रतट था। वहा यूरेनियम भी मिला था, जिससे प्रभु-सत्ता के विलुप्त होने के प्रश्न को एक नया सामरिक महत्त्व प्राप्त हो गया था।

जरूरत पडने पर यूरोपियनो को देश से निकाल ले जाने के तरीको पर भी विस्तार से स्पष्ट चर्चा हुई। जो लोग १९४८ के जून तक भारत से चले जाने के इच्छुक थे उनका एक रजिस्टर तैयार किया जायगा। यात्री-जहाजो की इतनी कमी थी कि साधारण बेडा तक जुटाने का प्रश्न नही उठता। माउन्टबेटन का आदेश था कि सब सम्बद्ध लोगो को समझाया जाय कि युद्ध के फलस्वरूप जहाजो की काफी कमी हो गई है। उनका यह भी आदेश था कि इस सबध मे जो योजना बनाई जाय उससे ऐसा आभास न हो कि आतक के कारण भगदड मचनेवाली है।

जिनकिन्स के साथ भोजन किया। जिनकिन्स ने बताया कि नेहरू तो गाधी का पश्चिमी रूप है। उन्होने इस सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से ईर्ष्या के योग्य होगा और यह मानना गलत होगा कि वह आर्थिक दृष्टि से जीवित न रह सकेगा। मैने उनसे इस पर एक घोषणा-पत्र तैयार करने को कहा, क्योकि मेरे खयाल से माउन्टबेटन को इसमे बहुत दिलचस्पी होगी। दैनिक गतिविधि की भगदड मे दीर्घकालीन विचारो की बडी सरलता से उपेक्षा हो जाती है। दूसरे अतिथि थे डूँगरपुर के महाराजा के छोटे भाई, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जिन्होने आई सी एस का जीवन अगीकार किया था। अकबर हैदरी के समान वह भी महसूस करते थे कि १९३५ के भारत शासन-विधान के दूसरे भाग को पुनरुज्जीवित करने का एक प्रयत्न और किया जाना चाहिए।

जिनकिन्स का कहना था कि नेहरू और कांग्रेस ने फील्ड मार्शल आचिनलेक का जो समर्थन किया था उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर फील्ड मार्शल स्लिम की नियुक्ति की जायगी, जो सही हो या गलत, अधिक मुस्लिम-परस्त माने जाते थे। लियाकत और मुस्लिम लीग द्वारा आचिनलेक को उत्तेजित किये जाने का यह भी कारण हो सकता था कि वह उन्हे यहा से जाने पर मजबूर करना चाहते हो।

नई दिल्ली, शनिवार, ५ अप्रैल, १९४७

अब प्रथम पखवारे के अंत मे माउन्टबेटन की योजना की मुख्य नीति और उसको कुशलता से लागू करने का ढग निश्चित हो गया। उन्हे बिल्कुल आदि से ही कार्य आरंभ करना पडा, लेकिन वक्त बरबाद नही हुआ। अब पहला उद्देश्य ऐसा हल निकालना था, जिससे काफी सद्भावना उत्पन्न हो जाय और जिससे भारत के विभिन्न दल राष्ट्रमडल के अन्दर ही बने रहे। वे मंत्रि-मडलीय योजना को जीवित रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु वह मानते थे कि यदि जिन्ना की शक्ति और इरादा कायम रहा तो विभाजन की व्यवस्था करनी होगी। वह इस तर्क को स्वीकार करते थे कि यदि केन्द्रीय सत्ता का विभाजन किया जाय तो उन प्रान्तो का भी आवश्यक है, जिनमे दोनो सम्प्रदायो के लोग बराबर बराबर है।

योजना कोई भी रूप ग्रहण करे, माउन्टबेटन को आरभ से ही विश्वास हो गया था कि राजनैतिक हल की आवश्यकता आज पहले से कही अधिक है और जून, १९४८ की समय की मर्यादा नाकाफी होने के अलावा बहुत लम्बी दिखलाई पडती थी। वह राजनैतिक स्थिति के दु साध्य होने का खतरा महसूस कर रहे थे। विभिन्न विरोधी दल—कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख—अपने-अपने दावो की होड लगाने की पर्याप्त शक्ति रखते थे। परन्तु यदि तुरन्त कोई समझौता नही होता तो वह भारत को चीन की जैसी स्थिति मे पडने से रोक न सकेगे। राजनैतिक हल जल्दी निकल आने का अर्थ है कि फिर निश्चित अवधि मे ही जटिल प्रशासकीय समस्या को भी सुलझाना होगा। कर्मचारी-मडल की सुबह की बैठक जिन्ना के आने तक जारी रही। गाधीजी की पहली भेट के समय जितने फोटोग्राफर थे, उतने इस समय नही थे। पत्रकारो के साथ जिन्ना का व्यवहार बहुत औपचारिक और रूखा रहता था। बातचीत खत्म होते ही प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा स्वीकार कराने के लिए मै माउन्टबेटन के पास गया। उन्होने सिर्फ एक छोटा-सा सशोधन किया।

माउन्टबेटन आज रात के बदले कल सायकाल जिन्ना और उनकी बहन के साथ भोजन करेगे। वह महसूस करते थे कि वह आज ही दूसरी बैठक का श्रम सहन न कर सकेगे। जिन्ना ने कहा था कि वह अपने-आपको पूर्णत माउन्टबेटन

की मरजी पर छोड देगे। माउन्टबेटन की पहली प्रतिक्रिया यह थी—"हे भगवान, वह तो विल्कुल बर्फ के समान ठडे थे! भेट का अधिकतर समय उन्हे पिघलाने मे ही लग गया।"

यहा से मे सीधा भोजन के लिए गया। नेहरू, उनकी पुत्री इदिरा और इडोनेशिया के प्रधान मत्री डा० शहरयार अपनी सुनहरे बालो वाली प्रफुल्ल-वदना डच पत्नी के साथ उपस्थित थे। आस्ट्रिया के 'ठिगने' प्रधान मत्री डालफस के बाद शहरयार शायद सबसे छोटे राजनीतिज्ञ थे। डच अटैची श्री विकलमैन भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे। मै इदिरा के पास बैठा। उन्होने मुझे बताया कि वह लन्दन के कुछ खतरनाक हवाई हमलो का अनुभव कर चुकी थी। एक दिन जब वह पिकेडिली मे एक आग लगाने वाला बम बुझाने का प्रयत्न कर रही थी, उन्हे किसी ने हवाई हमले के वार्डन का टोप दे दिया था। उसे उन्होने अब तक यादगार के रूप मे अपने पास सुरक्षित रखा था। वह शिमला जा रही थी।

भोजन के पश्चात् माउन्टबेटन के अनुरोध पर कृष्ण मेनन और इस्मे ने गाधीजी के प्रस्ताव के बारे मे लबी बातचीत की। आज यह स्वीकार किया गया कि गाधीजी के काग्रेस पर अत्यधिक जोर डालने के पूर्व ही नेहरू को स्पष्ट बता दिया जाय कि माउन्टबेटन गाधीजी की योजना से बधे हुए नही थे और उसकी बारीकी से छानबीन करना आवश्यक था। जैसा कि माउन्टबेटन ने आज प्रातःकाल कहा था, गाधीजी जिन्ना को मत्रि-मडल बनाने का आमन्त्रण देने पर तुले हुए थे और उन्होने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस पर काग्रेस का समर्थन प्राप्त कर लेगे।

शाम को माउन्टबेटन-दम्पती के साथ भोजन करनेवाला मै अकेला ही था और उस समय जिन्ना की महत्त्वपूर्ण भेट का वर्णन सुना। जिन्ना ने बिल्कुल रुखाई के साथ बातचीत शुरू की थी, "मै सिर्फ एक शर्त पर बात करूगा ।"

माउन्टबेटन ने बताया, "मैने उन्हे वाक्य पूरा करने के पहले ही टोक दिया, "जिन्ना साहब, मै किसी प्रकार की शर्तो पर विचार करने को तैयार नही हू, बल्कि जबतक आपका परिचय न पा लू और आपके मुह से आपके बारे मे कुछ और जान न लू, तबतक वर्तमान स्थिति पर कोई चर्चा ही नही करूगा।"

माउन्टबेटन के रुख मे जिन्ना बिल्कुल स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक वह गुमसुम और अकडे हुए बैठे रहे। परन्तु अत मे उनका रुख नर्म पडा और उन्होने माउन्टबेटन की इच्छा के सामने सिर झुका दिया। माउन्टबेटन सुनना चाहते थे कि उनकी कोशिशो मे मुस्लिम लीग किस प्रकार शक्तिशाली हुई।

नई दिल्ली, सोमवार, ७ अप्रैल, १९४७

कल रात जिन्ना और उनकी बहन ने माउन्टबेटन-दम्पती के साथ भोजन किया।

जिन्ना ने मुसलमानो के कत्लेआम का राग अलापा और उसकी विभीषिकाओ का वर्णन किया। जल्दी ही कुछ किये जाने की आवश्यकता है। "इसके लिए शल्य-चिकित्सा ही करनी पड़ेगी", माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, "शल्य-चिकित्सा करने के पहले बेहोशी की दवा सुघानी पडती है।"

जिन्ना के साथ अपनी इस दूसरी मुठभेड से माउन्टबेटन ज्यादा आश्वस्त थे। उनका विचार था कि जिन्ना बाते चाहे जितनी कर ले, लेकिन चलेगी मेरी ही।

जिन्ना ने जोर दिया कि गाधीजी की स्थिति शरारत से भरी हुई है, क्योकि उसमे अधिकार तो है, पर उत्तरदायित्व कोई नही। इसे सिद्ध करने के लिए गाधीजी के साथ हुई विभिन्न वार्ताओ का इतिहास बतलाते हुए अन्त उन्होने किया क्रिप्स-योजना की अस्वीकृति और सन् बयालिस का आन्दोलन छेडे जाने की घटना के साथ। व्यालीस के आन्दोलन को उन्होने महात्माजी की "हिमालय-जैसी भूल" कहा। उन्होने कहा कि काग्रेस सब कुछ हथियाना चाहती है और मुझे पाकिस्तान से महरूम रखने के लिए वह औपनिवेशिक स्वराज्य तक मजूर कर लेगी।

पहली मुलाकात के समय जब माउन्टबेटन-दम्पती और जिन्ना का चित्र खीचा जा रहा था तो जिन्ना ने लेडी माउन्टबेटन के प्रति उदारता दिखलाते हुए "दो काटो के बीच कोमल कुसुम" की बात कही। अभाग्यवश पता चला कि बीच मे वह खुद ही थे।

आज शाम की दूसरी बैठक के बाद माउन्टबेटन ने जिन्ना से मुलाकात करने के लिए मुझे अन्दर बुलाया। जिन्ना मेरी ओर बरछी के समान आखो से देखते रहे और बोले कुछ नही। फिर माउन्टबेटन के सकेत पर उन्होने कहा कि यदि मै उनके निवास-स्थान पर जाकर उन प्रेस-सम्बन्धी मामलो पर चर्चा करूगा तो उन्हे खुशी होगी। उनके चले जाने पर माउन्टबेटन ने कहा कि कल वह जटिल चर्चा करने वाले है।

नई दिल्ली, मंगलवार, ८ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मडल की आज की बैठक मे लियाकत का एक पत्र पढ़ा गया। इसमे शिकायत की गई थी कि सेना मे मुसलमानो को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। वह चाहते थे कि तुरन्त इनका पुनर्गठन किया जाय, जिससे उचित समय आने पर उन्हे अविलम्ब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच बाटा जा सके। इस्मे ने कहा कि लियाकत के पत्र पर कोई कार्रवाई करने का अर्थ होगा राजनैतिक प्रश्न को सकट मे डालना। जबतक वाइसराय ब्रिटिश सरकार को इसके [illegible] नही देते तबतक मत्रि-मडलीय योजना कायम है और योजना मे एक सेना की व्यवस्था है।

माउन्टबेटन सहमत थे कि अग्रेजो के भारत से जाने के पूर्व दो कारणो से भारतीय सेना विभाजित नही की जा सकती । 'पहला तो यह कि शासन-यत्र अनुमति नही देगा और दूसरा यह कि मै ऐसा नही होने दूगा ।" उन्होने कहा, "मैने जिन्ना को यह बतला देने का निश्चय कर लिया है कि मुझे न्याय और व्यवस्था की रक्षा करनी ही होगी । मै एक दल को नुकसान पहुचाकर दूसरे की सहायता नही करूगा । यदि विभिन्न प्रान्तो के वीच राजनैतिक सत्ता वाट देने का निश्चय हुआ तब भी प्रतिरक्षा को केन्द्र के अधीन रखना पडेगा ।" इस्मे ने कहा कि जबतक सत्ता नही बदलती तबतक ब्रिटिश सेना नही जाती । १९३५ का विधान भी तबतक लागू है ।

माउन्टबेटन ने गाधी-योजना पर नेहरू के मत की चर्चा की । नेहरू का कहना था कि जबतक सत्ता लेनेवाला कोई उपयुक्त पक्ष सामने न हो तब तक दृढ केन्द्र को तोडना उचित नही होगा । एबेल ने कहा कि मुख्य प्रश्न तो यह है मत्रि-मडलीय योजना जीवित है या मृत ? जिन्ना को जता दीजिए कि उससे इकार करने पर उन्हे क्या मिलेगा ? जबतक यह स्पष्ट नही किया जाता तबतक वह ठीक रास्ते पर नहीं आयगे ।

नई दिल्ली, बुधवार, ९ अप्रैल, १९४७

आज की बैठक मे माउन्टबेटन ने बतलाया कि कल उन्होने जिन्ना के सामने यह प्रश्न उठाया कि दोनो प्रधान दल साम्प्रदायिक दगो को बन्द कराने के लिए एक अपील निकाले । उन्होने जिन्ना से साफ-साफ पूछा कि क्या वह वास्तव मे इन दगो को रुकवाना चाहते है, या ऐसी अपील निकालने से मुस्लिम लीग का राजनैतिक पक्ष कमजोर हो जायगा ? आखिर जिन्ना राजी हो गए ।

हमने आज फिर नीति के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श किया । इस्मे ने जिन्ना के साथ हुई अपनी एक चर्चा का जिक्र किया । उन्होने कहा कि जिन्ना अपनी नीति से पैदा होने वाली शासकीय समस्याओ से बिल्कुल अनभिज्ञ है । ब्रिटिश लोगो का काम तो सिर्फ यहा से हिसाब चुकता कर चले जाना है । अगर पाकिस्तान देना स्वीकार कर लिया गया तो सब ठीक हो जायगा । लेकिन जिन्ना ने अपनी आशका व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उन्हे "घुन लगा पाकिस्तान" ही मिलेगा ।

कर्मचारी-मडल की बैठक के बाद मै जिन्ना से मिलने उनके निवासस्थान पर गया । १० औरगजेब रोड पर स्थित उनकी कोठी मसजिद के समान लगती थी । उसपर लाल तथा काली पच्चीकारी हो रही थी । एक ताक पर लकडी के ऊपर चादी से बना भारत का नक्शा रखा हुआ था । इस मे हरे रग से पाकिस्तान की सीमाए दिखाई गई थी । पहली 'मुठभेड़' की अपेक्षा वह इस बार ज्यादा सौहार्द से पेश आये । हमने समाचारपत्रो की स्थिति पर चर्चा की । उन्होने कहा

कि 'ऑल इडिया एडीटर्स कान्फ्रेस'[१] पूरीतौर पर हिन्दू जमात है। मुसलमान अखबारो मे से सिर्फ 'डान' पर उनकी मालकियत है। "हालाकि आप यकीन नही करेगे, मैने इसकी नीति पर कभी सीधा असर डालने की कोशिश नही की। इसे मैने हमेशा एडीटर का काम समझा है और इसे हमेशा उसीकी मर्जी पर छोडा है।" फिर उन्होने बिना मुस्कराहट के कहा, "लेकिन एडीटर हमेशा मेरे खयालो का रहा है।" नोआखाली मे मुसलमानो के हाथो हिन्दुओ की हत्या के समाचारो को झूठ बतलाते हुए उन्होने काफी देर तक उस पर चर्चा की। उन्होने कहा कि पहले इसे कई हजार लोगो का कत्ले-आम कहा गया था, लेकिन बाद मे सिद्ध हुआ कि सौ से ज्यादा लोग नही मरे और न सौ से ज्यादा घायल हुए। उन्होंने शिकायत की कि भारतीय समाचार-पत्रो के साथ खानगी चर्चा करना असभव है। लन्दन का अपना अनुभव बतलाते हुए उन्होने कहा कि वहा उन्होने अनौपचारिक चर्चा मे जो बाते कही उन्हे कोई छापने नही दौडा।

आज तीसरे पहर मैंने नेहरू-परिवार के साथ चाय पी। इदिरा और कृष्ण मेनन ने मुस्लिम लीग के उदय की कहानी बताते हुए कहा कि स्वय जिन्ना जन्म से हिन्दू है। कृष्ण मेनन ने कहा कि लीग को तब कुछ महत्त्व मिला जब काग्रेसी सीधी कार्रवाई करनेवाली सस्था बनी। लीग अग्रेजो के प्रोत्साहन से बढी। कृष्ण मेनन चाहते थे कि मै 'देशी राज्य प्रजा-परिषद्' के ग्वालियर-अधिवेशन मे जाऊ, जिसमे नेहरू काश्मीर के मुसलमान काग्रेसी नेता शेख अब्दुल्ला को, जो इस समय जेल मे थे, परिषद् की अध्यक्षता सौपेगे। केवल राजनैतिक तापमान ही नही बढ रहा है, भौतिक तापमान भी कल १०० अश तक पहुच गया था। जैसा कि नेहरू ने कहा था, "कठिनाई यह है कि हम गरमी की बात सोचकर ही गरम हो जाते है।"

नई दिल्ली, शनिवार, १२ अप्रैल, १९४७

माउन्टबेटन ने जिन्ना के साथ अपनी ताजा बातचीत का हाल सुनाया। जिन्ना ने बडे नाटकीय ढग से पाकिस्तान को राष्ट्रमडल मे रखने के लिए हाथ बढाया, परन्तु माउन्टबेटन पर इसकी कोई प्रतिक्रिया न होने से जिन्ना को बडा सदमा पहुचा।

हमारी आज की आम चर्चा मे 'खड योजना' के विरुद्ध 'अखड योजना' के सब विकल्पो पर स्पष्ट और पूर्ण विचार-विमर्श हुआ। माउन्टबेटन ने इस दुविधा के मूल मे जाकर यह इरादा किया कि वह काग्रेस से पूरी मत्रि-मडलीय योजना स्वीकार कराने का प्रयत्न करेगे और फिर जिन्ना से कहेगे कि या तो वह योजना को स्वीकार करे या कटा-फटा पाकिस्तान लेने को तैयार हो जाय। जार्ज एबेल को इसमे शक

---

[१] अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन।

है कि काग्रेस अपनी नीति वदलेगी। उत्तरी भाग के प्रातो पर दवाव डालकर वह पहले ही मुस्लिम लीग को पीछे हटने के लिए वाध्य कर चुकी है।

गाधीजी ने माउन्टबेटन को लिखा कि उनकी योजना काग्रेस को स्वीकार नही है और वह भावी बातचीत का सव भार काग्रेस कार्य-समिति को सौप रहे है। माउन्टवेटन कहते है कि वह कोशिश करेगे कि गाधीजी दिल्ली मे रुके रहे और काग्रेस मे मत्रि-मडलीय योजना को स्वीकार कराने मे अपने प्रभाव का उपयोग करे। वह महसूस करते है कि काग्रेस मे अब भी एक सघ की इच्छा वहुत प्रवल है।

सयोग से गाधीजी के पत्र मे 'पुनश्च' के बाद एक यह सुन्दर सुझाव भी था कि श्रीमती आसफअली को लेडी माउन्टवेटन से मिलना चाहिए। लेडी माउन्टवेटन ने तुरन्त निमत्रण भेजा, किन्तु श्रीमती आसफअली ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरे दिन जब गाधीजी वाइसराय से मिलने आये तब श्रीमती आसफअली उनके साथ थी।

गाधीजी ने कहा, "मैने सुना कि इसने निमत्रण अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मै इसे अपने साथ लेता आया हू।"

नई दिल्ली, सोमवार, १४ अप्रैल, १९४७

समाचार-पत्रो मे तरह-तरह की अटकले लगाई जा रही है। आज सवेरे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक लेख मे उस सयुक्त 'शाति-अपील' के निकाले जाने की 'भविष्यवाणी' की गई थी, जिसके लिए माउन्टवेटन प्रयत्नशील थे। 'भविष्यवाणी' मे बताया गया था कि शाति-अपील गाधीजी, जिन्ना और कृपालानी (काग्रेस-अध्यक्ष) के हस्ताक्षरो से शीघ्र ही निकाली जायगी। एक वडी समस्या यह थी कि काग्रेस कृपलानी के हस्ताक्षरो का आग्रह कर रही थी और जिन्ना इसके लिए तैयार नही थे।

अनिश्चय के कई झोको के वाद माउन्टबेटन के धैर्य और इच्छाशक्ति की विजय हुई और आज तीसरे पहर गाधीजी तथा जिन्ना के हस्ताक्षरो की अपील की मूल प्रति लेकर मै सूचना-विभाग मे गया। कृपलानी के हस्ताक्षर के वारे मे जिन्ना की विजय हुई और उन्हे हस्ताक्षर करने के लिए नही वुलाया गया। गाधीजी ने अपना नाम दो बार, अग्रेजी और उर्दू मे लिखा।

इस अपील की ध्वनि और सामयिकता मे माउन्टबेटन की एक भारी व्यक्तिगत विजय निहित थी। इससे उनके उन प्रयासो को बल मिला जो वह सर्वसम्मत राजनैतिक योजना तैयार करने के लिए कर रहे थे। इससे उनकी प्रतिष्ठा वढी और उनके आसपास फैले सद्भाव का पूरा लाभ उन्हे मिल गया। इसका उद्देश्य ऐसा सौहार्द था, जिसके विना कोई राजनैतिक हल तनिक भी महत्त्व का नही हो सकता। यह उनकी खुली कूटनीति की प्रथम विजय थी।

अब आगे की आयोजित कार्रवाइया मई के आरम्भ मे शिमले मे केद्रित रहेगी। उसमे इन अतिथियो के उपस्थित रहने की सभावना है—नेहरू, जिन्ना, पटेल, लियाकत, कृपलानी, बलदेवसिह और शायद गाधीजी, नवाब भोपाल तथा बीकानेर के महाराजा।

देशी राज्यो के रेजीडेटो की उपयोगी बैठक के बाद अब कल गवर्नरो की बैठक होनेवाली है। माउन्टबेटन ने अपनी योजना का मसविदा गवर्नरो के विचार जानने के लिए भेज दिया था। जबतक उसपर गवर्नरो के विचार ज्ञात न हो जाय तबतक माउन्टबेटन उसे अन्तिम रूप न देगे। माउन्टबेटन की योजना के मोटे सिद्धात ये थे

१ यदि देश का विभाजन हो तो उसका उत्तरदायित्व पूरी तरह से भारतीयो पर ही रहे।

२ आमतौर पर प्रातो को अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार हो।

३ मतदान के लिए बगाल और पजाब का कल्पित विभाजन करना होगा।

४ आसाम के ज्यादा मुसलमान-आबादी वाले जिले सिलहट को बगाल के विभाजन से बनने वाले नये मुस्लिम प्रात मे मिलने का विकल्प प्रदान किया जाय।

५ सीमा-प्रात मे आम चुनाव किया जाय।

कुछ गवर्नर वाइसराय-भवन पहुच गए थे और माउन्टबेटन ने सर फ्रेडरिक बोर्न (मध्यप्रात), सर जान कालविल (बबई) तथा सर आर्चीबाल्ड नाइ (मद्रास) से कुछ बाते भी कर ली थी। सब गवर्नरो के आ जाने पर माउन्टबेटन-दम्पती को एक ही भवन मे ११ गवर्नरो और उनकी पत्नियो, उनके प्राइवेट सेक्रेटरियो तथा अग-रक्षको का सत्कार करना होगा। ३४० कमरो और डेढ मील लम्बे बरामदो के वाइसराय-भवन के लिए भी मेहमानो की यह सख्या काफी बडी जान पड रही थी।

हैदराबाद के प्रधान मत्री सर मिर्जा इस्माइल को बोर्न के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया था और उनके बीच बरार के सबध मे बातचीत हुई। बरार हैदराबाद राज्य का पुश्तैनी इलाका है और हैदराबाद के युवराज को बरार का शाह-जादा कहा जाता है। परन्तु इसका शासन-प्रबध मध्यप्रात के गवर्नर के अधीन है। निजाम इसे अवश्य ही वापस मागेगे। मिर्जा इस्माइल ने बताया कि निजाम निकट-भविष्य मे ही जिन्ना से मिलेगे। जहा तक उनका खुद का सबध है, वह कहते है कि उन पर से निजाम का विश्वास तेजी से उठ रहा है और वह बहुत दिनो तक पदारूढ न रह सकेगे।

माउन्टबेटन के दिये गए भोज मे मै इस्माइल के साथ बैठा। वह नरम विचार, गभीर प्रकृति और तीव्र बुद्धिवाले मुसलमान है। इसीलिए वह अकेले से है। उन्होने मुझसे निजाम के प्रधानमत्री की उलझनो की मुक्त होकर चर्चा की। निजाम का कोई प्रधानमत्री चार वर्ष से अधिक पदारूढ रहने की आशा नही कर सकता।

इसमे केवल सर अकबर हैदरी, जो वृद्ध थे, अपवाद सिद्ध हुए। वह चौदह वर्ष तक जमे रहे। निजाम की राजनीति इतनी ही थी कि वह अपने प्रधानमत्रियो के विरुद्ध षड्यत्र रचते रहते थे और अन्तत उन्हे उन सब अधिकारो से वचित कर देते थे, जो उन्होने उनके लिए दूसरो से छीने थे। इस्माइल के कथनानुसार यह षड्यत्रो का ऐसा निराशाजनक चक्र था, जिसमे किये-कराये पर पानी फिरने के अलावा कुछ नही होता।

: ५ :

नई योजना पर गवर्नरों के विचार

नई दिल्ली, मंगलवार, १५ अप्रैल, १९४७

आज के पत्रो मे गाधी-जिन्ना शाति-अपील बडे-बडे शीर्षको के साथ प्रकाशित हुई। फलस्वरूप बडे उत्साह के वातावरण मे गर्वनरो का सम्मेलन आरम्भ हुआ। माउन्टबेटन ने अपने प्रारम्भिक भाषण मे ब्रिटिश सरकार के निर्णय के शब्दो तथा भावो के प्रति वफादारी की धाराप्रवाह और प्रभावोत्पादक अपील की। यदि किसी को शका हो तो उसकी जानकारी के लिए उन्होने इस बात पर जोर दिया कि जून, १९४८ ब्रिटिश-प्रस्थान की पक्की तारीख है।

यूरोपियनो के निष्क्रमण के विषय मे पूरी-पूरी चर्चा हुई। कालविल और नाइ—बबई तथा मद्रास प्रात के गवर्नर—इस विषय पर निश्चित थे। परन्तु पजाब के प्रतिभाशाली गवर्नर सर ईवान जेनकिन्स ने महसूस किया कि उन्हे पजाब की स्थिति की गभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। बिहार के गवर्नर हर ह्यूडो ने बताया कि उनके प्रात की चार करोड जनसख्या मे केवल ५० यूरोपियन कर्मचारी है। इसलिए आश्चर्य नही कि उनके प्रात मे न्याय और व्यवस्था बहुत कम है। आसाम के गवर्नर सर एड्र्यू क्लो ने, जो अब रिटायर हो रहे है, चाय-बागीचो के मालिको की चर्चा की। बगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज बीमार थे और सम्मेलन मे नही आ सके। उनके सैक्रेटरी जे डी टाइसन ने बताया कि बगाल मे २०,००० यूरोपियन है और मुफस्सिल जिलो मे रहने वाले ५,००० के बारे मे उन्हे गभीर चिन्ता है। वह महसूस करते थे कि प्रात मे न्याय और व्यवस्था की रक्षा कर सकने की गुजाइश बहुत कम है, वहा कम्यूनिस्टो का आन्दोलन दूसरे प्रातो से अधिक प्रबल है और वह निश्चित रूप से यूरोपियनो के विरुद्ध है।

माउन्टबेटन ने जोर देकर बताया कि यदि भारत मे लोगो का आना रोकने के

सबध मे कोई कानून बनाया जाय तो उसे ब्रिटिश मत्रि-मडल का समर्थन प्राप्त होने की कोई आशा नही है। अन्त मे यह निर्णय हुआ कि यूरोपियनो के आवागमन के संबंध मे समझाने-बुझाने का तरीका काम मे लाया जाय।

इसके पश्चात् मुआवजे के कठिन प्रश्न पर सविस्तार चर्चा हुई। माउन्टबेटन ने अबतक की चर्चाओ का विवरण उपस्थित किया। कालविल ने भारतीयो को मुआवजा दिलाने के सबध मे माउन्टबेटन द्वारा प्रकट की गई कठिनाइयो का समर्थन किया। त्रिवेदी और हैदरी दोनो महसूस करते थे कि भारतीय लोग विशुद्ध देश-भक्ति के कारण नौकरियो मे बने रहना और मुआवजा छोड देना पसन्द करेंगे।

दोपहर की बैठक मे विभिन्न गवर्नरो से अपने-अपने प्रात-सबधी रिपोर्टे सुनने के लिए बहस रोक दी गई। सीमाप्रात के बारे मे सर ओलफ कैरो ने नये चुनाव करने की माग की। सीमाप्रात के प्रधानमत्री डा खान साहब नये चुनाव नही चाहते थे। चुनावो से जिनको सबसे अधिक लाभ होना सभव था, वे सब लीग-समर्थक मुसलमान जेलो मे बन्द थे। माउन्टबेटन की राय थी कि यदि सभव हो तो अभी कुछ न किया जाय। परन्तु कैरो तने हुए थे और थके मालूम पडते थे। स्पष्ट था कि वह अपने विशाल उत्तरदायित्व के भार से दबे जा रहे थे।

जेनकिन्स ने पजाब के विभाजन के परिणामो का बडा साफ खाका खीचा। उन्होने बताया कि किस प्रकार मुसलमानों तथा गैरमुसलमानो का प्रश्न सिखो और हिन्दू जाटो की मागो से उलझ गया था। टाइसन ने उसी प्रकार बगाल की स्थिति का चित्रण किया। उन्होने कहा कि विभाजन होने पर पूर्वी बगाल एक देहाती गदी बस्ती का रूप धारण कर लेगा। बगाल मे ढाई करोड—कुल जनसख्या के ४५ प्रतिशत—हिन्दू है। वे सब भारत मे रहना चाहते थे। 'पूर्वी बगाल' की कल्पना अनेक स्थानीय मुसलमानो को स्वीकार नही थी। बगाल के वर्तमान प्रधान मत्री सुहरावर्दी और जिन्ना के बीच सबध अच्छे नही थे। सुहरावर्दी विभाजन से डरते थे और हिन्दुओ के साथ मेल करने को तैयार थे। जेनकिन्स ने भी पजाब तथा बगाल मे पाकिस्तान-विरोधी भावनाओ के उभडने की आशका बताई। बगाल के मुसलमान बगाल पर स्थानिक मुसलमानो का आधिपत्य हो जाने से सतुष्ट हो जायगे।

बिहार के गवर्नर ने खनिज सम्पत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया। स्वतत्र बगाल के निर्माण के लिए छोटा नागपुर का औद्योगिक विकास करना सुहरावर्दी की योजना का अग था। किन्तु गवर्नर महोदय महसूस करते थे कि यदि बिहार की सीमा का पुनर्निर्माण हुआ तो उसका परिणाम बहुत व्यापक होगा। आम बहस मे यह महसूस किया गया कि सिध-पजाब को मिलाकर बना पाकिस्तान आर्थिक-दृष्टि से व्यावहारिक न होगा। माउन्टबेटन का खयाल था कि पूर्वी बगाल सभवत पाकिस्तान से अलग हो जायगा और सीमाप्रात एक घाटे का राज्य रहेगा।

नई दिल्ली, बुधवार, १६ अप्रैल, १९४७

गवर्नरो की आज की बैठक मे जेनकिन्स ने पजाब के बटवारे और सीमा-आयोग की स्थापना की आवश्यकता बताई। माउन्टबेटन ने विभाजन की जो योजना पेश की थी उसपर विस्तारपूर्वक बहस हुई। गवर्नरो द्वारा व्यक्त किये विचारो से स्पष्ट था कि देश का बहुत बडा भाग शात था और किसी भी न्यायोचित हल को स्वीकार करने के लिए तैयार था।

आज मैंने पणिक्कर के साथ इम्पीरियल होटल मे भोजन किया। पणिक्कर ने बताया कि मुस्लिम लीग का विधान इस प्रकार बनाया गया था कि मुस्लिम अल्पमत क्षेत्रो के प्रतिनिधियो की सख्या उसमे बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए जिन्ना मुस्लिम-बहुल क्षेत्रो के प्रतिनिधियो पर विशेष प्रभाव डाल सकते थे। बगाल की वफादारी भारत के प्रति बढती जा रही थी। उसकी व्यवस्था सावधानी मे करनी होगी। उन्होने भारत मे प्रिवी कौसिल जैसी सस्था स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि अप्रत्याशित रूप से उठनेवाली राजनैतिक और न्याय-सम्बन्धी समस्याए उसके सामने पेश की जा सके।

माउन्टबेटन ने सुरक्षा-मत्री बलदेवसिह से बातचीत की। बलदेवसिह ने जेनकिन्स के सामने इन्कार किया कि वह सिखो की अपील-निधि के कोषाध्यक्ष है। इसमे कोई सदेह नही कि यह निधि युद्ध फैलाने तथा अन्य कार्यो के लिए इकट्ठी की जा रही थी।

बलदेवसिह ने सेना के राष्ट्रीयकरण की योजना पर सलाह मागी। जून, १९४८ के पश्चात् ब्रिटिश सेनाओ के बने रहने की गुजाइश कितनी थी? माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि यह सब इस बात पर निर्भर है कि भारत राष्ट्रमडल मे रहना चाहता है या नही। काग्रेस ने २०, फरवरी के पूर्व जो प्रस्ताव स्वीकार करके भारत को "सम्पूर्णसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य" बनाने का निश्चय किया था, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए एक नया हल निकालना पडेगा। बलदेवसिह के रुख से इस बात की पुष्टि होती थी कि अब विभाजन ही एकमात्र उपाय है, जिसे पजाब के सब दल स्वीकार कर सकते थे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, १८ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मडल की आज की बैठक मे माउन्टबेटन बडे प्रसन्न थे। कृष्ण मेनन के साथ उनकी मनोरजक चर्चा हुई। कृष्ण मेनन ने 'सम्पूर्णसत्तासम्पन्न स्वतत्र गणराज्य' के सूत्र को पेश करने का थोडा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। फिर भी वह और कुछ अन्य काग्रेसी नेता ब्रिटेन के साथ सबध बनाये रखने के लिए कोई दूसरा हल निकालने को प्रयत्नशील थे। मेनन ने बताया है कि काग्रेस के लिए स्वय

पहल करना असभव है। ऐसा कोई प्रयास करने से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुचेगा। इसका सुझाव तो किसी-न-किसी प्रकार हमारी तरफ से ही पेश किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, शनिवार, १९ अप्रैल, १९४७

माउन्टबेटन ने सिख-नेताओ के साथ हुई बातचीत का हाल सुनाया। यह चर्चा भय पैदा करनेवाली भी थी और रोचक भी। उन्होने अपने-आप को लम्बी दाढी और विशाल कृपाणो वाले बूढे सज्जनो के सामने पाया, जो चश्मे लगाये हुए थे और देखने मे शातिपूर्ण इरादो से परिपूर्ण दयालु प्रोफेसरो की भाति जान पडते थे। लेकिन बीच-बीच मे झूठ का सहारा लेने मे भी उन्होने सकोच नही किया। उन्होने इसी बात पर जोर दिया कि उन्हे पजाब का विभाजन कर देना चाहिए। उन्होने यह भी बतलाया कि रावलपिण्डी के दगो मे सबसे अधिक हानि सिखो को ही उठानी पडी थी।

कल डा० खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमे यह सुझाव सामने आया कि माउन्टबेटन को जल्दी ही उत्तर-पश्चिमी सीमात-प्रदेश का दौरा करना चाहिए। अभी तक निश्चय यही था कि जबतक योजना का बडा भाग तैयार होकर स्वीकार नही कर लिया जाता तबतक दौरे स्थगित रखे जाय। किन्तु लगता ऐसा था कि सीमा-प्रात की स्थिति को देखते हुए पहले से ही कुछ खास 'इलाज' करना पडेगा। आम नीति-सम्बधी हमारी चर्चाओ मे औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर फिर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। माउन्टबेटन ने बतलाया कि पूर्वी बगाल के लीगी नेता नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के बारे मे जिन्ना के समान ही जिद पर अडे हुए है। इस्मे ने कहा कि हम दो पाकिस्तान बनाने मे लगे हुए है। इस पर माउन्टबेटन ने कहा कि मुझे लगता था कि पाकिस्तान अवश्यम्भावी है, उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो।

नई दिल्ली. बुधवार, २३ अप्रैल, १९४७

आज सवेरे माउन्टबेटन ने जिन्ना के साथ तीन घटे तक बातचीत की। मैने जार्ज एबेल के साथ भोजन किया और उन्होने मुझे बताया कि जिन्ना का रुख मैत्रीपूर्ण था। कभी-कभी वह जान-बूझकर उद्धत बन जाते थे, परतु आज इनका रुख आदान-प्रदान का था। मालूम होता था कि उन्होने मजबूर होकर बगाल और पजाब के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। उन्होन यह नही पूछा कि इनकी सीमाए क्या होगी और न माउन्टबेटन ने ही कुछ बताया। वह सीमाप्रात के लिए 'बुद्धिमत्ता से काम लेने' की अपील निकाल रहे थे और यह जानकर उन्हे राहत मिली थी कि उन्हे वहा की 'सीधी कार्यवाही' को बन्द करने के लिए बाध्य नही किया जायगा।

उन्होने माउन्टवेटन से कहा "वात यह थी कि हिन्दुओ को किसी वात के लिए राजी कर पाना नामुमकिन था। वे हमेशा एक रुपये के सत्रह आने मागते हैं।" इस पर जार्ज की टीका यह थी, "मुझे लगता है, कि यह सही है। सावारणत हिन्दुओ का पक्ष मुसलमानो के पक्ष से प्रवल था, किन्तु वे ज्यादा ऊची वोली वोलकर उसे विगाड देते थे।"

काग्रेस के प्रमुख मुस्लिम-नेता मौलाना आजाद ने एक नया सूत्र पेश किया था। गत दिसम्वर मे भारतीय नेताओ और वेवल के वीच लन्दन मे हुई चर्चाओ के वाद व्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य निकाला था। इसमे कहा गया था कि प्रातो को किसी भी 'समूह' से वाहर रहने का अधिकार होगा। मौलाना आजाद का कहना था कि इस विषय मे उन्हे माउन्टवेटन द्वारा लगाया गया अर्थ स्वीकार होगा। उन्होने अपने सूत्र का आधार गाधीजी के इस कथन को वनाया था कि पूरे भारत के हित मे क्या था और क्या नही था, इसके एकमात्र निर्णायक व्यक्तिगत रूप मे माउन्टवेटन होगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मडल की आज की वैठक मे योजना के पहले ममविदे पर विचार किया गया। लेकिन यह साफ न हो सका कि इसे विभिन्न दलो और जनता के के सामने ठीक किस रूप मे पेश किया जाय। आइन स्काट ने एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया, जिसपर काफी वहस हुई। उनका कहना था कि योजना को दोनो दलो की कार्य-समितियो के पास भेजने के पहले उसका खूव जोरो से प्रचार किया जाना चाहिए। इसका फल यह होगा कि सारी दुनिया की नजर दोनो दलो की कार्य-समितियो पर केन्द्रित हो जायगी। इस प्रकार काग्रेस और लीग के अपेक्षाकृत ज्यादा नरम दली तत्व शायद फिर एक-दूसरे के नजदीक आ जायगे और एकता के महत्त्वपूर्ण ढाचे को वनाये रखने का प्रयास करेगे।

माउन्टवेटन इस वात से सहमत थे कि योजना की घोपणा मे ऐसा न लगे कि विभाजन पूर्व-निश्चित वात थी, वल्कि लोगो को मालूम यह पडे कि विभाजन के प्रश्न पर आखिरी निर्णय जनता की इच्छा पर छोड दिया जायगा। सयुक्त भारत की सभावना पर लौटने का अवसर देने के लिए घोपणा मे वचाव की धारा जोड दी जानी चाहिए। उन्होने कहा कि वह, किसी भी ऐसी योजना को सयुक्त भारत की योजना मानने को तैयार होगे, जिसमे मत्रिमडलीय-योजना मे वर्णित विपय केन्द्र के अधीन दिये गए होगे। उदाहरणार्थ, विदेशी मामले, सुरक्षा और सचार-साधन। उनकी नजर मे सारी वात का सार यह था कि मत्रिमडलीय योजना के अन्तर्गत, केन्द्र मे स्थित हिन्दू-वहुमत का पलडा हमेशा मुसलमान-अल्पमत मे भारी

रहेगा और वह सुरक्षित विषयो का उपभोग उन्हे दबाये रखने के लिए करेगा। दूसरा उपाय यह था कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समता के आधार पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करे। यदि ऐसे सयुक्त भारत का निर्माण हो सका तो पजाब, बगाल और आसाम अखड बने रह सकेगे। एबेल ने बतलाया कि दो सत्ता-सम्पन्न राज्यो की सापेक्ष्य शक्ति पर निर्भर करनेवाली समता सच्ची समता न होगी। माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि वह इस तथ्य के प्रति सजग है। उन्होने कहा, "मेरा उद्देश्य यह है कि या तो दो सर्व सत्तासम्पन्न राज्यो की स्थापना हो या ऐसे दो समूहो की रचना हो, जो केन्द्र के साथ आदान-प्रदान करे। बहुमत से निर्णय करने की प्रणाली के पक्ष मे मै नही हू।"

माउन्टबेटन ने कलकत्ते के भविष्य के बारे मे भी प्रश्न उठाया। उनका अनुमान था कि मुसलमान उसके लिए जनमत-सग्रह की माग करेगे और उसका भविष्य बडा पेचीदा प्रश्न बन जायगा। लेकिन इस सम्बन्ध मे आत्मनिर्णय का मार्ग अपनाना अवाछनीय होगा और उसका नतीजा भी शायद गलत निकले।

उन्होने कहा कि पटेल की शिकायत है कि "न आप खुद शासन करेगे, न हमे करने देगे।" लेकिन सच बात यह थी कि नेताओ के साथ अतिम चर्चा के लिए हम १९ मई जैसी निकट की तारीख तय कर रहे थे।

नई दिल्ली, शनिवार, २६ अप्रैल १९४७

कि यदि ब्रिटेन ने उसके साथ कोई सैनिक या राजनैतिक सधि करने का प्रयत्न किया तो भारत सघ उसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समझेगा।"

इसपर माउन्टबेटन का विचार यह था कि उन्हे कोई आदेश प्राप्त नही हुआ कि यदि भारत का कोई एक या अधिक भाग राष्ट्रमडल मे बने रहने की इच्छा प्रकट करे तो वह क्या रुख अपनाए। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट आदेश दिये है कि वह इस विषय मे कोई ऐसी बातचीत न करे, जिससे भारत की एकता की सभावना खतरे मे पड जाय। एकता स्थापित करना माउन्टबेटन की प्रथम महत्त्वाकाक्षा थी और यही उनका प्रमुख सकल्प रहेगा।

: ६ :

सीमा-प्रान्त की यात्रा

सरकारी भवन, पेशावर,
सोमवार, २८ अप्रैल, १९४७

आज सवेरे तडके मै वाइसराय के दल के साथ हवाई जहाज द्वारा पेशावर के लिए रवाना हो गया। माउन्टबेटन-दम्पती पमेला को भी अपने साथ लाये थे। दल के शेष सदस्य थे आइन स्काट (जिनके आई सी एस जीवन का अधिकाश भाग सीमाप्रात मे ही बीता था), लेडी माउन्टबेटन की सहायक म्यूरियल वाट्सन और मार्टिन गिलियट। यात्रा मे बहुत झोके लगे थे और खास तौर से पमेला और मुझे दोनो को ही कुछ-कुछ अस्वस्थता महसूस हो रही थी। मार्ग मे सर्वाधिक प्रभावशाली दृश्य नगापर्वत का था, जो हवाई जहाज से लगभग सौ मील उत्तर मे दिखलाई पड रहा था। वह बडी एकरूपता के साथ लगभग पच्चीस हजार फुट ऊचा उठा चला गया था, और आसपास के शिखरो से कम-से-कम दस हजार फुट ऊचा था। दोपहर के जरा बाद ही हम यहा के हवाई अड्डे पर उतरे।

हमे आशा थी कि सरकारी भवन मे पहुचने पर, तीसरे पहर की बैठक के पूर्व, हम शातिपूर्वक भोजन कर सकेगे। किन्तु यहा हमारा सामना एक सकटपूर्ण स्थिति से हुआ, जो आतक की हद तक पहुच गई थी।

गवर्नर सर ओलफ केरो ने हमे बताया कि एक मील से भी कम दूरी पर मुस्लिम लीगी एक विराट् प्रदर्शन कर रहे है। वे वाइसराय के सामने अपनी शिकायते रखना चाहते थे और जलूस बनाकर सरकारी भवन पर कूच करने, और इस प्रकार कानून-भग करने, पर भी तुले हुए थे। कैरो के कथनानुसार, इसका

एकमात्र उपाय यही था, कि वाइसराय स्वय पहले ही उनपर 'कूच' कर दे और भीड के सामने उपस्थित हो जाय। प्रदर्शनकारियो की सख्या ७० हजार से अधिक थी और वे दूर-दूर के भागो से एकत्रित हुए थे। उसमे से बहुत से कई-कई दिनो का मार्ग तय करके आये थे। माउटबेटन ने कैरो और प्रधान मत्री डा० खानसाहब के साथ सक्षेप मे 'युद्ध-मत्रणा' की और यह तय हुआ कि वाइसराय अविलम्ब भीड के सामने चले जाय।

इसके पश्चात् माउन्टबेटन प्रदर्शनकारियो के बीच पहुचे। लेडी माउन्टबेटन भी बडे साहस के साथ उनके साथ गई। नि सदेह, हमारे सामने एकत्र भीड भयावह थी। हम ऐतिहासिक किले 'बाला हिसार' के निकट रेलवे के बाध पर चढ गये और हमने कनिघम पार्क मे इकट्ठी तथा दूर-दूर के खेतो तक फैली हुई विशाल भीड देखी। वह अनेक प्रकार की चेष्टाए कर रही थी और पाकिस्तानी चाद-तारे के अनेक हरे झडे, जो गैरकानूनी थे, हिला रही थी। 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारो का समा बधा हुआ था।

परन्तु हमारे पहुचने के कुछ ही मिनट बाद वह मनहूस आवेश दब गया। नारा भी बदल गया। अब 'माउन्टबेटन जिन्दाबाद' का नारा सुनाई पडने लगा और क्रोधभरे चेहरो पर मुसकराहट खेलने लगी। माउन्टबेटन और लेडी माउन्टबेटन दोनो खाकी बुश-शर्ट पहने हुए लगभग आध घटे तक भीड की ओर, जिसमे बच्चो और स्त्रियो की भी आश्चर्यजनक सख्या थी, हाथ हिलाते रहे। किसी प्रकार के भाषण का तो प्रश्न ही नही था। परन्तु उस धर्मान्ध समुदाय पर उनके मैत्री तथा आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव आश्चर्यजनक था।

जब हम नीचे आये और भोजन के लिए सरकारी भवन की ओर चले, उस समय गवर्नर और स्थानीय अधिकारियो के चेहरो पर राहत का भाव छिपा नही रह सका। उन्होने बताया कि यदि भीड ने सरकारी भवन पर कूच करने का निश्चय कर लिया होता तो स्थानीय पुलिस और सेना उसे शातिमय उपाय से रोक नही सकती थी।

दोपहर के खाने के बाद माउन्टबेटन ने लबी मुलाकातो का सिलसिला शुरू किया। उनमे से दो के समय मै वहा मौजूद था—एक तो खानसाहब और उनके मत्रिमडल के चार सदस्यो के साथ और दूसरी स्थानीय हिन्दुओ के प्रतिनिधि-मडल के साथ। वह स्थानीय मुस्लिम लीगी नेताओ से भी मिले, जिन्हे इस मुलाकात के लिए जेल से लाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। उन झगडो के अलावा, जो काग्रेस और लीग के आम सघर्ष को गम्भीर स्वरूप देने के लिए पर्याप्त थे, गवर्नर और उनके काग्रेसी प्रधानमत्री के बीच के सम्बन्ध भी कम खराब नही थे। राष्ट्रीय-स्तर पर इस झगडे का भी काफी व्यापक असर पडा।

डा० खानसाहब तथा उनके साथियो के साथ भेट मे, जिसमे गवर्नर भी

उपस्थित थे, माउटबेटन की कूटनीतिक सूझबूझ का सुन्दर प्रदर्शन हुआ। मुलाकात शुरू करते हुए उन्होने कहा कि मै आपसे व्यक्तिगत भेट करके अनुगृहीत हुआ। उन्होने एक-दूसरे से प्रश्न पूछे। उन्होने डा० खानसाहब के इस परामर्श की सराहना की कि उन्हे प्रदर्शनकारियो से भेट करने जाना चाहिए। वास्तव मे बाध पर खडे हो जाने के अतिरिक्त उन्होने और कुछ नही किया था। पहले वह जिन्ना को सरकारी भवन तक जुलूस मे लाने की इजाजत देने से इन्कार कर चुके थे। डा० खानसाहब ने यह बताने की कोशिश की कि उन्होने लालकुर्ती दल के जुलूस का आयोजन भी रद्द कर दिया था।

माउन्टबेटन ने कहा कि मै भारत को भारतीयो के हाथ मे सौपने और जनता की इच्छा के अनुसार सत्ता हस्तान्तरित करने आया हू। मै पजाब तथा बगाल के लिए उपयुक्त समाधान की खोज कर रहा हू। परन्तु सीमाप्रान्त की स्थिति ने मेरे सामने विशेष कठिनाइया उपस्थित कर दी है। मै मुस्लिम लीग से कहूगा कि हिसा के सामने सिर नही झुकाया जायगा। मै निजी तौर पर आपको बताता हू कि चुनाव कराना आवश्यक है, परन्तु मै मुसलमानो को पक्का आश्वासन नही दे सकता कि चुनाव कराये ही जायगे। जिन्ना का वादा है कि यदि चुनाव हुए तो हिसा नही होगी। आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। जिन्ना यह स्थिति स्वीकार करते है और अपने अनुयायियो को आदेश दे रहे है कि वे कानून-भग करने का आदोलन बन्द कर दे।

माउन्टबेटन ने पूछा कि मुस्लिम लीग हाई कमान की बात कितनी मानी जाती थी। उत्तर मिला कि स्थानीय मुस्लिम लीग ने विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ मे ले ली है। गत चुनाव मे पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग को स्पष्ट पराजय हो चुकी थी और अब्दुर्रब निश्तर भी चुनाव मे सफल नही हो सके। उस समय काग्रेस की 'अग्रेजो, भारत छोडो' नीति की विजय हुई थी; परन्तु अब वह नारा लोगो को सगठित नही कर पा रहा था और लोग शका करने लगे थे कि कही वे हिन्दुओ के प्रभुत्व मे तो नही फस जायगे।

जब डा० खानसाहब ने पठानिस्तान का प्रश्न छेडा उस समय बातचीत कुछ विश्रृखल और विस्फोटक हो उठी। कुछ समय से गाधीजी पठानिस्तान की कल्पना मे सक्रिय दिलचस्पी ले रहे थे। और इधर उन्होने उसका काफी गुणगान किया था। यदि वह कल्पना मूर्त्त-रूप ग्रहण कर सकी, तो एक नई सीमाप्रातीय राष्ट्रीयता का उदय हो जायगा, जो पाकिस्तान के प्रति प्रान्त की साम्प्रदायिक और राजनैतिक एकता को खडित कर देगी। डा० खानसाहब ने चेतावनी दी, "पठान राष्ट्र को नष्ट करने के परिणाम भयानक होगे।"

माउन्टबेटन ने पूछा कि सीमाप्रान्त मे मिली-जुली सरकार का सगठन क्यो नही किया गया? डा० खानसाहब ने उत्तेजित होकर कहा, "यदि काग्रेस मिलीजुली

सरकार बनाना चाहेगी तो मैं उसमे न रहूंगा।" माउन्टबेटन ने तुरन्त उत्तर दिया, "मैंने केवल जानकारी के लिए पूछा था।"

खानसाहब ने आगे कहा, "हमारी जनता बहुत गरीब है। यहां की मुस्लिम लीग केवल अपने सकीर्ण, स्वार्थी और कुछ विशेषाधिकारी वर्गो का ही प्रतिनिधत्व करती है।" कैरो ने बताया, "काग्रेस के भी कुछ धनी समर्थक है।"

माउटबेटन ने प्रान्त मे साम्प्रदायिक स्थिति की बात पूछी। कैरो ने उत्तर दिया, "मुस्लिम जनता हिन्दुओ और सिखो की रक्षा कर रही है। केवल हजारा मे ऐसा नही। मुसलमानो का दिल और दिमाग सही है।" खानसाहब ने आरोप किया कि अधिकारियो ने मुसलमानो को कानून तोडने की छूट दे रखी है। कैरो ने दृढतापूर्वक कहा कि मुझे एक उदाहरण भी नही मालूम, जिसमे कर्मचारियो ने अपने कर्त्तव्य का पालन न किया हो, फिर भी उन्हे हमेशा दोष दिया जाता है।

इसके पश्चात् वैधानिक कार्यविधि के बारे मे बातचीत हुई। गवर्नर ने प्रधान मत्री पर अनुचित शासनिक दबाव डालने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, प्रधान मत्री ने गवर्नर पर हस्तक्षेप का दोषारोपण किया। माउन्टबेटन ने बीच मे दखल देते हुए कहा, "मै यहा कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नही आया। मै जनता की इच्छा के अनुसार सत्ता-हस्तातरण करना चाहता हू। आदर्श तो यह होता कि मै यहा की जनता का मतसग्रह कर लेता, परन्तु इसके लिए समय नही है।"

उन्होने प्रान्तो को सत्ता हस्तातरित करने और सामान्य दृष्टि से, तथा सीमा-प्रान्त की विशेष दृष्टि से देश के विभाजन की समस्याओ पर बातचीत की। अपने ऊपर आये हुए गभीर कर्तव्य की चर्चा करते हुए उन्होने कहा, "मेरे सामने समस्या यह है कि हम जाने के पूर्व यहा चुनाव करा दे या वर्तमान न्याय और व्यवस्था सरकार को कायम रखने के लिए काफी है।" उन्होने चुनावो के बारे मे सलाह देने के लिए दोनो हाई-कमानो की सयुक्त बैठक का सुझाव दिया। उन्होने कहा, "अग्रेजो ने सदैव मनमानी की थी, किन्तु मुझे निष्पक्ष रहने का आदेश मिला है।"

इस बैठक के बाद ही स्थानीय हिन्दुओ के प्रतिनिधियो के साथ बातचीत आरम्भ हो गई। उन्होने बताया कि उनका शिष्ट-मडल राजनैतिक या लीग-विरोधी नही है, बल्कि साम्प्रदायिक है। उन्हे मत्रि-मडल के भाग्य से कोई वास्ता नही, वे केवल निर्दोष हिन्दुओ और सिखो की रक्षा चाहते थे।

माउन्टबेटन ने कहा, "मै वस्तुस्थिति जानने का प्रयत्न कर रहा हू। क्या आप सरकार के समर्थक है?"

हिन्दुओ ने उत्तर दिया, "हम किसी भी सरकार के शासन मे शातिपूर्वक रहने को तैयार है।"

माउन्टबेटन ने कहा, "मुझे इस बुद्धिमत्तापूर्ण रुख से प्रसन्नता है। मै वैधानिक रूप मे काम करने का प्रयत्न कर रहा हू।"

पुलिस की कमी की शिकायते की गई। वास्तव मे उसपर असाधारण भार था। चार ब्रिटिश ब्रिगेड उपलब्ध थे, फिर भी पेशावर मे हत्याए जारी है और पुलिस कोई प्रभावोत्पादक कार्रवाई नही करती। माउटबेटन ने पुलिस के स्थान पर सैनिको के उपयोग का खतरा बताया। दोनो का काम भिन्न है। उन्होने कहा कि इस समय सीमाप्रान्त मे भारत के सब प्रान्तो की अपेक्षा अधिक सेना है। केरो ने कहा कि उसका उपयोग जितना इस समय किया जा रहा है उतना गत २५ वर्षों मे, जिनमे १९३०-३१ का काल भी सम्मिलित है, कभी नही हुआ। माउन्टबेटन ने कहा कि मै एक बडा हल निकालने और अस्थिरता का अन्त करने का प्रयत्न कर रहा हू, परन्तु यह ऐसा हल नही होगा, जो सबको स्वीकार हो।

मै तीसरी बैठक के लिए नही रुक सका। यह बैठक उन मुस्लिम लीगी नेताओ के साथ हुई, जो इसके लिए विशेष रूप से जेल से छोडे गए थे। इन व्यक्तियो मे मनकी शरीफ के नौजवान और धर्मान्ध पीर और खान अब्दुल कय्यूम खा सम्मिलित थे। आइन स्काट से मुझे ज्ञात हुआ कि इन लोगो ने अत्यन्त आवेश के साथ बडे विस्तारपूर्वक अपनी बाते कही। माउटबेटन ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण आदेश दिया था कि इन सबको एक ही जेल मे रखा जाय, जिससे ये एक-दूसरे से मिल सके और परस्पर विचार-विनिमय कर सके। वह उनके इस प्रस्ताव से भी सहमत हो गए कि उन्हे जिन्ना से परामर्श करने के लिए दिल्ली जाने दिया जाय।

वाइसराय-भवन, नई दिल्ली,
बुधवार, ३० अप्रैल, १९४७

हमारा दल दो टुकडो मे विभक्त हो गया—माउन्टबेटन पेशावर और रावलपिडी के दौरे के बाद सीधे दिल्ली लौटे और लेडी माउटबेटन ने दगाग्रस्त इलाके का दौरा जारी रखा। मै उन सम्वाददाताओ के साथ व्यस्त हो गया, जो इस दौरे के नतीजो के बारे मे अन्दरूनी जानकारी पाने के लिए उत्सुक थे। सावधानी से कदम रखने की जरूरत थी। काग्रेस और लीग की सारी नजरे अस्थायी रूप से सीमान्त प्रदेश पर केन्द्रित थी। वातावरण तरह-तरह की अटकलो से भरा हुआ था।

मेरा पहला काम था 'डान' के सम्पादक अल्ताफ हुसैन से निबटना। अल्ताफ हुसैन ने अपने पेशावर-सम्वाददाता की एक निहायत गलत कहानी इन बडे-बडे शीर्षको के अन्तर्गत छापी थी "माउटबेटन की सीमान्त नेताओ से चर्चा—मनकी और कय्यूम ने पेरौल पर छोडा जाना ठुकराया—पठान स्त्री-पुरुषो द्वारा विराट् प्रदर्शन—वाइसराय हवाई जहाज से जमरूद जा रहे है।" चूकि माउन्टबेटन ने दो घटे से भी अधिक मनकी शरीफ के पीर और कय्यूम के साथ चर्चा मे विताये थे, जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि-मडल के प्रमुख प्रवक्ता थे, इसलिए उनकी पहली

प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्हे जिन्ना के पास व्यक्तिगत रूप से विरोध भेजना चाहिए। लेकिन अल्पताफ हुसैन के इस वादे पर कि यह कहानी कल सुधार दी जायगी, मैने उन्हे ऐसा करने से रोका। इस पत्र के सम्वाददाता की कल्पना-शक्ति ने सबसे बडी अक्लमन्दी तो इस बात मे जाहिर की थी कि वाइसराय हवाई जहाज से जमरूद जायगे जबकि जमरूद मे हवाई अड्डा ही नही है।

रायटर के डून कैम्पबेल ने आधी रात गये मुझे फोन पर बतलाया कि जिन्ना और डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अभी-अभी बडे आवेशपूर्ण वक्तव्य पत्रो के लिए दिये है। उन्होने कहा कि जिन्ना ने असल मे 'कटे-फटे और घुन-लगे पाकिस्तान' के खिलाफ आन्दोलन का पहला तीर छोडा है, और कही अधिक विशाल आकार वाले राष्ट्रीय स्वदेश की महत्वाकाक्षा जाहिर की है। उनकी माग है कि मत्रिमडल-योजना के 'ख' और 'ग' भाग के समस्त प्रातो (सिध, पजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश, बलूचिस्तान, बगाल और आसाम) को उनके साम्प्रदायिक बहुमतो का विचार किये बिना प्रस्तावित "राष्ट्रीय स्वदेश" मे शामिल किया जाय। ऐसा प्रतीत होता था कि राजेन्द्रप्रसाद के वक्तव्य मे मुस्लिम लीग के १९४० के लाहौर-प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इसी प्रस्ताव मे पाकिस्तान की कल्पना सामने रखी गई थी, जिसमे कहा गया था कि केवल वही भाग पाकिस्तान मे शामिल होगे, जहा मुसलमानो का बहुमत है। विधान-सभा के तीसरे अधिवेशन मे, जो इसी सप्ताह प्रारम्भ हुआ था, डा० राजेन्द्रप्रसाद ने सभा के नये अध्यक्ष के नाते बोलते हुए सदस्यो के दिमाग भारत-विभाजन के लिए तैयार कर दिए थे। अब वह लोगो के दिमाग प्रान्तो के बटवारे के लिए तैयार कर रहे थे।

डा० राजेन्द्रप्रसाद काग्रेस हाई कमान के सबसे प्रभावशाली नेताओ मे से हैं और अतरिम सरकार मे खाद्य तथा कृषि विभाग के मत्री थे। अभी उस दिन, जब मै उनके यहा चाय पीने गया तो मेरे ऊपर उनकी सौम्यता, दिमाग की गहराई और चरित्र की दृढता का गहरा असर पडा। मूलत, वह नरम विचारो वाले व्यक्ति है और समझौतावादी है। वह जनता के आदमी है ओर उनकी कीर्ति मे किसी प्रकार के पाखड का कोई योग नही। उनकी कीर्ति तो राष्ट्र की ईमानदारी से लम्बी सेवाओ का फलमात्र है। चाहे भारत सयुक्त रहे या विभाजित हो, उसकी नई सरकार मे वह निश्चय ही महत्त्वपूर्ण स्थिति मे भाग लेगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २ मई, १९४७

मैने आज यह विज्ञप्ति प्रेस को दी थी कि माउटबेटन सपरिवार थोडे दिनो के लिए शिमला जा रहे है। माउन्टबेटन यह स्पष्ट करने को व्यग्र थे कि इससे उनके काम मे किसी प्रकार का खलल नही पडेगा। इसलिए वक्तव्य मे बतलाया

गया था कि भारतीय नेताओ के साथ उन्होने अपनी प्रारम्भिक बातचीत पूरी कर ली है और मत्रिमडल की साप्ताहिक बैठक मे भाग लेने के बाद वह ६ तारीख को यहा से रवाना होगे और मत्रिमडल की अगली बैठक के समय तक यहा लौट आवेगे ।

मै आज रात दिल्ली मेल से रवाना हो रहा हू, जिससे सोमवार को शिमला मे वाइसराय के मुख्य दल के पहुचने के पूर्व कुछ दिन अपने परिवार के साथ शाति से मशोबरा मे बिता सकू ।

: ७ :

शिमला में संकट

'दि रिट्रीट', मशोबरा, शिमला,
सोमवार, ५ मई, १९४७

पिछले अडतालीस घटे मैने आराम करने मे बिताये और अपने निवास मे बैठकर हिमालय की भव्यता और एकातवास का रसपान किया । कई-कई दिनो तक कोहरा और बादल विशाल पर्दे की भाति आकाश मे तन जाते और नीचे की घाटी तथा पडोस के 'शाली'-शिखर के अतिरिक्त, जो सिर्फ बारह हजार फुट ऊचा है, और कुछ दिखलाई नही पडता । 'शाली' भी वसन्त के मौसम मे बरफ से खाली रहता है। फिर सहसा यह पर्दा उठ जाता है और अनत हिम की एक अटूट अर्द्ध-चन्द्र रेखा सामने आ खडी होती है, जिसमे कितनी ही पर्वतमालाए है, अधिकाश सोलह सौ फुट से अधिक ऊचाई वाली । हिमालय की मुख्य पर्वतमाला मे इतने ही प्रभावशाली और दृश्य भी होगे, क्योकि "दुनिया की यह छत" दो सो पचास हजार वर्गमील मे फैली हुई है और चौबीस हजार फुट से अधिक ऊचाई वाले कम-से-कम चालीस शिखर उसमे शामिल है । शिमला से दृष्टिगोचर होनेवाला यह शानदार और सिहरन पैदा करनेवाला दृश्य उस विराट् का ही एक प्रतीक है ।

इधर मै मशोबरा मे आराम कर रहा था, उधर दिल्ली मे राजनैतिक घटनाओ की गति तेज हो रही थी । इस्मे और एबेल दो मई को लन्दन के लिए रवाना हुए । प्रस्तावित मसविदा ब्रिटिश सरकार के विचार के लिए वे अपने साथ ले गए थे ।

शनिवार को भारतीय पत्रो ने पहली बार माउटबेटन पर भारी हमला किया । महत्त्व की बात यह थी कि यह हमला 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मे शुरू हुआ । 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को काफी मान दिया जाता था ।

लेख का प्रारम्भ इस प्रकार था "जब से लार्ड माउन्टबेटन ने वाइसराय का पद सभाला है तबसे पहली बार काग्रेस-जनो और सिख-नेताओ के दिलो मे यह आशका उठी थी कि शायद वह ईमानदारी से काम नही कर रहे।" इसके बाद वाइसराय के मुख्य निष्कर्षो का जिक्र था, जिनके सही अदाज को देखकर लगता था कि पत्र को काफी अन्दरूनी जानकारी रही होगी। इसपर काग्रेस की धमकी-भरी प्रतिक्रिया का भी उल्लेख था। यह बात भी काफी सही थी। काग्रेस ने पजाब मे सिखो के लिए विशेष सुविधाओ की माग की थी। सीमाप्रान्त मे चुनाव की माग मजूर करने के बारे मे भी आशकापूर्ण अनिच्छा का प्रदर्शन किया गया था। लेख मे कहा गया था कि "काग्रेस कार्यकारिणी ने सीमान्त के प्रश्न को कसौटी मान लिया है। उसने वाइसराय को साफ बतला दिया है कि अगर सीमाप्रान्त मत्रिमडल को भग करने और नये चुनाव करवाने का सुझाव रखा गया तो काग्रेस ब्रिटिश सरकार के बारे मे अपने सारे दृष्टिकोण को बदल देगी।"

ज्ञात हुआ कि माउन्टबेटन ने कल गाधीजी और जिन्ना के साथ दो महत्त्वपूर्ण चर्चाए की। इन चर्चाओ का असर यह हुआ कि माउन्टबेटन सोचने लगे कि शायद इस्मे को भेजने मे जल्दबाजी हो गई। सयोगवश, पहले मुलाकाती के जाने के पहले दूसरे मुलाकाती वहा आ गए। माउन्टबेटन ने दोनो नेताओ को मिलाकर राजनैतिक सूझ-बूझ और सामाजिक शिष्टाचार का परिचय दिया। दोनो नेताओ की गत तीन वर्षो मे यह पहली मुलाकात थी। लेकिन परस्पर अभिवादन खत्म होते ही जो कुछ हुआ उस से माउटबटन के अनुमानो पर पानी फिर गया। दूर-दूर कुर्सियो पर बैठे गाधी और जिन्ना सुन सकने योग्य आवाज मे बोलने मे असमर्थ थे और लगता था, मानो दो पुराने षड्यत्रकारी कठपुतलियो का तमाशा कर रहे हो। लाख कान लगाने पर भी माउन्टबेटन उनकी बातो का अधिकाश भाग नही सुन पाये। फिर भी, उनका असली मकसद तो पूरा हो ही गया। दोनो नेता जिन्ना के निवासस्थान पर विस्तृत चर्चा करने पर राजी हो गये।

शिमला के लिए प्रस्थान करने के पूर्व माटउन्बेटन इस विषय मे पजाब, बगाल और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश के गवर्नरो के मत जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनके प्रान्तो मे मत-सग्रह करना उचित होगा या नही। केरो सीमान्त प्रदेश मे मत-सग्रह के पक्ष मे थे। बरोज बगाल के बारे मे गोलमोल बात कहते थे, हालाकि सब मिलकर इसके खिलाफ थे। जेनकिन्स स्थिति को नितात निराशाजनक समझते थे और उन्हें शक था कि न जिन्ना इसे स्वीकार करे और न सिख लोग। फिर भी माउन्टबेटन का यह पक्का विश्वास था कि अंत मे जिन्ना मत-सग्रह के लिए राजी हो जायगे और सिखो के लिए अपनी स्थिति को सुधारने का एकमात्र मार्ग है बातचीत।

शिमला, मगलवार, ६ मई, १९४७

गाधीजी और जिन्ना के बीच जिन्ना के औरगजेब रोड स्थित निवास-स्थान पर तीन घटे तक चर्चा हुई।

निम्नलिखित वक्तव्य दोनो की सहमति से प्रकाशित किया गया

"हमने दो विपयो पर चर्चा की। पहली भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान मे विभाजित करने के प्रश्न पर। श्रीगाधी विभाजन के सिद्धात से सहमत नही है। उनका विचार था कि विभाजन अवश्यभावी नही है। जबकि मेरा विचार है कि पाकिस्तान अवश्यभावी ही नही, बल्कि भारत की राजनैतिक समस्या का एकमात्र व्यावहारिक हल भी वही है।"

"जिस दूसरे विपय पर हमने चर्चा की वह था एक पत्र। जिसपर हम दोनो ने हस्ताक्षर कर जनता से शाति बनाये रखने की अपील की है। हम दोनो इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अपने-अपने दायरो मे हमे पूरा प्रयत्न कर यह चेष्टा करनी चाहिए कि हमारी इस अपील पर अमल हो और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम पूरी कोशिश करेगे।"

हालाकि जहा तक बातचीत का सम्बन्ध था, उसका कोई फल नही निकला, लेकिन, जैसाकि सयुक्त वक्तव्य के मसविदे से जाहिर था, पलडा जिन्ना का ही भारी रहा। मत्रिमडलीय-योजना एक कदम और नीचे को सरक गई। सवाल अब सिर्फ यही था कि विभाजन की दिशा मे बहने वाले प्रवाह को रोकने के लिए गाधीजी क्या कर सकते है और क्या करेगे।

शिमला, बुधवार, ७ मई, १९४७

आज वाइसराय भवन से बुलावा आने के साथ ही मेरे अल्पविश्राम का अन्त हो गया। माउटबेटन वी पी मेनन को अपने साथ लाये है। इन्होने १९४५ की शिमला-वार्ताओ और १९४६ की मत्रिमडलीय-योजना-सम्बन्धी चर्चाओ मे काफी हाथ बटाया था। वह सरदार पटेल के विश्वासपात्र है।

आते ही मै कर्मचारीमडल की दो लगातार बैठको मे व्यस्त हो गया। एक मे माउन्टबेटन उपस्थित नही थे। दोनो बैठको मे हमने वी पी मेनन की इस मान्यता के आधार पर दूसरी योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया कि जिन्ना प्रस्तावित योजना स्वीकार नही करेगे। माउन्टबेटन ने कहा कि इस सभावना को उन्होने हमेशा ध्यान मे रखा है कि जिन्ना उसे ठुकरा देगे। इसलिए जिन्ना और लियाकत के साथ हुई मुलाकातो मे इस इरादे का सकेत पाने के लिए सावधान रहे। लेकिन ऐसा कोई सकेत उन्हे नही मिला। हर नजर से विचार करने के बाद वह इसी नतीजे पर पहुचे कि वे योजना को स्वीकार करेगे। जिन्ना के इसे स्वीकार न करने के दो कारण हो सकते थे। पहला तो यह कि उनका असली इरादा अग्रेजो को भारत

मे रखना हो, और सोदेबाजी को लम्बा करके वह अग्रेजो के लिए यहा से जाना कठिन कर देना चाहते हो, जिससे अपने लिए और भी सुभीते पा सके। दूसरा यह कि वह इस निष्कर्ष पर पहुचे हो कि पाकिस्तान की स्थापना व्यावहारिक नही है।

लेकिन वह नही सोचते कि इन दोनो मे से कोई भी बात जिन्ना के दिमाग मे थी। फिर भी वह वी पी मेनन के इस सुझाव से सहमत हो गए थे कि जिन्ना के साथ बातचीत करते समय उन्हे एक दूसरी योजना भी तैयार रखनी चाहिए। दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रान्तो मे सत्ता का बटवारा वर्तमान विधान के अनुसार ही किया जायगा। प्रान्तीय विषय वर्तमान प्रान्तीय सरकारो को सौप दिये जायगे और केन्द्रीय विषय वर्तमान केन्द्रीय सरकार को। लेकिन इसमे मुसलमानो को हिन्दू बहुमत के अन्तर्गत काम करना पडेगा।

लन्दन भेजने के लिए एक तार का मजमून तैयार किया गया। सारी जानकारी देते हुए ऐसी योजना की स्वीकृति मागी गई। भारत को राष्ट्रमडल मे बनाये रखने की सभावनाओ पर हमने आगे विचार किया। मेनन ने इस सम्बन्ध मे पटेल और नेहरू के स्वीकारात्मक दृष्टिकोण की चर्चा की और सम्राट् तथा साम्राज्य शब्दो को निकालने की जरूरत बताई, क्योकि बहुत से भारतीय इनके खिलाफ थे अन्त मे वी. पी मेनन से एक अभिलेख तैयार करने को कहा गया, जिसमे विस्तार के साथ बतलाया गया हो कि विभाजन अथवा प्रान्तो मे सत्ता वितरण की योजना के अन्तर्गत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की क्या कार्यविधि होगी।

शिमला, शुक्रवार, ९ मई, १९४७

नेहरू और कृष्ण मेनन यहा पहुच गये है। अगर ओपनिवेशिक स्वराज्य का प्रश्न सामने आया तो उसकी सफलता का दारोमदार इसपर निर्भर करेगा कि माउन्टबेटन उसके लिए इन दोनो को राजी कर पाते है या नही। अभी से कृष्ण मेनन ओपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी आ जाने पर भारतीय सेना के टुकड किये जाने के खिलाफ थे। मिएविल का विचार था कि अगर भारत राष्ट्रमडल मे रहा तो राष्ट्रमडल की अपेक्षा भारत को इससे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन माउन्टबेटन का कहना था कि भारत के शामिल होने से ब्रिटेन का दुनिया मे मान भी बढेगा ओर युद्धनीति की दृष्टि से भी उसे अपार लाभ होगा।

कल तीसरे पहर चर्चाओ के गम्भीर दोर से जरा छुट्टी मिली। माउन्टबेटन-दम्पति नेहरू को चाय के लिए रिट्रीट लाये।

चाय के बाद नेहरू ने कहा कि वह हमारे बच्चो को देखना चाहेग। माउन्टबेटन ने मेरे लडके कीथ को अपना मुह-बोला बेटा बतलाते हुए कहा, "यह इतना सीधा खडा होता है कि पीछे को जा गिरेगा।" फिर हम विशाल भवन ओर उसके बागो की सैर करने चले गए।

शिमला, शनिवार, १० मई, १९४७

कर्मचारी-मंडल की आज की बैठक मे माउन्टबेटन ने बताया कि काग्रेसी नेताओ को औपनिवेशिक स्वराज्यवाली बात अधिकाधिक अपील कर रही है। कृष्ण मेनन का दावा है कि यह सुझाव सबसे पहले उन्होने ही दिया था। उनका खयाल है कि नेहरू भी इस सुझाव से आर्कर्पित हुए थे, क्योकि इसमे माउन्टबेटन अनिच्छुक राजाओ को प्रभावित कर सकेगे। वी पी मेनन सोचते थे कि जबतक भारत का स विधान पूरा न हो जाय तबतक के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य भी कोई बुरी चीज नही है। किन्तु काग्रेस के लिए सबमे बडी कठिनाई यह दीखती थी कि वामपक्षी लोग कहेगे कि औपनिवेशिक स्वराज्य लेकर ब्रिटेन के सामने घुटने टेक दिये गए है।

आज मैने यह महत्त्वपूर्ण सूचना निकाली कि वाइसराय ने शनिवार १७ मई को साढे दस बजे सवेरे पाच नेताओ को तथा दोपहर बाद रियासतो के प्रतिनिधियो को मिलने के लिए आमन्त्रित किया है। मुलाकात का उद्देश्य है सत्ता हस्तातरण की ब्रिटिश-योजना से उन्हे परिचित करना।

शिमला, रविवार, ११ मई, १९४७

माउन्टबेटन ने मुझे फोन किया कि कल रात की विज्ञप्ति मे नेताओ के साथ बैठक की जो घोषणा की गई थी उसे स्थगित करना पडेगा। उन्होने कहा कि मै दूसरी विज्ञप्ति तैयार कर डालू। शाम को साढे छ बजे जब मै वाइसराय भवन पहुचा तो निराशा और घबराहट का वातावरण देखने को मिला।

ऐसा लगता था कि माउन्टबेटन ने नेहरू को वह योजना दिखाई, जो लन्दन से सुधर कर और मजूर होकर आई थी। उसे पढकर नेहरू ने उसका कडा विरोध किया। उनका मत था कि मान्उन्टबेटन और उनके कर्मचारियो ने जो योजना तैयार की थी और जिसे लेकर इस्मे और जार्ज एबेल इस महीने के प्रारम्भ मे लन्दन गये थे, प्रस्तुत योजना उससे बुनियादी रूप से भिन्न थी।

नेहरू का विश्वास था कि मन्त्रिमडलीय-योजना और माउन्टबेटन के मसविदे मे यह मानकर चला गया था कि भारत कोई नया राज्य नही है। लेकिन लन्दन ने जो मसविदा भेजा था उसका अर्थ तो शुद्ध खडीकरण था। नेहरू असल मे चाहते यह थे कि यह बात स्पष्टत मान ली जाय कि भारत और उसकी विधान-सभा ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी है और पाकिस्तान तथा मुस्लिम लीग उससे पल्ला झाडनेवाले थे। उनकी उठाई बहुत-सी आपत्तिया बिल्कुल गौण थी और उन्हे सहज ही निबटाया जा सकता था। उदाहरण के लिए, उनका कहना था कि वह बलूचिस्तान के भाग्य के निबटारे के लिए सुझाई गई कार्यप्रणाली को नही मानेगे। यह वास्तव

मे अतिरजना थी, लेकिन असलियत यह थी कि लन्दन के मसविदे मे जो नई बाते जोडी गई थी उनसे उनका यह सशय फिर जाग उठा था कि लन्दन विदेशी सिविल कर्मचारियो का गढ है, जिनके दिल कठोर है और जहा तक भारत की समस्याओ का सम्बन्ध है, उनकी समझ निहायत सीमित है।

उनके इस दृष्टिकोण का एक तात्कालिक नतीजा यह हुआ कि माउन्टबेटन और उनके कर्मचारियो को तेजी के साथ एक सशोधित मसविदा तैयार करना पडेगा, जो तुरन्त इस्मे को भेजा जा सके।

दूसरी विज्ञप्ति तैयार कर मे मिएविल के साथ माउन्टबेटन की बैठक मे पहुचा। उन्होने बताया कि कैसे केवल उनकी सूझ मात्र से ही उनका सत्यानाश होते-होते बच गया है। इसके विना ब्रिटिश सरकार के सामने वह मूर्ख सिद्ध होते, क्योकि उन्होने लन्दन को यह आशा दिलाई थी कि नेहरू योजना को स्वीकार कर लेगे। उन्होने बतलाया कि उनके अधिकाश कर्मचारी नेहरू को पहले से योजना का मसविदा दिखाने के पक्ष मे नही थे। लेकिन उनकी सलाह की बजाय अपनी सूझ का अनुसरण कर उन्होने स्थिति सभाल ली।

काफी विचार-विमर्श के बाद यह विज्ञप्ति निकालना तय हुआ "चूँकि लन्दन की पार्लमेट का अधिवेशन शीघ्र ही खत्म होनेवाला है, इसलिए हिज एक्सलेन्सी वाइसराय की भारतीय नेताओ के साथ शनिवार, १७ मई को होनेवाली बैठक सोमवार २ जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।"

शिमला, सोमवार, १२ मई, १९४७

माउन्टबेटन ने कहा कि यद्यपि वह भारतीय नेताओ पर अपनी ईमानदारी का सिक्का जमा चुके है, फिर भी लन्दन से आनेवाले प्रस्तावो के बारे मे उनके दिलो मे पुरानी शकाए और भय मौजूद है। स्पष्ट है कि भविष्य मे योजनाओ का सशोधित मसविदा भारत मे ही उनके कर्मचारियो को बनाना होगा। उन्होने यह निश्चय किया कि एक सशोधन तो यह होगा कि बगाल या किसी अन्य प्रान्त के लिए दिये जाने का विकल्प मिटा दिया जायगा। उनका खयाल था कि इस निश्चय को दोनों पक्षो की प्रार्थना पर बदला भी जा सकता था। हमारी योजना के समान नेहरू की योजना थी कि अन्तरिम सरकार को ही औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर सत्ता सौपी जाय।

: ८ :

योजना मे परिवर्तन

वाइसराय भवन, नई दिल्ली,
बृहस्पतिवार, १५ मई, १९४७

माउन्टबेटन को काफी विनम्र किन्तु जोर का बुलावा आया था कि वह विचार-विनिमय के लिए लन्दन आवे। पहले तो इस प्रस्ताव की उनके ऊपर बडी कडी प्रतिक्रिया हुई। उन्होने कहा कि उनको लन्दन जाने की कोई जरूरत नही मालूम होती। किन्तु प्रधानमत्री का दूसरा सुझाव कि यदि वह न आ सके तो मत्रिमडल के किसी सदस्य को नई दिल्ली आना पडेगा, यह उन्हे और भी नापसन्द था।

आज की बैठक का अधिकाश समय इस्मे को दिये जानेवाले जरूरी सन्देश की तैयारी और स्वदेश जाने की व्यवस्था मे लग गया। लन्दन से प्रधानमत्री ने माउन्टबेटन की प्रस्तावित स्वदेश-यात्रा के बारे मे एक विज्ञप्ति का मसविदा भेजा था। मेरा खयाल है कि मसविदे की भाषा बहुत अच्छी थी। स्वभावत माउन्टबेटन यह स्पष्ट करने को उत्सुक थे कि वह अपनी स्वेच्छा से घर जा रहे है, केवल जरूरी बुलावे के कारण नही। उनका इरादा था कि प्रस्तावित योजना पहले जिन्ना को दिखलाए और फिर नेहरू को। पटेल और लियाकत से भी वह आज मिलनेवाले थे। वी पी मेनन का अनुमान था कि शिमला मे नेहरू की उदासी का मुख्य कारण था अपने साथियो से दूर होना। पटेल का सहारा प्राप्त होने पर उनकी उदासी दूर हो जायगी।

नई दिल्ली, शुक्रवार, १६ मई, १९४७

नेहरू और पटेल ने माग की थी कि काग्रेस अध्यक्ष कृपलानी का नाम भी नेताओ की बैठक मे आमत्रित व्यक्तियो मे शामिल कर लिया जाय। वे सोचते थे कि ऐसा करने से उन्हे काग्रेस का समर्थन प्राप्त करने मे सरलता होगी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि कृपालानी की स्थिति वैसी ही है जैसी मुस्लिम लीग के सभापति व नेता जिन्ना की। माउन्टबेटन ने यह लिखने और कहने का निश्चय किया था कि यद्यपि वह कृपालानी के महत्त्व को स्वीकार करते है तथापि वह उन्हे बैठक मे आमत्रित करना स्वीकार नही कर सकते। हा, उनसे बैठक मे तुरन्त पहले या बाद मे अवश्य मिल सकते है। यह समस्या बडी पेचीदा थी। पहले देखने मे तो यह बडी मामूली जान पडती थी किन्तु जल्दी ही सगीन स्थिति भी पैदा हो सकती थी। यदि कृपालानी को नही बुलाया जाता तो काग्रेस को यह शिकायत

रहेगी कि जिन्ना के सामने उसे एक बार और दबना पडा। यदि उन्हे बुलाया जाता है तो जिन्ना को बुरा लगता था।

वी पी मेनन ने उन विषयो की एक बडी प्रामाणिक सूची तैयार की थी जिन पर सबकी सहमति थी। इनकी सख्या कुल आठ थी। नेता लोग अप्रिय निर्णय लेने से कतराते थे। इस बहाने की आड मे छिपने का प्रयास करते है कि अपनी पार्टी की तरफ से वे हामी कैसे भरे। इस कठिनाई से पार उतरने का यह साहसिक प्रयास था। इस विषयसूची मे इस माग का उल्लेख था कि अन्तर्कालीन व्यवस्था के रूप मे भारत सरकार के १९३५ के विधान के सशोधित-आधार पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने की शीघ्रता की जाय। सर्वसत्ता-सम्पन्न एक अथवा दो राष्ट्रो का निर्माण हो। यदि एक ही राष्ट्र की स्थापना हो तो सत्ता वर्तमान केन्द्रीय सरकार को सौप दी जाय। छठे सूत्र मे कहा गया था कि दोनो राष्ट्रो का एक ही गर्वनर-जनरल हो। अत मे सेना के विभाजन के हल का उल्लेख था। इसमे कहा गया था कि टुकडियो का बटवारा भर्ती के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रदेश से भर्ती करके जो टुकडी बनाई गई हो उसे उसी प्रदेश की सरकार को सौप दिया जाय। मिली-जुली टुकडियो के लिए विशेष व्यवस्था का निर्देश था।

उक्त प्रस्ताव पर माउन्टबेटन जिन्ना और लियाकत अली की स्वीकृति पाने मे असफल रहे। प्रस्ताव के आम सिद्धातो से वे सहमत थे, लेकिन अपनी सम्मति लिखित रूप मे देने को तैयार नही थे। वी पी मेनन के अनुसार पटेल और नेहरू यह चाहते थे कि जिन्ना उक्त योजना को ऐसे ढग से स्वीकार कर ले कि यह निश्चित हो जाय कि यह उनकी आखिरी प्रादेशिक माग थी। यदि वह ऐसी घोषणा कर दे तो काग्रेस को सतोष हो जायगा।

माउन्टबेटन ने कहा कि समझौते के अभाव मे अन्तरिम सरकार को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के बारे मे जिन्ना की प्रतिक्रिया उन्होने परखी थी। जिन्ना ने शान्ति से कहा कि ऐसी स्थिति को वह किसी भी हालत मे नही रोक सकते। कुछ दृष्टियो से माउन्टबेटन और जिन्ना के बीच यह कूटनीति का सबसे सूक्ष्म दौर था। माउन्टबेटन के अनुसार जिन्ना की प्रतिक्रिया असाधारण ओर अशान्तिकारक थी।

नई दिल्ली, रविवार, १८ मई, १९४७

माउन्टबेटन सबेरे ८॥ बजे पालम मे लन्दन को रवाना हो गए। उनके स्थान पर कालविल स्थानापन्न वाइसराय बनेगे। माउन्टबेटन अपने साथ वी पी मेनन को भी ले गये थे। इन दिनो मेनन का सितारा चमक रहा था और वह माउन्टबेटन के पूर्ण विश्वासभाजन थे। शासनिक-योग्यता और मसविदा बनाने की निपुणता उनमे ऊचे दर्जे की है। समझौता-चर्चा मे भी उनका योग सराहनीय रहा था। इससे पता

चलता था कि माउन्टबेटन उपयुक्त व्यक्तियो का चुनाव करने मे कितने पटु थे।

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, २२ मई, १९४७

जिन्ना ने ऐन समय पर एक चौकाने वाली माग की थी। वह पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को जोडने के लिए ८०० मील लम्बा गलियारा माग रहे थे। अपनी माग प्रकाशित करने मे उन्होने स्टालिन का अनुकरण किया था। यह माग उन्होने रायटर के सवाददाता डून कैम्पबैल के प्रश्नो का उत्तर देते हुए व्यक्त की थी। अर्सकिन क्रम को मैंने जो लन्दन तार दिया, उसमे लिखा था, "जिन्ना ने उत्तर मौखिक रूप से नही, बल्कि लिखित रूप मे दिये।" ज्यो ही रायटर ने उक्त माग प्रकाशित की, त्यो ही जिन्ना के सेक्रेटरी ने फोन करके विदेशी पत्रकारो का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। सवाददाता ने मुझे यह बताया कि जिन्ना स्वय पत्रकारो से मिलने को तैयार थे। पत्रकारो का खयाल था कि जिन्ना अपना वक्तव्य देने को यो भी तैयार थे, रायटर के सवाददाता की प्रार्थना तो एक बहाना मात्र थी। रायटर का उपयोग जिन्ना ने अपना दबाव लन्दन पर डालने और ब्रिटिश समाचार-पत्रो मे पूरा प्रचार पाने मे किया।

माउन्टबेटन की समझौता-चर्चाए सरलतापूर्वक चल रही थी यद्यपि अटकल-बाजिया इसके विपरीत थी। लन्दन मे उनकी उपस्थिति से ब्रिटिश अधिकारियो को ढाढस मिला। विरोधी दल के नेताओ से भी उन्होने भेट की, क्योकि उनके सहयोग बिना पार्लमेंट मे 'भारतीय स्वतत्रता बिल' शीघ्रता से पास होना सभव नही था। श्री एटली ने भारत सरकार की नीति और उसके परिणामो की जिम्मेदारी स्वय अपने ऊपर ले ली थी। हा, विभाजन के सेना-सम्बन्धी प्रश्न पर अवश्य काफी चिन्ता प्रकट की जा रही थी। माउन्टबेटन ओर वी पी मेनन द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का जोरो से स्वागत किया गया।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २३ मई, १९४७

मैंने वरनोन को लन्दन मे निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी है :

"जिन्ना की रायटर सवाददाता से मुलाकात के बारे मे केवल 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने सम्पादकीय टिप्पणी की है। उसने दृढ रुख ग्रहण किया है। पर वह उत्तेजना फैलाने वाला नही है। गलियारे के बारे मे वह साफ लिखता है कि यदि पाकिस्तान का अस्तित्व गलियारे पर ही निर्भर करता है तो पाकिस्तान कभी नहीं बन सकेगा। मेरा खयाल है कि यहा राजनैतिक क्षेत्रो तथा समाचार-पत्रो की प्रतिक्रिया की जितनी आशा थी, उससे कही मद हुई है। जिन्ना की माग का उद्देश्य मुख्य रूप से लन्दन को प्रभावित करना था।"

नई दिल्ली, सोमवार, २६ मई, १९४७

जिन्ना की गलियारे की माग की देर से ही सही, किन्तु जोरदार प्रतिक्रिया हुई। विवाद की ज्वालाए भभक रही थी और किसी तात्कालिक राजनैतिक निर्णय से ही शान्त हो सकती थी। माउन्टबेटन द्वारा निर्माण की गई सद्भावना का स्रोत उनकी अनुपस्थिति मे सूख रहा था। राजेन्द्रप्रसाद और शकरराव देव (काग्रेस-मत्री) ने जोरदार वक्तव्य निकाले थे। राजेन्द्रप्रसाद कहते थे, "जिन्ना की माग जरा भी ध्यान देने योग्य नही है।" देव का कहना था, "जिन्ना की माग इस भ्राति के कारण बढ रही है कि अग्रेज अब भी उनकी मदद कर सकते है। देश पर इन धमकियो का कोई असर नही पडेगा तथा गलियारे की माग पूरी नही की जा सकेगी।"

'डान' ने देव और राजेन्द्रप्रसाद को उत्तेजनात्मक जवाब दिया था। 'सारे जड-मूर्ख है' शीर्षक से उसने लिखा, "गलियारे की माग कोई नई नही है। कायदे-आजम जिन्ना इस माग को कई बार दोहरा चुके है जो पाकिस्तान के लिए अनिवार्य है। पाकिस्तान को यदि वास्तविक रूप देना है तो उसके पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशो को जोडनेवाला गलियारा अत्यन्त आवश्यक है। हमे कोई सदेह नही है कि यदि मुसलमान पाकिस्तान ले सकते है तो कही-न-कही गलियारा भी बना सकते है। देव यह भली भाति जानते है।"

शनिवार को नेहरू ने 'युनाइटेड प्रेस आव अमरीका' को जो मुलाकात दी थी उसमे उन्होने पहली बार सार्वजनिक रूप से गलियारे की माग का उल्लेख किया। उन्होने कहा, "जिन्ना का हाल का वक्तव्य सर्वथा अवास्तविक है और यह बतलाता है कि वह किसी प्रकार का समझौता नही चाहते। गलियारे की माग विचित्र और निस्सार है। हम तो एक सयुक्त भारत के पक्ष मे है, जिसमे विशिष्ट प्रदेशो को अलग होने का अधिकार प्राप्त रहेगा। हम दबाव नही डालना चाहते। यदि और प्रादेशिक मागे किये बिना समझौता नही किया जाता तो हम सयुक्त भारत का विधान बनाने और उसे कार्यान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर देगे।"

नेहरू का कहना था कि चूकि जिन्ना ने प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर दिया है, अतएव अन्तरिम सरकार को ही ओपनिवेशिक सरकार बना दिया जाय। उनकी शिकायत थी कि जिन्ना को जो मिलता है, उसे तो वे स्वीकार कर ही लेते है और फिर अधिकाधिक मागते जाते है। इस प्रकार एकतरफा वादे कैसे किये जा सकते है?

नई दिल्ली, मंगलवार, २७ मई, १९४७

बरोज द्वारा भेजी गई रिपोर्टो से पता चलता था कि वह कलकत्ता की अशात स्थिति से बहुत चिंतित है। पिछले एक-दो दिनो मे उन्होने महसूस किया कि तनाव उनके अनुमान से कही अधिक गभीर था। इसलिए चाहते थे कि सबको शांत करने

के लिए रेडियो पर भाषण दे, जिसके लिए वह माउन्टबेटन की अनुमति चाहते थे। उन्होने 'अमृत बाजार पत्रिका' मे छपी एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमे नेहरू के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि सघर्ष का नया दौर २ जून से शुरू हो रहा है, और शाति-पूर्ण समझौते की उन्हे कोई आशा नही।

इस कथित वक्तव्य के विषय मे जाच करने पर मुझे मालूम हुआ कि यह निराधार था। यह घटना भी मौजूदा घबराहट और अनिश्चितता का उदाहरण थी।

मुझे मालूम हुआ कि कलकत्ता मे हिन्दू और मुसलमान मोर्चे बनाकर उन पर आ डटे है। मकानो और पूरी-की-पूरी सडको को लडाई की चौकियो का रूप दे दिया गया था।

नई दिल्ली, शनिवार, ३१ मई, १९४७

माउन्टबेटन दिल्ली लौट आये है। अपने कर्मचारियो को उन्होने तुरन्त विचार-विनिमय के लिए बुलाया। नेताओ की बैठक होने मे अब एक ही सप्ताह शेष था जिसमे भारत के भविष्य का निर्णय किया जायगा।

माउन्टबेटन की शारीरिक और मानसिक शक्ति आश्चर्यजनक थी। अपनी लम्बी यात्रा से अथवा लदन की चर्चाओ से वह बिलकुल भी थके हुए नही मालूम देते। इसके विपरीत वह पहले से कही अधिक तेजस्वी और उत्साही जान पडते थे और कर्मचारियो को आदेश-पर-आदेश देते जाते थे।

माउन्टबेटन गाधीजी के हाल के प्रार्थना-प्रवचनो पर विस्तार से विचार करने को व्यग्र थे। इन प्रवचनो मे गाधीजी ने सयुक्त भारत का पक्ष लिया था और उनके भाषणो से ऐसा लगता था मानो वह मत्रिमडलीय-योजना के जबरन लादे जाने के पक्ष मे हो। कालविल और वी० पी० मेनन, दोनो ने यह मत व्यक्त किया कि विभाजन के प्रति गाधीजी का विरोध योजना को तोडने की सीमा तक नही पहुँचेगा।

माउन्टबेटन का स्पष्ट मत था कि वह जिन्ना पर नाराजी के बजाय दुख ही प्रकट करेगे। जिन्ना को बतलाएगे कि उनकी गलियारे की माग से उन्हे कितनी परेशानी हुई। जिन्ना के नाम चर्चिल का एक सदेशा भी वह साथ लाये थे जिसे वह जरूरत पडने पर प्रयोग मे ला सकते थे। चर्चिल ने अपने सदेश मे कहा था कि योजना को स्वीकार करना जिन्ना के लिए जीवन-मरण के प्रश्न से कम नही है।

नई दिल्ली, रविवार, १ जून, १९४७

मैंने अपनी मा को लिखा

"यहा हम महत्त्वपूर्ण घटनाओ के द्वार पर खडे है और मैं सत्ता-हस्तातरण के बारे मे माउन्टबेटन की ऐतिहासिक घोषणा की प्रचार-व्यवस्था को अतिम रूप देने के काम मे आकठ डूबा हुआ हू। वातावरण बहुत ही क्षुब्ध है और अगर फैसला

विभाजन के पक्ष मे हुआ—जैसा कि निश्चय-सा है—तो काफी साम्प्रदायिक दगे हो सकते है। लेकिन आज की अनिश्चितता से तो कोई भी फैसला बेहतर ही होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह गुस्सा अन्तरिम और आपसी है। अग्रेज हिन्दू और मुसलमानो दोनो मे जितने लोकप्रिय आज है, उतने पहले कभी नही थे।

"सरकार की २० फरवरी वाली घोषणा का खास असर यह हुआ कि काग्रेस हाई कमान को यह मान लेना पडा था कि विभाजन अवश्यम्भावी है। गाधीजी इस विचार-धारा से सहमत नही हो रहे थे और इसके खिलाफ कडा सघर्ष कर रहे थे। उनके इस विरोध की सीमा क्या होगी, यह कहना मुश्किल था।

"अन्तरिम सरकार के दोनो प्रमुख काग्रेसी नेताओ नेहरू और पटेल ने इस धारणा पर विभाजन को स्वीकार किया था कि जिन्ना को पाकिस्तान देकर वे उनसे मुक्ति पा जायगे या जैसा कि नेहरू खानगी तौर से कहते थे, 'सिर कटाकर हम सिरदर्द से छुट्टी पा लेगे।' उनका यह रुख दूरदर्शितापूर्ण लगता था क्योकि अधिकाधिक खिलाने के साथ-साथ जिन्ना की भूख बढती ही जाती थी और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को जोडने के लिए ८०० मील लम्बे गलियारे की माग उनकी सर्वग्राही नीति का सुन्दर उदाहरण था। इसलिए दोनो पक्ष समझौते पर बहुत ही अशोभनीय ढग से विचार कर रहे थे। विभाजन निश्चय ही एक दुखात घटना थी, लेकिन इससे भी दुखात घटना होगी एक ऐसी एकता थोपने का प्रयास करना, जो १० करोड मुसलमानो के अधिकाश भाग को स्वीकार नही थी।"

: ९ :

ऐतिहासिक समझौता

नई दिल्ली, सोमवार, २ जून, १९४७

ऐतिहासिक घडी आ पहुची। अपनी बडी अमरीकी-कारो मे सवार नेता लोग उत्तरी आगन मे आने लगे हैं। जिन्ना सबसे बाद मे आये, कुछ मिनट देर से। माउन्टबेटन ने इधर-उधर की बाते करने की पूरी कोशिश की, किन्तु साफ जाहिर है कि वातावरण काफी आवेशपूर्ण है। कृपालानी को शामिल करने की समस्या जिन्ना को अपने साथ रबनिश्तर को लाने की अनुमति देकर हल कर ली गई थी। इस प्रकार 'पाच बडे' अब 'सात बडे' हो गए है।

माउन्टबेटन इस बात के लिए उत्सुक थे कि इस प्रारम्भिक बैठक की कार्यवाही

मे किसी प्रकार की रुकावट न आवे। इसलिए फोटो लेने का काम भारत सरकार के फोटोग्राफर तक ही सीमित रखा गया। इससे तत्काल भारतीय और विदेशी फोटोग्राफरो मे बहुत नाराजी फैल गई और उन्होने मेक्स डेस्फार के नेतृत्व मे 'वाक् आउट' कर दिया और मुझे एक विरोध-पत्र भेजा। मै उनकी शिकायत को पूरी तरह समझता था और आशा करता था कि कल इसका कोई इलाज कर सकूगा। लेकिन आज तो महत्त्व की बात यह थी कि बिना किसी मानसिक खिचाव या विघ्न के माउन्टबेटन कार्यवाही का शुभ श्रीगणेश कर सके।

बैठक ठीक दो घटे चली। वरनोन ने बतलाया कि अधिकाश बोलने का काम माउन्टबेटन ने ही किया और घटनाओ के विकास का तर्कपूर्ण विश्लेषण करने मे वडी कुशलता दिखाई। उनके शुरू के शब्दो मे नेताओ को उन परिस्थितियो के स्तर तक उठने की चुनौती थी, जिनका निर्माण उनके हाथो हो रहा था। उन्होने कहा कि गत पाच वर्षो मे उन्होने युद्ध के भाग्य का निर्णाय करने वाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बैठको मे भाग लिया। लेकिन शायद ही किसी बैठक मे किये गए निर्णयो का विश्व के इतिहास पर इतना गहरा असर हुआ हो जितना आज की बैठक के निर्णयो का होगा। माउन्टबेटन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नेताओ की इच्छाओ के खिलाफ रफ्तार बढाने की कोशिश नही कर रहे। जिन लोगो से उनकी बाते हुई, उन सबने ही स्थिति की विशद गभीरता पर जोर दिया था। उन सबने मौजूदा अनिश्चितता का अन्त करने की इच्छा जाहिर की। इसलिए जितनी जल्दी सत्ता-हस्तातरण हो, उतना अच्छा।

इसके बाद माउन्टबेटन ने मत्रिमडलीय-योजना को पुनरुज्जीवित करने का आखिरी औपचारिक प्रयास किया और जिन्ना ने अखिरी बार औपचारिक रूप से उसे ठुकरा दिया। अब माउन्टबेटन ने विभाजन द्वारा उत्पन्न दुविधा का जिक्र किया। उन्होने कहा कि काग्रेस भारत के विभाजन के सिद्धात से सहमत नही है। लेकिन अगर विभाजन टाला न जा सके तो वह प्रान्तो के विभाजन का आग्रह करेगी, जिसमे मुसलमान या हिन्दू बहुमतवाले इलाको पर कोई जोर-जबरदस्ती न हो। उधर जिन्ना प्रान्तो के विभाजन के विरोधी थे, लेकिन भारत के विभाजन की माग करते थे।

माउन्टबेटन ने यह बतलाने की कोशिश की कि उनकी योजना को ब्रिटिश विरोधी दल का समर्थन प्राप्त है। उन्होने कहा कि इस योजना को लन्दन मे पार्टीबन्दी की दृष्टि से नही देखा जा रहा। उन्होने सिखो की स्थिति के बारे मे अपनी व्यथा की चर्चा की और कलकत्ता को स्वतत्र बन्दरगाह बनाने या न बनाने के प्रश्न पर मत-सग्रह किये जाने के सुझाव को दृढता के साथ अन्तिम रूप मे रद्द कर दिया।

फिर वडी चतुराई के साथ उन्होने योजना की नई धारा २० को 'तुरन्त सत्ता-हस्तातरण' शीर्षक के अन्तर्गत पेश किया। उन्होने इसके फलस्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक स्वराज्य का पक्ष समर्थन किया, इसलिए नही कि समय की मर्यादा

बीत जाने पर भी ब्रिटेन यहा जमा रहना चाहता है, बल्कि यह आक्षेप किये जाने के भय से कि वह अपने दायित्व से भाग खडा हुआ। उन्होने कहा कि इसलिए आवश्यकता होने पर ब्रिटेन को सहयोग से असमय हाथ नही खीचना चाहिए।

जिन्ना ने अपनी एक पिछली मुलाकात मे एक प्रस्ताव पर 'सहमति' और 'स्वीकृति' मे भेद बताकर माउन्टबेटन को चौका दिया था। इस 'पाडित्य' का उपयोग आज माउन्टबेटन ने अपने सुभीते के लिए किया।

योजना की प्रतिया सबको बाट देने के बाद उन्होने कहा कि वह महसूस करते है कि नेताओ से योजना के प्रति पूरी सहमति की माग करना नेताओ को अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करने पर मजबूर करना होगा। इसलिए वह उनसे केवल यही अनुरोध करना चाहेगे कि वे योजना को शातिपूर्ण भावना से अपनी स्वीकृति दे दे। जब नेहरू ने 'स्वीकृति' और 'सहमति' के भेद और उसकी परिभाषा करने को कहा तो माउन्टबेटन ने तुरन्त उत्तर दिया कि सहमति मे यह विश्वास निहित है कि वह सही सिद्धातो पर आधारित है। लेकिन चूँकि उन्हे दोनो पक्षो के सिद्धातो की अवहेलना करनी पडी थी, इसलिए वह पूरी सहमति की माग नही कर सकते। वह केवल यह चाहते है कि योजना पर यह विश्वास प्रकट करते हुए स्वीकृति दे दी जाय कि देश की भलाई के लिए वह एक न्यायपूर्ण और ईमानदारी का हल है।

इस पर नेहरू ने कहा कि यद्यपि काग्रेस इस योजना से पूरी तौर से सहमत तो कभी नही हो सकती, लेकिन हा, उसे वह स्वीकार करने को तैयार है। निश्तर ने कहा कि योजना की स्वीकृति मे वस्तुत उसे कार्यान्वित करने की सहमति निहित है। माउन्टबेटन ने इस पर अपनी हार्दिक स्वीकृति प्रकट की, और उस क्षण से जान लिया कि असली लडाई जीती जा चुकी है।

तब जिन्ना ने इस बात की लम्बी-चौडी सफाई दी कि सर्वशक्तिमान कायदे-आजम होते हुए भी वह क्यो स्वय कोई निर्णय नही ले सकते। उन्होने कहा कि प्रस्तावो को उन्होने आतमसात् कर लिया है, किन्तु अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन्हे और उनकी कार्यसमिति दोनो को, अपने मालिको, आम जनता, के सामने जाना पडेगा। माउन्टबेटन ने कहा कि ऐसे मौके भी आते है जब नेताओ को बिना अपने अनुयायियो से सलाह किये महत्त्वपूर्ण निश्चय करने पडते है—इस विश्वास के साथ कि बाद मे वे उनका समर्थन प्राप्त कर सकेगे। ऊपर से एक निश्चय कर लिया जाय और बाद मे जनता द्वारा उसकी पुष्टि हो जाय तो यह जनतत्री कार्यविधि के अनुकूल होगा। फिर, जिन्ना स्वीकृतिसूचक निर्णय के इतने नजदीक पहुच गए जितनी एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती थी जो बार-बार 'नही' कहकर ही इतनी सफलता पा सका हो। उन्होने जोर देकर कहा कि वह अपने मालिको, आम जनता, के सामने इस योजना को तोडने नही, बल्कि उन्हे इसे स्वीकृति देने के लिए राजी करने के ईमानदारीपूर्ण इरादे से जायगे। अभी वह अपना व्यक्तिगत आश्वासन मात्र दे

सकते है कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगे ।

माउन्टबेटन काग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यसमितियो तथा सिखो की प्रतिक्रिया आधी रात तक जानना चाहते थे। कृपालानी और बलदेवसिह ने उसी शाम पत्र भेजना मजूर कर लिया। जिन्ना ने अपनी कार्यसमिति की राय को लिखित रूप से भेजने मे असमर्थता प्रकट की किन्तु वह इस बात पर राजी हो गए कि वाइसराय से मिलकर वह उन्हे मौखिक रिपोर्ट दे देगे। माउन्टबेटन इससे सतुष्ट हो गए।

नेहरू, जिन्ना और बलदेवसिह की इस बात के लिए स्वीकृति भी माउन्टबेटन ने प्राप्त कर ली कि अगले दिन शाम को वे उनके बाद आल इडिया रेडियो से जनता के नाम सदेश प्रसारित करे। माउन्टबेटन ने कहा कि वह उन्हे अपने भाषण का मसविदा सुबह दिखा देगे। पटेल ने, जो बहुत कम बोले थे, कुटिल मुसकान से कहा कि आम कायदा तो यह है कि रेडियो-भाषण की पाडुलिपिया प्रसारित होने से पहले सूचना-मत्री को (अर्थात् स्वय उन्हे) भेजी जानी चाहिए। जिन्ना ने बिना मुसकराए उत्तर दिया कि वह अपने भाषण मे वही कहेगे जो उस समय उनके दिल मे आयेगा।

जैसा कि पहले ही तय था, बैठक के बाद माउन्टबेटन ने जिन्ना से रुकने को कहा। इसके दो उद्देश्य थे। वह गाधीजी को, जो कभी काग्रेसी नेताओ के साथ नही आते थे, अलग मुलाकात देनेवाले थे और इस विषय मे मुस्लिम लीग की आलोचना को निस्सार कर देना चाहते थे। दूसरा कारण यह कि वह जिन्ना पर व्यक्तिगत दबाव डालना चाहते थे और जरा ज्यादा स्पष्टतया जानना चाहते थे कि अन्त मे जिन्ना क्या रुख अपनायगे। लेकिन जिन्ना ने योजना पर कुछ नही कहा। अब सारा दारोमदार उनकी रात की भेट पर निर्भर करता था।

फिर साढे बारह बजे महात्माजी आये। एक तरह से वह सारी कार्यवाही मे उपस्थित रहे थे। विभाजन-योजना के औपचारिक रूप से पेश किये जाने पर उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया के बारे मे अनिश्चितता ने सवेरे की बैठक मे काग्रेसी-नेताओ के हाथ-पैर बाधने का काम किया था। अपनी अन्तरात्मा के आदेशो पर गाधीजी किसी चीज के बारे मे क्या रुख अपनाते है, इस विषय मे अनिश्चितता से काग्रेसी नेता खूब परिचित थे। काफी लोगो को तो आशका थी कि अपनी अन्तरात्मा के आदेश पर वह योजना को तोडने का भरपूर प्रयास करेगे जिससे, भारत के विभाजन को रोक सके। माउन्टबेटन इस मुलाकात से काफी डर रहे थे। उनके आश्चर्य और राहत की सीमा न रही जब गाधीजी ने इस्तेमाल किये लिफाफो तथा रद्दी कागजो की पीठ पर लिखकर सूचित किया कि आज उनका मौन दिवस है।

भेट खत्म हो जाने के बाद माउन्टबेटन ने कागज के इन टुकडो को उठा लिया। इन्हे वह ऐतिहासिक स्मृति-चिह्न समझते थे। उनपर महात्माजी ने लिखा था, "खेद है कि मै बोल नही सकता। सोमवार के मौन का निर्णय लेते समय मैने केवल दो अपवाद रखे थे। जरूरी मामलो पर उच्च-अधिकारियो से बात करना और

बीमारो की परिचर्या। लेकिन मै जानता हू कि आप नही चाहते कि मै अपना मौन तोड़ू। क्या मैने अपने भाषणो मे एक भी शब्द आपके विरुद्ध कहा है? यदि आप स्वीकार करे कि मैने नही कहा तो आपकी चेतावनी अनावश्यक है। दो-एक चीजों पर मै आपसे कुछ कहना चाहता हू, लेकिन आज नही। अगर हम फिर मिले तो कहूगा।"

इस विचित्र कार्यविधि मे राजनैतिक त्याग, निस्पृहता और आत्मसयम का महान् कार्य छिपा हुआ था। जब इस ऐतिहासिक बैठक के बाद मै प्रेस-विज्ञप्ति के बारे मे माउन्टबेटन से दो शब्द कहने अन्दर गया तो मैने भी छोटी गोलमेज से एक तोफा खोज निकाला। यह था जिन्ना द्वारा अपनी महानतम राजनैतिक विजय के क्षण मे अनजाने एक सफेद कागज पर खीची लकीरो का गोरख-धधा। मै कोई मनोवैज्ञानिक नही, लेकिन मेरा खयाल है कि इस गोरख-धधे मे शक्ति और गौरव के चिह्न सहज ही देखे जा सकते थे।

नई दिल्ली, मंगलवार, ३ जून, १९४७

माउन्टबेटन ने आजका काम सुबह ही कर्मचारी-मडल की बैठक से शुरु किया, जिसमे उन्होने कल आधी रात के समय जिन्ना के साथ हुई नाटकीय झडप का हाल बताया। चूँकि जिन्नाने योजना पर अपना उत्तर लिखित रूप मे दे देने से साफ इन्कार कर दिया था इसलिए उनकी जबानी बात के गवाह के रूप मे इस्मे भी माउन्टबेटन के साथ शामिल हो गए। जिन्ना ने उन्ही बातो को विस्तार से दोहराना शुरू किया जो उन्होने सुबह नेताओ की बैठक मे कही थी, और माउन्टबेटन के कितना ही दबाव डालने पर भी वह स्वीकृति देने पर राजी नही हुए कि मुस्लिम लीग कौसिल की बैठक योजना पर दृढतापूर्वक अपनी सहमति प्रकट कर देगी। वह केवल इतना जिम्मा लेने को तैयार थे कि कौसिल से योजना मनवाने का वह वैधानिक तरीके से भरसक प्रयत्न करेगे और इस कार्य मे उनकी कार्यसमिति उनका समर्थन करेगी।

माउन्टबेटन ने तब जिन्ना को याद दिलाई कि काग्रेस को उनकी इस तरह की पैतरेबाजी पर भयकर सदेह है, जिसे वह हमेशा इस्तेमाल करते है। वह यह कि जब तक किसी योजना के बारे मे काग्रेस कोई पक्का निश्चय नही कर लेती तब तक तो वह इतजार करते रहते है और उसके कई दिन बाद मुस्लिम लीग के मन-माफिक फैसले की घोषणा करने की छूट रखते है। माउन्टबेटन ने चेतावनी दी कि नेहरू, कृपालानी और पटेल ने यह शर्त रखी थी कि यदि मुस्लिम लीग ने भी उनके साथ ही योजना को स्वीकार नही किया तो वे योजना को ठुकरा देगे। उन्होने यह भी शर्त रखी थी कि मुस्लिम लीग इसे एक अन्तिम समझौते के रूप मे स्वीकार करे।

माउन्टबेटन के लाख कहने पर भी जिन्ना टस-से-मस न हुए। जिन्ना ने फिर एक बार यह बहाना किया कि मुस्लिम लीग कौसिल की सलाह के बिना उन्हे निर्णय

करने का कोई वैधानिक अधिकार नही और कहा कि कौसिल की बैठक तो वह अभी कई दिनो तक नही बुला सकेगे।' माउन्टबेटन ने कहा, "अगर यही आपका रुख है तो काग्रेसी और सिख नेता भी कल सुबह की बैठक मे योजना को नामजूर कर देगे, फिर अराजकता फैल जायगी और आप अपना पाकिस्तान भी खो बैठेगे शायद हमेशा के लिए।" जिन्ना ने कधे हिलाते हुए केवल इतना कहा "जो होना होगा हो जायगा।"

इस पर माउन्टबेटन ने कहा, "मि जिन्ना, इस समझौते को तैयार करने मे जो मेहनत लगी थी, उसे मै आपको इस तरह बेकार नही करने दूगा। चूकि आप मुस्लिम लीग की ओर से स्वीकृति देने को तैयार नही इसलिए मै उसकी ओर से बोलूगा। मै यह कहने का खतरा उठाऊगा कि जो आश्वासन आपने मुझे दिये थे उनसे मै सतुष्ट हू। यदि आपकी कौसिल समझौते की पुष्टि नही करे तो आप मुझे दोष दे सकते है। लेकिन मेरी एक शर्त है। जब सुबह की बैठक मे मै यह कहू कि मि जिन्ना ने मुझे कुछ आश्वासन दिये है, जिन्हे मैने स्वीकार कर लिया है और मै उनसे सतुष्ट हू तो आप किसी भी हालत मे उसका खडन नही करेगे। और जब मै आपकी ओर देखू तो आपको सहमति स्वरूप अपना सिर हिलाना होगा।"

इस प्रस्ताव के उत्तर मे भी जिन्ना ने कोई मौखिक स्वीकृति न देकर केवल सिर हिला दिया। माउन्टबेटन का अन्तिम प्रश्न यह था, "क्या मेरा एटली को यह सलाह भेजना ठीक होगा कि वह योजना की घोषणा कल कर दे?" इसके उत्तर मे जिन्ना ने कहा, "हा!" इस अन्तिम आश्वासन से माउन्टबेटन और इस्मे ने यह समझ लिया कि मुस्लिम लीग कौसिल की बैठक होने से पहले, जो एक सप्ताह के अन्दर होगी, जिन्ना से जिस हद तक 'हा' कराना सभव था, वह करा ली गई।

जिन्ना के जाने के थोडी देर बाद ही कृपालानी का पत्र आया। इसमे कुछ छोटी बातो पर स्वीकृति न देने के अलावा वैसे आम तौर से पूरी योजना पर काग्रेस कार्य-समिति की दृढ स्वीकृति प्रकट की गई थी।

नेताओ के साथ दूसरी बैठक का प्रारम्भ माउन्टबेटन ने कल रात जिन्ना के साथ हुई मुलाकात की रिपोर्ट देकर किया। उन्होने बताया कि जिन्ना के आश्वासन उन्होने स्वीकार कर लिये है। जिन्ना ने इसकी पुष्टि चुपचाप सिर हिलाकर की। फिर उन्होने उन गभीर आपत्तियो का जिक्र किया जो विभिन्न दलो ने योजना के अलग-अलग मुद्दो पर उठाई थी। इनके उठाए जाने पर उन्होने कृतज्ञता प्रकट की। लेकिन उन्होने कहा कि चूकि वह अच्छी तरह जानते है कि किसी दल का कोई सुझाव किसी दूसरे दल को स्वीकार नही होगा, इसलिए वह उन्हे इस बैठक मे छेडना ठीक नही समझते। अत उन्होने नेताओ से आग्रह किया कि वे उनकी इस बात को स्वीकार करे। नेताओ ने बात मान ली। इस प्रकार अपने-आप, और शायद अनजाने ही, विवाद के सब प्रश्न ठिकाने लग गये।

माउन्टबेटन के यह घोषणा करते ही कि शतप्रतिशत सहमति के जितने नजदीक पहुचना सभव था, यह योजना, उतने नजदीक पहुच गई है। जिन्ना, कृपालानी और बलदेवसिह ने कहा कि वाइसराय ने उनके विचारो का ठीक अर्थ समझा है। माउन्टबेटन ने कहा कि अब योजना की सरकारी रूप से घोषणा की जायगी। इस पर किसी नेता ने कोई आपत्ति नही की।

इसलिए ऐसा लगने लगा कि आगे का रास्ता अब साफ है। लेकिन माउन्टबेटन के यह अपील करने पर कि छोटे नेता सयम से काम ले और अतीत को भूल जाय जिससे सुन्दर भविष्य निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त हो सके, लियाकत से यह कहे बिना नही रहा गया कि सयम की ज्यादा जरूरत छोटे नेताओ के बजाय बडे नेताओ को है, जैसे गाधीजी को अपनी प्रार्थना सभाओ के समय। इससे कटुता के पुराने जख्म फिर हरे हो गए।

जिन्ना और लियाकत ने आरोप लगाया कि गाधीजी लोगो को मनमानी करने के लिए उकसा रहे है और इस बैठक मे भाग लेनेवाले नेताओ की बजाय और किसी पर आस लगाने की सलाह दे रहे है। इस पर कृपालानी ने जवाब दिया कि गाधीजी के सारे क्रम अहिसात्मक होते है। पटेल ने मत व्यक्त किया कि गाधीजी किसी भी फैसले का निष्ठा के साथ पालन करेगे। माउन्टबेटन को यह कहकर इस खतरनाक विवाद का अन्त करना पडा कि उनकी राय मे इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है।

फिर माउन्टबेटन ने बडे नाटकीय ढग के साथ विभाजन के प्रशासन-सबधी नतीजो के अभिलेख को सिर तक उठा कर और फिर मेज पर पटकते हुए नेताओ के सामने पेश किया। बडे-बडे अधिकारियो द्वारा लिखा यह दस्तावेज आज ही के दिन के लिए तैयार किया गया था। इसमे फुलस्केप आकार के घने टाइप वाले चौतीस पृष्ठ थे। थोडे मे लिखने की कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण था।

बोलने की जरा-सी भूल को लेकर तिल का ताड बनाये जाने का एक और उदाहरण सामने आया। माउन्टबेटन ने सुझाव दिया कि इस दस्तावेज को 'मत्रिमडल की बैठक' के सामने पेश करने के पहले उसपर प्रारम्भिक चर्चा कर ली जाय। जिन्ना और लियाकत ने खट से लम्बी-चौडी आपत्ति की कि 'ब्रिटिश मत्रि-मडल' इस बारे मे निर्णायक अधिकारी नही। कई मिनट बाद पता चला कि जिन्ना समझे कि माउन्टबेटन का आशय भारतीय मत्रिमडल या अन्तरिम सरकार से नही, बल्कि ब्रिटिश मत्रिमडल से है। इसपर उन्होने शिकायत की कि उन्हे भ्रम मे डाल दिया गया था। उन्होने कहा, "आपका आशय वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौसिल से है तो फिर स्पष्ट बात क्यो नही कहते ?" उन्होने कहा कि उनका दिमाग वैधानिक ढग से काम करता है।

दस्तावेज मे सुझाया गया था कि दोनो दलो की एक मिली-जुली विभाजन-समिति की रचना की जाय। इसके बारे मे लियाकत ने पूछा कि क्या इस समिति मे प्रश्नो का

निवटारा वहुमत के आधार पर किया जायगा ? माउन्टवेटन ने कहा, कि नही, वार्तालाप के आधार पर ही औचित्य का निर्णय किया जायगा। उन्होने कहा कि उन्हे भरोसा है कि चूकि विभाजन का प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो चुका है, इसलिए शेष प्रश्नो पर विचार करने मे एक नई भावना से काम लिया जायगा। लियाकत ने वडी तेजी से उत्तर दिया कि यह नई भावना का प्रश्न नही है। सेनाओ के विभाजन के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर गभीर मतभेद है।

लेकिन जल्दी ही इस विवाद की गर्मी जाती रही। यह तय होते देर नही लगी कि वटवारा नागरिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और नागरिकता का आधार भौगोलिक होना चाहिए। जिन्ना ने वडे जोश के साथ ऐलान किया कि पाकिस्तान मे कोई साम्प्रदायिक भेदभाव नही किया जायगा और वहा रहनेवाले लोगो को उनके धर्म का विचार किये विना पूरा नागरिक माना जायगा।

चार वजे रियासती वार्ता कमेटी के सदस्य कौसिल भवन मे एकत्रित हुए, जिससे आज रात के सरकारी ऐलान और भाषणो के पहले उन्हे माउन्टवेटन और नेताओ के वीच हुए समझौते की पृष्ठभूमि समझाई जा सके।

विशाल अडाकार मेज के इर्द-गिर्द रियासती जगत के श्रेष्ठ सलाहकार वैठे हुए थे। भोपाल, पटियाला, डूगरपुर, नवानगर और विलासपुर के शासक स्वय। हैदरावाद के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, वडोदा के सर वी एल मित्तर, मैसूर के सर रामास्वामी मुदलियार, काश्मीर के काक, ग्वालियर के श्रीनिवासन, त्रावनकोर के सर सी पी रामास्वामी ऐयर, जयपुर के सर वी टी कृष्णमाचारी, वीकानेर के पणिक्कर, सर सुल्तान अहमद और नरेंद्र मडल के प्रतिनिधि डी के सेन।

यह बात मार्के की थी कि ब्रिटिश भारत के वहुत से श्रेष्ठतम वुद्धिमान लोग रियासतो के दीवान है। उनमे से कई तो पहले दर्जे के वकील थे, जिससे उन्हे 'सार्व-भौमता के अन्त' के समान गुत्थीदार समस्याओ से निवटने मे सहायता मिलती है। अपने राजाओ के साथ उनका वही सवध रहता था जो एक वैरिस्टर का अपने मूल्य-वान मवक्किल के साथ होता है।

वे लोग खासतौर से यह जानने को उत्सुक थे कि क्या ब्रिटिश भारत मे सत्ता-हस्तातरण के पहले ब्रिटिश-सत्ता का अन्त करना सभव होगा ? उनकी कल्पना यही थी कि ऐसा होने पर रियासते सत्ता पाने वाली सरकारो से ज्यादा सुभीते के साथ मोल-भाव कर सकेगी।

माउन्टवेटन ने वैठक को वास्तविकता के निकट लाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होने वतलाया कि दो राज्यो के निर्माण का अर्थ होगा दो मजवूत केद्रीय सरकारे, जो अपनी सत्ता का विभाजन सहन नही कर सकेगी। दूसरी ओर ओपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेने से उन राजाओ को, जिन्होने ब्रिटेन के साथ हुई अपनी सधियो और दोस्ती का स्वामिभक्ति के साथ पालन किया था, सुरक्षा और मुआवजा

उनके शुरू के वाक्य मे अधिकारियो की इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि एक गैरसरकारी व्यक्ति के रूप मे आज से पहले उन्हे रेडियो पर भाषण देने की सहूलियत नही दी गई थी।" मै उम्मीद करता हू कि भविष्य मे अपनी राय जाहिर करने की ज्यादा सुविधाए मुझे मिल सकेगी और मेरी आवाज अखबारो के बेजान अक्षरो की बजाय ताजगी और सजीव आपके पास पहुचा करेगी।" लेकिन उन्होने जो कहा उसमे न मुझे ताजगी मिली, न सजीवता। इसका अगर थोडा बहुत आभास मिल ा तो उन शब्दो मे, जो उन्होने माउन्टबेटन को श्रद्धाजलि देते हुए कहे।

बडी चतुराई से उन्होने योजना पर कोई ऐलान भी नही किया और स्वीकृति का आभास भी बनाये रखा। सब मे बडी गुत्थी उनके इन शब्दो मे छिपी हुई थी "हमे यह सोचना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश की गई योजना को हम सहमति समझे या समझौता। इस बारे मे मै पहले से कुछ कहना नही चाहता।" नेहरू के अन्तिम शब्द थे "जय हिन्द।" जिन्ना ने भाषण का अन्त "पाकिस्तान जिन्दाबाद" कहकर किया। लेकिन यह उन्होने ऐसे जोर से कहा कि कुछ सुननेवालो को ऐसा लगा मानो कायदे-आजम ने सारी सज्जनता को तिलाजलि देकर कहा हो, "पाकिस्तान हमारी मुट्ठी मे है।"

बलदेवसिह सबसे बाद मे बोले। और यह देखते हुए कि विभाजन से सिखो को कितनी भारी हानि उठानी पडेगी और इससे उनके सहधर्मियो मे कितनी गहरी कटुता फैलेगी, उनके शब्द काफी जानदार और साहसपूर्ण थे। उन्होने भारत की सेनाओ को आह्वान किया कि वे अनुशासन के ऊचे आदर्शो पर कायम रहे, खासकर आतरिक सुरक्षा के अप्रिय काम को अन्जाम देने मे। जिन्ना के विपरीत उन्होने योजना को समझौता नही माना। उन्होने कहा, "मै इसे सहमति कहना पसन्द करूगा।"

नई दिल्ली, बुधवार, ४ जून, १९४७

आज सवेरे लगभग तीन सौ भारतीय और विदेशी पत्रकारो के सामने लेजिस्लेटिव असेम्बली-भवन मे माउन्टबेटन ने जिस कुशाग्रता का परिचय दिया, वह मेरे लिए अभूतपूर्व था। बिना किसी कागज की सहायता लिये, और बिना भूले-भटके उन्होने पौन घटे तक योजना के बारे मे विभिन्न गुत्थियो की सुन्दर व्याख्या की।

इसके बाद उनसे करीब सौ सवाल पूछे गए। सवाल पूछनेवाले मुख्यत भारतीय पत्रकार थे, जिनके प्रश्नो का उद्देश्य उतना जानकारी हासिल करना नही था जितना राजनैतिक प्रचार करना। माउन्टबेटन के ठीक नीचे इस्मे, मिएविल, जार्ज एबेल, आएन स्काट, वी पी मेनन, बरनोन और मै बैठे थे। लेकिन केवल दो बार ही उन्हे अपने कर्मचारियो की सहायता की आवश्यकता पडी।

काफी प्रश्न केवल कल्पना पर आधारित थे, जिनके उत्तर भी उसी ढग से दिये गए। जैसे, बिलकुल प्रारम्भ मे उनसे पूछा गया, "अपने पिछले अनुभवो के आधार पर हम यह पूछना चाहेगे कि यदि मुस्लिम लीग कौसिल ने योजना को ठुकरा दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा ?"

माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, "यह तो एक कल्पित प्रश्न है। अगर यह सवाल कभी उठे तो मेरे पास आइएगा। मै बतला दूँगा कि मै क्या करना चाहता हू।"

प्रश्नकर्त्ता ने फिर पूछा, "लेकिन ऐसे अनुभव हमे पहले हो चुके है।" माउन्टबेटन बोले, "आपको हुए होगे लेकिन मुझे नही। सच, अगर ऐसा हो तो मेरे पास आइएगा।"

उत्तर-पश्चिमी-सीमात-प्रदेश मे प्रस्तावित जनमत-सग्रह के प्रश्न पर भी उनसे बहुत से प्रश्न पूछे गये। इस प्रश्न पर आज भी काग्रेस का ध्यान केन्द्रित है। राजाओं के बारे मे भी उनसे काफी देर तक सवाल पूछे गये। इन सवालो का उत्तर देने मे भी माउन्टबेटन का पलडा भारी रहा, क्योकि प्रत्येक उत्तर के साथ वह योजना का वैधानिक औचित्य स्पष्ट करने मे सफल हुए थे।

जब एक प्रश्नकर्त्ता ने मुस्लिम लीग की "गलियारे" की माग पर उनसे भेद निकालना चाहा, तो माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, "आप योजना की किस धारा का जिक्र कर रहे है ?" उनसे सिखो के भविष्य और उनके प्रति अपनाए रुख के बारे मे भी प्रश्न पूछे गये। उन्होने स्पष्ट कहा कि योजना के अन्तर्गत सिखो की समस्या ने उन्हे जितनी चिन्ता मे डाला है, उतना अन्य किसी प्रश्न ने नही। सीमा-आयोग के बारे मे उनसे विशेषकर प्रश्न पूछे गये। सीमा-आयोग को पजाब, बगाल और आसाम के मुस्लिम बहुमत प्रदेश की सीमाए निर्धारित करने का भार सौपा गया था। एक सिख सवाददाता ने पूछा कि क्या सीमाए निर्धारित करने मे अचल सपत्ति सबधी योग्यता को भी एक आधार माना जायगा ? माउन्टबेटन ने मुसकराते हुए उत्तर दिया, "ब्रिटिश सरकार से यह अपेक्षा नही की जा सकती कि वह अचल सपत्ति के आधार पर विभाजन से सहमत होगी, मौजूदा सरकार तो बिलकुल ही नही।"

इस सम्मेलन मे उन्होने पहली बार अनौपचारिक रूप से यह सकेत किया कि दोनो उपनिवेशो की सत्ता हस्तातरित किये जाने की सभावित तिथि १५ अगस्त होगी। असल मे उनको सबसे अधिक कसा गया इसी औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर। इसी प्रश्न पर देवदास गाधी से उनकी टक्कर हुई। देवदास गाधी का बात करने का ढक ऐसा विनम्र है कि वह विरोधी के सारे शस्त्र बेकार कर देते है। मुझे ऐसा लगा कि जिस आग्रह के साथ वह प्रश्न करते रहे उससे उनके पिता की मन-स्थिति का भी कुछ अदाज किया जा सकता था।

पहले तो माउन्टबेटन की समझ मे ही नही आया कि देवदास पूछ क्या रहे थे। लेकिन असल मे वह कह यही रहे थे कि यदि कोई एक रियासत औपनिवेशिक दर्जा

प्राप्त करना चाहे तो ब्रिटेन को यह माग ठुकरा देनी चाहिए और जोर देना चाहिए कि पूरा भारत ही राष्ट्रमडल की सदस्यता का फैसला करे। उन्होने कहा कि उन्हे लगता है कि विभिन्न विधान-सभाओ को यह निर्णय करने की छूट देकर "भारी शैतानी की गुजाइश" पैदा कर दी गई है। इस प्रश्न के पीछे यही पुराना शक काम कर रहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य स्वाधीनता से कम है। इसके साथ यह डर भी जुडा हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने राष्ट्रमडल के भीतर रहने का फैसला किया और भारत बाहर चला गया, तो शायद पाकिस्तान मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अड्डा बन जायगा।

इस सबध मे माउन्टबेटन के अन्तिम शब्द ये थे, "जो प्रश्न यहा पूछे गए है उनसे मुझे लगता है कि एक बात लोगो के सामने स्पष्ट नही है। न जाने क्यो लोगो के दिलो मे इस शब्द औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे मे कुछ शक भरे हुए है। इसका अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता है। अन्तर केवल इतना है कि राष्ट्रमडल के सदस्य राष्ट्रो का आपस मे स्वेच्छा से नाता बना रहेगा। सहायता, पारस्परिक विश्वास और आगे चलकर स्नेह के लिए वे एक-दूसरे का मुह ताकेगे।"

वाइसराय-भवन लौटते ही माउन्टबेटन को यह मालूम होते देर न लगी कि देवदास की शकाओ का आधार जितना लगा उससे कही गभीर था। महात्माजी असतुष्ट थे और शाम की प्रार्थना सभा मे योजना की कडी आलोचना करनेवाले थे। इतना ही नही, कल नेताओ के रेडियो-भाषण के पहले उन्होने कहा था कि कोई नेता आलोचना के परे नही है। उन्होने अपनी दुधारी आलोचना का खास लक्ष्य बनाया था नेहरू को। उनको 'हमारे राजा' कहने के बाद उन्होने कहा, "राजा जो कुछ करता है या नही करता, हमे उसके कहे मे नही आना चाहिए। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो हमे उसके गुण गाना चाहिए। अगर उसने ऐसा नही किया है तो हमे यह भी साफ-साफ कह देना चाहिए।"

माउन्टबेटन का यह निश्चय ठीक रहा कि गाधीजी को समझाने का समय आ गया है। उनकी शकाओ की जडे गहरी होने और खतरनाक शक्ल लेने के पहले ही यह काम किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना सभा के जरा पहले उन्होने गांधीजी को वाइसराय-भवन आने का आमत्रण दिया। गाधीजी सचमुच दुखी थे, योजना के पहले सदमे से उन्हे लग रहा था कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए उनके सारे जीवन के प्रयत्नो पर पानी फिर गया था। किन्तु माउन्टबेटन ने मनाने की अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर उनसे कहा कि सरकारी ऐलान को माउन्ट-बेटन-योजना न समझ कर गाधी-योजना समझे। पूरी ईमानदारी के साथ उन्होने गाधीजी के प्रमुख विचारो——जोर-जबरदस्ती न किया जाना, आत्मनिर्णय, अग्रेजो के जाने की निकटतम तिथि और औपनिवेशिक स्वराज्य——को योजना मे शामिल करने का भरपूर प्रयास किया था।

आज के दिन फिर माउन्टबेटन की ही जीत हुई। यह आज रात की गाधीजी की कही हुई बातो मे देखा जा सकता है। उन्होने अपनी प्रार्थना सभा मे कहा, 'विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नही है। वाइसराय का इसमे कोई हाथ नही। सच बात तो यह है कि वह विभाजन के इतने ही विरोधी है जितनी कि काग्रेस है। लेकिन अगर हम दोनो—हिन्दू और मुसलमान—किसी और बात पर राजी होने को तैयार नही तो वाइसराय के सामने दूसरा चारा नही रह जाता है।" उन्होने बतलाया कि वाइसराय ने बहुत मेहनत की है और समझौता कराने की जी-तोड कोशिश। यह योजना ही ऐसी चीज थी, जिसके आधार पर समझौता हो सका। वाइसराय देश को अराजकता के हाथो छोडकर नही जाना चाहते। इसीलिए उन्होने समझौते की इतनी कोशिशे की। शायद ही किसी और वाइसराय ने गाधीजी के दिलोदिमाग पर इतनी तेजी से इतनी गहरी जीत हासिल की हो।

कल की तारीख का एक व्यक्तिगत तार, जिसे जॉएम ने भेजा है, आज मुझे मिला। इसमे लिखा था "आज तीसरे पहर ठसाठस भरी कामन्स सभा मे बडी गहरी उत्सुकता के साथ प्रधानमत्री का ऐलान सुना गया। भारत मे आये सुझावो और प्रतिक्रियाओ से यहा सब दलो को सतोष हुआ। आज जितनी एकता की भावना है और घटनाओ के भारी महत्त्व को समझने का जो प्रयास दिखाई देता है, उसकी तुलना लडाई के दिनो के ऐतिहासिक क्षणो मे ही की जा सकती है।"

शाम को ७ ३० बजे माउन्टबेटन ने कर्मचारी मडल की बैठक की। एक पीढी पुराना गतिरोध तोडने के बाद भी उनके या हमारे किसी के लिए चैन नही थी।

रियासतो के प्रश्न पर तूफान के लक्षण मुझे नजर आ रहे थे। नवाब भोपाल ने नरेन्द्र-मडल की अध्यक्षता से स्तीफा दे दिया था और वह व्यक्तिगत अलगाव एव स्वाधीनता के मार्ग से हटाए नही हटते थे, जो आज की मौजूदा प्रगति के खिलाफ पडता था।

'विभाजन के प्रशासन सबधी नतीजो' पर तैयार दस्तावेज के बारे मे नेहरू की प्रतिक्रिया अच्छी नही हो रही थी और अन्तरिम सरकार का ढाचा तथा अस्तित्व बनाए रखने मे लोहे के चने चबाने पडेगे।

नई दिल्ली, गुरुवार, ५ जून, १९४७

जरूरत थी। आरोप और प्रत्यारोप के इस वातावरण मे माउन्टबेटन ने स्पष्ट कह दिया कि इन झगडो मे पच बनने की प्रार्थना वह स्वीकार नही करेगे। इस कृतज्ञता-हीन काम को पूरा करने के लिए वह एक ऐसे पच की नियुक्ति करने पर सहमत हो गये जो दोनो को मजूर हो।

अडतालीस घटे पुरानी विभाजन-योजना से निस्सदेह पूरे देश मे तनाव कम हुआ, लेकिन दिल्ली-स्थित नेताओ मे इससे कोई भाईचारे की भावना नही पैदा हो सकी। यहा की स्थिति अब भी तनावपूर्ण थी और मामूली-सी बात से भी गभीर सकट पैदा हो सकता था।

: १० :

प्रशासन सम्बन्धी नतीजे

नई दिल्ली, रविवार, ८ जून, १९४७

माउन्टबेटन की मुख्य समस्या अब भी मूलत राजनैतिक ही है और इस समय सबसे बडा भय यह था कि किसी दल द्वारा त्यागपत्र दे देने से अन्तरिम सरकार भग न हो जाय। अन्तरिम सरकार हमेशा से नाजुक चीज रही थी। विभाजन का सिद्धान्त पूरे तौर से स्वीकार हो जाने के बाद उसे मिलाकर स्थिर रखनेवाली आन्तरिक निष्ठा और उद्देश्य का दिखावा तक भी शेष नही रह गया था। माउन्टबेटन यह बात अच्छी तरह समझते थे कि विभाजन-योजना को ब्रिटिश पार्लामेट द्वारा पुष्टि मिलने के पूर्व यदि किसी दल ने अन्तरिम सरकार से त्याग-पत्र दे दिया तो ३ जून की योजना की सफलता को भारी खतरा पैदा हो जायगा और उनकी स्थिति भी बुरी तरह से खराब हो जायगी।

आज ऐसा लगा कि ठीक यही आफत आनेवाली है, क्योकि बडी मुश्किल से माउन्टबेटन उसे भग होने से रोक पाए। अन्तरिम सरकार के कर्तव्यो को सीमित करके झगडे कम करने के इरादे से उन्होने सुझाया कि नीति और बडी नियुक्तियों सम्बन्धी सब फैसलो को फिलहाल स्थगित रखा जाय।

मत्रिमडल मे प्रश्नो का निबटारा काग्रेस के बहुमत द्वारा ही न हो जाया करे, इसलिए यह रास्ता निकाला गया कि ऐसे मामले सीधे माउन्टबेटन के पास भेजे जाया करे। इसके बाद नेहरू ने कुछ कूटनीतिक नियुक्तियो के लिए माउन्टबेटन की स्वीकृति मागी और कहा कि माउन्टबेटन मानेगे कि इससे पाकिस्तान को कोई

वास्ता नही। लियाकत ने तुरन्त आपत्ति उठाते हुए कहा कि उदाहरण के लिए वह नही चाहते कि मास्को मे किसी राजदूत की नियुक्ति की जाय। दुर्भाग्य की बात यह कि सुझाव ठीक इसी नियुक्ति के विषय मे किया गया था और जिनकी नियुक्ति की जानी थी वह थी स्वय नेहरू की बहन श्रीमती विजयालक्ष्मी।

इसके बाद का दृश्य कोलाहलपूर्ण था—सब लोग एक साथ गरमी से बोल रहे थे। नेहरू ने कहा कि सरकारी काम मे मुस्लिम लीग का हस्तक्षेप सहन करने की बजाय वह बहुमत के आधार पर काम करने का आग्रह करेगे और अगर सरकार लीग को ही सौपी जानी है तो वह तुरन्त स्तीफा दे देगे।

नई दिल्ली, मगलवार, १० जून, १९४७

मुस्लिम लीग कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका स्वर काग्रेस को उभाडने वाला था। कितु प्रस्ताव के शब्द ऐसे थे कि जिन्ना योजना को स्वीकार करने मे इससे आगे शायद ही बढना चाहेगे। मत्रिमडलीय-योजना को त्यागने के प्रति सतोष प्रगट करने के बाद प्रस्ताव मे कहा गया था कि बगाल और पजाब के विभाजन के लिए सहमति या असहमति सत्ता-हस्तातरण के लिये ३ जून की योजना का पूरा अध्ययन कर लेने के बाद ही दी जायगी। प्रस्ताव मे जिन्ना को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह चाहे तो योजना के मूल-सिद्धान्तो को समझौते के रूप मे स्वीकार कर सकते है।

समाचार-पत्रो को मैने यह समाचार देकर फिलहाल मौन कर दिया था कि वाइसराय शिमला और वहा से काश्मीर जा रहे है।

नई दिल्ली, सोमवार, २३ जून, १९४७

शिमले मे आराम करने के बाद फिर दिल्ली की भट्टी मे जलने आ गया हूँ।

पिछले दस दिन माउन्टबेटन और उनके कर्मचारियो ने एक बडे व्यापक क्षेत्र मे काम करने मे बिताए थे, जिससे योजना के स्वीकार किये जाने के काम मे भारी सहायता पहुची थी। मुख्य घटना हुई थी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा योजना की स्पष्ट स्वीकृति। दोनो दलो के मुख्य राजनैतिक निर्णयो के बारे मे अब किसी प्रकार के सदेह की गुजाइश नही रह गई थी।

ऐन मौके पर गाधीजी ने भी योजना का समर्थन कर दिया और काग्रेस हाई कमान के साम्प्रदायिक तत्वो का अन्दरूनी विरोध दुबले-पतले शरीर वाले इस व्यक्ति की अजेय शक्ति के आगे साकार नही हो सका।

जहा तक उन प्रान्तो का प्रश्न था, जिनपर योजना का सीधा असर पडता था, काफी आत्म-चिन्तन और कुछ टालमटोल के बाद काग्रेस ने उत्तर पश्चिमी-सीमान्त-

प्रदेश मे मतसग्रह करना स्वीकार कर लिया था। पहले तो डा खान साहब ने इसका बहिष्कार करने की धमकी दी। पर गाधीजी की सलाह पर तय हुआ कि स्थानीय लालकुर्ती वाले सविनय-अवज्ञा के सिद्धान्तो को अमल मे लायगे और शान्ति के साथ इसमे भाग लेने से इन्कार कर देगे। मत-सग्रह के समय केरो छुट्टी पर चले जायगे। माउन्टबेटन ने बुद्धिमानी से प्रान्त का शासन फौज के हवाले करने का निश्चय किया। भारत की दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेन्ट-जनरल सर रॉब लॉकहार्ट केरो की जगह गवर्नर का पद सभालेगे।

बगाल के प्रश्न पर जिन्ना की जिद बढती जा रही थी। अन्तरिम सरकार मे तो वह अपनी मुस्लिम लीग के लिए मत्रिपद की माग करना अपना अधिकार समझते थे लेकिन पश्चिमी बगाल के काग्रेसजनो को बगाल के अन्तरिम शासन मे यह अधिकार देने को तयार नही थे।

पजाब व्यवस्थापिका सभा ने आज ओपचारिक रूप से विभाजन का निश्चय किया है। तीन दिन पहले बगाल ने भी ऐसा ही फैसला किया था। वहा सुहरावर्दी द्वारा रखा यह प्रस्ताव कि एक स्वतन्त्र और सयुक्त बगाल का निर्माण किया जाय, दोनो दलो के विरोध से गिर गया था। इस प्रकार नियति का चक्र एक पूरा चक्र लगा चुका था और जिस काग्रेस ने कर्जन की बग-भग योजना का कटुता से विरोध किया था, वही चालीस साल बाद आज खुद उसी नीति का सुझाव दे रही थी।

रियासतो के बारे मे अपनी नीति के सबध मे नेताओ ने एक बुनियादी फैसला किया था। दिल्ली मे एक रियासती विभाग कायम किया जायगा जो रियासतो के साथ नये सबधो तथा उनसे सबधित अन्य विषयो के लिए उत्तरदायी होगा। इस बीच यह तय किया गया कि यह नया विभाग सत्ता को छोडकर अन्य सभी चीजे ब्रिटिश सम्राट् के प्रतिनिधि के राजनैतिक विभाग से अपने हाथ मे ले ले।

सत्ता-हस्तातरण के बाद सर्वसत्ता-सम्पन्नता का प्रश्न राजनैतिक और कानूनी प्रश्नो से भरा हुआ था। यह बात माउन्टबेटन को उन चर्चाओ से स्पष्ट हो गई, जो उन्होने पिछले दस दिनो विभिन्न नेताओ, निजाम के वैधानिक सलाहकार और आने पुराने दोस्त सर वाल्टर मॉकटन, नवाब भोपाल और उनके सलाहकार सर जफरुल्लाखा के साथ की थी। वे कुछ रियासतो के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माग कर रहे थे।

राजाओ की अनिश्चितता और निष्क्रियता का अनुभव तो माउन्टबेटन स्वय काश्मीर मे कर आय थे, जहा से वह आज ही लौटे थे। नेहरू और गाधी दोनो दस इस बात के लिए बहुत व्यग्र थे कि काश्मीर के महाराज स्वाधीनता की कोई घोषणा न करे। नेहरू खुद काश्मीर जाने को उत्सुक थे, जिससे अपने दोस्त शेख अबदुल्ला को, जो रियासती राज्य-परिषद् के अध्यक्ष थे, जेल से छुडवा सके। गत वर्ष जब नेहरू काश्मीर गय थे तो काश्मीर सरकार ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया था। गान्धीजी का

मत यह था कि उन्हे नेहरू के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। काश्मीर के महाराज ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वह दोनो मे से किसी को आने देना नही चाहते। माउन्टबेटन यह कह कर दोनो की यात्रा टालने मे समर्थ हुए थे कि महाराज ने उन्हे बहुत दिनो से काश्मीर आने का निमन्त्रण दे रखा है और पहले वह स्वय वहाँ जाना पसन्द करेंगे।

वहा पहुचने पर उन्होने पाया कि महाराजा राजनैतिक रूप से सहज पकड मे नही आ रहे। उनके बीच तभी कुछ बातचीत हो पाती जब वह मोटर मे बैठकर साथ घूमने निकलते थे। इन मौको पर माउन्टबेटन ने उनको और उनके प्रधानमत्री काक को समझाया कि स्वाधीनता की कोई घोषणा न करे, बल्कि जितनी जल्दी हो सके, काश्मीर की जनता की इच्छा मालूम करने की कोशिश करे और १४ अगस्त तक फैसला कर ले कि वह किस देश की विधान-सभा मे अपने प्रतिनिधि भेजेगे। माउन्टबेटन ने उन्हे बतलाया कि नव-निर्मित रियासती विभाग यह आश्वासन देने को तैयार है कि अगर काश्मीर पाकिस्तान मे शामिल हुआ तो भारत सरकार इसे मित्रताहीन काम नही समझेगी। उन्होने समझाया कि यदि सत्ता-हस्तातरण के दिन तक काश्मीर को दोनो उपनिवेशो मे से किसी का समर्थन प्राप्त न हो सका तो उसकी स्थिति कितनी खतरनाक हो जायगी। उनका इरादा था कि पहले यह सलाह महाराजा को व्यक्तिगत रूप मे अकेले मे दे और फिर इसे उनके प्रधानमत्री के सामने जार्ज एबेल और रेजीडेट कर्नल वेब की उपस्थिति मे होनेवाली एक छोटी बैठक मे दोहराए और इस बैठक की कार्यवाही का लेखा रखा जाय।

महाराजा ने सुझाया कि यह बैठक उनकी यात्रा के अन्तिम दिन हो। माउन्टबेटन यह सोचकर राजी हो गए कि इससे महाराज को किसी नतीजे पर पहुचने के लिए काफी समय मिल जायगा। लेकिन जब बैठक का समय आया तो महाराजा ने कहला भेजा कि पेट मे शूल उठने के कारण वह खाट से उठने मे मजबूर है और इसलिए बैठक मे भाग लेने मे असमर्थ है।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २७ जून, १९४७

नई कौसिल की आज एक महत्त्वपूर्ण वैठक हुई। माउन्टवेटन आज की वैठक के भी अध्यक्ष थे और उन्होने आज भी पच का काम करने से इन्कार कर दिया। लेकिन उनके लिए यह काम करना जरूरी नही रह गया था, क्योकि कौसिल ने बडी आश्चर्यजनक तेजी और एकमत के साथ जिन्ना का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि पजाब और बगाल के सीमा-आयोगो की अध्यक्षता के लिए सर साइरिल रेडक्लिफ को आमत्रित किया जाय। दोनो आयोगो के बारे मे उन्हे अपने निर्णायक-मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

उधर नेहरू सीमा-आयोग के लिए सरल उद्देश्य निश्चित करवाने मे सफल हुए। यह उद्देश्य निम्न थे "मुसलमानो और गैर मुसलमानो के बहुमत वाले प्रदेशो के आधार पर दोनो नये प्रान्तो की सीमाए तय की जाय और ऐसा करते समय अन्य अशो का ध्यान भी रखा जाय।" इस समझौते से दोनो दलो को सतोष हुआ। मुस्लिम लीग ने सोचा कि बगाल के बारे मे विस्तृत शर्तो के आधार पर उसकी कलकत्ता पा लेने की सभावना बढ जायगी। काग्रेस और सिखो ने सोचा कि अन्य अशो के अन्तर्गत सम्पत्ति तथा अन्य चीजो पर ध्यान देने से पजाब मे उनको फायदा होगा।

पहले इरादा यह था कि सीमा निश्चित करने का कटीला काम सयुक्त राष्ट्र-सघ को सौप दिया जाय। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसकी कार्यविधि बहुत पेचीदा होगी और समय भी बहुत अधिक लग जायगा। दोनो आयोगो मे रेडक्लिफ की सहायता के लिए चार हाईकोर्ट के जज रहेगे। इनमे से दो काग्रेस द्वारा नामाकित किये जायगे और दो मुस्लिम लीग द्वारा।

नई दिल्ली, सोमवार, ३० जून, १९४७

माउन्टबेटन के सुझाव पर स्थापित विभाजन कौसिल बिना देरी या विवाद के भारतीय सेना के बटवारे के सवाल पर सहमत हो गई।

इसके लिए आचिल्लेक और इस्मे की जितनी प्रशसा की जाय थोडी होगी, क्योकि उन्होने सेना के 'पुनर्निर्माण' का ढाचा तैयार किया। लेकिन सकट की घडी मे उडीसा के गर्वनर त्रिवेदी को विचार-विमर्श मे सम्मिलित कर माउन्टबेटन ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। त्रिवेदी ही एकमात्र ऐसे भारतीय सिविल अधिकारी थे, जिन्हे युद्धकाल मे सुरक्षा-विभाग के सचिव पद पर काम करने के कारण ऊचे स्तर के सुरक्षा सगठन का काफी अनुभव था। उन्हे नेहरू और पटेल का विश्वास-भाजन बनते देर न लगी। लियाकतअली खा से उनकी पुरानी दोस्ती थी। पिछले सात दिन विस्तृत चर्चाए कर वह दोनो पक्षोको कुछ सहूलियते देने पर राजी कर सके, जिसके फलस्वरुप वास्तविक समझौता हो सका।

प्रशासन सम्बन्धी नतीजे

इस विषय मे यह बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार किया गया भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाए रखे, जिनमे क्रमश गैर-मुसलमानो और मुसलमानो का बाहुल्य रहे। पन्द्रह अगस्त से यह सेनाए अपनी-अपनी पृथक् कमानो के अन्तर्गत काम करे। दोनो पक्ष इस बात पर दृढता से जमे हुए थे कि समझौते की पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उनकी सेनाए पूर्णत स्वतन्त्र रहेगी। जिन्ना और लियाकत-अली खा ने तो खुले तौर से कहा था कि जबतक उनकी फौज नही बन जाती तबतक राष्ट्र-सघ को सौप दिया जाय। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसकी कार्यविधि बहुत पेचीदा होगी और समय भी बहुत अधिक लग जायगा। दोनो आयोगो मे रेडक्लिफ की सहायता के लिए चार हाईकोर्ट के जज रहेगे। इनमे से दो काग्रेस द्वारा नामाकित किये जायगे और दो मुस्लिम लीग द्वारा।

नई दिल्ली, सोमवार ३० जून १९४७

माउन्टबेटन के सुझाव पर स्थापित विभाजन कौसिल बिना देरी या विवाद के भारतीय सेना के बटवारे के सवाल पर सहमत हो गई।

इसके लिए आचिन्लेक और इस्मे की जितनी प्रशसा की जाय थोडी होगी, क्योकि उन्होने सेना के 'पुनर्निर्माण' का ढाचा तैयार किया। लेकिन सकट की घडी मे उडीसा के गवर्नर त्रिवेदी को विचार-विमर्श मे सम्मिलित कर माउन्टबटन ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। त्रिवेदी ही एकमात्र ऐसे भारतीय सिविल अधिकारी थे जिन्हे युद्धकाल मे सुरक्षा-विभाग के सचिव पद पर काम करने के कारण ऊचे स्तर के सुरक्षा सगठन का काफी अनुभव था। उन्हे नेहरू और पटेल का विश्वास-भाजन बनते देर न लगी। लियाकतअली खा से उनकी पुरानी दोस्ती थी। पिछले सात दिन विस्तृत चर्चाए कर वह दोनो पक्षो को कुछ सहूलियते देने पर राजी कर सके, जिसके फलस्वरूप वास्तविक समझौता हो सका।

इस विपय मे यह बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार किया गया भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाए रखे, जिनमे क्रमश गैर-मुसलमानो और मुसलमानो का बाहुल्य रहे। पन्द्रह अगस्त से यह सेनाए अपनी-अपनी पृथक् कमानो के अन्तर्गत काम करे। दोनो पक्ष इस बात पर दृढता से जमे हुए थे कि समझौते की पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उनकी सेनाए पूर्णत स्वतन्त्र रहेगी। जिन्ना और लियाकतअली खा ने तो खुले तौर से कहा था कि जबतक उनकी फौज नही बन जाती तबतक वे सरकार की बागडोर अपने हाथ मे नही लेगे।

१५ अगस्त के बाद किसी प्रकार के केन्द्रीय प्रशासन सबधी नियत्रण के खिलाफ भी दोनो पक्षो ने जोरदार आपत्तिया उठाई। लेकिन माउन्टबेटन ने इस प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जबतक सिपाहियो और साज-सामान के बटवारे का

काम पूरा नही हो जाता तबतक सेना के सचालन का काम आचिन्लेक के हाथ मे रहना चाहिए। फिलहाल वह भारत मे रहकर भारतीय सशस्त्र सेना का शासन चलायेगे। यह काम वह सयुक्त सुरक्षा परिषद् के अन्तर्गत करेग, जिसमे उनके अतिरिक्त दोनो देशो के गवर्नर-जनरल और सुरक्षा-मत्री सम्मिलित रहेगे।

दोनो देशो के नये प्रधान-सेनापतियो के बारे मे भ्रम से बचने के लिए १५ अगस्त से लेकर इस कार्य की समाप्ति तक आचिन्लेक को सर्वोच्च सेनापति कहा जायगा। सेना के बटवारे का काम करने की अन्तिम तिथि १ अप्रल १९४८ ठहराई गई।

नई दिल्ली, मगलवार, १ जुलाई १९४७

ज्यो-ज्यो १५ अगस्त का दिन नजदीक आता जा रहा था, पजाब मे तनातनी बढ रही थी। इस हवा के रुख का पता उस पत्र से मिलता ह जो आचिन्लेक को दिल्ली के एक सिख विस्थापित ने भेजा था। पत्र मे लिखा था, "सातवी सिख पल्टन अब भी बसरा मे पडी फारस के तैल-क्षेत्रो पर पहरा दे रही है जबकि पिछले बारह महीनो मे उनके स्वदेश मे दुखान्त घटनाए घटी है, जिनसे विदेश मे रहनेवाले हमारे बहादुर सिख भाइयो के दिमाग ठिकाने नही रह गए। जब भारत का विभाजन हो रहा है तो हमारे सिपाहियो को स्वदेश मे अपने घरवालो के बीच होना चाहिए। मै आशा करता हू कि अगस्त का नाटक शुरु होनेके पहले आप उन्हे घर लौटने की उचित आज्ञा देने मे देरी न करेगे।"

जेनकिन्स ने सूचना भेजी थी कि लाहौर और अमृतसर की स्थिति अत्यधिक चिन्तनीय है। यहा की व्यापक-हिसा हत्या और लूट का रूप ले रही है। यह काम ऐसे चुपचाप और अचानक किये जाते है कि सामान्य सैनिक और पुलिस की कार्यवाही द्वारा उन्हे दबाना बहुत मुश्किल है। एक बार यह पता लग जाने पर कि भारत के नगरो को जलाना कितना सहज है, सबमे अधिक खतरा आग लगाने-वाली चीजो से पदा हो गया है।

: ११

नये गवर्नर-जनरल का प्रश्न

नई दिल्ली, बुधवार, २ जुलाई १९४७

काग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता वाइसराय भवन के अलग अलग कमरो मे बैठे हुए प्रस्तावित 'उपनिवेश विधेयक' की शर्तो पर विचार कर रहे थे। इस विधेयक का नाम अब 'भारतीय स्वाधीनता विधेयक' रख दिया गया था।

दोहरा रहे थे कि 'आप स्वय हुकूमत नही करना चाहते, तो कम-से-कम हमे तो करने दीजिए।' इसपर जिन्ना की प्रतिक्रिया यह थी कि अगर एक भी लीगी-मत्री को हटाया गया तो वे सब सामूहिक रूप से स्तीफा दे देगे, और कह देगे कि वे अब किसी प्रकार का सहयोग नही देगे और पूरी विभाजन-योजना से हाथ धो रहे है। माउन्टबेटन जानते थे कि अगर उन्होने ऐसा कोई कदम उठाया तो शाति और पाकिस्तान दोनो की सारी सभावनाए नष्ट हो जायगी।

थके और बोझ से दबे नेहरू पर काग्रेस की इस माग का दबाव बढता जा रहा था कि वह तुरन्त अपने घर के मालिक बने। इसके कारण पिछले सप्ताह नेहरू स्तीफा देनेवाले थे। पहले तो जिन्ना ने ऐसे किसी भी सूत्र पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसका अर्थ मुस्लिम लीग सदस्यो द्वारा पद छोडना हो। इसे उन्होने लीग के लिए अपमानजनक बतलाया। जब माउन्टबेटनने एक योजना तैयार की और उनकी इस प्रकार की आपत्तियो का समाधान करने के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया तो जिन्ना बदल गए। उन्होने कहा कि इस योजना को १९३५ के विधान के अन्तर्गत गैरकानूनी मानकर वह इसका विरोध करेगे। इससे माउन्टबेटन ने एक नया रास्ता निकाल लिया। लन्दन से पूछ-ताछ करने पर उन्हे पता चला कि जिन्ना की कानूनी आपत्ति मे इतनी सचाई थी कि नये विधान के पास होने के पूर्व वह सरकार का पुनर्सगठन नही कर सकते।

१५ अगस्त के बाद वह भारत के गवर्नर-जनरल पद पर बने रहे या नही, इस प्रश्न पर कोई आखिरी निर्णय करने के पहले माउन्टबेटन लदन से राजा, प्रधान-मत्री तथा अन्य लोगो की अधिकृत सलाह चाहते थे। उनको यह भी आशका थी कि कही ब्रिटिश सरकार यह न समझ बैठे, और उसका समझना गलत नही होगा, कि उन्होने दोनो राष्ट्रो के सयुक्त गवर्नर-जनरल की सभावना के बारे मे गलत विश्वास दिलाकर उन्हे भुलावे मे डाल दिया है।

इसलिए उन्होने निश्चय किया कि इस्म तुरन्त लदन के लिए प्रस्थान करे। अधिकृत तौर से यही कहा जायगा कि वह लन्दन इसलिए जा रहे है, जिसमे 'भारत स्वाधीनता विधेयक' को ससद मे पास करवाने मे सरकार की सहायता कर सके। लेकिन इसके अलावा उन्हे गुप्त रूप से प्रमुख लोगो की राय भी प्राप्त करनी पडगी कि माउन्टबेटन भारत रुके रहे या स्वदेश लौट आये। मै भी इस्मे के साथ जा रहा हू, जिससे नई स्थिति के बारे मे समाचारपत्रो तथा अन्य जानकारो की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकूँ।

लदन, मगलवार, ८ जुलाई १९४७

रात को भोजन के बाद कल इस्मे ने १०, डाउनिग स्ट्रीट मे एक वार्ता मे भाग लिया, जो आधी रात के बाद तक चलती रही। हालाकि इस बारे मे कुछ शकाए

दोहरा रहे थे कि 'आप स्वय हुकूमत नही करना चाहते, तो कम-से-कम हमे तो करने दीजिए।' इसपर जिन्ना की प्रतिक्रिया यह थी कि अगर एक भी लीगी-मत्री को हटाया गया तो वे सब सामूहिक रूप से स्तीफा दे देगे, और कह देगे कि वे अब किसी प्रकार का सहयोग नही देगे और पूरी विभाजन-योजना से हाथ धो रहे है। माउन्टबेटन जानते थे कि अगर उन्होने ऐसा कोई कदम उठाया तो शाति और पाकिस्तान दोनो की सारी सभावनाए नष्ट हो जायगी।

थके और बोझ से दबे नेहरू पर काग्रेस की इस माग का दबाव बढता जा रहा था कि वह तुरन्त अपने घर के मालिक बने। इसके कारण पिछले सप्ताह नेहरू स्तीफा देनेवाले थे। पहले तो जिन्ना ने ऐसे किसी भी सूत्र पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसका अर्थ मुस्लिम लीग सदस्यो द्वारा पद छोडना हो। इसे उन्होने लीग के लिए अपमानजनक बतलाया। जब माउन्टबेटनने एक योजना तैयार की और उनकी इस प्रकार की आपत्तियो का समाधान करने के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया तो जिन्ना बदल गए। उन्होने कहा कि इस योजना को १९३५ के विधान के अन्तर्गत गैरकानूनी मानकर वह इसका विरोध करेगे। इससे माउन्टबेटन ने एक नया रास्ता निकाल लिया। लन्दन से पूछ-ताछ करने पर उन्हे पता चला कि जिन्ना की कानूनी आपत्ति मे इतनी सचाई थी कि नये विधान के पास होने के पूर्व वह सरकार का पुनर्सगठन नही कर सकते।

१५ अगस्त के बाद वह भारत के गवर्नर-जनरल पद पर बने रहे या नही, इस प्रश्न पर कोई आखिरी निर्णय करने के पहले माउन्टबेटन लदन से राजा, प्रधान-मत्री तथा अन्य लोगो की अधिकृत सलाह चाहते थे। उनको यह भी आशका थी कि कही ब्रिटिश सरकार यह न समझ बैठे, और उसका समझना गलत नही होगा, कि उन्होने दोनो राष्ट्रो के सयुक्त गवर्नर-जनरल की सभावना के बारे मे गलत विश्वास दिलाकर उन्हे भुलावे मे डाल दिया है।

इसलिए उन्होने निश्चय किया कि इस्मे तुरन्त लदन के लिए प्रस्थान करे। अधिकृत तौर से यही कहा जायगा कि वह लन्दन इसलिए जा रहे है, जिसमे 'भारत स्वाधीनता विधेयक' को ससद मे पास करवाने मे सरकार की सहायता कर सके। लेकिन इसके अलावा उन्हे गुप्त रूप से प्रमुख लोगो की राय भी प्राप्त करनी पडगी कि माउन्टबेटन भारत रुके रहे या स्वदेश लौट आये। मै भी इस्मे के साथ जा रहा हू, जिससे नई स्थिति के बारे मे समाचारपत्रो तथा अन्य जानकारो की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकू।

लदन, मगलवार, ८ जुलाई १९४७

रात को भोजन के बाद कल इस्मे ने १०, डाउनिग स्ट्रीट मे एक वार्ता मे भाग लिया, जो आधी रात के बाद तक चलती रही। हालाकि इस बारे मे कुछ शकाए

उठाई गई कि दोनो देशो के गवर्नर-जनरल के रूप मे पच होने की बजाय केवल एक देश का गवर्नर-जनरल बनने से उनकी स्थिति कैसी होगी, खासकर जब दोनो के बीच कोई झगडे के सवाल उठेगे। फिर भी मत्रियो की सामान्य राय यह थी कि माउन्टबेटन भारत के आमत्रण को स्वीकार कर ले। एटली ने तो यहा तक कह डाला कि माउन्टबेटन के अलावा कोई और इस काम को सिरे नही चढा सकता। इस सुझाव के बारे मे मुस्लिम लीग की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप लियाकत का जो पत्र इस्मे अपने साथ लन्दन ले गए थे, उसका सरकार पर गहरा असर पडा। दरअसल अब स्थिति यह थी कि दोनो दलो ने माउन्टबेटन से भारत मे रुके रहने की प्रार्थना की थी।

आज सवेरे प्रधान-मत्री ने निम्नलिखित विरोधी नेताओ को मिलने के लिए बुलाया। सेल्सबरी, मेकमिलन, बटलर, सेम्युअल और क्लैम डेविस। इस्मे ने स्थिति का खुलासा उनके सामने रखा। लार्ड सेम्युअल अपने इस विचार पर अमल कराने के लिए उत्सुक थे कि वाइसराय दो गवर्नर-जनरलो का प्रधान रहे। यह सुझाव उन्होने माउन्टबेटन को मेरे निवास-स्थान पर माउन्टबेटन के भारत जाने के पूर्व भी दिया था। लेकिन लोगो का आम मत यह था कि इस सुझाव को अमल मे लाने का समय बीत चुका है, और काग्रेस शायद ही इसे स्वीकार करे। उदारदली सदस्यो का हार्दिक मत था कि माउन्टबेटन भारत के गवर्नर-जनरल का पद सभाले। किन्तु अनुदार दली नेता भी, यद्यपि इस सुझाव से सहमत थे, तथापि उनका कहना था कि चर्चिल से सलाह किये बिना वे कोई फैसला नही कर सकते। चर्चिल उस समय हाल ही की बीमारी के बाद चार्टवेल मे आराम कर रहे थे और ईडन भी बैठक मे सम्मिलित नही हो पाए थे।

एटली ने इस्मे को सुझाया कि वह चार्टवेल जाकर चर्चिल से मिल आवे। इस्मे को जाते देर नही लगी। इस महान् नेता से अपनी मुलाकात के बारे मे इस्मे के दिल मे जो डर थे, वे तुरन्त दूर हो गए। चर्चिल का विचार था कि जिन्ना के फैसले से स्थिति मे किसी प्रकार का फर्क नही पडा। समुद्रीतार द्वारा वाइसराय को भेजे जाने के लिए एक सदेश का मजमून उन्होने इस्मे को लिखाया। इसका आशय यह था कि वैधानिक गवर्नर-जनरल को जानकारी प्राप्त करने और सलाह देने का असीम अधिकार रहता है। इसके आधार पर माउन्टबेटन नई सरकार को काफी मदद दे सकते थे, जिससे उन्हे सकोच नही करना चाहिए। यह फैसला माउन्ट-बेटन की कल्पना पर छोडते हुए कि उनकी उपयोगिता कब तक रहेगी, चर्चिल ने खास जोर उनके कर्तव्यो के राजनैतिक पक्ष पर दिया। उन्होने कहा कि माउन्टबेटन साम्प्रदायिक तनाव कम करने, राजाओ के हितो को सुरक्षित रखने और भारत तथा शेष राष्ट्र-मडल के बीच दोस्ती के सबध पुष्ट करने का काम कर सकते है।

बडी राहत के साथ इस्मे तुरन्त लन्दन लौटे और चर्चिल के अनुदारदली साथियो को अपनी मुलाकात और स देश का पूरा ब्योरा दिया। स देशा तुरन्त दिल्ली भेज दिया गया। इस निर्णायक सलाह ने सबके दिलो को हल्का कर दिया।

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था औपचारिक चर्चाओ द्वारा कूटनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने के बारे मे मेरा विश्वास बढता जा रहा था। जिस तरह से इस्मे माउन्टबेटन, ब्रिटिश सरकार और विरोधी दल के दिलो की शकाए मिटाने मे सफल हुए, वह काम इतनी सफलता और फुर्ती के साथ लम्बे पत्रो या तारो से करना सभव नही था।

लन्दन, बृहस्पतिवार, १७ जुलाई १९४७

आज शामको वुडरो वाएट ने कामन्स सभाभवन मे पटवर्धन से मेरा परिचय कराया। पटवर्धन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के विश्वासपात्र है और भारतीय स्वाधीनता-विधेयक पर होने वाली बहस सुनने लदन आये हुए है। उन्होने कहा कि उनका मत है कि माउन्टबेटन को गवर्नर-जनरल पद पर बने रहने का आमत्रण देकर काग्रेस ने दूरदर्शिता का काम किया है। समाजवादियो को आशा है कि माउन्टबेटन की उपस्थिति से राजाओ की अपरिवर्तनशीलता कम हो सकेगी और पुनर्मिलनके लिए द्वार खुला रहेगा। मैने उनसे पूछा कि इस बारे मे उनका स्पष्ट मत क्या है कि काग्रेस द्वारा जनतत्र की स्थापना करने क निर्णय किये जाने के बाद भी माउन्टबेटन से गवर्नर-जनरल के पद पर रुकने का आग्रह किया गया है? व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए उन्होने कहा कि समय आने पर इस बारे मे नेहरू जो रुख अपनाएगे उससे समाजवादियो को सतोष होगा। मैने उनसे कहा कि वह विश्वास रखे कि माउन्टबेटन प्राप्त आमत्रण से एक घटा भी ज्यादा नही रुकेगे।

इस मुलाकात से मेरी यह धारणा बन गई है कि समाजवादी लोग माउन्टबेटन या औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर झगडा नही खडा करेगे। वे अपना ध्यान केन्द्रित करेगे रियासतो पर, जहा काग्रेस-समाजवादियो की काफी बडी सख्या मौजूद है। पटवर्धन इस बात के लिए व्यग्र है कि वाइसराय को रियासतो में प्रजातात्रिक अधिकार दिलवाने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। मैने कहा कि कुछ वामपथियो मे मैने वह प्रवृत्ति पाई है कि वे केवल 'क्राति के लिए क्राति' चाहते है। किन्तु पटवर्धन ने दृढता से कहा कि स्वत क्राति कोई अच्छी चीज नही है। वह वैधानिक रीति से परिवर्तन के पक्ष मे है और आखिरी हथियार के तौर परही क्रातिकारी कार्रवाई करने की सलाह देते है।

लन्दन, शुक्रवार, १८ जुलाई १९४७

वुडरो वाएट के साथ, जो १९४५ के चुनाव मे बर्मिघम से लेबर-सदस्य

चुने गए थे, मेरी कई मनोरजक मुलाकाते हुई। दोनो पक्षो मे वह ही एकमात्र तरुण ससद-सदस्य है, जिन्होने भारत को अपना विशेष विषय बनाया है। मत्रिमडलीय योजना के समय वह क्रिप्स के व्यक्तिगत सहायक के रूप मे भारत आये थे। सुदूरपूर्व के लिए ससदीय प्रतिनिधि-मडल के भी वह एक सदस्य थे।

इस महत्वपूर्ण प्रवास के बारे मे उन्होने एक मजेदार घटना सुनाई, जिसका सबध उनकी सहयोगिनी, एक स्पष्टवादी ससद-सदस्या मिसेज निकोल्स से था। प्रतिनिधिमडल की गाधीजी से मुलाकात के समय उन्होने सोचा कि दल की एकमात्र महिला-सदस्य के नाते उन्हे वातचीत को थोडा पारिवारिक स्वरूप देना चाहिए। इसलिए उन्होने महात्माजी से उनके बच्चो के बारे मे सवाल पूछा, "आपके कोई लडकी भी है ?"

महात्मा जी ने उत्तर दिया, "मेरी लाखो बेटिया है ? क्या आप इतने सतुष्ट है ?"

मिसेज निकोल्स ने उत्तर दिया, "मे तो सतुष्ट हू, मि गाधी ! पर क्या आपको भी सतोष है ?"

: १२ :

संघ-प्रवेश-पत्र पर राजाओं के हस्ताक्षर

नई दिल्ली, मंगलवार, २२ जुलाई १९४७

आज तीसरे पहर हम पालम हवाई अड्डे पर पहुच गए। यात्रा वैसे तो निर्विघ्न थी, लेकिन थकान बेहद हो गई थी। इस छ हजार मील लम्बी हवाई यात्रा के वाद कोई भी अभी तक ताजगी महसूस नही कर पाया था, और लदन मे घटनाओ की सरगर्मी के दोर के बाद तो हम राजनैतिक सता-परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण आखिरी चरण मे भाग लेने के लिए भी नितात पगु-से हो गए थे।

हमारी अनुपस्थिति मे एक सकट को सरकारी तौर पर हल कर दिया गया था, हालाकि तनातनी अव भी काफी थी। माउन्टबेटन ने अन्तरिम सरकार का इस प्रकार पूर्ण गठन कर लिया था कि वास्तव मे दो अस्थायी सरकार कायम हो गई। एक भारत और दूसरी पाकिस्तान के लिए। इनमे से प्रत्येक सरकार अपने निजी मामलो से मतलब रखेगी और केवल दोनो देशो से सम्बन्धित प्रश्नो पर ही एक-दूसरे से सलाह लिया करेगी। इस योजना का लाभ यह हुआ कि लीगी-मत्रियो के त्यागपत्र देने का प्रश्न हल हो गया।

भारतीय स्वतन्त्रता-अधिनियम पर शाही-स्वीकृति प्राप्त होने के करीब चौबीस घटे बाद, गत शनिवार को प्रकाशित आज्ञा मे कहा गया था कि गवर्नर-जनरल ने 'मत्रि-पदो के पुनर्वितरण' की मजूरी दे दी। नेहरू और पटेल बडी मुश्किल से इस योजना पर राजी हुए। जहा तक जिन्ना का सवाल था, जब माउन्ट-बेटन ने यह योजना उनके सामने रखी तो उन्होने फिर यही कहा कि वह उसपर विचार करेगे। लेकिन माउन्टबेटन अब उनसे यह कह सकने की स्थिति मे थे कि उनके विचारो और सलाह की जरूरत नही है, क्योकि माउन्टबेटन अपने बलबूते और जिम्मेदारी पर ही नई व्यवस्था को लागू करने की आज्ञा जारी कर रहे थे।

अपनी स्वाभाविक मौलिकता के साथ माउन्टबेटन ने अपने कर्मचारियो, मत्रियो और विभाजन की व्यवस्था से सबध रखनेवाले अन्य अधिकारियो के सुभीते के लिए एक कैलेडर तैयार किया, जिसमे दिन और महीना दिया हुआ था और हर दिन के नीचे लिखा था, "सत्ताहस्तातरण तैयारी के लिए इतने दिन शेष है।" विभाजन-कौसिल इस काम के महत्व को समझ गई थी और फुर्ती से काम कर रही थी। वह काम मे पिछडी भी नही। इसका मुख्य कारण यह था कि सचालन-समिति ने उसको बहुत अच्छी तरह सारा काम समझा दिया था। एच एम पटेल और मुहम्मदअली प्रारम्भिक काम निबटाने मे काफी मेहनत करते थे। इसका फल यह हुआ कि १५ जुलाई की बैठक मे कम-से-कम सात ऐसे विषय पच्चीस मिनट से भी कम समय मे निबटा दिये गए, जिनको माउन्टबेटन अत्यधिक पेचीदा और विवादग्रस्त समझ रहे थे। स्वय विभाजन-कौन्सिल की भी नियमित रूप से हफ्ते मे तीन बैठके होती थी।

आज शाम मैने सवा सात बजे माउन्टबेटन से मुलाकात की और चूंकि मै अपने अन्तिम पत्र के पहले ही यहा पहुच गया था, इसलिए उन्हे विभिन्न सदेशो और अनुभवो से लाद दिया। माउन्टबेटन बहुत खुश थे और लदन के हमारे काम की प्रशसा करते नही अघाते थे। जब वह रात के खाने के लिए कपडे पहन रहे थे, तब भी मै उनसे बाते करता रहा। मैने उन्हे बतलाया कि उनके भविष्य के बारे मे कैसी-कैसी बाते चल रही है। लदन मे तो यह भी अफवाह है कि आपको वाशिगटन मे ब्रिटिश राजदूत का पद दिया जायगा उन्होने फिर कहा कि वह अखाडे मे नही है और उनका यही निश्चय स्थिर है कि ब्रिटिश सरकार को वह यह वादा पूरा करने के लिए कहेगे कि उन्हे नौसेना मे ही वापस भेज दिया जाय। इसका एक कारण यह भी था कि वह थक गए थे। फिर अचानक उन्होने पूछा, "तुमने समाचारपत्रो मे मुझे दिये जाने वाले पद के बारे मे सबसे ताजी खबर देखी है? मामूली चीज नही, जर्मनी का सिहासन दिया जा रहा है।"

अब माउन्टबेटन रियासतो की समस्या मे आकण्ठ डूबे हुए है। जैसा उन्होने ३ जून की योजना के पहले की कूटनीति मे किया था, वैसे ही इस समय भी वह जान-

बूझ कर एक जोखिम उठा रहे है। रियासतो के सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजाओ को समझाने का काम वह खुद ही कर रहे थे। इस बीच वी पी मेनन ने काग्रेस को इस योजना पर राजी कर लिया है। अपने काम का आरम्भ उन्होने पटेल के उस सशक्त सहयोग के आश्वासन के बल पर किया था, जो पटेल ने हमारे लदन जाने के दिन नये रियासती-विभाग का उद्घाटन करते समय अपने राजनैतिक पूर्ण भाषण मे व्यक्त किया था। लेकिन सबसे कठिन सवाल तो हैदराबाद का था, जिस पर निश्चय ही विशेष ध्यान देना पडेगा। माउन्टबेटन का कहना था, कि जब जरूरत हो वह वहा जाने के लिए तैयार है। उनकी धारणा थी की कोई उचित समझौता करने का एकमात्र तरीका यही है कि निजाम से व्यक्तिगत रूप मे मिला जाय।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, २४ जुलाई १९४७

मेरा अधिकाश दिन विभाजन-कौसिल के उस महत्त्वपूर्ण वक्तव्य के प्रसार की व्यवस्था करने मे बीता, जिसमे पजाब के विभाजित क्षेत्रो मे एक सीमा-फौज स्थापना का ऐलान किया गया था। यह विशेष फौज १४ मे से उन १२ जिलो मे रखी जायगी, जिन्हे कोई-न-कोई पक्ष विवादग्रस्त बतला रहा था। इसके सेनापति होगे मेजर-जनरल 'पीट' रीस, जो इसके पहले तक चौथी भारतीय डिवीजन के कमाडर थे।

नई फौज का निर्माण भी असल मे मुख्यत इसी डिवीजन से किया जायगा। सब मिलाकर इस फौज मे पचास हजार अफसर और सैनिक होगे, जो ज्यादातर उन टुकडियो मे लिये जायगे, जिनका अभी तक विभाजन नही हुआ और जिनमे ब्रिटिश अफसरो का भारी अनुपात है। शाति-काल मे न्याय और व्यवस्था की रक्षा के लिए इतनी बडी फौज का इस्तेमाल पहले कभी नही किया गया था। अज्ञात आकार-प्रकार के खतरो के खिलाफ की जानेवाली यह सबसे बडी भौतिक तैयारी थी। और इस तयारी मे यह सट्टा खेला गया था कि शेप सारे देश मे साम्प्रदायिक शाति बनी रहे। रीस को दो उच्च अधिकार-सपन्न सैनिक-सलाहकार मिलेगे। भारतीय-सेना का एक सिख और पाकिस्तान-सेना का एक मुसलमान। पन्द्रह अगस्त के बाद इन क्षेत्रो मे मौजूद दोनो देशो की सेनाओ के सचालन का भार रीस के हाथो मे रहेगा। सर्वोच्च सेनापति और सयुक्त विभाजन-कौसिल द्वारा वह दोनो सरकारो के प्रति उत्तरदायी होगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २५ जुलाई १९४७

आज राजाओ के साथ माउन्टबेटन की पहली और आखिरी मुलाकात हुई, क्योकि वाइसराय और ताज के प्रतिनिधि के रूप मे वह अब कभी राजाओ के

सम्मेलन मे भाषण नही दे सकेगे। यह दुआ-सलाम और विदाई का औपचारिक मौका नही था, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक अवसर था। राजाओ मे फूट थी और वे बडी दुविधा मे थे। घटनाओ की तेजी ने उन्हे चकरा दिया था। उधर माउन्टबेटन के पास भी अपने मत-समर्थन के लिए लदन से कोई विस्तृत आदेश नही आ पाए थे। तीन जून और मत्रिमडल-मिशन योजना दोनो मे राजाओ के बारे मे जो थोडा जिक्र था, उनसे यही नतीजा निकलता था कि सत्ता का असली हस्तातरण तो ब्रिटेन और ब्रिटिश-भारत के बीच ही होगा।

कौसिल-हाउस मे वाइसराय तथा राजा-महाराजाओ के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछा दी गई। नरेंद्रमडल के अध्यक्ष, विशाल दाढी वाले महाराजा पटियाला और उनके छ फुटे शरीर के पास बौने से लगने वाले वी पी मेनन माउन्टबेटन का स्वागत करने के लिए प्रवेश-द्वार पर खडे हो गए। वी पी मेनन यहा प्रस्तावित रियासती-विभाग के मनोनीत मत्री के रूप मे उपस्थित थे। पटेल ने उन्हे माउन्टबेटन के हार्दिक अनुमोदन के साथ अपना बाया हाथ बनाना निश्चित किया था। उनका नया पद इस नई व्यवस्था मे निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

लगभग चालीस बडे राजा और उनके प्रतिनिधि विशेष परिचय के लिए पास के कमरे मे एकत्रित थे और करीब आधा दर्जन मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर अच्छी जगहो पर अड्डा जमाने के लिए उनके बीच बेतकल्लुफी से इधर-उधर भाग रहे थे। बेहद उमस थी और नवानगर के स्थूलकाय जामसाहब कमरे के एकमात्र पखे के नीचे हवा लेते हुए शिकायत कर रहे थे कि यह पखा कितने धीरे-धीरे घूम रहा है। सब मिलाकर पच्चीस बडे राजा और चौहत्तर रियासती प्रतिनिधि नरेंद्र-मडल के आदित्य-चन्द्राकार भवन मे उपस्थित थे।

जब माउन्टबेटन इस गौरवशाली समुदाय के सामने भाषण देने के लिए खडे हुए तो इस ऐतिहासिक सभा का चित्र लेने के लिए कुछ समय दिया गया। अपने चारो ओर फ्लैश बल्बो की चमक के समय माउन्टबेटन धीरज के साथ स्थिर रहे। इस मौके पर कुछ फोटोग्राफर उत्साह की सीमा पार गए और उनकी भागदौड से ऐसा लगता था कि मानो किसी मजाकिया फिल्म का दृश्य खीचा जा रहा हो। चूँकि भाषण बिलकुल गोपनीय था, इसलिए फोटोग्राफरो के जाने के पहले माउन्टबेटन उसे शुरू भी नही कर सकते थे। फलत, विवश होकर मुझे मच के नीचे मेनन के पास से उठकर उनको बाहर खदेडना पडा।

माउन्टबेटन पूरी पोशाक मे थे। इतने तमगे और पुरस्कार सीने पर लगे थे कि राजसी ठाठ के अभ्यस्त राजे भी चकित रह गए। आज भी वह किसी प्रकार के लिखे हुए सकेत देखे बिना बोले और एक जगह भी अटके या भटके नही।

अपने तरकस के सारे तीरो का उपयोग उन्होने यही समझाने और स्पष्ट

करने से किया कि वी पी मेनन ने जो सघ-प्रवेश-पत्र तैयार किया था वह कांग्रेस की ओर से दिया जाने वाला ऐसा राजनैतिक मौका है, जो फिर दोहराया नही जायगा। दरअसल तो यह अभी पक्का रुक्का नही है, और इसके पक्के होने की संभावना इसी बात पर निर्भर करती है कि वे इसकी सामूहिक स्वीकृति पटेल तक पहुचा सकते है या नही। उन्होने राजाओ को याद दिलाया कि पन्द्रह अगस्त के बाद वह ताज के प्रतिनिधि के रूप मे उनकी ओर से मध्यस्थता नही कर सकेगे। जो राजा अपने हथियारो के जखीरे बढाने की सोच रहे थे, उनको उन्होन चेतावनी देते हुए कहा कि उनको मिलनेवाले हथियार पुराने और बेकार होगे। उन्होने एक बात ऐसे मौके की और ऐसे बल के साथ कही कि राजाओ पर उसका वार खाली नही गया। उन्होने कहा कि अगर उन्होने सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तो उन्हे विश्वास कि औपनिवेशिक स्वराज्य के अन्तर्गत भी पटेल और कांग्रेस ब्रिटेन से उन्हे खिताब और सम्मान मिलने पर रोक नही लगावेगे। माउन्टबेटन जानते थे कि राजतन्त्र के समर्थक होने के कारण उनके लिए इन खिताबो का कितना मूल्य है। इस सबध मे राजाओ से बात करने मे उन्हे एक बडा सहारा यह रहा था कि वह ताज के प्रतिनिधि की हैसियत से ही नही, बल्कि ब्रिटेन के बादशाह के चचेरे भाई की हैसियत से भी बोल सके थे। इन पुश्तैनी राजाओ के लिए शाही खून का बडा मान है। उनके आज के सदेश का सार यह था, "जिस प्रकार आप उस प्रजा से जान बचा कर नही भाग सकते, जिसके कल्याण का दायित्व आपके ऊपर है, उसी प्रकार आप अपनी पडौसी औपनिवेशिक सरकार से भी नही भाग सकते।"

लेकिन, मेरे लिए, इससे अधिक उलझन वाली सभा की कल्पना करना असभव था, कि जिसमे माउन्टबेटन ने भाषण दिया। यह सभा तो ऐसे पुश्तैनी गडरियो की थी, जो अपनी भेडो को खोकर बडी दयनीय स्थिति मे पड गए थे। आज फिर मनोबल बढाने की अपनी क्षमता का माउन्टबेटन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अपनी स्वाभाविक स्फूर्ति और फैसले लेने की शक्ति का उन्होने न जाने कैसे राजाओं मे भी सचार कर दिया। जैसे ही माउन्टबेटन ने उनके पूछे आडे-टेढे प्रश्नो का उत्तर देना शुरू किया, गभीर रूपमे प्रारम्भ हुई इस सभा ने हसी-मजाक का रूप धारण कर लिया।

इस नाजुक घडी मे अपने राज्य और देश दोनो से ही अनुपस्थित एक महाराजा ने न तो स्वय इस बैठक मे आने की जरूरत समझी और न अपने दीवान को कोई ही आदेश देने की। दीवान को कोई आदेश प्राप्त नही हुआ था। माउन्टबेटन ने उनसे पूछा, "निश्चय ही आप अपने राजा के मन की बातो से तो परिचित ही है और उनकी ओर से फैसला कर सकते है?" बेचारे दीवान ने कहा, "मैं अपने राजा के मन की बात नही जानता और समुद्री तार से उत्तर भी नही मगवा सकता।" यह सुनकर माउन्टबेटन ने अपने सामने रखा हुआ शीशे का बडा-सा गोल पेपरवेट अपने

हाथ मे उठाते हुए कहा, "इस काच मे देखकर मै आपको ठीक उत्तर वता देता हू ।" फिर थोडी देर के नाटकीय मौन के वाद उन्होने गभीरता से कहा, "आपके महाराजा आपको सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे है।"

इस विशिष्ट-समुदाय की भावनाए उन्होने इतनी अच्छी तरह भाप ली थी कि इस विनोद पर सव लोग ठहाका मार कर हसे। उनका विनोद सचमुच सौजन्य-पूर्ण झिडकी भी था, और समयोचित सलाह भी। ऐसा लगता था कि उपस्थित समुदाय के दिमाग की अभेद्य दीवारो को वेधने के लिए विनोद का प्रयोग करना ही उचित था।

वाइसराय-भवन लौट कर मैने माउन्टवेटन को वतलाया कि उनके आज के काम की सभी पर गहरी छाप पडी है। मैने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमे पत्रो के लिए पूरे गोपनीय भाषण का काफी कटा-छटा रूप ही तैयार करना पडेगा, जिसे मै वी पी मेनन के साथ वैठकर तैयार किये लेता हू। माउन्टवेटन ने कहा कि मेनन और हम जो मसविदा तैयार करेगे वह उन्हे स्वीकार होगा। वह उसे दुवारा नही देखना चाहेगे। उनका विचार था कि आज उनसे जो प्रश्न पूछे गए थे इनके पीछे कोई वास्तविकता नही थी। वहुत कम राजाओ अथवा उनके प्रतिनिधियो को दुनिया की घटनाओ का कोई ज्ञान था। अगर वे सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर नही करेगे, तो वे खत्म हो जायगे।

फिर, उन्होने वी पी मेनन की तारीफ करते हुए कहा कि वह सचमुच ही मेनन को चाहने लगे है और मेनन के समान राजनीति-कुशल बुद्धिवाले व्यक्ति उन्होने कम देखे है।

इस मौके को माउन्टवेटन अपनी एक और व्यक्तिगत विजय मान सकते है। नेतृत्वहीन और कलहग्रस्त राजाओ ने अवसरवादिता और निर्णय-हीनता के पर्दे के पीछे मुह छिपाने की हरचन्द कोशिश की, लेकिन घटनाओ का प्रवाह इतना व्यापक और इतना तीव्र था कि रुकावट की उनकी चाले नही चल पाई। पहले की नीतियो के गुण-दोष चाहे जो रहे हो, लेकिन ताज के अतिम प्रतिनिधि के रूप मे आज माउन्टवेटन को जिस परिस्थिति से साविका पडा था, वह ऐसी थी कि केवल किसी प्रकार की मध्यस्थता के द्वारा ही इस असामयिक सामन्तवाद से पिड छुडाया जा सकता था।

नई दिल्ली, शनिवार, २६ जुलाई १९४७

कल रात माउन्टवेटन-दम्पति ने जिन्ना परिवार को जो दावत दी थी, उसके वारे मे जार्ज एवल के साथ मेरी एक मनोरजक वात हुई। दावत विल्कुल अनौपचारिक थी और वाइसराय भवन के मेहमानो और कर्मचारी-मडल के सदस्यो के अलावा कोई वाहरी लोग नही थे। खूब लम्वे और अधिकाश विनोदहीन मजाक

करके जिन्ना बातचीत पर एकाधिकार जमा बैठे। जब माउन्टबेटन ने जिन्ना को लेडी माउन्टबेटन से बाते करने के लिए छोडकर अपने पास बैठे मेहमानो से बात करके चर्चा को सतुलित करने का प्रयास किया तो जिन्ना सहसा रुके और फिर मेज के उस ओर से चिल्लाकर बोले, "मेरा खयाल है, माउन्टबेटन इस मजाक को सुनना चाहेगे।" प्रथा के अनुसार राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला वाइसराय भोजन करने के कमरे मे आने और जाने मे सबमे आगे रहता है। लेकिन इस दावत के खत्म होते ही जिन्ना भी माउन्टबेटन के साथ उठ खडे हुए और उन्हीके साथ-साथ बाहर गए।

जार्ज ने बतलाया कि दावत के बाद उन्होने इस भावना से कि मै तो पन्द्रह अगस्त को जा ही रहा हू, जिन्ना को सिखो के प्रश्न पर खूब आडे हाथो लिया। जार्ज ने कहा कि पश्चिमी-पजाब की सीमा के पास वाले इलाको मे निहायत अयोग्य आदमी नियुक्त किये जा रहे है। जिन्ना ने बुरा नही माना और इतना ही कहा कि अपने लोगो की वह नस-नस पहचानते है। वह जरा तैश मे आ गए जब जार्ज ने कहा कि असली दिक्कत यह है कि जिन्ना की योग्यता के लोग एक साथ सब जगह तो मौजूद हो नहीं सकते और इसमे कोई शक नही कि जिन्ना उन लोगो को देखने नही गये है कि जिनकी आलोचना की जा रही है। जार्ज का खयाल था कि सिखो के बारे मे जिन्ना का रुख निहायत खतरनाक है।

नई दिल्ली, रविवार, २७ जुलाई १९४७

आज फिर माउन्टबेटन ने मुझे मिलने बुलाया। उन्होने मुझे एक घटना का हाल सुनाया जो आज तो विचित्रसी लगती है, पर उस समय गभीर शक्ल भी ले सकती थी। उन्होने लार्ड किल्लर्न को सिगापुर से बुलवाया था और उनके साथ इस सभावना पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि क्या वह पूर्वी-बगाल का गवर्नर-पद सभाल सकेगे? यह इसलिए, क्योकि जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान की इस चौकी को कोई ऊची योग्यता वाला ब्रिटिश-शासक सभाले। जब वह नौकरी की शर्तो पर विचार कर रहे थे तब लार्ड किल्लर्न ने पूछा कि क्या दार्जिलिग के पाकिस्तान मे शामिल होने की कोई सभावना है? अगर यह नही, तो क्या यह व्यवस्था करना मुमकिन होगा कि बहुत गरम मौसम को वह आसाम के किसी पहाडी मुकाम, जैसे शिलाग, मे बिता सके? उन्होने कहा कि अब वह छियासठ वर्ष के हो आए है, उनके कई छोटे-छोटे बच्चे है और वह पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की गरमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगे। इसके अलावा, उन्हे जानकारी मिली है कि ढाका मे गर्वनर का प्रस्तावित-निवास बहुत ही खस्ता हालत मे है। माउन्टबेटन ने इस विषय में पता लगाने का वादा किया।

सयोगवश इसके बाद ही उनकी मुलाकात हुई आसाम के प्रधान-मत्री बार्दोलोई से। आसाम के बारे मे कुछ मामूली कामो को चन्द मिनटो मे निबटाने के बाद उन्होने बार्दोलोई से ढाका के बारे मे पूछा। क्या वहा कोई पहाडी जगह है? बार्दोलोई ने कहा कि पूरे इलाके मे ग्यारह सौ फुट से ऊची कोई जगह नही है। फिर माउन्टबेटन ने दार्जिलिग के बारे मे पूछा। सीमा-आयोग द्वारा उसके किधर दिये जाने की सभावना है, पाकिस्तान को या भारत को? बार्दोलोई ने कहा कि उसका भारत मे रहना निश्चित है। इसके बाद माउन्टबेटन ने शिलाग और आसाम के पहाडी क्षेत्रो के बारे मे भी पूछताछ की।

बार्दोलोई इस पूछताछ के उद्देश्य को बिलकुल गलत समझ बैठे और बडी घबराई हुई हालत मे गाधीजी के पास पहुचे। शिकायत की कि दार्जिलिग, शिलाग और पहाडी क्षेत्रो को पाकिस्तान मे शामिल करने के लिए भयकर षड्यन्त्र रचा जा रहा है। गाधीजी ने कहा कि इसमे शक नही कि अग्रेज ऐसी धोखाधडी करने की सामर्थ्य रखते है लेकिन वह यह विश्वास नही कर सकते कि माउन्टबेटन ऐसे किसी काम मे हाथ बटाएगे। इसके बाद बार्दोलोई पटेल के पास गये और पटेल इस प्रश्न को लेकर काफी फिक्र मे पड गए। फलस्वरूप, आज सवेरे वी पी मेनन परेशान-से माउन्टबेटन के सोने के कमरे मे आये।

माउन्टबेटन को पूरी बात का खुलासा करते देर नही लगी। उन्हे उम्मीद थी कि एकाध दिन मे इस प्रश्न पर वह काग्रेसी नेताओ से हसी-मजाक भी कर सकेगे। लेकिन वह इस घटना को बडा उद्बोधक भी मानते थे, क्योकि यह मामूली-सी गलतफहमी बडे भारी सकट का रूप भी ले सकती थी।

नई दिल्ली, सोमवार, २८ जुलाई १९४७

आज रात लगभग पचास से ऊपर राजाओ और करीब सौ रियासती प्रतिनिधियो के सम्मान मे वाइसराय भवन मे एक शानदार समारोह हुआ। समारोह का ठाटबाट उस अयथार्थता और वेदना को ही बल देने वाला था, जो आज राजाओ को घेरे हुए थी। आज जब कि उद्देश्य की एकता का सवाल उनके लिए सबसे अधिक महत्व का होना चाहिए था, वे बेचैनी के साथ इन समस्याओ मे डूबे हुए थे कि कौन किससे बडा है? हर एक का ध्यान इसी ओर था कि दूसरा क्या कर रहा है, और जैसा कि एक दीवान ने कहा, "वह बैरग लिफाफे के समान भटक रहे थे।"

जिन श्रीमन्तो ने अभी तक सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जाहिर नही की थी, उनको एक-एक कर ए डी सी मित्रतापूर्ण बातचीत के लिए माउन्ट-बेटन के पास ले जाने लगे। माउन्टबेटन उनको सबके सामने वी पी मेनन के हवाले

कर देते और मेनन उन्हे पटेल के पास पहुचा आते। तीन-तीन की कतार मे अर्द्ध-चन्द्राकार खडे हुए राजालोग यह कार्यवाही देख रहे थे।

एक खुर्राट राजा ने टिप्पणी की, "माउन्टबेटन अब किस पर डोरे डाल रहे है?" गर्दन आगे बढा कर देखने का प्रयास करते हुए उन्होने बडे मजे से कहा, "उन्हे मेरे ऊपर डोरे डालने की जरूरत नही। मै कल हस्ताक्षर कर रहा हू।" फे ने एक बूढे और एक तरुण राजा के बीच यह बातचीत होते सुनी बूढे राजा ने पूछा, "आपकी रियासत मे कैसी स्थिति है?" तरुण राजा ने उत्तर दिया, "हमारे यहा एक जगह (जगह का नाम बतलाया) स्थिति ठीक नही थी, लेकिन अब समझौता हो गया है।" इस पर बूढे राजा ने कहा, "हमारे यहा हर जगह स्थिति खराब है, लेकिन मै उसे समझौते की सीमा तक नही पहुचने देता।"

नई दिल्ली, बुधवार, ३० जुलाई १९४७

पौ फटते ही माउन्टबेटन कलकत्ता के लिए रवाना हो गए, जहा की गभीर स्थिति का वह तत्काल परीक्षण करेगे। बडी रात गये फोन पर उन्होने मुझसे पत्रो सबधी कुछ मामूली समस्याओ को सुलझाने के लिए कहा, मानो सत्ता-हस्तातरण का काम उन्हीके सुलझाये जाने पर निर्भर करता हो! बडी बातो पर वह कभी दुराग्रह नही करते, उन्हे परेशानी करती थी छोटी बाते, जो कर्मचारियो का नाको दम कर डालती थी, अगर उनका काम करना हो और उनके दल का सदस्य बने रहना हो तो उन्हे इन छोटी समस्याओ से दूर रखना ही श्रेयस्कर था। लेकिन जब आपका ध्यान दूसरी ओर हो तो वह एकाध ऐसी समस्या कही-न-कही से पकड ही लाते थे।

उनकी गैरहाजिरी से मिले इस छोटे से विश्राम का उपयोग मैने गाधीजी से भेट करने मे किया। इसके लिए मैने बहुत दिनो से वादा किया हुआ था। उनसे मिलने मै दोपहर को भगी बस्ती पहुच गया। गत मई मे, जब मै शिमला मे राजकुमारी अमृतकौर से मिला था, तबसे वह यह मुलाकात जमाने की कोशिश करती आ रही थी।

दिल्ली मे अपने रहने के लिए भगी बस्ती का चुनाव करना वास्तव मे गाधीजी का एक बडा सकेतात्मक काम है। लेकिन वैरागीपन की भी अपनी प्रशासनिक समस्याए होती ही है। मेरा खयाल है, शायद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक बार भगी बस्ती के बारे मे कहा था, "काश, बापू जानते कि उन्हे गरीबी मे रखना कितना खर्चीला होता है!" उनके इर्द-गिर्द यहा जो गरीबी है, बिल्कुल वास्तविक है। बस्ती उस ऊजर भूमि पर स्थित है जो दिल्ली को घेरे हुए है, और उसकी पृष्ठ-भूमि कठोर चट्टानो और भूरी मिट्टी से अटी हुई है।

दो काफी भद्दे पहरेदारो ने मुझसे मेरा नाम-पता पूछा और मुझे एक सेक्रेटरी के पास पहुचा दिया। इन सज्जन ने जो निर्देश दिये उनसे कुछ पता ही नही चलता था कि मुझे किधर जाना चाहिए। इतने मे एक दूसरे सेक्रेटरी दिखलाई पडे और वह मुझे एक खाली कमरे मे ले गए। मुझे बाद मे बताया गया कि गाधीजी वहा सोते और काम करते है। मैने उन्हे चबूतरे पर तकियो के सहारे बैठे हुए पाया। हमारी मुलाकात के बीच दो सेक्रेटरी चुपचाप अन्दर आये और चतुर अनुयायियो की भाति अपना काम करने लगे।

जैसे ही मै अन्दर दाखिल हुआ, गाधीजी ने हसते हुए कहा, "आप मुझसे खडे होने की आशा तो नही करेगे ?" मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। लेकिन मैने उनके सामने पालथी मारकर बैठना पसन्द किया। मैने उन्हे याद दिलाई, "आपसे पहली बार मिलने का सौभाग्य मुझे आज से सत्रह वर्ष पूर्व हुआ था, जब मै बालक था और वेस्टमिन्स्टर स्कूल मे पढता था। आप अचानक हमारे सामने भाषण देने आये थे और हम सब पर इस घटना की गहरी छाप पडी थी।" उन्होने कहा कि यह घटना उन्हे थोडी-थोडी याद है—शायद किसी भले ईसाई पादरी ने उन्हे वहा आमत्रित किया था। मैने बतलाया कि उनके आने के दो दिन बाद लार्ड हैलीफेक्स भी हमारे सामने भाषण देने आये थे। गाधी-इर्विन समझौते के उस साल की सबसे याद रहने-वाली बात यह थी कि दोनो ने एक दूसरे के बारे मे कितने सौहार्द से बात की थी। दोनो ने हमारे शिशु-हृदयो पर यह छाप छोडी थी कि यह मानवता-भरी सद्भावना ही सच्चे समझौते को जन्म दे सकती है।" उन दिनो मै लार्ड हैलीफेक्स के बहुत निकट था", गाधीजी ने बीते दिनो को याद करते हुए कहा, "लेकिन इसका मतलब यह नही कि आज नजदीक नही हू।"

मैने कहा कि मै अभी-अभी लन्दन से लौटा हू, जहा मैने भारतीय स्वतत्रता-अधिनियम को ससद् के दोनो सदनो से गुजरते हुए देखा था। इस विषय मे हुई बहस की रिपोर्ट की तीन प्रतिया भी मैने उन्हे भेट की, जिससे उन्हे खुशी हुई। लार्ड-सभा मे लार्ड सेम्युअल ने उनकी जो प्रशसा की थी, उसकी ओर मैने उनका विशेष ध्यान खीचा। कहा कि यह उन्होने देख लिया था और यह लार्ड सेम्युअल की कृपा है कि उन्होने ऐसे शब्द कहे। एक बार उनका लार्ड सेम्युअल के साथ किसी विषय पर पत्र-व्यवहार हुआ था और उसमे चले तर्क मे लार्ड सेम्युअल ने अपनी गलती मानने की उदारता दिखलाई थी। गाधीजीने कहा कि यह व्यक्ति के बडप्पन का लक्षण होता है।

स्वतन्त्रता-अधिनियम से पैदा हुई आम स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि ब्रिटिश-सत्ता के समाप्त होने से काग्रेसी नेताओ के कन्धो पर भारी उत्तर-दायित्व आ पडा है। अबतक तो ये लोग केवल चद लाखो रुपयो से ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब राज्य के विशाल साधन उनके हाथो मे आ गए है। दोनो

सरकारो को समय की जरूरत है—सास लेने के मौके की, जिसमे वे अपने पाये मजबूत बना सके। वह विभाजन को एक बुराई समझते है, लेकिन यह मानने को तैयार थे कि अगर दोनो सरकारे एक-दूसरे के साथ न्याय का व्यवहार करे तो इस अशुभ से शुभ परिणाम भी निकल सकता है। मैने कहा कि भारत ही नही, समूचे एशिया का भाग्य दाव पर है। खास तौर से दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश भारत की ओर आखे लगाये है और चीन के गृह-युद्ध ने भारत के महत्व को और भी बढा दिया है। उन्होने हार्दिक स्वीकृति जतलाते हुए कहा, "सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत कसौटी पर है।"

फिर यहा के अपने खास काम—समाचारपत्रो—की चर्चा करते हुए मैने कहा कि भारतीय पत्रो को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भारतीय पत्रकारो को विदेश जाकर नये अनुभव प्राप्त करने चाहिए। उन्होने मजर किया कि इसकी जरूरत है, लेकिन इस मान्यता ने उन्हे अपने प्रिय विषय पर पहुचा दिया। उन्होने कहा, "भारतीयो मे अपने निराकारण के लिए दूसरो का मुह ताकने की खतरनाक प्रवृत्ति है। अपने आत्म-सम्मान की रक्षा कर हमे स्वय अपनी मदद करनी चाहिए। दवाओ और डाक्टरो की ही बात लीजिये। म एक भी ऐसे अग्रेज की बात नही जानता जो इलाज के लिए भारत आया हो। लेकिन इस या उस प्रसिद्ध यूरोपीय सर्जन से इलाज करवाने के लिए भारतीयो के विदेश जाने की बात हम बराबर सुनते रहते ह। यह ठीक नही है कि भारत को भारतीयो के मरने की ही जगह माना जाय। हमारे यहा काफी योग्य सर्जन है, जैसे डाक्टर अन्सारी थे।"

उनके तर्क का सार यह था चूकि भारत ने अब अपनी राजनैतिक स्वाधीनता पा ली है, इसलिए भारतीयो का कर्त्तव्य यह है कि शब्दो नही, कर्मो के द्वारा देश के प्रति अपने विश्वास और गर्व का परिचय दे। वह यह समझे कि जो-सुविधा के साधन उन्हे विरासत मे मिले है वे बाहरी दुनिया की चीज है और हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य नही है। भारतीय स्वाधीनता की यह असली चुनौती है।

प्रदर्शित करने के बाद वे राजा-लोग वाइसराय के ए डी सी लोगो के पजे मे फस गए, जिन्होने सघ-प्रवेश-पत्र के बारे मे उनके मत के अनुसार उन्हे "हा" और "नही" की कतारो मे खडा कर दिया। पटियाला और बीकानेर 'नही' की कतार मे खडे हो गए और खूब हसे। इससे विनोद का वातावरण और भी गाढा हो गया।

हैदराबाद और काश्मीर को छोड कर, जिनकी विशेष समस्याये है, अन्य सब पर माउन्टबेटन की सलाह का असर हुआ। केवल दो या तीन ही बडे नरेश यह समझते है कि सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर न करने से लाभ होगा। दुर्भाग्यवश माउन्टबेटन के मित्र, भोपाल-नरेश, इस दल के अगुआ है, और उसमे भोपाल के निकट और महत्वपूर्ण पडोसी महाराज इन्दौर भी शामिल है। सबमे योग्य मुसलमान नरेश होने के नाते मै खयाल करता हू कि वह पाकिस्तान की उच्च-स्तर की राजनीति मे महत्वपूर्ण भाग लेने मे सकोच नही करेगे। कुछ दिनो तक वह जिन्ना के निकटतम सलाहकार भी रहे थे। उनके लिए अभाग्य की बात यह है कि उनकी रियासत की अधिकाश आबादी हिन्दू है और वह भारत के मध्य मे स्थित है।

•

नई दिल्ली, रविवार, ३ अगस्त १९४७

माउन्टबेटन उन नरेशो से मुलाकात करने के लिए जी-तोड कोशिश कर रहे है, जिनके सामने सघ-प्रवेश का प्रश्न विशेष समस्याए पैदा कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे अन्तिम घडी नजदीक आ रही है, जिम्मेदारिया और फैसले लेने का काम बढता जा रहा है। इसलिए धौलपुर के महाराज राणा से व्यक्तिगत और गैर-सरकारी रूप से सम्पर्क स्थापित करने का काम उन्होने मुझे सौप दिया। महाराज राणा ब्रिटेन के युवराज की १९२१ मे भारत-यात्रा के समय से उनके मित्र है। उस समय दोनो युवराज के ए डी सी. थे।

उनके साथ अपनी लम्बी बातचीत के आधार पर मै यह कह सकता हू कि वह बडे विद्यानुरागी, पाण्डित्यपूर्ण और साधु-वृत्ति के व्यक्ति है। राजाओ के दैवी-अधिकारो मे उनका गहरा विश्वास है। ब्रिटिशराज के साथ अपने दर्जे और अपनी जनता के साथ अपने सम्बन्धो के बारे मे उनकी धारणाए बडी ही रहस्यमयी हैं। अपने विशेषाधिकारो के बारे मे बेहद ऊचे खयालो के बावजूद अपने व्यवहार और पहरावे मे वह बहुत सरल है। वह काफी ठिगने व्यक्ति है, गाधीजी से ज्यादा ऊचे नही। वह गुलाबी साफा बाधे थे और बहुत चिंतित नजर आते थे।

ब्रिटेन के साथ अपनी सन्धि के समाप्त होने के बारे मे उन्होने बडी भावुकता के साथ धीमे-धीमे चर्चा की। उनकी आवाज मे नाराजी नही, आत्म-समर्पण था। भाग्यवादियो मे पाई जानेवाली खिन्नता उनमे भरी हुई थी। ऐसे व्यक्ति के साथ यह तर्क काफी नही कि उसका हित कैसे सध सकता है। मूलत वह यह सहानुभूति

और आश्वासन चाहते थे कि वह जो कुछ करेगे, उसे उचित माना जायगा। अपने दिल मे उनको जरा भी उम्मीद नही थी कि नया भारतीय-उपनिवेश जिन्दा रह सकेगा। थोडे ही दिन पूर्व की क्रान्तिकारी स्थितियो मे ब्रिटेन के साथ १७६५ मे हुई सार्वभौमिकता की सन्धि की वह अपने शासन काल की लम्बी और स्वामिभक्ति-पूर्ण परम्पराओ के साथ तुलना करते थे। ऐसे भावुक और ईमानदार व्यक्ति को ऐसी दुविधा मे पडे देखकर बडी वेदना होती थी। स्वाधीनता का तूफान इस तेजी से चल रहा था कि वह कुछ भी समझने मे असमर्थ थे। अगर उनकी चेतना इतनी प्रबल न होती तो शायद वह एक तरफ हट जाना पसन्द करते।

जैसे-जैसे सत्ता-हस्तातरण का दिन नजदीक आ रहा था, माउन्टबेटन ओर उनके अमले पर पडनेवाले काम का बोझ बढ रहा था। मेरे ऊपर जन-सम्पर्क ओर पत्रो सम्बन्धी समस्याओं का इतना काम आ पडा था कि पूरा केन्द्रीय सूचना-कार्यालय उसे निबटाने मे व्यस्त रहता था। कराची और दिल्ली मे होने वाले समारोहो की बडे सोच-विचार के साथ योजना तैयार की जा रही थी। जिन्ना ने एक बडा पेचीदा सवाल खडा कर दिया था। कराची मे १३ अगस्त के समारोहो के अवसर पर माउन्टबेटन को क्या प्राथमिकता दी जाय? काफी दृढता के साथ पर बडे सरल शब्दो मे उन्हे बतला दिया गया था कि माउन्टबेटन इस समारोह मे वाइसराय के नाते भाग लेगे। ओर उनसे यह भी कह दिया गया था कि यह सुझाव बिलकुल निरर्थक होगा कि विधान-सभा की विशेष बैठक मे वह जिन्ना के नीचे बैठे।

मेरी जिम्मेदारियो मे ये काम भी शामिल है दोनो उपनिवेशो को भेजे जाने के लिए ब्रिटेन के राजा के सन्देशो का मसविदा तैयार करना। दोनो देशो की विधान-सभाओ को दिये जानेवाले माउन्टबेटन के भाषणो को ठीक-ठाक कर देना।

नई दिल्ली मगलवार, ५ अगस्त, १९४७

पटेल इस कार्रवाई के बिलकुल खिलाफ थे। उनका तर्क था कि इससे वह स्थिति और भी भयकर रूप ले लेगी, जो आज भी हमारे नियत्रण के बाहर है।

माउन्टबेटन ने कहा कि एक शर्त पर वह इन गिरफ्तारियो का समर्थन करने को तैयार है। स्थानीय अधिकारी इसे ठीक समझे तो। इसलिए माउन्टबेटन ने जनकिन्स को लिख भेजा कि पूर्वी और पश्चिमी पजाव के मनोनीत गवर्नरो, त्रिवेदी और मूडी, से चर्चा करे कि १५ अगस्त के पहले तारासिह और उनके अन्य सिर-फिरे साथियो को गिरफ्तार करना ठीक होगा या नही।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, ७ अगस्त १९४७

हमारे जीवन मे विनोद के क्षण भी आते है। वाइसराय के कर्मचारी मडल की अडसठवी बैठक का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ पहला विषय ज्योतिष। वाइसराय ने कहा कि उन्होने मध्यप्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री मगलदास पकवासा को यह सुझाया था कि आप १४ अगस्त की वजाय १३ अगस्त को ही अपना कार्यभार सभाल ले, जिससे सर फ्रेडरिक वोर्न पूर्वी-वगाल के राज्यपाल का पद १५ अगस्त को सभाल सके। पकवासा ने कहा कि ज्योतिष के अनुसार यह सभव नही हो सकता। वाइसराय ने कहा कि मेरे कर्मचारियो मे ज्योतिष-विषयक सलाह देने वालो का अभाव है। इसका इलाज तुरन्त ही यह घोषणा करके किया गया, "वाइसराय महोदय ने गवर्नर-जनरल के अवैतनिक ज्योतिषी-पद के लिए अपने 'प्रेस एटेची' की नियुक्ति की।"

इसके वाद मै पकवासा से मिला। पटेल ने उन्हे एक दावत दी थी और उसमे मै और फे भी निमत्रित थे। यह अवसर अनौपचारिक था। पकवासा और हम दोनो के अतिरिक्त केवल एक अतिथि और थे—मि डल नाम के एक अमरीकी सज्जन। पटेल के निजी सेक्रेटरी शकर, जो आक्सफोर्ड मे मेरे सहपाठी थे, तथा सरदार की पुत्री और अनन्य सेविका मणिबेन को मिला कर हम लोग कुल सात व्यक्ति थे। पटेल का घर नेहरू के घर के बिलकुल पडोस मे है तथा शान-शौकत और लम्बाई-चौडाई मे उससे बहुत कम है।

सत्ता-हस्तान्तरण के वाद नेहरू और पटेल भारत की बागडोर सभालेगे, और दोनो मे अन्तर बतलाना स्वाभाविक बात है। दोनो की व्यक्तिगत और बाहरी आकृति मे भी कम अन्तर नही है। धोती मे सज्जित पटेल चोगा पहने हुए रोमन-सम्राट् का स्मरण कराते है। सच पूछिए तो इस पुरुष मे काफी रोमन विशेषताए है—प्रशासनिक योग्यता, कठोर निर्णय करने और निभाने की क्षमता तथा चरित्र-बल के साथ पाई जाने वाली सौम्यता। पर नेहरू के समान विश्व-ख्याति और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उनमे अभाव है। उन्होने जान-बूझकर अपने-

आपको आन्तरिक राजनीति की समस्याओ तक ही सीमित रखा है। इस क्षेत्र मे उनकी शक्ति और जिम्मेदारिया काफी व्यापक है। इनके अन्तर्गत सरकारी सूचना-विभाग, आन्तरिक सुरक्षा, पुलिस तथा भारतीय रियासती मामले शामिल है। जब उनकी सघ-प्रवेश-सबधी नीति पर पूरा अमल हो जायगा तो पाकिस्तान बनने से भारत को जितने नागरिको की हानि होगी, उससे कही अधिक नागरिक उसमे शामिल हो जायगे, क्योकि इससे हैदराबाद और काश्मीर की दो करोड जनसख्या के अतिरिक्त ९ करोड रियासती जनता भारत मे मिल जायगी, जो पाकिस्तान की आबादी से कही अधिक है। पटेल के हाथ मे ही काग्रेस की सारी बागडोर है। किसी भी देश मे एक व्यक्ति के हाथ मे सत्ता का इतना केन्द्रीकरण होना मामूली बात नही है। इस व्यस्तता के बावजूद पटेल ससार मे भारत की स्थिति को बडी अच्छी तरह जानते है।

जब पटेल राज-काज के मामलो मे नही लगे रहते तब वह एक विनम्र हिन्दू का आदर्श रूप उपस्थित करते है। औदार्य और स्मित के तो वह भडार है। मैने भारतीय-स्वतन्त्रता-अधिनियम के लदन मे पास होने का हाल उन्हे बताया, जिसे उन्होने दिलचस्पी से सुना। बातचीत के दौरान मे भाषण देने की बात भी उठी। जब मैने उनसे पूछा कि क्या आपको भाषण देना अच्छा लगता है, तब वह और मणिबेन हस पडे। मणिबेन ने मुझे बताया कि उनके पिता गुजराती के एक महान् वक्ता है।

भोजन के अधिकाश समय मणिबेन मौन रही। वह सरदार की सभी गोपनीय एव सरकारी हलचलो मे उनकी विश्वास-पात्र है। तपस्विनी की भाति खादी की साडी पहने हुए तथा कमर मे चाबियो का गुच्छा खोसे, वह सरदार की गृहस्थी की सुयोग्य एव दत्तचित्त सचालिका जान पडती है।

प्राय सभी भारतीय नेता अपने परिवार की महिलाओ से घिरे रहते है—चाहे वे पत्नी हो या पुत्री या बहन। नेताओ के जीवन पर उनका बडा प्रभाव है। मै यह खयाल लेकर भारत आया था कि भारतीय स्त्रिया बाहर नही आती और राजकीय मामलो मे उनकी कोई आवाज या अभिरुचि नही है। किन्तु ऊचे वर्गो मे यह बात नही है। मिस फातिमा जिन्ना, श्रीमती विजयालक्ष्मी पडित, बेगम लियाकतअलीखा और श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली स्त्रिया है, जिनकी महत्त्वाकाक्षाए और रुचिया अपने सबधित पुरुषो से कुछ कम नही। उनमे से सभी मणिबेन की तरह पृष्ठभूमि मे रहना पसन्द नही करेगी, किन्तु अपने पिता पर जितना उनका असर है शायद ही उतना किसी और का अपने घरो मे हो।

लेडी माउन्टबेटन समाज-सेवा के क्षेत्र मे भारतीय स्त्रियो के सम्पर्क मे आकर बडी प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र मे उनकी योग्यता ही बढी-चढी नही है प्रत्युत वे अपने बन्धनो को भी तोड रही है। भारतीय महिलाओ की मुक्ति भारतीय

स्वाधीनता-सग्राम का एक महत्वपूर्ण अग है। इस समय लेडी माउन्टबेटन के नेतृत्व मे इस मुक्ति-आन्दोलन को और भी गति मिल रही है।

नई दिल्ली, शनिवार ९ अगस्त १९४७

आज भी कर्मचारी मडल की बैठक मे हमने पजाव के सकट पर विस्तार से चर्चा की। सीमा-प्रदेश की निहायत गभीर स्थिति की रिपोर्ट भेजने के साथ ही जेनकिन्स ने सेना, हवाई फौज और पुलिस की कुमुक जल्दी भेजे जानेकी माग की है। इसके अतिरिक्त, जनसम्पर्क का विशाल काम भी माउन्टबेटन के सामने है जिस पर लोगो मे मनोबल और व्यवस्था कायम रखना निर्भर करता है।

सुनने मे आया है कि रेडक्लिफ आज शाम तक पजाव सीमा आयोग का फैसला वाइसराय को दे देंगे। उनके हिन्दू और मुसलमान सहयोगियो मे प्रत्याशित असहमति के कारण रेडक्लिफ को सारे फैसले अपने ही बूते पर करने पडे है। लेकिन प्रकाशन का दायित्व जरूर वाइसराय पर है। शुरू से ही माउन्टबेटन ने अपने कर्मचारियो को स्पप्ट आदेश दे दिये थे कि जबतक रेडक्लिफ मध्यस्थता के कठिन और नाजुक काम मे लगे है, तबतक उनसे कोई सम्बन्ध न रखे जाय। वह खुद भी उनसे दूर ही रहे। इसलिए हमे ठीक-ठीक पता न था कि रेडक्लिफ ने कितनी मजिल पार कर ली है और किस रास्ते से आगे बढ रहे है।

फैसले के प्रकाशन के बारे मे कई सुझाव आये। प्रशासनिक दृष्टि से यह तर्क दिया गया कि उसका ऐलान जल्दी होने से जेनकिन्स को मदद मिलेगी और सत्ता-हस्तातरण के पहले सेनाए सकट-ग्रस्त इलाको मे भेजी जा सकेगी। दूसरा सुझाव यह था कि चूँकि इन फैसलो से अशान्ति फैलना सुनिश्चित है, इसलिए इनके प्रकाशन की सबमे उचित तिथि १४ अगस्त होगी। माउन्टबेटन ने कहा कि यदि इस बारे मे उनकी कुछ भी चले तो वह इसका प्रकाश स्वाधीनता-दिवस के समारोहो के वाद तक के लिए मुल्तवी कर देगे। उनकी धारणा थी कि प्रकाशन के समय का प्रश्न वास्तव मे मनोवैज्ञानिक है। वह नही चाहते कि इसके प्रकाशन से जो विवाद और विषाद पैदा होनेवाला था उससे दोनो देशो के स्वाधीनता-दिवसो का उत्साह भग होने दिया जाय।

इस राय से मै विलकुल सहमत हू। मै तो यहा तक कहता हू कि रैडक्लिफ-फैसले को स्वतन्त्रता-समारोह के पहले या उसी दिन प्रकाशित करना हिन्दू, मुसलमान और सिखो को मिलने वाली स्वतन्त्रता के महत्व को ही नष्ट करना होगा। एक भारतीय की मित्रता जितनी सरलता से पाई जा सकती है, उतनी ही सरलता से खोई भी जा सकती है। उसकी आशाओ तथा उसके वातावरण के कारण उसके सुख और दुख के बीच कोई ज्यादा दूरी नही रहती। उसके आनन्द की शर्त यह है कि

वह आनन्द अनियन्त्रित हो और अपने शाश्वत भयो से अस्थायी छुटकारा मिले।

आज की बैठक मे इसके बारे मे कोई अन्तिम निश्चय नही किया गया। वाइसराय के निजी सेक्रेटरी एबेल को आदेश दिया गया कि वह प्रकाशन के समय के विषय मे जेनकिन्स के साथ भी चर्चा कर ले। सीमा-आयोग के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्पष्ट करने के लिए माउन्टबेटन ने यह निश्चय किया कि उसकी घोषणा वाइसराय भवन की विज्ञप्ति के रूप मे न की जाकर 'असाधारण गजट' के रूप मे हो।

जेनकिन्स ने इस सुझाव को ठुकरा दिया है कि सिख-नेताओ को १५ अगस्त के पहले गिरफ्तार कर लिया जाय। उन्होने माउन्टबेटन को बतलाया कि उन्होने इस विषय की चर्चा मूडी और त्रिवेदी से कर ली है ओर वे भी एकमत है कि ऐसी कार्रवाई से परिस्थिति बिगड जायगी। इसलिए तीनो ने यह निश्चय किया कि कोई गिरफ्तारिया न की जाय।

: १३ :

पाक-भारत में स्वाधीनता-दिवस

सरकारी भवन, कराची, बुधवार, १३ अगस्त १९४७

माउन्टबेटन संयुक्त ब्रिटिश भारत के वाइसराय की हैसियत से अपने अंतिम कर्तव्य का पालन करने के लिए आज प्रातःकाल दिल्ली से कराची के लिए रवाना हुए। यह कर्तव्य है नये पाकिस्तानी उपनिवेश के जन्म के समय, राजा की तथा अपनी शुभ-कामनाएं व्यक्त करना।

जब हम वायुयान से उतरे तो सिन्ध के मनोनीत गवर्नर हिदायतउल्ला ने माउन्टबेटन-दम्पत्ति का स्वागत किया। फोटोग्राफरो का समुदाय भी बदस्तूर मौजूद था। सरकारी भवन को जाते समय जिन्ना के सैनिक सेक्रेटरी कर्नल बर्नी ने माउन्टबेटन से कहा कि उन्हे कल के जुलूस मे जिन्ना के ऊपर बम फेकने के एक षड्यन्त्र की सूचना मिली है। इसलिए विचार यह चल रहा है कि जुलूस ही रद्द कर दिया जाय या सिर्फ रास्ता बदला जाय। जिन्ना ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि माउन्टबेटन जुलूस मे रहने को तैयार है, तो मै भी तैयार हू। माउन्ट-बेटन तुरन्त सहमत हो गए कि कार्यक्रम मे कोई परिवर्तन न किया जाय।

जिन्ना और मिस जिन्ना बडे कमरे के प्रवेश-द्वार पर माउन्टबेटन-दम्पति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरा हालीवुड मे फिल्म सेट के सेट की भाति सजा हुआ

था। चारो ओर बड-बड लैंपो के चौधिया देनेवाले प्रकाश और झुलसा देने-वाली गर्मी के नीचे खडे रह कर बारबार फोटो खिंचवाने की अग्नि-परीक्षा देनी पडी।

मैंने पलेस होटल मे सरकारी सूचना-अधिकारी कर्नल मलिक से सम्पर्क स्थापित किया और कुछ विदेशी सवाददाताओ से भेट की, जो कराची के अबतक के आयोजनो के कडे आलोचक थे। कुछ का कहना था कि जिन्ना ने माउन्टबेटन के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित न रह कर उनका अपमान किया है। परन्तु मैंने तुरन्त कहा कि माउन्टबेटन यह नही मानते कि शिष्टाचार का कोई अभाव रहा है या उसका कोई उल्लघन हुआ है।

उन्होने बतलाया कि कल सविधान-सभा की बैठक मे जिन्ना के प्रति पूर्ण दासता की भावना का वातावरण था। प्रत्येक व्यक्ति कायदे-आजम के सामने जबानी आत्म-समर्पण करने मे एक-दूसरे से होड लगाये हुआ था।

मेरी उत्सुक पूछताछ के उत्तर मे मलिक ने बताया कि आज रात के भोज मे जिन्ना प्रकाशन के लिए कोई निश्चित भाषण करने का विचार नही कर रहे है। इसकी सूचना मैने माउन्टबेटन को दे दी। परन्तु मरे आश्चर्य की सीमा न रही जब भोज के अत मे मैने देखा कि जिन्ना बडे आदमियो के उस समुदाय मे, जिसमे न केवल पाकिस्तान के प्रमुख लोग वरन् कूटनीतिक मडलो के सदस्य भी उपस्थित थे, खडे हुए और अपना चश्मा सवार कर कृत्रिम-स्वर मे एक लिखित-भाषण पढने लगे। वह भाषण भारी राजनैतिक महत्व का निकला, क्योकि उसमे ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान के भावी-सबधो के बारे मे आत्मीयतापूर्ण विचार प्रकट किये गए थे और पाकिस्तान के निर्माण मे माउन्टबेटन के योग की चर्चा की गई थी।

यदि माउन्टबेटन को इस प्रकार अचानक भाषण के व्यूह मे फसने के कारण कोई घबराहट हुई हो तो उन्होने उसे व्यक्त नही होने दिया। उन्होने ऐसा सुन्दर भाषण दिया कि जिन्ना के लिखित-भाषण को भी मात कर दिया। दो मिनट तक उपयुक्त शब्दो और वाक्यो की अटूट धारा उनके मुख से प्रवाहित होती रही। कथाए कहने की उनमे विलक्षण योग्यता है। और उनके अनौपचारिक निशाने पर चोट करने वाले उनके भाषण, भोज के बाद दिये जाने वाले भाषणो का आदर्श उपस्थित करते है।

भोज के बाद हम एक भारी सत्कार-सभा मे शामिल हुए। उसमे हलके पेय तथा सगीत का कार्यक्रम था। सब परिस्थितियो का खयाल रखते हुए यह सत्कार सफल रहा। आज के मेजबान और मुख्य व्यक्ति के रूप मे जिन्ना अकेले-अकेले और कुछ अलग-अलग लगे। सभवत इसीसे वातावरण कुछ दबा-दबा सा था। अपने रुपहले बालो और बेदाग सफेद अचकन मे वह सबके ऊपर छाये नजर आते थे और बहुत ही कम बाते करते दीख पडते थे। लोग भी उनसे आत्मीयता जताने

का साहस नही करते। 'बेतार' से नेतृत्व करने की क्षमता की वह साक्षात प्रतिमा थे। मैंने कभी कल्पना नही की थी कि किसी देश का निर्माता अपनी सफलता के सर्वोच्च क्षण मे अपने अनुयायियो से इतनी दूर भाग सकेगा। उन्हे अकेला पाकर मैंने कुछ क्षणो तक उनसे बात की। मैंने उन्हे बधाई देने के लिए उपयुक्त शब्द खोजने का प्रयत्न किया, परन्तु उनकी ध्यानावस्थित अवस्था से सहम कर मेरे शब्द मुरझा गए।

सरकारी भवन, कराची और सरकारी भवन, नई दिल्ली,

बृहस्पतिवार-शुक्रवार, १४-१५ अगस्त १९४७

विधान-सभा मे होनेवाले समारोह मे भाग लेने के लिए हम काफी तडके उठ गए। जुलूस के लिए निश्चित रास्ते से होता हुआ मै जिन्ना और माउन्टबेटन के आध घटे पहले वहा पहुच गया। जनता का उत्साह और भीड मेरी आशा मे बहुत कम थी। यहा का उत्साह उससे अधिक नही था जो ससद के वार्षिक उद्घाटनो के अवसर पर हुआ करता है। लेकिन अर्द्धचन्द्राकार और गोल गुम्बद की शक्ल वाले विधान-सभा-भवन के सामने के मैदान की इच-इच जगह ठसाठस भरी हुई थी। माउन्टबेटन-दम्पति को भी वही स्वागत-सत्कार मिला, जो उनसे कुछ पहले आने वाले जिन्ना को मिला था। माउन्टबेटन और जिन्ना के भाषणो का मुख्य स्वर सौहार्द का था और उपस्थित सदस्यो की प्रतिक्रिया भी सौहार्द-पूर्ण थी। प्राथमिकता का प्रश्न अपने-आप हल हो गया। जैसे ही जिन्ना भाषण देकर बैठने लगे लेडी माउन्टबेटन ने स्नेह मे कुमारी जिन्ना का हाथ दबाया।

अगर जिन्ना का व्यक्तित्व भावनाहीन और एकाकी था तो उसमे एक चमत्कारिक गुण भी था। उनमे नेतृत्व की ऐसी शक्ति थी जिसके आगे लोगो के घुटने टिक जाते थे। वैधानिक गवर्नर-जनरल होने का वह बहुत उथला और ऊपरी दिखावा करते थे, और उस पद के लिए स्वय अपना नाम सुझाने के बाद उन्होने जो पहला काम किया वह था १९३५ के विधान के भाग दो की बजाय नवी अनुसूची के अनुसार विशेषाधिकार ग्रहण करने की घोषणा करना। इससे ऐसे तानाशाही अधिकार उनके हाथ मे आ गए जो बादशाह का प्रतिनिधित्व करने वाले वैधानिक गवर्नर-जनरल को शायद ही पहले कभी मिले हो। पाकिस्तान के बादशाह, गवर्नर, स्पीकर और प्रधान-मत्री—इन सबके अधिकार शक्तिशाली कायदे-आजम मे निहित थे।

मे प्रवेश करने लगी, जिन्ना ने बडी भावुकता के साथ माउन्टबेटन के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, "खुदा का शुक्र है कि मैं आपको हिफाजत से वापस ले आया हू।" दोपहर तक माउन्टबेटन-दम्पति ने बिदाई की रस्मे पूरी कर ली। मिस जिन्ना ने लेडी माउन्टबेटन को गले लगाया और जिन्ना ने, जिनकी भावुकता अभी चुकी नही थी, अपनी शाश्वत दोस्ती और एहसानमदी के इजहार किये। अब वह दिल्ली के विशाल समारोहो मे भाग लेने के लिए हवाई जहाज से रवाना हुए। जब हम पजाब के सीमा-प्रदेश के ऊपर से गुजरे तो हमने मनहूसियत की प्रतीक कई विशाल आगों को आसपास के मैदान पर मीलो तक फैले देखा।

दिल्ली पहुचते ही मैं प्रचार-व्यवस्था के तूफान मे फस गया। मुझे समय की चुस्त पाबदी और उलझे कार्यक्रम की समस्याओ से निबटना था, फोटोग्राफरो और फिल्मे लेने वालो के साथ रिहर्सल करने थे, सूचना मत्रालय के साथ विचार-विमर्श करना था, प्रचार-सामग्री बाटनी थी, दिल्ली के एक सौ बीस भारतीय और विदेशी पत्रकारो को निमत्रण देने थे और उनकी पूछताछ के उत्तर देने थे। रात की आखिरी घडी तक माउन्टबेटन और उनके कर्मचारी अपने काम मे जुटे रहे। अपना डेरा-डण्डा उठाने के काम मे वाइसराय का अमला आखिरी क्षण तक पूरे वेग से व्यस्त था।

जैसे ही आधी रात का समय होने को हुआ और वाइसराय की ओर से सेक्रेटरी आव् स्टेट के नाम अन्तिम तार का मसविदा तैयार कर भेजा गया, मैंने अपने-आप को माउन्टबेटन के साथ उनके अध्ययन-कक्ष मे अकेला पाया। नये कानून के लागू होते ही तुरन्त सर्वशक्ति-सम्पन्नता का अधिकार ग्रहण किया जा सके इसलिए विधान-सभा का अधिवेशन चौदह तारीख की आधी रात को आयोजित किया गया था। स्वाधीनता की घोषणा, और माउन्टबेटन से पहले वैधानिक गवर्नर-जनरल के रूप मे पद सभालने का प्रस्ताव पास होते ही डा राजेन्द्रप्रसाद और नेहरू माउन्टबेटन से मिलने आयगे और औपचारिक रूप से उन्हे न्योता देगे। उम्मीद है कि पौन बजे के लगभग उनका आना होगा।

जब आधी रात मे घडी ने टन किया उस समय माउन्टबेटन बहुत चुपचाप बैठे हुए थे। मैं उन्हे करीब-करीब हर प्रकार की मन स्थिति मे देख चुका हूँ। कह सकता हू कि आज रात वह निहायत शान्त और निर्लिप्त थे। उनकी व्यक्तिगत सफलता इतनी महान् थी कि उसे खुशी दिखाकर व्यक्त नही किया जा सकता था, बल्कि इस नाटकीय घडी मे, जब नये और पुराने का मिलन उनमे साकार होने को था, उनके इतिहास-विषयक ज्ञान और विवेक ने उनमे भारी धीरज भर दिया था।

धीरे-धीरे उन्होने अपना चश्मा उतारा, कागज-पत्र रखने के सन्दूको को बन्द किया और वाइसराय की सक्रियता के चिह्नो को हटाकर सफाई करने मे मेरी मदद

चाही। हालाकि बाहर नौकरो की पल्टन-की-पल्टन मौजूद थी, उनकी मदद लेने का खयाल हम दोनो मे से किसी के भी दिमाग मे नही आया। जब सारे कागज करीने से लगा दिये गए और उनकी मेज साफ हो गई तब उन्हे बुलाकर कुछ भारी फर्नीचर इधर-उधर सरकाया गया, जिससे पत्रकारो के लिए जगह हो जाय।

विधान-सभा के समारोह मे उपस्थित पत्रकारो का आना शुरू हो गया। उन्होने बतलाया कि अपार भीड मार्ग पर खडी हुई है और इसीसे नेहरू और राजेद्रप्रसाद बाबू को जरा देर हो गई है। विधान-सभा की कार्यवाही बहुत ही शानदार रही थी। बडे भावुकता पूर्ण ढग से नेहरू ने कहा, "बहुत साल बीते हमने तकदीर के साथ एक बाजी बदी थी। और आज वह दिन आया है कि जब हम उस प्रण को पूरा करेगे—पूर्णता के साथ तो नही, लेकिन काफी हद तक। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही है, हमारा भारत जीवन और स्वाधीनता के नव-जागरण मे प्रवेश कर रहा है।"

विशाल जन-समूह की हर्ष-ध्वनि को पार कर थके लेकिन प्रसन्न राजेन्द्रप्रसाद और नेहरू ने प्रवेश किया। आगे जो हुआ उसमे दोस्ती की भावना ने औपचारिकता के सारे बधनो को तोड दिया। पत्र-सम्वाददाता घेरा बनाये खडे थे और फोटोग्राफर मेज के पास मौजूद थे। हालाकि नेहरू ने सम्वाददाताओ की उपस्थिति की स्वीकृति दी थी, लेकिन मेरा खयाल है कि वह यह बात भूल गए थे। चाहे इस उपस्थिति के कारण हो, चाहे विधान-सभा की ऐतिहासिक घटनाओ के कारण, वे दोनो कर्तव्य-विमूढ खडे थे।

आखिर, माउन्टबेटन और राजेद्रप्रसाद बाबू आमने-सामने आ खडे हुए और नेहरू उनके बीच माउन्टबेटन की मेज पर आ बैठे। राजेद्रबाबू औपचारिक निमत्रण देने लगे। लेकिन वह कहने वाले शब्दो को भूल गए और नेहरू उन्हे ठीक शब्द याद दिलाने लगे। दोनोने मिलकर बतलाया कि विधान-सभा ने अधिकार सभाल लिये है और नेताओ की यह विनय मान ली है कि माउन्टबेटन भारत के नये गवर्नर-जनरल बने। इस सन्देश के उत्तर मे माउन्टबेटन ने मुसकराते हुए कहा, "इस सम्मान को मै अपना गौरव मानता हू। आपकी सलाह पर वैधानिक ढग से अमल करने की पूरी कोशिश करूगा।"

यह होते ही नेहरू ने एक बडा-सा लिफाफा, जिस पर सुन्दर अक्षर लिखे हुए थे, माउन्टबेटन को देते हुए बडे शिष्टाचार के साथ कहा, "नये मत्रिमडल की सूची सेवा मे प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिये।" सारा समारोह दस मिनट के अन्दर पूरा हो गया। लेकिन इस उत्सव मे विशाल समारोहो और परेडो की अपेक्षा कही अधिक इन्सानियत और आशा भरी हुई थी।

मै फिर माउन्टबेटन के साथ अकेला रह गया। अपनी उत्सुकता शान्त करने और अपनी सरकार के नये मन्त्रियो के नाम याद करने के लिए उन्होने बडे लिफाफे-

-को खोला। लेकिन अपने प्रधान-मन्त्री द्वारा तैयार की हुई सूची आज देखना उनकी तकदीर मे नही बदा था। दैवयोग से नेहरूजी का दिया लिफाफा बिलकुल खाली था।

सरकारी भवन, नई दिल्ली, शुक्रवार, १५ अगस्त, १९४७

आज से अधिक व्यस्त और स्मरणीय दिन शायद ही मुझे फिर देखने को मिले।

जिन तुरहियो और लाल-सुनहरी सजावटो के बीच बीस गवर्नर-जनरल पद ग्रहण कर चुके थे, उन्हीके बीच आज सवेरे ८-३० बजे दरबार हाल मे स्वतन्त्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल के रूप मे लार्ड माउन्टबेटन के प्रवेश की घोषणा हुई। इस समारोह की खासियत यह नही थी कि वह माउन्टबेटन के वाइसराय-पद पर आसीन होने के समारोह से किसी प्रकार भिन्न था, बल्कि खासियत यह थी कि आज का समारोह हर बात मे मार्च के समारोह से मिलता-जुलता था। फरक अगर था तो इतना ही कि गवर्नर-जनरल को शपथ दिलाने का काम एक भारतीय न्यायाधीश, डा० कानिया के जिम्मे था और नये उपनिवेश के मन्त्रियो को शपथ दिलाई गृह-विभाग के एक भारतीय सेक्रेटरी ने। एक बार फिर सुनहरे सिहासन पर लगे कीमती लाल मखमल के चदोवे छिपी हुई रोशनियो से जगमगा उठे। कालीन सुनहरे काम से चमचमा रहे थे और लेडी माउन्टबेटन अपनी सुनहरी पोशाक मे इस समारोह की रौनक बढा रही थी।

लार्ड और लेडी माउन्टबेटन सिहासनो पर मुश्किल से बैठे ही होगे कि किसी फोटोग्राफर के 'फ्लैश बल्ब' के धडाके से सारा दरबार-हाल गूंज उठा। बम की इस हू-ब-हू नकल से चिता की एक क्षणिक लहर दौड गई। माउन्टबेटन दम्पति पर तेज रोशनिया पड रही थी, फिर भी उन्होने चेहरे से ऐसा नही लगने दिया कि बल्ब की चमक या उसके धडाके की आवाज उनके कानो तक पहुची होगी। समारोह समाप्त होने के समय दरबार-हाल के विशाल दरवाजे खोल दिये गए। पहले 'गाड सेव दि किग' और फिर 'जन गण मन' की धुने बजी, जो पुराने और नये युग को जोडने वाली कडी की प्रतीक थी।

कुछ ही पलो मे सारे सम्भ्रान्त दर्शक वहा से लुप्त हो गए और वे कौसिल-भवन को घेरे खडी अपार भीड मे खो गए। माउन्टबेटन की राजकीय सवारी सरकारी भवन (जिसे कल तक वाइसराय भवन कहते थे) के मुख्य दरवाजो से निकल कर सरकारी सचिवालय भवनो के बीच से ढलवा मार्ग पर बढना शुरू हुई थी, कि भारी भीड ने उसे रोक लिया और विशाल तथा प्रसन्न जनसमूह ने उनकी बग्घी को मानो हाथो मे उठा लिया।

इससे पहले कि भीड का दबाव जोर पकडे, मै फुर्ती से सरकारी भवन के क बगल के रास्ते से चलकर कौसिल-भवन मे जा पहुचा। किन्तु ज्यो-ज्यो समय

बीतता जाता था कौसिल-भवन के विशाल दरवाजो से सरकारी अतिथियो को अन्दर आने देना कठिन होता जाता था। उनके अन्दर आने के साथ ही जोरो से 'जय हिन्द' चिल्लाने वाले नागरिको का एक रेला भी अन्दर घुस आता। कुछ देर मे ही विशाल गोलाकार कौसिल भवन ने फौजी घेरे मे पडे एक किले का रूप धारण कर लिया। किसी को सुझाई न देता था कि जब माउन्टबेटन दरवाजे पर पहुचेगे तो गाडी से उतर कर उनके अन्दर आने के लिए रास्ता कैसे किया जायगा। काफी देर तक स्थिति बडी खराब रही। लगभग ढाई लाख जनसमूह बलात अन्दर घुसने की जो तोड कोशिश करने लगा। जनता को शात करने के लिए नेहरू तथा अन्य बडे नेताओ को बाहर बुलाना पडा। नेताओ की उपस्थिति ने पहले तो जनता की उत्तेजना को और भडकाने का काम किया लेकिन बावजूद इसके कि भारी भीड उनसे हाथ मिलाने के लिए धक्कामुक्की करती हुई आगे पिली पड रही थी, जैसे-तैसे माउन्टबेटन-दम्पति को अन्दर पहुचा दिया गया। उनके पदक और राजचिह्न बिल्कुल ज्यो-के-त्यो थे।

भवन के अन्दर भी उत्साह और आगे होने वाली घटनाओ के प्रति प्रतीक्षा की भावना बाहर-जैसी ही थी, लेकिन इतनी सयत अवश्य थी कि औपचारिक समारोह सपन्न हो सके। डा राजेद्रप्रसाद ने कार्रवाई का आरम्भ दुनियाभर से आये हुए बधाई सदेशो को पढकर सुनाने से किया। किन्तु किसी चूक के कारण, जिसकी तुलना कल रात के खाली लिफाफे की घटना से की जा सकती है, वह राष्ट्रपति ट्रूमैन का सदेश पढना भूल गए। यह त्रुटि वह तभी सुधार सके जब अमरीकी राजदूत डा ग्रेडी ने जोर से फुसफुसा कर उसकी याद दिलाई। हमेशा की तरह फोटोग्राफरो के बल्वो के धमाको के बीच माउन्टबेटन भाषण देने के लिए खडे हुए। उन्होने सबसे पहले राजा जार्ज षष्ठ का सदेश पढकर सुनाया, जिसका हृदय से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होने जो भाषण दिया उसमे उनके लिखित भाषणो की अपेक्षा कही अधिक जोश और बल था। हालाकि शब्दो का चुनाव बडी सावधानी से किया गया था, किन्तु उनमे जो सच्चाई व हार्दिकता निहित थी वह भरी सभा की सहानुभूति और प्रशसा प्राप्त करने मे सफल हुई। उनके भाषण मे रियासतो के सघ-प्रवेश की नीति की सफलता, नेहरू और पटेल के नेतृत्व के उल्लेख, तथा उनके इस अनुरोध पर कि "मुझे आप अपना ही समझे" बडी हर्ष ध्वनि की गई। किन्तु गाधीजी के प्रति उनके उद्गारो पर सबसे अधिक तालिया पीटी गई और काफी देर तक उन्हे रुके रहना पडा।

इसके बाद डा राजेद्रप्रसाद ने एक लम्बा भाषण दिया—पहले हिंदी और फिर अग्रेजी मे। दोनो ही भाषण सुनाई नही पडते थे। काग्रेस के बुजुर्ग नेताओं मे डा प्रसाद नम्र विचारो और स्वभाव वाले व्यक्ति माने जाते है। वह न कभी उत्तेजित होते है, न अतिशयोक्ति करते है। आज उन्होने अपना दिल खोलकर

रख दिया। उन्होने कहा, "आइये, हम कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे कि, हालाकि हमारी सफलता का काफी श्रेय हमारे बलिदानो और त्यागो को है, लेकिन वह विश्व की घटनाओ और स्थिति का भी परिणाम है। ब्रिटिश जाति की ऐतिहासिक परम्पराओ और जनतात्रिक आदर्शो का भी उसमे कम हाथ नही है।" उस जाति के प्रतिनिधि के रूप मे माउन्टबेटन को श्रद्धाजलि देने के बाद उन्होने कहा, "भारत के ऊपर ब्रिटिश सत्ता का आज अन्त हो रहा है और भविष्य मे ब्रिटेन के साथ हमारे सबध समानता, आपसी सद्भाव और पारस्परिक लाभ के आधारित पर होगे।"

भाषणो के बाद विधान-सभा भवन के ऊपर राष्ट्रीय झडा फहराया गया और ३१ तोपो की सलामी दागी गई। आज दिन मे जो अनेको तूफानी सवारिया निकलने वाली थी, उनमे माउन्टबेटन के वापिस लौटने की सवारी का नम्बर केवल दूसरा था। सरकारी भवन तक का सारा रास्ता 'जय हिन्द' और "माउन्टबेटन की जय" के नारो से गूँज रहा था। कही-कही "पडित माउन्टबेटन की जय" का घो भी कानो मे पड जाता था।

दोपहर के खाने के बाद हमारी मोटरो का काफिला रोशनआराबाग की ओर चला, जहा पहुच कर भीषण गर्मी मे माउन्टबेटन-दम्पति पाच हजार स्कूली छात्रो की भीड मे घुलमिल गए। यहा अनेको प्रकार के खेल-तमाशो का आयोजन था। इनमे से कुछ ने मनोरजन किया, कुछ ने चकित और कुछ ने डरा दिया। एक फकीर को साप का फन खाते हुए देखकर और गर्मी तथा कोलाहल के मारे बेचारी पमेला की तो जान ही निकल गई। फिर भी पमेला और उसके माता-पिता बडे साहस और सद्भाव के साथ समारोह मे भाग लेते रहे।

पुरानी भारतीय परम्परा के अनुसार जाने के पहले माउन्टबेटन ने जो आखिरी काम किया वह था बच्चो मे मिठाई बाटना।

सरकारी भवन लौटकर माउन्टबेटन-दम्पति को मुश्किल से इतना समय मिल पाया कि आज के सब-से-बडे सार्वजनिक समारोह मे भाग लेने के लिए वे कपडे बदल सके। यह समारोह था प्रिंसेज पार्क के निकट युद्ध-स्मारक पर राष्ट्रीय झडा फहराना। वहा जाकर देखा तो तीन लाख के लगभग जनता एकत्र थी जब कि समारोह के आयोजको ने कुल ३० हजार के करीब जन-समुदाय के लिए प्रबन्ध किया था। नतीजा यह हुआ कि कोई व्यवस्था न रही और भीड बेकाबू हो गई। जन-समुदाय ने सब कुर्सियो पर अधिकार कर लिया था और एक-एक कुर्सी पर कुछ लोग आ खडे हुए।

जन समुदाय के इस विशाल भवर मे बडे छोटे, काले-गोरे, स्त्री-पुरुष तथा नाना जातियो के व्यक्ति मिल कर एकाकार हो गए थे। हजारो लोगो की एकमात्र इच्छा यही थी कि जहा झडा फहराया जाने वाला था उस केन्द्रीय मच तक पहुच जाय। दरअसल भीड ने एक विशाल महासागर का रूप धारण कर

लिया था जो चारो ओर से एक छोटे से द्वीप को घेरने के लिए आगे बढा चला जा रहा था, और यह खतरा था कि किसी भी क्षण वह उस द्वीप को निगल जायगा। स्वय नेहरू बडी मुश्किल से केन्द्रीय मच पर पहुच पाए और जब उन्होने देखा कि पमेला भीड मे फस गई है तो लपके और धक्का-मुक्की करते, इसके सिर की टोपी उतार कर उसके सिर पर रखते हुए, पमेला को निकाल लाये। एक व्याकुल ए डी सी घबराया कि कही दगा न हो जाय। किन्तु उसने इस विशाल जन-समुदाय की मस्त और प्रसन्न-मुद्रा को नही पहचाना था।

जहा मै खडा था, वही एक सूरमा साईकिल चलाने का असभव प्रयत्न कर रहा था। ऐसा लगता था कि अपनी मजिल तक पहुचने के पहले ही वह भीड मे आ फसा था। नतीजा यह हुआ कि वह न आगे बढ सकता था और न साइकिल से उतर सकता था। फे, मार्जोरी, ब्राकमेन तथा पमेला, निकोल्स भी बीच मे फस गए थे, लेकिन खुश भीड चिल्ला रही थी, "मेम-साहबो के लिए रास्ता छोड दो!" फे आखिर बी बी सी[1] की गाडी पर पहुच गए, जहा से विन्फोर्ड वागा टामस विदेशो के लिए एक अत्यन्त विस्तृत और शानदार ब्राडकास्ट कर रहे थे। उन्होने बाद मे मुझे बताया कि इससे बडी भीड उन्होने जीवन मे नही देखी।

सहसा हर्ष-ध्वनि ने गरज का रूप ले लिया। जहा मै खडा था वहा से सफेद-पोश ए डी सी की एक झलक दिखलाई दी। उसके पीछे गवर्नर-जनरल के अगरक्षको के भालो के ऊपर फहराते झडो की झलक, फिर गवर्नर-जनरल की गाडी और फिर अगरक्षक। गाडी और अगरक्षक रुकते-चलते किसी प्रकार केन्द्रीय मच के पच्चीस गज पास तक पहुच गए। मैने माउन्टबेटन को खडे होकर जन-समूह का अभिनन्दन करते देखा जो हर्ष-ध्वनि करती हुई उनकी ओर हाथ हिला रही थी· लोगो को शात करने और थोडी जगह साफ करने के लिए नेहरू ने आखिरी बार कोशिश कर देखी, लेकिन जब उनकी आरजू-मिन्नत का कोई फल नही हुआ तो इसके सिवा कोई चारा ही न रहा कि माउन्टबेटन गाडी मे ही खडे रहे और झडा फहराये जाने पर वही से सलामी ले।

झडे के फहराये जाते ही बूँदा-बादी होने लगी और इन्द्रधनुष आकाश के आरपार तन गया। लगता था मानो झडे के केसरिया, सफेद और हरे रगो से होड कर रहा हो। अगर हालीवुड ने यह दृश्य अपनी किसी फिल्म मे दिखाया होता तो हम सब यही शिकायत करते कि यह अतिरजना है, लेकिन यह दृश्य निहायत स्वाभाविक था। मानना पडेगा कि जिस व्यक्ति का दिल लोहे का बना हुआ हो वही ऐसे शुभ-अवसर पर प्रकट हुए इन शुभ-शकुन से प्रभावित हुए बिना रह सकता था।

---

१. ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन—ब्रिटेन का रेडियो संगठन।

माउन्टबेटन की सवारी की सरकारी भवन को वापिसी दोस्ती-भरी अनौपचारिकता की अन्तिम विजय थी। नेहरू अपनी मोटर तक पहुचने मे असफल रहे थे, इसलिए माउन्टबेटन ने उन्हे भी अपनी बग्घी मे खीच लिया, और वह गाडी के 'हुड' पर बठ गए। रास्ते मे चार औरतो, एक बच्चे और गाडी के पहियो के नीचे दबते एक फाटोग्राफर को भी माउन्टबेटन ने अपने साथ ले लिया, जिससे गाडी मे बैठे लोगो की सख्या बारह तक पहुच गई। कर्जन और उनके दरबार की यह पुनरावृत्ति थी।

फिर, आज के इस ऐतिहासिक दिन के उपसहार स्वरूप हम सरकारी भोज में भाग लेने सरकारी भवन पहुचे। मत्रिमडल के सदस्य, कूटनीतिज्ञ लोग और बडे-बडे सैनिक तथा असैनिक नेता भोज मे उपस्थित थे। गैरहाजिरो मे खास थे वे एक-दो राजे-महाराजे, जो नई सरकार के सदस्यो के सामने उचित प्राथमिकता न मिलने के भय से हाजिर नही हुए थे। जब नेहरू ने खडे होकर ब्रिटिश राजा के स्वास्थ्य की कामना की और उसके उत्तर मे माउन्टबेटन ने औपनिवेशिक सरकार की शुभकामना की तो समारोह अपनी चरम सीमा पर पहुच गया। इन दोनो के भाषण बिलकुल अलिखित थे और केवल उपस्थित लोगो के कानो के लिए थे। इसलिए उनमे वह सजीदगी नही थी जो विश्वव्यापक प्रचार के विचार से भाषणो मे आ जाया करती है।

नेहरू ने कहा, "आप लोगो ने देखा होगा कि कितने उत्साह से दिल्ली की जनता ने आज का दिन मनाया है। कोई शक नही कि सारे भारत मे ऐसे ही दृश्य दिखलाई पडे होगे। दो देशो के बीच पैदा होने वाले सबधो मे राजनीति और अर्थ का बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन भारत की जनता के साथ व्यवहार करने मे मैं मनोवैज्ञानिक और भावना-सबधी पक्षो के महत्व की ओर घ्यान खीचना चाहता हू। जो लोग दिल्ली मे अपने दफ्तरो मे बैठे हुए राजनैतिक समस्याओ और आर्थिक योजना पर विचार किया करते है, उनका देश के साथ वास्तविक सपर्क नही होता है। इस बारे मे अनक मत हो सकते है कि ब्रिटेन के साथ अपने अतीत सबधो से भारत को फायदा हुआ या नही। लेकिन यह सोचना सरासर गलत होगा कि आजादी की जद्दो-जहद करने वाली जनता पर किसी बडे राष्ट्र को अपना आधिपत्य जमाये रखना चाहिये। चूंकि अब हिन्दुस्तान आजाद है, इसलिए जनता खुश ही नही, वल्कि अग्रेजो के प्रति उसके रुख मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है।"

माउन्टबेटन को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उन्होने कहा कि माउन्टबेटन को आते ही यह समझने मे देर नही लगी थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति का पालन करने के लिए फुर्ती से काम करने और भारत की ओर ठीक मनोवैज्ञानिक रुख अपनाना कितना अहम है। भारत और ब्रिटेन के सबध भविष्य मे चाहे जैसा रूप

धारण कर ले, लेकिन एक नई शुरूआत तो हो गई है। उन्होने आशा प्रकट की कि उनके बीच मैत्री कायम रहेगी।

अपने उत्तर में माउन्टबेटन ने कहा कि उनके पूर्वगामियो का दुर्भाग्य था कि उन्हे खडी साइकिल पर बैठने को तो मजबूर होना पडा था, और उस पर सतुलन बनाए रखना बडा कठिन काम होता है। लेकिन उन्हे तो पैडल मार कर तत्काल 'आगे बढने' का आदेश दिया गया था। उनका काम था अधिकाधिक तेजी से पडल मारना और आज वह इस स्थिति मे पहुच गए है कि यह साईकिल अपनी सरकार के हाथो मे सौप रहे है, जिसने हैन्डिल को कसकर पकड लिया है।

सवा नौ बजे तीन हजार मेहमान कतार से ऊपर पहुचे और एक-एक कर माउन्टबेटन के सामने पेश किये गए। सरकारी भवन के सारे कमरे और बैठके मेहमानो के लिए खोल दिये गए। तेज रोशनी से जगमग मुगल-उद्यान बडा मनोरम प्रतीत हो रहा था। अब जरा ठडक भी हो गई थी और हवा मजेदार और सुगधित थी। बडे सद्भाव और हसी-खुशी के साथ यह दावत देर तक चलती रही। वह तनाव और अकड भी अब नही रही थी, जो मार्च की गार्डन-पार्टी मे भारतीय मेहमानो मे दिखलाई पडती थी। ऐसी सरलता और स्वच्छन्दता का वातावरण था जो समानता की व्याप्त भावना ही पैदा कर सकती है।

स्वाधीनता के अवसर पर निकाले गए विशेषाको मे बहुत-सी मोजूँ बाते लिखी गई थी। लेकिन सबसे अच्छे मुझे के एम मुशी के शब्द लगे, जो उन्होने माउन्ट-बेटन की गवर्नर-जनरल पद पर नियुक्ति के बारे मे लिखे थे

वह लिखते है "ब्रिटेन के अलावा इतिहास का कोई राष्ट्र इतनी शान से आजादी का दान नही दे सकता था, और भारत के अलावा कोई दूसरा देश इतनी शान के साथ इस ऋण का आभार नही मान सकता था।"

: १४ :

उत्तराधिकार का युद्ध

नई दिल्ली, शनिवार, १६ अगस्त १९४७

आज सवेरे तडके दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झडा फहराया गया। इस अवसर पर नेहरू ने लगभग पाच लाख जनता के सामने भाषण दिया। भीड मुगलो के गौरव के एक और प्रतीक, विशाल जामा मसजिद तक फैली हुई थी।

लेकिन आज तीसरे पहर जब माउन्टबेटन ने रेडक्लिफ का फैसला नेताओ के हाथ मे सौपा तो सवेरे की खुशहाली पर उदासी की चादर पड गई। सरकारी भवन के कौसिल-कक्ष मे मत्रिमडल की बैठक बुलाने के पूर्व उन्होने फैसले का अध्ययन करने के लिए दो घटे का समय दिया। लियाकत भी यहा मौजूद थे—और दरअसल माउन्टबेटन की यह बडी सफलता थी कि वह जिन्ना को इस बात के लिए राजी कर पाये कि पाकिस्तान के प्रधान-मत्री का पद सभालने के चौबीस घटे बाद ही लियाकतअली दिल्ली की यात्रा करे। मत्रिमडल की इस उदास और नाराजीभरी बैठक मे मै उपस्थित था। अगर इसमे किसी बात पर सहमति थी तो वह इस या उस साम्प्रदायिक 'अन्याय' की निदा के विषय मे थी। इससे माउन्टबेटन को काफी सामयिकता के साथ यह कहने का अवसर मिला कि चूँकि सब दल रेडक्लिफ के फैसले मे समान रूप से सतुष्ट नही है, इसलिए फैसले के उचित होने की सबसे असदिग्ध कसौटी यही है कि सब उससे नाखुश है।

आनेवाली लम्बी और आवेशपूर्ण बहस का पहला सकेत हमे मिला। गुरदासपुर जिला पूर्वी पजाब मे शामिल किये जाने पर लियाकत को उतनी ही निराशा हुई जितनी चटगाव का पहाडी इलाका पूर्वी पाकिस्तान मे मिलाये जाने पर पटेल को क्रोध। बलदेवसिह की वेदना के आगे तो तीनो का रोष फीका पड गया। लेकिन किसी नेता ने पहले से बिना शर्त दिये गए इस वचन को भग नही किया कि फैसला चाहे जो हो, उसे अस्वीकार नही किया जायगा।

इधर हमारी बैठक हो रही थी उधर दोनो विभाजित प्रातो से ऐसे समाचार आ रहे थे जो एक चेतावनी के साथ साहसपूर्ण नेतृत्व को चुनौती भी देते थे। पजाब मे लोगो ने कानून को ताक पर रखकर स्थिति अपने हाथ मे ले ली थी। जिसे जेनकिन्स ने उत्तराधिकार का युद्ध कहा है, वह पाच नदियो के इस देश मे पूरी वीभत्सता के साथ शुरू हो गया था। आज तीसरे पहर आचिन्लेक ने नेताओ को स्थिति के बारे मे इतनी कटु और डरावनी रिपोर्ट दी कि नेताओ को अविलम्ब सीमा-फौज को मजबूत करने का फैसला करना पडा।

उधर कलकत्ता मे, जहा इसी प्रकार की हिसा का डर किसी प्रकार भी कम नही था, अपेक्षाकृत शाति है। हिसा की घटनाए इक्की-दुक्की है। गाधीजी की उपस्थिति ने बगाल के जख्म पर मरहम का काम किया है। वस्तु-स्थिति के औचित्य के बारे मे अपने विवेक के अनुसार स्वाधीनता समारोह शुरु होने के पहले ही गाधीजी दिल्ली से चले गए थे। उनका विचार शायद यही था कि इन सरकारी उत्सवो मे वह कोई मौजू भूमिका नही खेल सकेगे और उनकी जरूरत पूरब को ज्यादा है। १३ तारीख को उन्होने सयुक्त बगाल के अन्तिम प्रधान मत्री शहीद सुहरावर्दी को, जो काफी रईसी तबियत के व्यक्ति है, न्योता दिया कि मुसलमान बस्ती के एक मामूली मकान मे उनके साथ रहने आये और उनके सेवा-कार्य मे हाथ बटाये। उसी रात हिन्दू

नौजवानो ने उनके मकान पर पत्थर फेंके। इसके उत्तर मे गाधीजी ने कल के स्वाधीनता-दिवस को उपवास-दिवस के रूप मे मनाया।

पजाब की गभीर स्थिति को देखते हुए नेहरू और लियाकत ने साथ-साथ तुरन्त अम्बाला जाने का निश्चय किया। अम्बाला से वे अमृतसर जायगे, जहा स्थिति का ठीक-ठीक मूल्याकन कर तत्काल महत्वपूर्ण निर्णय करेगे।

आज रात अचानक मेरी मुलाकात उस फोटोग्राफर से हुई जिसे कल माउन्टबेटन ने कुचलने से बचाकर अपनी बग्घी मे बैठा लिया था। वह एक चरम वामपथी पत्र का प्रतिनिधि है। लेकिन अपने विचारो के बावजूद उसने मेरा हाथ झकझोरते हुए कहा, "दो सौ साल के बाद आखिर ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान को जीत ही लिया।"

नई दिल्ली, बुधवार, २० अगस्त १९४७

भारी वर्षा के कारण कल हमारी बबई से दिल्ली की यात्रा कई घटे पिछड गई और हम तीसरे पहर के बाद यहा पहुचे। यहा हमने स्थिति को काफी गभीर पाया है। नेहरू और लियाकत अम्बाला से अमृतसर गये, जहा पहुचकर उन्होने शाति के लिए एक महत्वपूर्ण अपील निकाली। नेहरू ने एक रेडियो भाषण भी दिया, जिसमे उन्होने कहा कि पजाब की सरकारे भारत और पाकिस्तान की सरकारो के पूरे सहयोग से इस वीभत्स काड का अन्त करने पर कटिबद्ध है। उन्होने कहा, "भारत कोई साम्प्रदायिक नही, धर्म-निरपेक्ष राज्य है, जिसमे हर नागरिक को समान अधिकार है। सरकार इन अधिकारो की रक्षा करने पर अटल है।"

विस्थापितो की समस्या भी तूल पकडती जा रही है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग दो लाख व्यक्ति अस्थायी विस्थापित कैम्पो मे भरे हुए है और ऐसी परिस्थितियो मे रह रहे है कि किसी भी समय बडे पमाने पर हैजे का प्रकोप हो सकता है।

नई दिल्ली, सोमवार, २५ अगस्त १९४७

सयुक्त सुरक्षा-परिषद् की बैठक मे पजाब सीमा-सेना के भविष्य पर माउन्टबेटन को बडी कठिनाई का सामना करना पडा। दोनो सरकारे चाहती है कि सीमा-फौज को राष्ट्रीय आधार पर विभाजित कर दिया जाय और उसके दोनो भाग अपने-अपने देश के प्रधान सेनापति के अधीन रहे। माउन्टबेटन इस जानकारी के साथ बैठक मे गये थे कि यह कल्पना आचिन्लेक तथा रीस को बिलकुल स्वीकार न होगी। वह खुद भी उसके बिलकुल खिलाफ थे। उन्होने पूरी बहस का सचालन ऐसी चतुरता से किया कि यह प्रश्न औपचारिक रूप से उठाया ही नही गया। किन्तु वह पाकिस्तानी वित्त-मत्री और प्रतिनिधि चुन्द्रीगर को सीमा-फौज की गति-विधि के बारे मे कुछ आपत्तिजनक बाते कहने से रोकने मे असमर्थ रहे।

माउन्टबेटन के लिए यह बिलकुल असह्य था, क्योकि वह जानते थे कि सीमा-फौज के मनोबल को बनाये रखन के लिए उसे नेताओ की शाबाशी और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर सीमा सेना को उचित सहारा नही मिला तो उसे हटाने के सिवा कोई चारा नही रह जायगा। इसके हटने से जो रक्तपात होगा उसकी जिम्मेदारी उन लोगो के कधो पर होगी जो उसके भग किये जाने के दोषी है। एक बार उन्होने चुन्द्रीगर को पितृतुल्य डाट बताते हुए कहा, "यदि आपके गवर्नर-जनरल आपको इस प्रकार बाते करते हुए सुने तो वह जो कुछ कहेगे उसकी कल्पना करना भी मुझे अप्रिय मालूम होता है।"

बैठक मे सीमा-फौज के बारे मे एक विज्ञप्ति प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। मैने और वर्नोन ने विज्ञप्ति का मसविदा तैयार किया। किंतु चुन्द्रीगर अड गए कि उसमे इस आशय का वाक्य होना चाहिए कि यदि सीमा-फौज ने अपना कर्त्तव्य पूरा न किया तो उसके विरुद्ध कडी कार्रवाई की जायगी। दूसरी ओर, हम वर्तमान मसविदे के ही इस वाक्य को मुलायम करने का प्रयत्न कर रहे थे कि "कुछ अपवादो को छोड कर" सीमा-फौज बहुत अच्छा काम रही है।

काफी बहस के बाद इन कठोर शब्दो को निकालना तय पाया। इस पूरी घटना से यह साफ जाहिर है कि यदि दोनो सरकारे विद्रोह की स्थिति पैदा नही करना चाहती है तो उन्हे नाजुक काम मे सलग्न अपनी सेनाओ के बारे मे अपने रुख मे भारी परिवर्तन करना पडेगा।

सरकारी भवन लौटने पर माउन्टबेटन ने हमे माकटन का एक तार दिखलाया। इसमे उन्होने कहा था कि मै निजाम के वैधानिक परामर्शदाता के पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो गया हू, हालाकि निजाम का विश्वास अवतक मुझ पर कायम है। उन्होने यह भी कहा है कि मै महसूस करता हू कि मुझे अब सरकारी भवन मे नही ठहरना चाहिए, क्योकि इसका अर्थ गलत लगाया जा सकता है। इस समाचार से माउन्टबेटन को भारी चोट पहुची। वह कह उठे, "हम डूब गए!"

सत्ता-हस्तातरण के बाद भारत सरकार ओर हैदराबाद के बीच क्या सबध रहना चाहिए—इस सबध मे जो कठिन बातचीत चल रही है, उसका बहुत कुछ दारोमदार जुलाई से ही माकटन के प्रभाव और निजाम के प्रतिनिधि-मडल के सदस्य के रूप मे उनके उपलब्ध होने पर निर्भर रहा है।

अभी १२ अगस्त को ही माउन्टबेटन ने, समझौते का कोई लक्षण न देखकर निजाम को सूचित किया था कि उन्होने निजाम के लिए स्वाधीनता-दिवस के बाद दो महीने की विशेष मोहलत मजूर करवा ली है। सरकार इस अवधि मे हैदराबाद का सघ-प्रवेश-पत्र स्वीकार करने को तैयार है। अतएव, वह इस सुअवसर का फायदा उठाए। उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हालाकि अब वह ताज के प्रतिनिधि नही है, पर उन्हे भारत की ओर से बातचीत जारी रखने का अधिकार दे

दिया गया है। इस बीच, उन्होने बरार के सबध मे, जो वैध रूप से निजाम-राज्य का अग है, किन्तु अबतक मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रशासित होता रहा है, भारत से यथापूर्व स्थिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अन्त मे उन्होने वी पी मेनन से परामर्श करने के पश्चात् निजाम को यह महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया था कि यदि निजाम वर्तमान परिस्थितियो मे सघ-प्रवेश न करने का निश्चय करे तो नई सरकार इसे शत्रुतापूर्ण कार्य नही मानेगी। उन्होने यह भी कहा कि नेताओ का कोई ऐसा इरादा नही है कि आर्थिक नाकेबन्दी करके कूटनीतिक दबाव डाला जाय।

हैदराबाद के प्रतिनिधिमडल के साथ आज बातचीत फिर शुरू होनी थी। माकटन का तार मिलने पर माउन्टबेटन ने वी पी मेनन को बुलाकर उनके साथ नई स्थिति पर विचार विमर्श किया। वर्नोन और मै सीमा-फौज सबधी विज्ञप्ति को ठिकाने लगाने के काम मे लग गए। हमारे लौटने पर स्थिति मे सुधार दिखलाई पडा। निजाम के पास से एक तार आया था। उसमे माउन्टबेटन से अनुरोध किया गया था कि वह निजाम की ओर से माकटन से मिले और उन्हे अपने पद पर बने रहने के लिए समझाए। निजाम ने स्वीकार किया था कि यदि माकटन इस सकट के समय चले गए तो उनके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त करने मे बहुत कठिनाई होगी।

माकटन तुरन्त आये और उन्होने बताया कि उनके त्यागपत्र देने का कारण उनके विरुद्ध राज्य के पत्रो का अतिशय उग्र आक्रमण है। इस आक्रमण का सगठन उग्र मुस्लिम सस्था इत्तिहादुल-मुसलमीन ने किया है। उन्होने कहा कि इसी कारण प्रधान मत्री (नवाब छतारी) और वैधानिक मामलो के मत्री ने भी त्यागपत्र दे दिया है। ये दोनो भी प्रतिनिधिमडल मे शामिल थे। निजाम ने छतारी का त्यागपत्र स्वीकार करने मे इन्कार कर दिया है। माकटन ने कहा कि यदि इत्तिहाद सार्वजनिक रूप से अपना वक्तव्य वापस ले ले तो मै भी अपना त्याग-पत्र वापस लेने को तैयार हू।

माकटन ने माउन्टबेटन को बताया कि उन्होने निजाम को ऐसी सधि के लिए लगभग राजी कर लिया है जिसमे तीनो केद्रीय विषयो, सुरक्षा, वैदेशिक मामलो और सचार का समावेश हो जायगा। उन्होने अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि वह निजाम को 'सघप्रवेश' के बराबर ही कोई दूसरी बात स्वीकार करने के लिए राजी कर लेगे, बशर्ते कि 'सघ-प्रवेश-पत्र' नाम को बदलकर 'मैत्री-सधि' जैसा कोई ऊपर से मीठा लगने वाला नाम रख दिया जाय। माउन्टबेटन ने उन्हे बताया कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पटेल लगभग अटल है। उनको भय है कि ऐसा करने से सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले अन्य राजा-महाराजा उन पर विश्वासघात का आरोप करेगे। परन्तु माउन्टबेटन ने वचन दिया कि यदि माकटन सघ-प्रवेश-पत्र के मूल तत्वो पर निजाम की स्वीकृति प्राप्त कर सके, तो वह उस

पर भारत सरकार का समर्थन प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

आज यह समाचार भी मिला कि आखिर भोपाल नरेश भी भारत-संघ मे शामिल हो गए है, भोपाल के नवाब को संघ-प्रवेश-पत्र की शर्त प्रकाशित होने के दिन से १० दिन की मोहलत दी गई थी। माउन्टबेटन ने कहा, "आजकल के दिन १५ अगस्त के पहले दिनो से कम तूफानी नही है।"

शिमला, शनिवार, ३० अगस्त १९४७

संयुक्त सुरक्षा-परिषद् की अध्यक्षता करने माउन्टबेटन कल लाहौर गये थे। जिन्ना को उसमे सदस्य के रूप मे उपस्थित देखकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। काफी लम्बी-चौडी बहस के बाद सीमा-फौज को भंग करने का फैसला किया गया। इतना बेजोड और कठिन काम करने के लिए पीट रीस का उचित आभार नही माना गया। दोनो देशो की सरकारो और समाचारपत्रो के समर्थन के अभाव मे सीमा फौज और उसके कमाडर की स्थिति विचित्र हो गई। विश्वस्त और अनुभवी सेनाए भी साम्प्रदायिक खिचावो को अपने सैनिक अनुशासन की अपेक्षा कही उग्रता से महसूस करने लगी।

पंजाब-सीमा-सेना के भंग होने के साथ ही माउन्टबेटन के आखिरी शासकीय काम का अन्त हो गया है। उनका विचार है कि अब उन्हे अपने वैधानिक पद के अनुसार रोजाना के कामो से अलग हो जाना चाहिए। इसीलिए वह अब आराम के लिए शिमला आये हुए है।

शिमला, बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर १९४७

आज तीसरे पहर माउन्टबेटन ने हमे बतलाया कि वी पी मेनन ने दिल्ली से फोन पर पटेल का यह आवश्यक संदेश दिया है कि माउन्टबेटन तुरन्त दिल्ली लौट आये। वी पी मेनन ने कहा कि नेहरू, पटेल और अन्य जिम्मेदार मंत्रियो का मत है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि माउन्टबेटन की उपस्थिति ही उसे संभाल सकती है।

कल सवेरे हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

सकटकालीन कमेटी की पहली बैठक आज शाम को पाच बजे सरकारी भवन के कौसिल कक्ष मे हुई और दो घटे तक चली। कमेटी की कार्यवाही शुरू करते हुए नेहरू ने माउन्टबेटन से कहा, "आपकी सलाह मै इमी शर्त पर मान सकता हूं कि आप अध्यक्षपद सभाले।" यह सुझाव माउन्टबेटन ने एक दूसरी शर्त पर स्वीकार कर लिया—वह यह कि इस बात को गुप्त रखा जायगा।

तय हुआ कि कमेटी मे केवल कुछ मत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग ही शामिल हो। जैसे—प्रधान सेनापति, सर्वोच्च-सेनापति के प्रतिनिधि, दिल्ली के चीफ कमिश्नर, पुलिस विभाग के अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन विभाग के डाइरेक्टर-जनरल और चिकित्सा तथा रेलवे विभाग के प्रतिनिधि। अन्य लोगो को जरूरत के अनुसार विशेष निमत्रण पर बुलाया जा सकता था। नेहरू और पटेल कमेटी के स्थायी सदस्य होगे। इनके अलावा यह मत्री भी कमेटी मे मिल जायगे बलदेव-सिह (सुरक्षा), मथाई (रेलवे) और नियोगी (नव-निर्मित विस्थापित विभाग)। कुल मिलाकर पन्द्रह लोगो ने प्रारम्भिक बैठक मे भाग लिया।

कमेटी का विधान तय होते ही हमने तुरन्त "अत्यन्त आवश्यक" प्रश्नो पर विचार शुरू कर दिया। विस्थापित मत्रालय की स्थापना अभी नही हो पाई थी। कमेटी कल सवेरे तक यह जानना चाहेगी कि इस मत्रालय के सेक्रेटरी पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद कमेटी ने इस विभाग के लिए जगह दिये जाने के कठिन और आवश्यक प्रश्न पर विचार किया। सकटकालीन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच सपर्क साधने का काम इस्मे को सौपा गया।

'मार्शल-ला' लगाये जाने के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। माउन्टबेटन का विचार था कि पजाब की स्थिति 'मार्शल-ला' लगाये जाने के अनुकूल है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब चारो सबधित सरकारे इससे सहमत हो। लेकिन यह सभावना बिलकुल असभव होने के कारण कमेटी ने आदेश दिया कि पूर्वी पजाब मे लागू कानूनो को कडा करने की सभावनाओ और तरीको पर अविलम्ब विचार किया जाय। कुल मिलाकर बारह प्रश्नो का निबटारा किया गया—लेडी माउन्ट-बेटन के अधीन रिलीफ कमेटी की स्थापना के प्रश्न से लेकर शाही हवाई बेडे के यातायात के नियत्रण और इश्तिहार गिराये जाने के प्रश्न तक। जब बैठक खत्म हुई तो सब लोग पस्त थे।

कल की बैठक मे पूर्वी पजाब के गवर्नर त्रिवेदी, उनके प्रधानमत्री गोपीचन्द भार्गव और गृह-मत्री स्वर्णसिह भी भाग लेगे।

कलकत्ता से गाधीजी के 'चमत्कार' का समाचार आया है। सुहरावर्दी के साथ उनकी साझेदारी का अपेक्षित फल नही हुआ। इक्की-दुक्की हत्याए और हिसा जारी रही। इसलिए उन्होने सोमवार से उपवास शुरू किया, जो नगर मे शान्ति स्थापित होने पर ही खत्म होगा। बृहस्पतिवार को जब विभिन्न सम्प्रदायो

सकटकालीन कमेटी की पहली बैठक आज शाम को पाच बजे सरकारी भवन के कौसिल कक्ष मे हुई और दो घटे तक चली। कमेटी की कार्यवाही शुरू करते हुए नेहरू ने माउन्टबेटन से कहा, "आपकी सलाह मै इसी शर्त पर मान सकता हू कि आप अध्यक्षपद सभाले।" यह सुझाव माउन्टबेटन ने एक दूसरी शर्त पर स्वीकार कर लिया—वह यह कि इस बात को गुप्त रखा जायगा।

तय हुआ कि कमेटी मे केवल कुछ मत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग ही शामिल हो। जैसे—प्रधान सेनापति, सर्वोच्च-सेनापति के प्रतिनिधि, दिल्ली के चीफ कमिश्नर, पुलिस विभाग के अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन विभाग के डाइरेक्टर-जनरल और चिकित्सा तथा रेलवे विभाग के प्रतिनिधि। अन्य लोगो को जरूरत के अनुसार विशेष निमत्रण पर बुलाया जा सकता था। नेहरू और पटेल कमेटी के स्थायी सदस्य होगे। इनके अलावा यह मत्री भी कमेटी मे मिल जायगे बलदेव-सिह (सुरक्षा), मथाई (रेलवे) और नियोगी (नव-निर्मित विस्थापित विभाग)। कुल मिलाकर पन्द्रह लोगो ने प्रारम्भिक बैठक मे भाग लिया।

कमेटी का विधान तय होते ही हमने तुरन्त "अत्यन्त आवश्यक" प्रश्नो पर विचार शुरू कर दिया। विस्थापित मत्रालय की स्थापना अभी नही हो पाई थी। कमेटी कल सवेरे तक यह जानना चाहेगी कि इस मत्रालय के सेक्रेटरी पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद कमेटी ने इस विभाग के लिए जगह दिये जाने के कठिन और आवश्यक प्रश्न पर विचार किया। सकटकालीन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच सपर्क साधने का काम इस्मे को सौपा गया।

'मार्शल-ला' लगाये जाने के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। माउन्टबेटन का विचार था कि पजाब की स्थिति 'मार्शल-ला' लगाये जाने के अनुकूल है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब चारो सबधित सरकारे इससे सहमत हो। लेकिन यह सभावना बिलकुल असभव होने के कारण कमेटी ने आदेश दिया कि पूर्वी पजाब मे लागू कानूनो को कडा करने की सभावनाओ और तरीको पर अविलम्ब विचार किया जाय। कुल मिलाकर बारह प्रश्नो का निबटारा किया गया—लेडी माउन्ट-बेटन के अधीन रिलीफ कमेटी की स्थापना के प्रश्न से लेकर शाही हवाई बेडे के यातायात के नियत्रण और इश्तिहार गिराये जाने के प्रश्न तक। जब बैठक खतम हुई तो सब लोग पस्त-थे।

कल की बैठक मे पूर्वी पजाब के गवर्नर त्रिवेदी, उनके प्रधानमत्री गोपीचन्द भार्गव और गृह-मत्री स्वर्णसिह भी भाग लेगे।

कलकत्ता से गाधीजी के 'चमत्कार' का समाचार आया है। सुहरावर्दी के साथ उनकी साझेदारी का अपेक्षित फल नही हुआ। इक्की-दुक्की हत्याए और हिसा जारी रही। इसलिए उन्होने सोमवार से उपवास शुरु किया, जो नगर मे शान्ति स्थापित होने पर ही खतम होगा। बृहस्पतिवार को जब विभिन्न सम्प्रदायो

के नेताओ ने उन्हे विश्वास दिलाया कि महात्माजी की हृदय-परिवर्तन की अपील का जनता पर उचित असर हुआ है, तो गाधीजी ने अपना उपवास खतम कर दिया।

गाधीजी की प्रार्थना सभा के बाद हिन्दू और मुसलमान बडी सख्या मे एक-दूसरे के गले मिले। मजे हुए पत्र-सम्वाददाताओ का कहना था कि सामूहिक प्रभाव का ऐसा बेजोड दृश्य उन्होने पहले कभी नही देखा। माउन्टबेटन का अनुमान था कि जो चीज गाधीजी ने केवल आत्मिक-बल से प्राप्त कर ली है, उसे चार फौजी डिवीजन भी बल-प्रयोग से हासिल नही कर सकते थे।

नई दिल्ली, रविवार, ७ सितम्बर १९४७

हमारी बैठक ग्यारह बजे प्रारम्भ हुई, लेकिन त्रिवेदी और पूर्वी पजाब के मत्री-गण ठीक समय पर उपस्थित नही हुए। बैठक शुरू करते हुए माउन्टबेटन ने कहा कि गत चौबीस घटे मे दिल्ली की स्थिति काफी बिगड गई है। काफी हिंसा की घटनाए घटी है। यहा तक कि सरकारी भवन के इलाके तक मे छुरे-बाजी हुई है। विस्थापित लोग भारी सख्या मे आ रहे है और उनका प्रबध करने के लिए कोई व्यवस्था नही है।

इसके बाद उन्होने हर प्रकार के हथियार रखने के ऊपर पाबदी लगाने के प्रश्न की बात छेडी। इससे सिखो द्वारा बाधे जानेवाले कृपाण का सवाल अपने-आप उठ खडा हुआ। पटेल महसूस करते थे कि कृपाण पर किसी प्रकार की पाबदी लगाने मे बडी कठिनाइया उठ खडी होगी, क्योकि काफी वर्षो से सरकार कृपाण को धार्मिक हथियार मानती आई है। माउन्टबेटन ने कहा कि सिखो को कृपाण बाधने का आम अधिकार दिया जाना न्याय और व्यवस्था के लिए कार्रवाई करने मे बाधक बन रहा है। लेकिन उन्होने मजूर किया कि बुनियादी सवाल यह है कि किस निर्णय मे कम लोगो की हत्या होगी—कृपाण पर नन्दिश लगाने मे या सिखो की धार्मिक भावना की रक्षा करने मे ?

को देखते हुए दृढता और ठडे दिमाग के साथ काम किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। विलिगडन हवाई अड्डे पर कत्लेआम होने का समाचार आया। सिखो ने आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और अमरीकी राजदूत को धमकी भरे पत्र भेजे थे। माउन्टबेटन ने बैठक मे चेतावनी दी कि कूटनीतिक प्रतिनिधियो की जान-माल की हिफाजत करने के प्रश्न पर भारत की इज्जत की बाजी लगी हुई है।

नई दिल्ली, सोमवार, ८ दिसम्बर १९४७

शाम को निजाम के प्रधान-मत्री नवाब छतारी से मेरी लम्बी बातचीत हुई। वह निजाम के प्रति वफादार तो रहना चाहते है, परन्तु उन्हे जो विविध हुक्म मिलते रहते है, उनका मतलब समझने मे उन्हे कठिनाई होती है। स्पष्ट है कि उनका कार्य-काल और प्रभाव बहुत दिन न रहेगा। उन्होने और माकटन ने—जो सरकारी भवन मे ठहरे हुए थे—आज माउन्टबेटन से भी भेट की।

दिल्ली की मौजूदा सकट पूर्ण स्थिति के कारण हैदराबाद की समस्या कम आवश्यक मालूम पडती है। इससे माउन्टबेटन सोचते है कि 'सघ-प्रवेश' के नाम मे परिवर्तन करने के लिए यह समय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल है। उधर, हैदराबाद मे, माकटन की नौकरी कायम रखने की इच्छा के प्रमाणस्वरूप निजाम ने एक सप्ताह पूर्व जोरदार फर्मान निकाल दिया था। उसमे उन्होने प्रतिनिधि-मडल के सदस्यो के विरुद्ध किये गए आक्रमण को राज्य के हितो के विरुद्ध बताकर उसकी कडी निन्दा की थी। माउन्टबेटन को लिखे पत्रो मे भी उन्होने इसकी चर्चा की और माकटन पर अपना विश्वास जाहिर किया। उन्होने इत्तिहाद, और विशेषत उसके धर्मांध अध्यक्ष कासिम रिजवी, की प्रवृत्तियो की स्पष्ट भाषा मे निन्दा की।

निजाम काफी झिझकते हुए समझौते की ओर बढ रहे है। परन्तु इस समय कांग्रेसी गुप्तचर विभाग ने, जो कि रियासती मामलो की बहुत अच्छी जानकारी रखता है, निजाम सरकार के चेकोस्लोवाकिया से शस्त्रास्त्र मगाने और पृथक् प्रभुसत्ता स्थापित करने के प्रयत्नो के चितनीय समाचार प्राप्त किये है। तथापि छतारी भली-भाति जानते है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई हैदराबाद तथा भारत दोनो के लिए घातक होगी। आज की बैठक मे दोनो पक्षो मे गतिरोध को दूर करने की सच्ची इच्छा दिखलाई पडी। यह स्वीकार कर लिया गया कि शायद बातचीत मे हिस्सा लेने वाले दोनो पक्षो के प्रमुख नेता पहले प्रयत्न मे किसी सूत्र पर सहमत न हो सकेगे। इस खयाल से यह निश्चय किया गया कि माकटन और छतारी हैदराबाद जाकर मतभेद को कम करने की फिर कोशिश करे।

नई दिल्ली, मंगलवार, ९ सितम्बर १९४७

आज माउन्टबेटन गाधीजी से मिले। गाधीजी अपने कलकत्ता के चमत्कारो के बाद अभी-अभी दिल्ली पहुचे है। अपनी कलकत्ता की सफलताओ के बारे मे गाधीजी बहुत विनम्र है, और उसे विशेष महत्व नही देते। उन्होने माउन्टबेटन से कहा कि अब सरकारी भवन के बारे मे उनका मत बदल गया है। विदेशी और झूठी सत्ता का प्रतीक कह कर अबतक वह इसकी निदा करते आये थे। उन्होने कहा कि मुझे खुशी है कि "आपदाओ के सागर मे वह निरापद द्वीप" का काम कर रहा है।

सकटकालीन कमेटी की सवेरे की बैठक मे पेशावर तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश (जो अब पाकिस्तान का अग है) की गभीर स्थिति के बारे मे रिपोर्टो पर विचार किया गया। इन रिपोर्टो की तात्कालिक प्रतिक्रिया यह है कि रिपोर्टे सही है।

: १६ :

जूनागढ़ का संकट

नई दिल्ली, रविवार, १४ सितम्बर १९४७

माउन्टबेटन ने आज कर्मचारी-मडल की जो बैठक की, उसमे मुख्यत पुराने किले की स्थिति पर विचार हुआ। पटेल करीब-करीब तय कर चुके है कि मुसलमानो से हथियार छीनने के लिए एक बटालियन भेजी जाय। माउन्टबेटन का कहना है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई विनाशकारी होगी और कत्लेआम भडका देगी।

नान-कमीशण्ड अफसर और सैनिक विस्थापितो के शिविरो का सगठन करने मे मदद करे। उनकी यह सहायता उपयोगी सिद्ध हुई और उसमे ब्रिटिश-प्रतिष्ठा भी बढी। उन्हे आशा है कि तीन-चार सप्ताह मे वह संकटकालीन कमेटी की अध्यक्षता नेहरू को सौप कर उसके कार्य से मुक्त हो जायगे। अब वह मानते है कि १५ अगस्त को भारत न छोड कर उन्होने अच्छा ही किया।

इस्मे कराची मे लौट आये हे। उनका खयाल है कि इस समय उनका कराची जाना बहुत ठीक हुआ। उन्होने पाया कि जिन्ना भारत-सरकार पर से अपना विश्वास उठने के बारे मे कसमे खा रहे है और भारत से कूटनीतिक सबध तोड देने पर उतारू है। इस्मे अडतालीस घटे कराची मे रहे, जिनमे से ग्यारह घटे उन्होने जिन्ना के साथ बाते करने मे बिताये। उन्हे लगता है कि उन्होने जिन्ना का विश्वास पा लिया है। जिन्ना ने उनके मुह पर ही उन्हे "सज्जन व्यक्ति" कहते हुए उनकी प्रशसा की।

साफ जाहिर है कि जिन्ना काग्रेस के विरुद्ध क्रोध से उबल रहे थे। उन्होने कहा कि मै इन आदमियो के द्वेष को कभी समझ नही सकता। युद्ध ठान कर निबटने के अलावा और कोई चारा नजर नही आता।

इस्मे ने बतलाया कि वह जिन्ना के साथ भिड गए और उन्होने कहा कि मै अतिशयोक्ति करने का अभ्यस्त नही हू, फिर भी मै अपने प्राणो की शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि भारत-सरकार पूरी शक्ति के साथ दगो को दबाने के लिए कमर कसे है। वे सब सच्चे आदमी है और पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न कर रहे हैं। इस्मे का खयाल है कि उन्होने जिन्ना को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया।

नई दिल्ली, सोमवार, १५ सितम्बर १९४७

कर्मचारी-मडल की आज की बैठक मे इस्मे की कराची-यात्रा से पैदा हुई आम स्थिति पर विचार किया गया। माउन्टबेटन का विश्लेषण यह था कि हिन्दू और मुसलमान तो समान अनुपात मे अपनी-अपनी सरकारो के वश मे है किन्तु सिख काबू के बाहर हैं और अब उनके नेता भी उनसे डरने लगे है। वी पी. मेनन का खयाल है कि निकट भविष्य मे भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई शाति नही हो सकती। ऐसी दशा मे माउन्टबेटन को दोनो उपनिवेशो के बीच युद्ध की आशका दृष्टिगोचर होती है। वह कहते है कि हमे युद्ध से जितनी दूर हो सके, रहना चाहिए। परन्तु वी पी मेनन मानते है कि जिन्ना के वर्तमान रुख मे यह आशा भी पूर्ण नही हो सकती।

माउन्टबेटन ने सिखो के उद्देश्य के बारे मे पूछा। क्या उनका उद्देश्य सिख-राज्य कायम करना है? वी पी मेनन ने उत्तर दिया कि नहीं, राजनीतिक

मे आम छुट्टी मनाई गई थी।

जूनागढ के बारे मे यह सब गडबडी फैली कैसे ? २५ जुलाई को माउन्टबेटन के साथ राजाओ की जो मुलाकात हुई थी, उसमे जूनागढ के तत्कालीन दीवान ने बहुत से प्रश्न पूछे थे। उनमे किसी मे जूनागढ के पाकिस्तान प्रवेश के इरादे का सकेत नही मिला था। दीवान ने तो यहा तक कहा था कि वह नवाब को भारत के साथ रहने की सलाह देगा। जूनागढ की सरकार ने घोषणा की थी कि जूनागढ काठियावाड की अन्य रियासतो के साथ रहेगा। ये सभी रियासते भारत-सघ मे शामिल हो गई है। परन्तु, सत्ता-हस्तातरण के केवल ५ दिन पहले—१० अगस्त को—वहा तख्ता पलट गया। सिंधी मुसलमानो के एक गुट ने शासन पर अधिकार कर लिया। शाह नवाज भुट्टो दीवान बन गए और नवाब अपने ही महल मे बन्दी बना दिया गया।

यह मुक्त रूप से माना जाता है कि सघ-प्रवेश राजाओ के विशेष अधिकार की बात है। लेकिन भारत सरकार ने यह भी कह दिया था कि सघ-प्रवेश की अन्तिम तारीख १५ अगस्त होगी। माउन्टबेटन ने २५ जुलाई को राजाओ से जो अपील की थी उसका आधार भी यही था। माउन्टबेटन के उस भाषण से दो तत्व और भी निकले थे। सघ-प्रवेश का निर्णय करने मे जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना गया था, उनमे से एक तो, माउन्टबेटन के ही शब्दो मे था, "भौगोलिक विवशताए, जिनकी उपेक्षा नही की जा सकती।" दूसरा प्रजा मे किस धर्म वाले लोगो का बहुमत है।

यद्यपि जूनागढ के पास समुद्र-तट भी है, एक छोटा-सा बन्दरगाह, वेरावल भी, और वह कराची के साथ सीधी पहुच का दावा भी कर सकता है, फिर भी स्पष्ट है कि उसका पाकिस्तान-सघ मे शामिल होना पूरी सघ-प्रवेश-नीति की बुनियादी वैधानिकता को एक सीधी चुनौती होगी। काठियावाड के राज्यो और हैदराबाद की वार्ताओ पर इसका विनाशकारी प्रभाव पडेगा। हैदराबाद के उग्र-पथी मुसलमानो को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जिन्ना ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जूनागढ के अलग रह जाने की भूल का भारी फायदा उठाया जा सकता है। भारत-सरकार ने जूनागढ पर भारत मे शामिल होने के लिए कोई दबाव नही डाला। परन्तु जब जूनागढ के पाकिस्तान मे प्रवेश करने के लक्षण दिखलाई पडे तो भारत-सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दो बार अनुरोध किया कि वह अपने इरादो का साफ-साफ ऐलान करे लेकिन इनका, अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ।

माउन्टबेटन ने मुझे उन बैठको मे बुलाया, जो वह जूनागढ के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए इस्मे और वी पी मेनन के साथ कर रहे है। वी पी बहुत चिन्तित है। उन्होने माउन्टबेटन को समझाने का प्रयत्न किया कि फौजी और

मे आम छुट्टी मनाई गई थी।

जूनागढ के बारे मे यह सब गडबडी फैली कैसे? २५ जुलाई को माउन्टबेटन के साथ राजाओ की जो मुलाकात हुई थी, उसमे जूनागढ के तत्कालीन दीवान ने बहुत से प्रश्न पूछे थे। उनमे किसी मे जूनागढ के पाकिस्तान प्रवेश के इरादे का सकेत नही मिला था। दीवान ने तो यहा तक कहा था कि वह नवाब को भारत के साथ रहने की सलाह देगा। जूनागढ की सरकार ने घोषणा की थी कि जूनागढ काठियावाड की अन्य रियासतो के साथ रहेगा। ये सभी रियासते भारत-सघ मे शामिल हो गई है। परन्तु, सत्ता-हस्तातरण के केवल ५ दिन पहले—१० अगस्त को—वहा तख्ता पलट गया। सिधी मुसलमानो के एक गुट ने शासन पर अधिकार कर लिया। शाह नवाज भुट्टो दीवान बन गए और नवाब अपने ही महल मे बन्दी बना दिया गया।

यह मुक्त रूप से माना जाता है कि सघ-प्रवेश राजाओ के विशेष अधिकार की बात है। लेकिन भारत सरकार ने यह भी कह दिया था कि सघ-प्रवेश की अन्तिम तारीख १५ अगस्त होगी। माउन्टबेटन ने २५ जुलाई को राजाओ से जो अपील की थी उसका आधार भी यही था। माउन्टबेटन के उस भाषण से दो तत्व और भी निकले थे। सघ-प्रवेश का निर्णय करने मे जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना गया था, उनमे से एक तो, माउन्टबेटन के ही शब्दो मे था, "भौगोलिक विवशताए, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।" दूसरा प्रजा मे किस धर्म वाले लोगो का बहुमत है।

यद्यपि जूनागढ के पास समुद्र-तट भी है, एक छोटा-सा बन्दरगाह, वेरावल भी, और वह कराची के साथ सीधी पहुच का दावा भी कर सकता है, फिर भी स्पष्ट है कि उसका पाकिस्तान-सघ मे शामिल होना पूरी सघ-प्रवेश-नीति की बुनियादी वैधानिकता को एक सीधी चुनौती होगी। काठियावाड के राज्यो और हैदराबाद की वार्ताओ पर इसका विनाशकारी प्रभाव पडेगा। हैदराबाद के उग्र-पथी मुसलमानो को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जिन्ना ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जूनागढ के अलग रह जाने की भूल का भारी फायदा उठाया जा सकता है। भारत-सरकार ने जूनागढ पर भारत मे शामिल होने के लिए कोई दबाव नही डाला। परन्तु जब जूनागढ के पाकिस्तान मे प्रवेश करने के लक्षण दिखलाई पडे तो भारत-सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दो बार अनुरोध किया कि वह अपने इरादो का साफ-साफ ऐलान करे लेकिन इनका, अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ।

माउन्टबेटन ने मुझे उन बैठको मे बुलाया, जो वह जूनागढ के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए इस्मे और वी पी मेनन के साथ कर रहे है। वी पी बहुत चिन्तित है। उन्होने माउन्टबेटन को समझाने का प्रयत्न किया कि फौजी और

नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करना आवश्यक था। उन्होने यह मानकर एक वक्तव्य तैयार किया कि पाकिस्तान जूनागढ को धन-जन से सहायता करने को तैयार था।

शाम को मै इस्मे से मिलने उनके निवास-स्थान पर गया। मैने पाया कि जूनागढ के प्रश्न से जो बेचैनी का वातावरण उत्पन्न हो गया था उससे उन्हे बहुत चिंता हो रही थी। उनका खयाल था कि पाकिस्तान के वर्तमान साधनो और दायित्वो को देखते हुए यह समाचार मूर्खतापूर्ण मालूम होता था कि वह जूनागढ मे हस्तक्षेप करेगा और उसने जूनागढ के बन्दरगाह के विकास के लिए आठ करोड रुपयो का ऋण देने तथा उसकी सहायता के लिए २५,००० सेना भेजने का वचन दिया है।

नई दिल्ली, मंगलवार, १६ सितम्बर १९४७

हमे सूचना मिली कि जूनागढ के संघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर हो गए है और सील-सिक्का लगाकर उसे कराची भेज दिया गया है। परन्तु यह बात अभी तक सरकारी तौर पर पक्की नही हुई है। वी पी और माउन्टबेटन को दुबारा बातचीत के समय मै उपस्थित था। इस्मे ने जूनागढ के सम्बन्ध मे जिन्ना की संभावित चालो पर बडे तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। प्रत्यक्ष रूप मे जूनागढ जिन्ना के लिए बेकार है। सैनिक दृष्टि से वह एक असह्य भार होगा। जहातक बुद्धि काम करती है जिन्ना की नीति इधर-उधर बिखरे हुए मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रो को मिलाने की नही है, क्योकि अभी भारत के अन्दर चार करोड मुसलमान मौजूद है।

इस्मे का खयाल था कि जिन्ना की इस कार्रवाई का मूल उद्देश्य भारत को चक्कर मे डालकर परेशान करना था। उन्हे आशा थी कि भारत को युद्ध मे फसाकर वह कानूनी मुद्दो पर अपने पक्ष मे फैसले करवा लेगे। इसका उपयोग वे काश्मीर और हैदराबाद की बडी रियासतो पर अपने दात लगाने मे कर सकेगे। कुछ हद तक जूनागढ हैदराबाद का एक छोटा रूप ही है। उसका नवाब मुसलमान है, किन्तु प्रजा अधिकांशत हिन्दू। राज्य भी भारतीय प्रदेश के अन्दर है।

मैने विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया। कागजी तौर पर भारतीय पक्ष काफी मजबूत दिखलाई पडता था। परन्तु जहा तक पत्रो की प्रतिक्रिया का सबंध था मुझे यह चेतावनी देनी पडी "हालाकि उपरोक्त तर्क खुद मे काफी सबल है, फिर भी इस समय सैनिक कार्रवाई करने से विदेशी पत्रो की प्रतिक्रिया बहुत हानिकारक होगी। किसी भी सैनिक कार्रवाई को आक्रमण-मूलक माना जायगा। विदेशी पत्र दोनो देशो की सैनिक कार्रवाइयो के बारे मे बहुत सजग है।" मैने सुझाव दिया कि अभी केवल यह घोषणा कर दी जाय कि जूनागढ का पाकिस्तान-प्रवेश हमे मान्य नही है और भविष्य मे कोई भी कार्रवाई करने का हमारा अधिकार सुरक्षित

है। बातचीत के लिए भी गुजाइश छोड दी जाय।

नई दिल्ली, बुधवार, १७ सितम्बर १९४७

आज तीसरे पहर जूनागढ के बारे मे मत्रिमडल की महत्वपूर्ण बैठक के पहले माउन्टबेटन ने नेहरू और पटेल दोनो के साथ लम्बी बातचीत की। उन्होने दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि हमे कोई ऐसी कार्रवाई नही करनी चाहिए जिससे ससार हमारी ओर अगुली उठा सके। हमे उस प्रदेश के विरुद्ध, जो अब पाकिस्तान का हो चुका है, युद्ध का निश्चय भी नही करना चाहिए।

उन्होने इस्मे के इस मत को दोहराया कि जिन्ना की यह सारी कार्रवाई एक जाल है। यह सब उनकी बृहत्तर योजना का अग है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को ससार की दृष्टि मे निर्दोप तथा असहाय राष्ट्र के रूप मे पेश करना है, जिसपर भारतीय-आक्रमण का खतरा झूल रहा है। उन्होने जोर दिया कि भारत जनमत-सग्रह के सिद्धान्त पर दृढ रहे जिसमे जनता की इच्छा भी मालूम की जा सके और हमला करके इलाके पर दखल करने के प्रश्न का भी अत हो जाय।

माउन्टबेटन को नेहरू को सहमत करने मे कोई कठिनाई नही हुई, किंतु पटेल को समझाने मे समय लगा। जूनागढ ने पटेल की सारी सघ-प्रवेश नीति और व्यक्तिगत भावनाओ पर भारी असर किया है। परन्तु माउन्टबेटन के तर्क और जिन्ना की मनोभावनाओ और इरादो के बारे मे इस्मे के मत वह भी मान गए। मत्रि-मडल की बैठक मे जाकर उन्होने अपना नया दृष्टिकोण सामने रखा। इससे उनके साथियो को अचभा तो जरूर हुआ होगा लेकिन अपने साथियो को समझाने मे उन्हे मुश्किल नही हुई। बैठक मे यह दो निर्णय किये गए एक—भारत की फौजे और सघ मे शामिल होने वाली रियासतो की स्थानीय फौजे जूनागढ की सीमा पर तैनात कर दी जाय। लेकिन वे जूनागढ पर दखल न करे। दो—वीं पी मेनन जूनागढ जाकर नवाब और दीवान को बतलाये कि उनके पाकिस्तान मे शामिल होने के क्या नतीजे होगे।

लेकिन पहले की ये घटनाए बहुधा किसी एक ही सम्प्रदाय तक सीमित होती थी और साथ ही यह आशा भी बनी रहती थी कि किसी-न-किसी दिन ये निष्क्रमणार्थी फिर अपने घरो को वापिस लौटेगे। लेकिन आज बात दूसरी थी। इन निष्क्रमणार्थियो की सख्या पहले से कही विशाल थी और इस बार उनका लौटना कदापि न होगा।

निष्क्रमणार्थियो के काफिले की पहली झलक हमने फिरोजपुर और बुलाकी-हेड के बीच देखी थी। इसका पीछा करते हुए हम रावी पार बहुत दूर तक उडे। विस्थापितो के इस प्रवाह के साथ लगभग पचास मील आगे तक गये किन्तु इसका छोर न मिला। बीच-बीच मे बैलगाडियो ओर पैदल चलनेवाले परिवारो की सख्या बिल्कुल इनी-गिनी रह जाती थी, लेकिन जरा आगे बढते ही फिर घनी अटूट कतारे नजर आने लगती।

बुलाकी हेड मे, जो वास्तविक सीमा है, पुल पार करने की प्रतीक्षा करनेवाले विस्थापितो की अपार भीड थी और ऐसा लगता था मानो जबरदस्ती जमीन पर दखल करने वालो की बस्ती हो। यहा उनका चलना बिल्कुल रुक गया था, लेकिन वैसे भी उनकी गति बहुत धीमी थी। कुछ घुडसवार हमे दिखाई पड रहे थे जो इधर-उधर घूमते हुए अपार जन-समूह को किसी प्रकार के आदेश दे रहे थे। सडक के किनारे कुछ परिवार अपने जानवरो को लिये खडे थे। कुछ लोगो की एकमात्र दौलत यह जानवर ही थे। लेकिन इनमे शायद ही कोई जानवर पुलपार कर सके। क्योकि पुलपर इतनी भीड थी कि जो कि उसकी शक्ति से बाहर की थी।

भारत मे दाखिल होने पर लायलपुर-लाहौर सडक पर धीमी गति से आगे बढने वाले मुसलमान विस्थापितो का काफिला देखा। अमृतसर शहर को बचाकर निकलने के लिए उन्हे बहुत लम्बा चक्कर खाना पडा था। हमने यह अनुमान लगाया कि इस काफिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उडने मे हमे पन्द्रह मिनट से भी अधिक लगे जबकि हमारे विमान की गति लगभग एक सौ अस्सी मील प्रति घटा थी। इस प्रकार यह काफिला कम-से-कम पैतालीस मील लम्बा रहा होगा।

गत रविवार को हुए सम्मेलन मे नेहरू और लियाकत ने कहा था कि शुरू-शुरू मे वे आबादियो के सामूहिक परिवर्तन के कितने खिलाफ थे। लेकिन बाद मे स्थिति उनके बूते के बाहर हो गई।

नई दिल्ली, सोमवार, २९ सितम्बर १९४७

माउन्टबेटन का सारा दिन जूनागढ तथा पजाब सबधी नीति पर विचार करने वाली बैठको मे बीता। जूनागढ का सकट उत्तरोत्तर शतरज की बडी जटिल बाजी

लेकिन पहले की ये घटनाए बहुधा किसी एक ही सम्प्रदाय तक सीमित होती थी और साथ ही यह आशा भी बनी रहती थी कि किसी-न-किसी दिन ये निष्क्रमणार्थी फिर अपने घरो को वापिस लौटेगे। लेकिन आज बात दूसरी थी। इन निष्क्रमणार्थियो की सख्या पहले से कही विशाल थी और इस बार उनका लौटना कदापि न होगा।

निष्क्रमणार्थियो के काफिले की पहली झलक हमने फिरोजपुर और बुलाकी-हेड के बीच देखी थी। इसका पीछा करते हुए हम रावी पार बहुत दूर तक उडे। विस्थापितो के इस प्रवाह के साथ लगभग पचास मील आगे तक गये किन्तु इसका छोर न मिला। बीच-बीच मे बैलगाडियो और पैदल चलनेवाले परिवारो की सख्या बिल्कुल इनी-गिनी रह जाती थी, लेकिन जरा आगे बढते ही फिर घनी अटूट कतारे नजर आने लगती।

बुलाकी हेड मे, जो वास्तविक सीमा है, पुल पार करने की प्रतीक्षा करनेवाले विस्थापितो की अपार भीड थी और ऐसा लगता था मानो जबरदस्ती जमीन पर दखल करने वालो की बस्ती हो। यहा उनका चलना बिल्कुल रुक गया था, लेकिन वैसे भी उनकी गति बहुत धीमी थी। कुछ घुडसवार हमे दिखाई पड रहे थे जो इधर-उधर घूमते हुए अपार जन-समूह को किसी प्रकार के आदेश दे रहे थे। सडक के किनारे कुछ परिवार अपने जानवरो को लिये खडे थे। कुछ लोगो की एकमात्र दौलत यह जानवर ही थे। लेकिन इनमे शायद ही कोई जानवर पुलपार कर सके। क्योकि पुलपर इतनी भीड थी कि जो कि उसकी शक्ति से बाहर की थी।

भारत मे दाखिल होने पर लायलपुर-लाहौर सडक पर धीमी गति से आगे बढने वाले मुसलमान विस्थापितो का काफिला देखा। अमृतसर शहर को बचाकर निकलने के लिए उन्हे बहुत लम्बा चक्कर खाना पडा था। हमने यह अनुमान लगाया कि इस काफिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उडने मे हमे पन्द्रह मिनट से भी अधिक लगे जबकि हमारे विमान की गति लगभग एक सौ अस्सी मील प्रति घटा थी। इस प्रकार यह काफिला कम-से-कम पैतालीस मील लम्बा रहा होगा।

गत रविवार को हुए सम्मेलन मे नेहरू और लियाकत ने कहा था कि शुरू-शुरू मे वे आबादियो के सामूहिक परिवर्तन के कितने खिलाफ थे। लेकिन बाद मे स्थिति उनके बूते के बाहर हो गई।

नई दिल्ली, सोमवार, २९ सितम्बर १९४७

माउन्टबेटन का सारा दिन जूनागढ तथा पजाब सबधी नीति पर विचार करने वाली बैठको मे बीता। जूनागढ का सकट उत्तरोत्तर शतरज की बडी जटिल बाजी

का रूप धारण करता जा रहा है। इस शतरज की बिसात है जूनागढ, उसके पडोसी और अधीनस्थ राज्य, और मोहरे चलने वाले खिलाडी है कराची और दिल्ली।

पिछली बार जब लियाकतअली दिल्ली आये थे तब इस्मे ने उनसे बातचीत की थी। उसके आधार पर इस्मे को पूरा विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान जूनागढ के मामले को काश्मीर के लिए सौदेबाजी का आधार बनाना चाहता था। पाकिस्तान की यही चाल थी। इस विश्वास का सबूत लियाकतअली के इन शब्दो से मिला, जो उन्होने उसी दिल्ली-प्रवास मे माउन्टबेटन से कहे थे, "अच्छी बात है, भारत को आगे बढकर युद्ध छेडने दीजिये। फिर देखियेगा क्या होता है।"

दस दिन पूर्व वी पी मेनन जूनागढ गये थे। उनकी यात्रा का परिणाम सीमित रहा था। वह दीवान से मिले। दीवान ने कहा कि नवाब अस्वस्थ है और उनसे मिलना नही हो सकेगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मगरोल की छोटी-सी रियासत के शेख वी पी की उपस्थिति का फायदा उठाकर अपनी रियासत से आये और स्वेच्छापूर्वक भारत-सघ मे शामिल हो गए। इसके पहले मगरोल जूनागढ को खिराज देने वाली रियासत थी। इसके पूर्व बाबरियावाड का शासक भी ऐसा ही कर चुका था। लेकिन मगरोल वापिस लौटने पर शेख को सघ-प्रवेश का निर्णय रद्द करना पडा। २२ तारीख को भारत-सरकार ने निश्चय किया कि जिन परिस्थितियो मे सघ-प्रवेश को रद्द करने का पत्र लिखा गया था, वे ऐसी थी कि पत्र पर विचार नही किया जा सकता। जूनागढ ने मगरोल पर इस रक्तहीन विजय से प्रोत्साहित होकर बाबरियावाड पर अपनी सेनाए दोडा दी।

ये घटनाए पटेल के क्रोध को भडकाने के लिए काफी थी। उनका खयाल था कि जूनागढ ने बाबरियावाड पर सैनिक चढाई करके युद्ध छेड दिया है और भारत को उन सेनाओ को बाहर खदेडने के लिए सब आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। वास्तविकता यह थी कि यदि शक्ति का प्रदर्शन ओर अन्तिम उपाय के रूप मे उसका प्रयोग नही किया जायगा तो वह त्यागपत्र दे देगे।

माउन्टबेटन ने कल नेहरू को एक पत्र लिखकर सैनिक कार्यवाहियो की योजनाए बनाने और उन्हे कार्यान्वित करने के अन्तर पर प्रकाश डाला। उन्होने जोर दिया कि दोनो उपनिवेशो के बीच प्रत्यक्ष युद्ध से न केवल दोनो की नैतिक प्रतिष्ठा कम हो जायगी, बल्कि दोनो का अस्तित्व भी भयानक खतरे मे पड जायगा। माउन्टबेटन की यह सलाह मान ली गई। किन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय सेना की तीनो शाखाओ के प्रमुखो ने अपनी स्वतत्र समझ से भी इसी खतरे की ओर ध्यान दिलाया ओर इस काम मे वे सैनिक सलाह की सीमा का उल्लघन कर राजनैतिक क्षेत्र मे पहुच गए। इसने पटेल के क्रोध की आग मे घी का काम किया।

माउन्टबेटन ने एक बीच का रास्ता सुझाया। उनके अनुसार जूनागढ के आस-

पास के विवादरहित प्रदेशो मे भारतीय सेना की कुमुक भेजना जारी रखा जा सकता था। उन्होने यह भी सलाह दी कि लियाकत को काठियावाड मे आयोजित सैनिक गति-विधि की सूचना दे दी जाय और भारत-सरकार स्पष्ट घोषणा कर दे कि जिस राज्य के सघ-प्रवेश का प्रश्न विवादग्रस्त होगा, उसके सम्बन्ध मे भारत सरकार वहा के जनमत का निर्णय स्वीकार करेगी।

नई दिल्ली, बुधवार, १ अक्तूबर १९४७

लियाकत सयुक्त सुरक्षा-कौसिल की बैठक मे भाग लेने के लिए दिल्ली आये। मेरा खयाल है कि आज सवेरे की बैठक बडी सकटपूर्ण रही। बैठक के बाद दोपहर के खाने के समय महमान थे नेहरू और लियाकत और कर्मचारी मडल मे वर्नोन तथा मैं। यहा भी वातावरण कुछ-कुछ तनावपूर्ण था। अम्बाला से मुसलमानो के निष्क्रमण के प्रश्न पर लियाकत नेहरू से उलझ पडे। ऐसे मौके पर हम सबकी यही इच्छा थी कि किसी भी तरह विषय को बदल दिया जाय, लेकिन ऐसा करना शक्ति से बाहर था।

इस तनावपूर्ण बातचीत का असली कारण यह था कि पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पजाब की सीमा मे स्थित रावी पार 'बुलाकी-हेड' पुल पर आवागमन बन्द कर दिया था। कौसिल की बठक मे पटेल ने लियाकत को इस पुल को खुलवाने के लिए हरचन्द मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फल नही हुआ। बाद मे, निजी चर्चा के समय माउन्टबेटन ने लियाकत से अन्तिम अपील की और पाकिस्तान रवाना होने से पूर्व वह लियाकत से इस फैसले को रद्द करवाने मे सफल हुए।

जूनागढ के बारे मे भी कुछ साफ-साफ बाते हुई। माउन्टबेटन को पहले तो किसी प्रधान मत्री द्वारा इस प्रश्न को उठवाने मे ही भारी कठिनाई का सामना करना पडा। लियाकत का रुख था—"मै क्यो उठाऊ? हमने कोई गलती नही की। यदि भारत को परेशानी है तो वह उठाये।" उधर नेहरू महसूस करते थे कि यदि मैंने प्रश्न उठाया तो इसे कमजोरी का चिह्न समझा जायगा। आखिर माउन्टबेटन ने लियाकत को चर्चा छेडने के लिए राजी कर लिया। मगरोल और बाबरियावाड पर बातचीत होने लगी। नेहरू और माउन्टबेटन ने स्पष्ट किया कि इन दोनो राज्यो को भारत मे शामिल होने का पूरा अधिकार है। नेहरू ने लियाकत से अनुरोध किया कि वह बाबरियावाड से जूनागढ की फौजे हटाने का आदेश दे। जब ये बाते हो रही थी उस समय एक तार मिला कि जूनागढ की सेनाए मगरोल मे घुस गई है। नेहरू ने वचन दिया कि यदि जूनागढ की सेनाए तुरन्त हटा ली गई तो वह भारतीय सेनाओ को तबतक उन रियासतो मे दाखिल न होने देगे, जबतक उन दोनो की कानूनी स्थिति किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा तय न करा ली जायगी।

इस विषय में लियाकत का रुख समझौते का था, किन्तु जूनागढ़ के पाकिस्तान-प्रवेश के प्रश्न पर उनका हठ था कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। उनके तर्क का आधार यह था कि राज्य के शासक को नैतिक या साम्प्रदायिक पहलुओं का विचार किये बिना किसी भी संघ में शामिल होने का पूरा अधिकार है।

: १८ :

काश्मीर का झमेला

नई दिल्ली, मंगलवार, २८ अक्तूबर १९४७

सोमवार के सवेरे से भारतीय सेनाएं हवाई जहाज द्वारा काश्मीर जा रही थीं, यह सूचना पालम हवाई अड्डे पर उतरते ही वर्नोन ने मुझे दी। लगभग पौने तीन बजे रात को मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि इतने में पीटर रीस ने मुझे बुलाया और कहा कि माउन्टबेटन काश्मीर की नवीनतम स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी देने को बुला रहे हैं।

माउन्टबेटन ने कहा कि घटनाओं ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। काश्मीर की ग्रीष्म राजधानी श्रीनगर पर तेजी से आने वाले उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश के कबाइलियों का विशाल हमला रोकने के लिए पहली सिख बटालियन के तीन सौ तीस सिपाही काश्मीर भेजे जा चुके हैं। वह चाहते थे कि समाचार पत्रों से सम्पर्क बना रखने का काम मैं कल सवेरे से ही शुरू कर दूं। लेकिन वह महसूस कर रहे थे कि इसके लिए पहले यह जरूरी होगा कि हम इस घटना के उन मूल-तत्वों को जान लें जो हमारे लन्दन-प्रवास के दौरान में घटी थीं। मुझे इतनी जानकारी तो थी कि सितम्बर के प्रारम्भ में काश्मीर और पाकिस्तान के बीच कायम हुए नये-नये सम्बन्धों में गड़बड़ी उठ खड़ी हुई थी। काश्मीर सरकार ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया था कि वह कई अत्यावश्यक वस्तुएं भेजने में आनाकानी कर रहा है और साथ ही सीमावर्ती हमलों के बारे में भी शिकायत की थी। उधर पाकिस्तान ने भी प्रत्युत्तर में कई आरोप लगाए थे। सत्ता-हस्तांतरण और संघ-प्रवेश की आखिरी तारीख के तीन दिन पहले काश्मीर सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ "यथास्थिति समझौते" पर हस्ताक्षर करने के अपने निश्चय की घोषणा की। इसके फलस्वरूप भारत सरकार की नीति यह थी कि काश्मीर को संघ-प्रवेश के लिए कुछ भी कहा-सुना न

जाय। इतना ही नही, पटेल के आदेशानुसार रियासती सचिवालय ने ऐसे सब कामो से अपना हाथ खीच लिया, जिसका अर्थ काश्मीर पर दबाव डालना हो सकता था और उन्होने यह आश्वासन दिया कि काश्मीर का पाकिस्तान मे शामिल होना भारत मे गलत नही समझा जायगा। प्रस्तुत सकट का सब मे बडा कारण काश्मीर-नरेश की निर्णय न करने की पुरानी बीमारी समझना चाहिए। अगर कोई भी मार्ग अविलम्ब अपना लिया गया होता तो काश्मीर इस आफत से बच जाता। टालमटोल ही घातक सिद्ध हुआ। लेकिन लगता यह था कि बडे सकट का सामना करने के लिए निजाम की भाति काश्मीर नरेश भी अपने कूटनीतिक तरकस के इसी तीर का आसरा लेते है।

आज जो कदम उठाया गया था उसकी सैनिक और राजनैतिक प्रतिक्रिया काफी गभीर होगी, इसके बारे मे माउन्टबेटन को किसी प्रकार का शक नही। हालाकि अब वह सलाह देने के अतिरिक्त और कुछ भी नही कर सकते, लेकिन मेरी यह दृढ धारणा थी कि उनकी उपस्थिति ने पजाब और जूनागढ की समस्याओ मे उलझी उनकी सरकार को नाजुक खतरो से बचाने मे भारी सहायता पहुचाई थी।

उनसे मझे पता चला कि गत शुक्रवार की रात को (२४ अक्तूबर) स्याम के विदेश-मत्री के स्वागत मे दिये गए भोज के समय नेहरू ने इस अशुभ समाचार का पहली बार जिक्र किया था और बतलाया था कि सैनिक लारियो द्वारा कबाइलियो को रावलपिडी रोड से काश्मीर भेजा जा रहा है। रियासती सेनाओ का कही पता नही था और स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही थी। माउन्टबेटन शनिवार २५ अक्तूबर को सुरक्षा-कमेटी की बैठक मे उपस्थित थे। उसमे जनरल लाकहार्ट ने पाकिस्तान सेना के प्रधान कार्यालय से प्राप्त एक तार पढ कर सुनाया, जिसमे कहा गया था कि लगभग पाच हजार कबाइलियो ने मुजफ्फराबाद और दोमेल पर कब्जा कर लिया था और बडी भारी सख्या मे कबाइली कुमुक इन स्थानो मे पहुचने की सभावना है। सूचनाओ से पता चलता था कि वे श्रीनगर से पैंतीस मील से ज्यादा दूरी पर नही थे।

सुरक्षा समिति का विचार था कि तात्कालिक आवश्यकता शस्त्र और गोला-बारूद भेजने की है, जिसकी काश्मीर सरकार ने माग की थी। इसकी मदद से श्रीनगर की स्थानीय जनता हमलावरो के खिलाफ थोडी-बहुत मोर्चेबदी कर सकेगी। सेनाए भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। इस पर माउन्टबेटन ने समझाया कि जबतक काश्मीर भारत-सघ मे शामिल नही हो जाता तबतक वहा सेनाए भेजना खतरनाक होगा। उन्होने यह भी कहा कि सघ-प्रवेश अस्थायी होना चाहिए ौर उसकी पुष्टि बाद मे जनमत-सग्रह द्वारा की जाय। २५ तारीख की ब क मे इन महत्वपूर्ण प्रश्नो पर कोई आखिरी फैसला नही किया गया, लेकिन यह जरूर तय हुआ कि वी पी मेनन तुरन्त हवाई जहाज से श्रीनगर जाय और वहा

की ठीक-ठीक स्थिति का पता लगावे ।

दूसरे दिन सुरक्षा-समिति को जो जानकारी मेनन ने श्रीनगर से लौट कर दी वह निश्चय ही काफी चिंताजनक थी। उन्होंने बतलाया कि घटनाओं के इस तेज दौर से महाराज के हाथ-पैर फूल गए है और वह अपने एकाकीपन और बेबसी के भार से दबे हुए है। आखिर स्थिति को गंभीरता का बोध उन्हें हुआ और उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत ने सहायता नही दी तो सब चौपट हो जायगा। मेनन की जोरदार सलाह को मान कर उसी दिन महाराज ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ श्रीनगर छोड दिया। मेनन ने उन्हे समझाया कि हमलावरो ने बारामूला पर अधिकार कर लिया है। इसलिये उनका राजधानी मे ठहरना भारी भूल होगी। महाराज ने संघ-प्रवेश-पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस पत्र को मेनन ने सब-सुरक्षा-कमेटी के सामने पेश किया।

जहा तक सैनिक स्थिति का प्रश्न था, मेनन ने राय दी कि श्रीनगर मे बाकी बची फौजे हमलावरो को रोकने मे कामयाब नही होगी, क्योकि वह घुडसवार सेना का एक स्क्वेडरन मात्र है। इस निराशापूर्ण परिस्थिति को ध्यान मे रखकर मंत्रि-मंडल ने निश्चय किया कि महाराज द्वारा भेजे संघ-प्रवेश-पत्र को स्वीकार किया जाय और दूसरे दिन सवेरे पैदल सेना की एक बटालियन हवाई जहाज द्वारा रवाना की जाय।

इसके बाद माउन्टबेटन ने मुझे विस्तार के साथ बतलाया कि उन्होंने संघ-प्रवेश के प्रश्न पर सुरक्षा-समिति मे यह रुख क्यो अपनाया था और क्यो वह इस विषय पर अपने पहले के मत को बदलने के लिए बाध्य हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज को उन्होंने यह सलाह दी थी कि वह सत्ताहस्तान्तरण के पहले यह निश्चय कर ले कि वह किस देश मे शामिल होगे। लेकिन साथ ही, उन्होंने जून मे अपनी काश्मीर-यात्रा के समय से लेकर अपना सारा जोर इस बात पर लगाया था कि जनता का मत लिये बिना वह दोनो मे से किसी भी देश मे शामिल न हो। जनता की राय वह मत-गणना या चुनाव या सार्वजनिक प्रतिनिधि सभाओ द्वारा प्राप्त कर सकते थे। जब पिछले अडतालिस घण्टो मे उन्हे निश्चय हो गया कि अपने सेना-पतियो और खुद उनकी सैनिक सलाह के बावजूद सरकार काश्मीर की प्रार्थना पर हवाई जहाज द्वारा सहायता के लिए फौज भेजने पर तुली हुई है तो वह फिर संघ-प्रवेश के प्रश्न पर अड गए।

उन्होंने कहा कि एक तटस्थ देश मे फौजे भेजना भयंकर भूल होगी, क्योकि ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नही और पाकिस्तान भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। और ऐसा होने का नतीजा सिवा युद्ध के और कुछ नही होगा। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि यदि वे फौजे भेजनेपर तुले हुए है तो इसकी अनिवार्य शर्त यह होगी कि इसके पूर्व ही संघ-प्रवेश की कार्यवाही पूरी हो जाय और यदि यह स्पष्ट

नही कर दिया जाता कि सघ-प्रवेश काश्मीर हथियाने की चालमात्र नही तो यह खुद युद्ध भडकाने का कारण बन सकता था। इसलिए उन्होने इजाजत चाही कि अपनी सरकार की तरफ से महाराज के सघ-प्रवेश के विलय-पत्र के उत्तर मे भेजे जाने वाले पत्र मे उन्हे यह भी जोड दिया जाय यह सघ-प्रवेश जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा, जिसका निश्चय न्याय और व्यवस्था कायम होते ही किया जायगा। यह सिद्धान्त तुरन्त स्वीकार कर लिया गया ओर नेहरू ने निर्विरोध इसे प्रस्ताव के रूप मे पेश कर दिया।

सघ-प्रवेश के वाद लोकप्रिय सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से महाराज ने नेशनल कार्फेस के नेता शेख अव्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया था। अब उन्हे अन्तरिम सरकार का प्रधान बनाया जा रहा था। सघ-प्रवेश की नियमितता असदिग्ध थी। इस प्रश्न पर जिन्ना को अपनी ही चाल का शिकार होना पडा, क्योकि उन्होने ही जूनागढ के प्रश्न पर शासक के व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार की अकाट्यता का सिद्धान्त पेश किया था।

चार बजे सवेरे के जरा पहले ही माउन्टबेटन ने हमारे ऊपर तरस खा कर हमे छुट्टी दे दी, अन्यथा मै शायद उनके सामने ही झपकी लेने लगता।

आज के आफत भरे दिन ही सारी-की-सारी चीजे एक साथ टूट पडी थी। पत्रकारो को मुलाकाते देने के लम्बे ताते के बाद माउन्टबेटन और नेहरू से चर्चा करने के लिए बुलावा आ गया। उनके साथ आजतक की शासकीय सफलताओ के बारे मे एक वक्तव्य तैयार करने के प्रश्न पर चर्चा हुई। इस वक्त तो यह चीज मुझे एक अच्छी-खासी दिमागी कसरत लग रही थी। नेहरू को इतना परेशान और अस्वस्थ देख कर मुझे वडा सदमा पहुचा।

माउन्टबेटन 'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय रुख से चिंतित थे। इस पत्र ने बिगडते हुए भारत-पाक-सम्बन्धो से व्यग्र होकर भारतीय सेनाओ के काश्मीर-प्रवेश की भर्त्सना कर डाली थी। माउन्टबेटन ने मुझसे कहा कि पत्र के सम्पादक आइन स्टीफेस को मिलने के लिए बुलाने की व्यवस्था करो। लगभग एक घटे बाद आइन स्टीफेस हमारे बीच आ पहुचे। माउन्टबेटन ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, "किसी राष्ट्र का निर्माण तिकडमबाजी के आधार पर नही किया जा सकता।" उन्होने कहा कि एबटाबाद मे बैठे जिन्ना विजेता के रूप मे काश्मीर पहुचने की आस लगाये है। उनकी आशाओ पर तुषारपात हो गया। पहले जूनागढ की घटना घटी और फिर कल हैदराबाद के प्रतिनिधि मडल के जबरन रोके जाने की प्रमादपूर्ण घटना। काश्मीर के बारे मे भारत ने जो कदम उठाया वह बिलकुल अलग किस्म की बात थी। जनमत को स्वीकार करने का अपना निश्चय उसने पहले ही घोषित कर दिया था। अगर कोई फौजी कदम नही उठाया जाता तो कबाइलियो द्वारा कत्लेआम किया जाना अनिवार्य हो जाता—श्रीनगर के कुछ सौ ब्रिटिश

नागरिक भी उससे नही बचते। महाराज द्वारा सघ-प्रवेश कर लेने के बाद जो भी कदम उठाये गए वे कानूनी तौर से बिलकुल जायज है।

अपनी चर्चा समाप्त करते हुए उन्होने स्टीफेस से कहा कि आचिन्लेक के हस्तक्षेप के फलस्वरूप जिन्ना को इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि काश्मीर-सकट के विषय मे चर्चा करने के लिए माउन्टबेटन ओर नेहरूको कल लाहौर आमन्त्रित किया जाय।

आज की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद आचिन्लेक ने लाहौर से माउन्ट-बेटन को फोन पर कहा कि उन्होने जिन्ना को कल रात का उनका यह हुक्म रद्द करने पर राजी कर लिया है कि पाकिस्तानी सेनाए काश्मीर मे भेज दी जाय। जनरल मेसर्वी की अस्थायी अनुपस्थिति मे जिन्ना का हुक्म पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान सेनापति जनरल ग्रेसी के पास पश्चिमी पजाब के गवर्नर के सेक्रेटरी द्वारा पहुचा था, जहा जिन्ना ठहरे हुए थे। ग्रेसी ने उत्तर दिया कि सर्वोच्च सेनापति की स्वीकृति के बिना वह ऐसे कोई आदेश जारी करने को तैयार नही। ग्रेसी के जरूरी बुलावे पर आचिन्लेक आज सवेरे हवाई जहाज से लाहौर पहुचे। उन्होने जिन्ना को समझाया कि चूंकि काश्मीर भारत-सघं मे शामिल हो गया है, इसलिए भारत सरकार को महाराज की प्रार्थना पर अपनी सेनाए काश्मीर मे भेजने का पूरा-पूरा अधिकार है।

आचिन्लेक के वहा से चलने के पूर्व न सिर्फ यह हुक्म ही रद्द कर दिया गया बल्कि माउन्टबेटन और नेहरू को लाहौर आने का निमत्रण भी दे दिया गया।

टेलीफोन पर लबी माथापच्ची करने के बाद जब वर्नोन काफी देर के बाद रात का खाना खाने पहुचे तो उन्होने कहा, "सब चोपट हो गया।" उन्होन कहा कि "सारी योजना ठडी हो गई, क्योकि अस्वस्थता के कारण नेहरू लाहौर जाने मे असमर्थ है।"

आज रात फिल्म-प्रदर्शन के बाद माउन्टबेटन ने रोनी, वर्नोन तथा मुझे आज की घटनाओ पर चर्चा करने के लिए बुलाया। माउन्टबेटन ने कहा कि उन्होन आज सवेरे हुई सुरक्षा समिति की बैठक मे लाहौर जाने के लिए बहुत जोर डाला। उनका रोब इतना अधिक था कि वहा तो किसी ने उनका विरोध नही किया, किन्तु उन्हे पता चला कि आज तीसरे पहर मत्रिमडल की बैठक मे नेहरू पर लाहौर न जाने के लिए भारी दबाव डाला गया। घर पहुचने पर नेहरू कमजोरी के मारे गिरते-गिरते बचे और उन्हे लिटा दिया गया। माउन्टबेटन का विश्वास था कि नेहरूकी अस्वस्थता वास्तविक है। नेहरू इस बात के लिए सहमत हो गए कि माउन्टबेटन जिन्ना को सन्देश भेज कर उनकी बीमारी की बात बतलाते हुए बैठक की तारीख बढाने के लिए कहे। माउन्टबेटन ने कल सवेरे जिन्ना को फोन करने का निश्चय किया, जिससे नेहरू के स्वास्थ्य के बारे मे व्यक्तिगत जानकारी दे.

उन्हे खुद दिल्ली बुलाने की कोशिश कर सके।

नई दिल्ली, बुधवार, २९ अक्तूबर १९४७

माउन्टबेटन आज सवेरे नेहरू को देखने उनके घर गये। पटेल भी वहा पहुचे। लाहौर-यात्रा की उपादेयता के विषय मे साफ-साफ बाते हुई। माउन्टबेटन ने कहा कि वह अकेले जाने को तैयार है—जब दोनो देशो को विनाश से बचाने का सवाल सामने है तो वह अपने स्वाभिमान की भावनाओ को ताक पर रखने के लिए तैयार है। पटेल ने कहा कि वह और मत्रिमडल के अन्य सदस्य दोनो मे से किसी के भी जाने के सख्त खिलाफ है। इसपर माउन्टबेटन ने याद दिलाई कि लियाकत बीमार है और सयुक्त सुरक्षा-कौसिल की बैठक वैसे भी इस सप्ताह होने को है। इस बैठक मे भाग लेने के लिए नेहरू और उनका लाहौर जाना दोस्ती की भावना को बल देगा। नेहरू राजी हो गए। माउन्टबेटन ने सरकारी भवन लौटते ही जिन्ना को फोन किया। जिन्ना को इस प्रस्ताव से खुशी हुई। पाच मिनट बाद डून केम्पबेल ने मुझ से फोन पर पूछा कि क्या इस अफवाह मे कोई सचाई है कि माउन्टबेटन ने अभी-अभी जिन्ना से बात की है।

माउन्टबेटन की आज गाधीजी के साथ नव्वे मिनट तक बातचीत हुई। कल की प्रार्थना सभा के समय महात्माजी ने काश्मीर के बारे मे एक बिल्कुल 'चर्चिल-पथी' बात कह डाली थी। उसका भाव कुछ इस प्रकार था—फल भगवान् के हाथ मे है। मनुष्य तो केवल कर या मर ही सकता है। यदि काश्मीर की रक्षा करने वाली नन्ही-सी भारतीय सेना का थर्मोपली की वीरता से रक्षा करने वाली स्पार्टा-फौजो के समान सफाया हो गया, तो भी वह आसू नही बहाएगे। शेख अब्दुल्ला और उनके मुसलमान, हिन्दू तथा सिख साथी यदि काश्मीर की रक्षा करते हुए काम आयगे तो उन्हे जरा भी दु ख नही होगा। पूरे भारत के लिए यह एक ज्वलत उदाहरण होगा। इस वीरता भरे मुकाबले का पूरे देश पर असर पडेगा और सब लोग यह भूल जायगे कि हिन्दू, मुसलमान और सिख कभी एक-दूसरे के दुश्मन भी रहे थे।

तात्कालिक सैनिक स्थिति गभीर थी। सोमवार को जो बटालियन हवाई जहाज द्वारा भेजी गई थी उसके कमाडिग अफसर मारे गए थे। फौजो को पीछे हटना पडा था और श्रीनगर के पश्चिम मे लगभग साढे चार मील की दूरी पर भयकर युद्ध हो रहा था।

यह ध्यान देने की बात है कि काश्मीर के सकट की हैदराबाद पर बडी तेज प्रतिक्रिया हुई। काश्मीर के सघ-प्रवेश और वहा फौजो के पहुचने के चौबीस घटे बाद ही यह समाचार आया कि दिल्ली मे यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रवाना होने वाले हैदराबादी प्रतिनिधि मडल को इत्तिहादी भीड द्वारा बडे

भारत मे शामिल होता है तब तो "धोखा और हिंसा" लेकिन जब जूनागढ पाकिस्तान मे शामिल होता है तो कानूनी रूप से वैध। भारत के लिए जूनागढ संबधी प्रचार का तात्कालिक महत्व बहुत अधिक था, परन्तु पटेल अपने को रियासती-मत्री पहले और प्रचार-मत्री बाद को मानते थे।

यह मानना होगा कि भारत सरकार को उत्तेजित करने मे कोई कसर नही छोडी गई थी। १ अक्तूबर को लियाकत के साथ भेट होने के बाद नेहरू को कम-से-कम तीन बार पाकिस्तान सरकार को लिखना पडा कि मगरोल तथा बाबरियावाड से जूनागढ की सेनाए तुरन्त हटाई जावे। तीन सप्ताह बाद लियाकत का उत्तर आया, जिसमे पहले के एक लापता उत्तर का उल्लेख था और कहा गया था कि सेनाए हटाने का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद भी हुआ कुछ नही।

अक्तूबर १६ को लाहौर मे सयुक्त सुरक्षा-कौन्सिल की बैठक मे लियाकत ने कहा कि मै जूनागढ मे जनमत-सग्रह के सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हू। नेहरू ने प्रस्ताव किया कि वी पी मेनन को सामान्य विचार-विमर्श के लिए लाहौर भेजा जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वी पी को कराची भेजने को कहा। २१ तारीख को सुरक्षा-समिति ने स्वीकार कर लिया कि मगरोल और बाबरियावाड पर अधिकार करना ही होगा। दो दिन बाद एक योजना बनाई गई और उसके दो दिन बाद—किन्तु काश्मीर के विस्फोट से केवल ३६ घटे पूर्व—उसे अतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

नई दिल्ली, रविवार, २ नवम्बर १९४७

अपने परिवार से मिलने मै हवाई जहाज से शिमला गया था। जब दिल्ली लौटा तब मुझे माउन्टबेटन-परिवार के साथ भोजन करने का निमत्रण मिला। अतिथियो मे बीकानेर के महाराजा भी थे। भोजन के बाद एक फिल्म दिखाई गई, जिसमे विस्थापितो की निकासी और कल्याण-कार्य मे बीकानेर राज्य के सहयोग का प्रदर्शन था। बीकानेर महाराज इस फिल्म की टीका करते जाते थे। इस सुन्दर रगीन फिल्म मे यह दिखाया गया था कि किस प्रकार पाच लाख से अधिक विस्थापित राज्य से बाहर भेजे गए। ये लोग हजारो के झुड बनाकर ऊसर जमीन पर होते हुए आगे बढने लगे। इसके कारण बीकानेर की साधन-सामग्री तथा यातायात के साधनो, पर, अचानक अत्यधिक भार आ पडा। इस पर भी सारी निकासी मे केवल १५० मुसलमानो की रास्ते मे मृत्यु हुई।

माउन्टबेटन खुश थे। उन्होने मुझे बताया कि लाहौर मे उनकी जिन्ना से ३॥ घटे तक बातचीत हुई, जिससे उन्हे सतोष था। दोनो ने काफी खुल कर बातचीत की। यदि वह अपने-अपने प्रधान मत्रियो के साथ होते तो ऐसा सम्भव न हो पाता। जिन्ना

भारत मे शामिल होता है तब तो "धोखा और हिसा" लेकिन जब जूनागढ पाकिस्तान मे शामिल होता है तो कानूनी रूप से वैध। भारत के लिए जूनागढ सबधी प्रचार का तात्कालिक महत्व बहुत अधिक था, परन्तु पटेल अपने को रियासती-मत्री पहले और प्रचार-मत्री बाद को मानते थे।

यह मानना होगा कि भारत सरकार को उत्तेजित करने मे कोई कसर नही छोडी गई थी। १ अक्तूबर को लियाकत के साथ भेट होने के बाद नेहरू को कम-से-कम तीन बार पाकिस्तान सरकार को लिखना पडा कि मगरोल तथा बाबरियावाड से जूनागढ की सेनाए तुरन्त हटाई जावे। तीन सप्ताह बाद लियाकत का उत्तर आया, जिसमे पहले के एक लापता उत्तर का उल्लेख था और कहा गया था कि सेनाए हटाने का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद भी हुआ कुछ नही।

अक्तूबर १६ को लाहौर मे सयुक्त सुरक्षा-कौन्सिल की बैठक मे लियाकत ने कहा कि मै जूनागढ मे जनमत-सग्रह के सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हू। नेहरू ने प्रस्ताव किया कि वी पी मेनन को सामान्य विचार-विमर्श के लिए लाहौर भेजा जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वी पी को कराची भेजने को कहा। २१ तारीख को सुरक्षा-समिति ने स्वीकार कर लिया कि मगरोल और बाबरियावाड पर अधिकार करना ही होगा। दो दिन बाद एक योजना बनाई गई और उसके दो दिन बाद—किन्तु काश्मीर के विस्फोट से केवल ३६ घटे पूर्व—उसे अतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

नई दिल्ली, रविवार, २ नवम्बर १९४७

अपने परिवार से मिलने मै हवाई जहाज से शिमला गया था। जब दिल्ली लौटा तब मुझे माउन्टबेटन-परिवार के साथ भोजन करने का निमत्रण मिला। अतिथियो मे बीकानेर के महाराजा भी थे। भोजन के बाद एक फिल्म दिखाई गई, जिसमे विस्थापितो की निकासी और कल्याण-कार्य मे बीकानेर राज्य के सहयोग का प्रदर्शन था। बीकानेर महाराज इस फिल्म की टीका करते जाते थे। इस सुन्दर रगीन फिल्म मे यह दिखाया गया था कि किस प्रकार पाच लाख से अधिक विस्थापित राज्य से बाहर भेजे गए। ये लोग हजारो के झुड बनाकर ऊसर जमीन पर होते हुए आगे बढने लगे। इसके कारण बीकानेर की साधन-सामग्री तथा यातायात के साधनो, पर, अचानक अत्यधिक भार आ पडा। इस पर भी सारी निकासी मे केवल १५० मुसलमानो की रास्ते मे मृत्यु हुई।

माउन्टबेटन खुश थे। उन्होने मुझे बताया कि लाहौर मे उनकी जिन्ना से ३॥ घटे तक बातचीत हुई, जिससे उन्हे सतोप था। दोनो ने काफी खुलकर बातचीत की। यदि वह अपने-अपने प्रधान मत्रियो के साथ होते तो ऐसा सम्भव न हो पाता। जिन्ना

ने बातचीत की शुरुआत इस शिकायत से की कि भारत सरकार ने अपने इरादो की चेतावनी पाकिस्तान सरकार को समय पर नही दी। माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि जिस बैठक मे काश्मीर को हवाई जहाज से फौज भेजने का निर्णय किया गया, उसकी समाप्ति पर नेहरू ने जो काम सबसे पहले किया, वह था लियाकतअली को तार देना। तब जिन्ना ने अपने इस सार्वजनिक वक्तव्य को दोहराया कि काश्मीर का भारत मे मिल जाना वास्तविक नही, क्योकि वह हिसा और धोखेवडी पर आधारित था, और इसलिए उसको पाकिस्तान स्वीकार नही कर सकता।

इसके बाद तर्क-वितर्क का एक बडा ही विषम-चक्र चल पडा। माउन्टबेटन ने इस बात को स्वीकार किया कि बल-प्रयोग के ही कारण काश्मीर भारत मे सम्मिलित हुआ है। किन्तु बल-प्रयोग कबाइलियो की ओर से हुआ था, जिसके लिए भारत नही, पाकिस्तान उत्तरदायी था। इसके उत्तर मे जिन्ना ने कहा कि मेरी राय मे तो सेना भेजकर भारत ने ही बल-प्रयोग किया है। किन्तु माउन्टबेटन अपने इसी तर्क पर अडे रहे कि बल-प्रयोग तो वास्तव मे कबाइलियो ने किया। बहस इसी तरह चलती रही। आखिर जिन्ना इसे माउन्टबेटन की धावली कह कर अपने क्रोध को छिपा नही सके।

माउन्टबेटन ने जिन्ना को बतलाया कि श्रीनगर मे भारतीय सेनाओ की शक्ति कितनी थी और अगले कुछ दिनो मे वह कितनी बढ जायगी। उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब कबाइलियो के श्रीनगर मे घुसने की सभावना नही रही। इस पर जिन्ना ने फिर अपना वही पुराना प्रस्ताव रखा कि दोनो दल अपनी-अपनी सेनाए फौरन और एक साथ हटा ले। जब माउन्टबेटन ने उनसे पूछा कि कबाइलियों को वापस जाने के लिए किस तरह तैयार किया जायगा तो जिन्ना ने जवाब दिया "अगर आप इतना कर देगे तो मै आक्रमण का अन्त करवा दूँगा।" इससे कम-से-कम यह ध्वनि तो निकलती ही थी कि पाकिस्तान के इस सार्वजनिक प्रचार का, कि कबाइलियो का आक्रमण पाकिस्तान के अधिकार से बाहर की बात थी, आपसी बातचीत मे ज्यादा सहारा नही लिया जायगा।

जाच-पडताल करने पर माउन्टबेटन को यह पता चला कि जनमत-सग्रह के बारे मे जिन्ना की जो मनोवृत्ति थी, उसके पीछे यह विश्वास काम कर रहा था कि काश्मीर मे भारतीय सेना की उपस्थिति और वहा की सत्ता का शेख अब्दुल्ला के हाथो रहने का अर्थ यह होगा कि वहा की साधारण मुस्लिम जनता इतनी भयभीत हो जायगी कि पाकिस्तान के पक्ष मे मत नही देगी। माउन्टबेटन ने प्रस्ताव रखा कि सयुक्त राष्ट्र सघ के तत्वावधान मे जनमत सग्रह किया जाय। इस पर जिन्ना ने कहा कि यह काम तो केवल दोनो गवर्नर-जनरल ही कर सकते है। इस सुझाव को माउन्टबेटन ने तुरन्त ठुकरा दिया और इस बात पर जोर दिया कि जिन्ना के हाथो मे कितने ही अधिकार क्यो न हो, जहा तक (माउन्टबेटन का) अपना सवाल है,

उनकी वैधानिक स्थिति ऐसी है कि वह केवल अपनी सरकार के परामर्श के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं।

जिन्ना को इससे बडी निराशा हुई और उन्होने सोचा कि जो भाग्य मे बदा होगा, वही होगा। वह यही राग अलापते रहे कि भारत उनके बनाये हुए राष्ट्र को मिटा देना चाहता है। काश्मीर के सम्बन्ध मे जिस किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता या जिस किसी नीति की चर्चा की जाती, सभी को जिन्ना अपने इसी रंगीन चश्मे से देखते। माउन्टबेटन और इस्मे ने, जो अधिकाश वार्तालाप मे मौजूद थे, जिन्ना को हर तरह से आश्वासन देने की भरपूर चेष्टा की। यह तो कहना कठिन है कि इसका उनपर प्रभाव पडा या नही। किन्तु कम-से-कम बाहरी तौर पर वे सौहार्द की भावना के साथ ही एक-दूसरे से विदा हुए।

माउन्टबेटन का कहना था कि २७ अक्तूबर को भारत ने हवाई जहाजो द्वारा सेना भेजने का जो काम किया था, उसकी गति के सामने तो दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान की सरगर्मी भी फीकी पड गई। निस्सन्देह इससे जिन्ना भी स्तब्ध रह गए थे, क्योकि भारतीय सेना का वह चमत्कार उनके अनुमान के बिलकुल परे था।

माउन्टबेटन के आशावाद और स्पष्टवादिता के बावजूद पिछले कुछ दिनो मे जो घटनाए घटी, उनसे माउन्टबेटन और जिन्ना के बीच की खाई अनिवार्य रूप से चौडी ही होती गई। उसे यह पिछली मुलाकात भी किसी प्रकार कम न कर सकी। जिन्ना ने माउन्टबेटन को अपने ही दृष्टिकोण से आका होगा और यह मान लिया होगा कि उन्हे अब भी वाइसराय के सभी अधिकार प्राप्त है। सम्भवत उसी के फलस्वरूप उन्होने यह भी सोचा होगा कि शायद माउन्टबेटन ने ही काश्मीर के विलय को स्वीकार करनेवाले पत्र को लिखवाया होगा, उन्होने ही २७ अक्तूबर वाले वीरतापूर्ण चमत्कार का निर्देशन किया होगा। पाकिस्तान के हितो तथा महत्वाकाक्षाओ मे अचानक यह जो गम्भीर बाधा पड़ी थी, साधन रूप मे उसके भी वही प्रेरक रहे होगे।

यदि बात ऐसी थी तो निस्सन्देह यह सत्य का एक विकृत और दु खपूर्ण दिग्दर्शन था। ३ जून की योजना की स्वीकृति के बाद से ही माउन्टबेटन ने दोनो उत्तराधिकारी राज्यो के बीच सद्भावना को बढाना अपने मिशन का मुख्य लक्ष्य बना लिया था। जिन्ना वैयक्तिक मान-मर्यादा की ओर से उदासीन नही थे। किन्तु आश्चर्यकी बात थी कि वह यह नही समझ पा रहे थे कि इस कार्य मे असफल होने को माउन्टबेटन भी एक वैयक्तिक असफलता मान सकते है। जिन्ना को काश्मीर के सम्बन्ध मे बौखलाहट तो थी ही, इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव था कि जिन्ना इस बात को नही समझते कि व्यापक-दृष्टि से अब माउन्टबेटन को भारत सरकार के निश्चयो मे नरमी लाने या मध्यस्थता कराने के अधिकार ही रह गए थे। जैसा कि हम देख चुके है, गवर्नर-जनरल के उचित कर्त्तव्यो के सम्बन्ध मे जिन्ना के विचार उसी समय स्पष्ट हो गए थे

जब उन्होंने स्वतन्त्रता विधेयक के अन्तर्गत मिले हुए अपने विशेष अधिकारों को फौरन ही अपने हाथों में ले लिया था।

यह बात भी कम महत्व की नहीं थी कि यद्यपि जिन्ना और माउन्टबेटन में एक-दूसरे के लिए काफी आदर की भावना थी, फिर भी जिन्ना ने अब अपना सारा ध्यान कूटनीति में ही लगा दिया था। गहरे भय और कठोर दावपेच की जिन अतुल गहराइयों तक माउन्टबेटन नहीं पहुंच सकते, वे ही आज जिन्ना पर हावी थीं।[1]

नई दिल्ली, सोमवार, ३ नवम्बर १९४७

सारा ध्यान काश्मीर के प्रश्न पर केन्द्रित होने के कारण हैदराबाद नजरों में ओझल हो गया था। लेकिन कल ही माउन्टबेटन के सामने हैदराबाद का एक नया प्रतिनिधि-मंडल आया। तीन व्यक्तियों वाले इस प्रतिनिधि-मंडल के नेता मोइन-नवाज जंग थे, जो इत्तिहाद के मजबूत लोगों में गिने जाते थे। लगता था कि १५ अगस्त की अपेक्षा आज हम समझौते से कहीं दूर थे। काश्मीर के संघ-प्रवेश और वहां सेनाएं उतरने के दूसरे दिन जो घटनाएं घटीं उनको देखते हुए यही कम अचरज की बात नहीं कि चर्चाएं अब भी जारी थीं। अगर माउन्टबेटन और मांकटन ने दृढ़ता न दिखाई होती तो चर्चाएं कब की खतम हो गई होतीं। आज हालत यह थी कि निजाम ने वह बचाखुचा विश्वास भी खो दिया था, जो भारत सरकार, खास कर सरदार पटेल, को उनमें था। मुझे शक था कि उनमें कभी फिर पहले जैसे सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे।

इसमें और मेरी लंदन-यात्रा के काल में माउन्टबेटन ने ऐसा हल खोजने में समझौता कराने की अपनी सारी कला खर्च कर दी थी, जिससे संघ प्रवेश और संघ-सरकार के बीच के अन्तर को पाटा जा सके। उन्होंने यहां तक किया कि एक भारी भरकम मसविदा तैयार कराया जो समझौते के रूप में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जा सके, और सरदार के लिए उसका अर्थ संघ-प्रवेश हो और निजाम के लिए सहकार।

---

१. माउन्टबेटन के लिए जिन्ना का यह आदर-भाव कितना गहरा था इसका रहस्योद्घाटन जिन्ना के एक निजी मित्र ने मुझसे पिछले दिनों किया। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले जिन्ना ने यहां तक कहा था कि अपनी तमाम जिन्दगी में जिस एक आदमी ने मुझ पर असर डाला है, वह है लार्ड माउन्टबेटन। जब मैं उनसे पहली बार मिला तब मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें 'नूर' है। उन्होंने यह भी कहा था कि माउन्टबेटन जितने समय भी भारत में रहे मैंने कभी उनकी ईमानदारी पर शंका नहीं की।

इस विश्वास से कि जबतक-माकटन मोजूद रहते है तभी तक निजाम पर आधुनिकता का प्रभाव रह सकता था, माउन्टबेटन ने यह बात मजूर कराने की जीतोड कोशिश की कि वी पी मेनन को वहा जाने दिया जाय, जिसमे चर्चाए हैदराबाद मे ही हो सके। जब वी पी को दोनो ओर से परवानगी मिल गई और वह जाने के लिए बिलकुल तैयार बैठे थे कि निजाम ने इस बिना पर मेनन की यात्रा खारिज करा दी कि उनके आगमन से व्यर्थ प्रदर्शन होगा। जिन शब्दो मे निजाम ने यह यात्रा खारिज की और जिन शब्दो मे पटेल ने इसका उत्तर दिया वह दोनो पक्षो की भावनाओ को इस कदर चोट पहुँचानेवाले थे कि चर्चाओ का हमेशा के लिए अन्त हो जाता।

इसी समय माउन्टबेटन ने माकटन को अपने व्यक्तिगत अतिथि के नाते दिल्ली आने का बुलावा दिया। १० अक्तूबर को माकटन ने एक वर्ष के लिए 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर किये जाने का सुझाव दिया, जिससे भारत को सघ-प्रवेश के अधिकाश लाभ मिल जाते और निजाम का प्रतीकात्मक पद भी कायम रहता। इस आधार पर चर्चा चलाने के लिए माउन्टबेटन ने दो महीने की अवधि मे भी वृद्धि करवा ली। इसके बाद ऐसी भयकर और कटु सौदेबाजी चली कि चर्चाओ का अन्त निकट जान पडने लगा। लेकिन २२ अक्तूबर को 'यथास्थिति समझौते' का एक ऐसा मसविदा तैयार हो गया जो मेनन और निजाम के प्रतिनिधि-मडल, दोनो को स्वीकार था।

इस विषय को ठोस रूप देने के लिए प्रतिनिधि-मडल हैदराबाद लौट गया। उसी शाम मसविदा निजाम को दिखाया गया, जिन्हे उसका रूप-रग अच्छा नही लगा और उन्होने पूरे मसविदे को अपनी कार्यकारिणी समिति को सौपने का निश्चय किया। कार्यकारिणी समिति ने अगले तीन दिन मसविदे पर विचार करने मे लगाये। प्रतिनिधि-मडल भी इस विचार के समय उपस्थित रहा, जिससे आवश्यक स्पष्टीकरण कर सके। शनिवार २५ अक्तूबर को तीन मतो के खिलाफ छ मतो से यह औपचारिक फैसला किया गया कि निजाम को सलाह दी जाय कि मसविदे को बिना किसी परिवर्तन या विलम्ब के स्वीकार कर ले। मतदान का नतीजा प्रतिनिधि-मडल ने निजाम को उसी शाम सूचित कर दिया और निजाम ने फैसले पर अपनी स्वीकृति दे दी। ऐसा मालूम हुआ कि अगला पूरा दिन निजाम ने दो नत्थी-पत्र तैयार करने मे लगाया। इन पत्रो मे से एक मे यह वचन दिया गया था कि वह पाकिस्तान मे शामिल नही होगे, और दूसरे पत्र मे उन्होने भारत के राष्ट्र-मडल छोडने या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिडने की हालत मे अपनी स्थिति के परिवर्तन का उल्लेख किया था। चूँकि प्रतिनिधि-मडल दूसरे दिन सवेरे दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था इसलिए उन्होने निजाम से मसविदा मगवाया। लेकिन बिना किसी खुलासे के निजाम ने उस रात उस पर अपने हस्ताक्षर करने से

इन्कार कर दिया।

दूसरे दिन सवेरे तीन बजे के लगभग बीस हजार लोगो की एक भीड ने छतारी, माकटन और सर सुलतान अहमद के मकानो को घेर लिया। भीड के बीच लाउड स्पीकर लगे हुए थे, जिनके द्वारा लोगो से व्यवस्थित रहने की अपील की जा रही थी और समझाया जा रहा था कि प्रतिनिधि-मंडल को जाने से रोकने के अलावा और कोई दगा न करे। पूरी घटना के समय हैदराबाद पुलिस कही दिखलाई नही पडी और इस लडाकू चुनौती का इत्तिहाद ने खुले रूप से श्रेय अपने ऊपर लिया। करीब पाच बजे सवेरे छतारी सेना के अधिकारियो से सम्पर्क करने मे सफल हुए और प्रतिनिधि-मडल के सदस्यो और लेडी माकटन को निरापद एक सैनिक अधिकारी के घर मे पहुचाया जा सका।

आठ बजे सवेरे निजाम ने प्रतिनिधियो को सन्देश भेजा कि अभी कुछ दिनो वे दिल्ली न जाय। उन्होने तार द्वारा माउन्टबेटन को भी सूचित कर दिया कि अप्रत्याशित परिस्थितियो के कारण प्रतिनिधि-मडल तुरन्त दिल्ली लौटने मे असमर्थ है। और आशा प्रकट की कि यदि प्रतिनिधि-मडल बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक पहुचेगा तो गवर्नर-जनरल बुरा नही मानेगे। माउन्टबेटन तुरन्त राजी हो गए। निजाम ने २७ अक्तूबर को प्रतिनिधि-मडल को मुलाकात देने पर कहा कि वह पूरी स्थिति पर फिर से विचार कर रहे है और इस बीच उनको रोके रखना चाहते है। लेकिन अपनी कार्यकारिणी के फैसले से उन्होने पूरी सहमति बतलाई। साफ शब्दो मे उन्होने इत्तिहाद और रिजवी की निन्दा की, जो व्यक्तिगत रूप से इस विरोध-प्रदर्शन का सगठन करने के उत्तरदायी थे। उन्होने कहा कि वह रिजवी को यह फैसला मजूर कराने पर मजबूर करेगे।

दूसरे दिन निजाम ने प्रतिनिधि-मडल को दूसरी बार मिलने के लिए बुलाया। रिजवी भी उसमे बुलाये गए। लेकिन बजाय इसके कि वह रिजवी को राजी कर पाते, रिजवी निजाम पर छा गए। रिजवी ने इस मसविदे को हैदराबाद की मौत बतलाते हुए फिर से चर्चा शुरू करने के लिए मौका खोजने की सलाह दी। उनका खयाल था कि भारत सरकार दूसरी जगह दिक्कतो मे फसी हुई है और चर्चा करने के लिए यह ज्यादा मुनासिब का मौका था। उन्होने एक नये प्रतिनिधि-मडल का सुझाव रखा, जिसमे उन लोगो को रखना उचित होगा जिन्होने कार्यकारिणी मे इस मसविदे के खिलाफ मत दिये थे। माकटन छतारी और अहमद सईद ने कहा कि ऐसा कोई कदम उठाना धोखा और विनाशकारी होगा। इस पर उन्होने अपने इस्तीफे भी दे दिये।

कहा था "यह तुम्हारा और तुम्हारी दौलत दोनो का अन्त है।"

इसी समय माउन्टबेटन के नाम निजाम का तार आया। उसमे कहा गया था, "बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति" के कारण पुराना प्रतिनिधि-मडल भग कर दिया गया है और नयेका निर्माण कार्यकारिणी के विरोधी सदस्योमे से किया गया है। नये प्रतिनिधि-मडल के अध्यक्ष मोइन नवाज जग, मीर लायक अली के साले जो छतारी के स्थान पर प्रधान मत्री बनाये गए थे। सितम्बर तक वह सयुक्त-राष्ट्र-सघ मे पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे।

यह सभावना असभव नही है कि निजाम की ये सब चाले हैदराबाद को पाकिस्तान मे शामिल करने की भूमिका है। लाहौर मे जिन्ना के साथ हुई बातचीत मे माउन्टबेटन ने खुले शब्दो मे यह बात छेडी थी। सत्ताहस्तातरण के पहले से कराची और हैदराबाद के बीच बराबर सम्पर्क कायम रहा था। लेकिन जिन्ना ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि निजाम के फैसले मे परिवर्तन होने का उनसे कोई सम्बन्ध नही और उन्होने निजाम के साथ कभी किसी प्रकार के समझौते पर चर्चा नही की थी।

आते ही मोइन ने दून की हाकना शुरू किया। उन्होने कहा कि निजाम हैदराबाद को सर्व-प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य बनाना चाहते है, जिसका दोनो देशो से गहरा सम्बन्ध रहेगा और जिसकी विदेश-नीति आमतौर से भारत के समान होगी। लेकिन माउन्टबेटन उनके और उनके प्रतिनिधि-मडल के साथ बडी कठोरता से पेश आये। कल उनसे पहली मुलाकात के समय उन्होने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय चर्चाओ के अपने लम्बे अनुभव मे उन्होने कभी ऐसा नासमझी भरा और अजीबो-गरीब रवैया नही देखा, जो हैदराबाद ने अपनाया था। कितने ही दिनो के धैर्यपूर्ण विचार के बाद जिस मसविदे को दूसरा पक्ष ठुकरा चुका था, उसे फिर सामने लाना क्या अर्थ रखता था। शक की किसी गुजाइश के बिना उन्होने स्पष्ट कह दिया कि उनकी सरकार 'यथास्थिति समझौते' के इसी अन्तिम मसविदे पर दृढ है, जो पिछले-प्रतिनिधि-मडल के दिल्ली से जाने के पूर्व लिखा गया था, जिसे निजाम की कार्य-कारिणी ने स्वीकार किया था और जिसे कुलॉट लगाने के पहले स्वय निजाम ने मजूर कर लिया था। अगर निजाम अपने ही फैसलो को भग करते रहेगे तो चर्चाए टूटे की सारी जिम्मेदारी उन पर ही होगी और भारत सरकार सारी दुनिया को यह बात बतलायगी।

एक रेडियो-भाषण द्वारा नेहरू ने काश्मीर के प्रश्न पर राष्ट्र-सघ के तत्वावधान मे जनमत-सग्रह किये जाने का उदार सुझाव रखा है। यही बात माउन्टबेटन गत शनिवार को जिन्ना से कह चुके थे। उनका वक्तव्य काफी उदार और तर्कपूर्ण था। लेकिन, जैसा कि जिन्ना लाहौर की बैठक मे स्पष्ट कर चुके थे, उनका विरोध जनमत-सग्रह के सुझाव से नही, बल्कि, उसके दौरान मे काश्मीर मे भारतीय-

सेनाओ की उपस्थिति से था। उनका कहना था कि ऐसा होने पर जनमत-सग्रह निष्पक्ष नही होगा। नेहरू और पटेल का अनुमान था कि जनमत-सग्रह का काम जाडे के दिनो मे नही हो सकेगा और उसके इन्तजाम मे समय लगेगा।

नई दिल्ली, शनिवार, ८ नवम्बर १९४७

जूनागढ की समस्या नया सिरदर्द पैदा कर रही है। गत सोमवार को सुरक्षा-समिति की बैठक मे केवल यह साधारण सूचना दी गई थी कि १ नवम्बर को मगरोल तथा बाबरियावाड पर भारतीय सेनाओ ने शातिपूर्वक अधिकार कर लिया। यह आशा करना उचित ही था कि पटेल यही पसन्द करेगे कि अन्य बडी समस्याओ के हल होने तक जूनागढ पर अधिकार करने का प्रश्न उठा रखा जाय।

परन्तु आज लगभग १ बजे रात को जूनागढ के दीवान ने भारत सरकार को राज्य पर अधिकार करने का औपचारिक आमन्त्रण दिया। दीवान ने लियाकत को सूचित किया कि वह लोकमत के बल, राज्य परिषद् के विशषाधिकार और स्वय नवाब की सम्मति से यह कार्यवाही कर रहे है। नवाब थोडे ही समय पूव कराची चला गया था। भारत-सरकार ने तुरन्त दीवान का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने राजकोटस्थित प्रादेशिक कमिश्नर को आवश्यक कायवाही करन का आदेश दे दिया।

ये सब बाते आज शाम को ही माउन्टबेटन को बताई गई। यह पहला ही अवसर था, जबकि सरकार ने उनके साथ पूर्ण विचार-विनिमय किये बिना नीति-सम्बन्धी बडा निर्णय किया। वह महसूस करते है कि शायद पटेल और श्री वी पी मेनन ने उन्हे विपम उलझन से बचाने के लिए ही ऐसा किया था।

उधर निजाम बडी धृष्टता के साथ नई दिल्ली मे उनके प्रति बची-खुची सद्भावना को भी खत्म किये दे रहे थे। 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्होने और समय की माग की है। चार दिन के कठोर परिश्रम के बाद उनके प्रतिनिधिमडल को इस बात के लिए राजी किया जा सका था कि वह निजाम को सलाह देगा कि बिना किसी फेर-बदल के समझौते को स्वीकार कर लिया जाय। इस बिना पर कि माउन्टबेटन लन्दन जानेवाले थे, निजाम ने २५ नवम्बर तक की मोहलत मागी। अपनी सरकार से सलाह करने के बाद माउन्टबेटन न इसको स्वीकृति दे दी, बशर्ते कि इस महीने के अन्त तक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिय जाय।

नई दिल्ली, रविवार, ९ नवम्बर १९४७

माउन्टबेटन-दम्पत्ति को लन्दन के लिए विदा करने हम सवेरे तडके पालम पहुच गए। आखिरी मिनट तक माउन्टबेटन जाने मे हिचकिचा रहे थे। लेकिन

इस बात के अलावा कि राजकुमारी एलिजाबेथ उनकी चचेरी बहन है, दूल्हे लेफ्टिनेन्ट फिलिप माउन्टबेटन उनके भतीजे होने के अतिरिक्त पिछले अठारह वर्षो से उन्हीके परिवार मे रहते रहे है, इसलिए उनका जाना अनिवार्य था।

दस बजे सवेरे मैने राजगोपालाचारी की शपथ-विधि समारोह मे भाग लिया। माउन्टबेटन की अनुपस्थिति मे राजाजी ही गवर्नर-जनरल का कार्य करेगे। सत्ता-हस्तातरण के बाद से काग्रेस के यह बुजुर्ग और प्रसिद्ध नेता बडी दक्षता के साथ पश्चिमी-बगाल के गवर्नर का कार्य कर रहे है। यह समारोह कौसिल भवन मे मत्रिमडल की उपस्थिति मे सम्पन्न हुआ। सफेद धोती पहने हुए राजाजी ने अपने मोटे और काले चश्मे के पीछे से हसते हुए दोनो हाथ जोडकर सबका अभिवादन किया। जब गृह-विभाग के सेक्रेटरी बनर्जी ने शाही आज्ञा-पत्र पढना शुरू किया तो सब लोग उठकर खडे हो गए, "हमारे विश्वस्त और सर्वप्रिय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बधाई।" प्रमुख न्यायाधीश कानिया ने शपथ दिलवाई, जिसमे केवल एक ही परिवर्तन किया गया था, "सोगन्ध" की जगह "प्रतिज्ञा" शब्द रखकर।

समारोह पाच मिनट के अन्दर पूरा हो गया, लेकिन अपने ऐतिहासिक महत्व का बोध कराने के लिए यह समय काफी था। अग्रेजी राज्य के प्रतीक, जिस राजा की सत्ता का खात्मा करना इस बूढे काग्रेसी के जीवन का मुख्य लक्ष्य था, उसीके द्वारा राज्य के प्रधान पद पर नियुक्त किये जाने के दृश्य मे उद्देश्य-पूर्ति भी थी और नाटकीय व्यग्य भी था।

कार्यवाहक गवर्नर-जनरल ने अपने अमले के लोगो को पहली भोज-पार्टी दी। मै भी उसमे उपस्थित था। राजाजी की लजीली और गम्भीर प्रकृति वाली विवाहिता पुत्री श्रीमती नामगिरी ने अतिथिसत्कार का भार ग्रहण किया। जब परिचय के समय महिलाओ ने झुककर राजाजी का औपचारिक अभिवादन किया तो उन्होने विनय से कहा, "मेरे लिए एसा मत कीजिए।"

: १९ :

प्रगति और अवगति

शिमला, शनिवार, २९ नवम्बर १९४७

राजाजी की अनुमति लेकर मै अपने परिवार के साथ कुछ दिनो के लिए यहा आ गया हू। मेरी सेक्रेटरी मेगी सदरलैड सरकारी भवन से आवश्यक कागज-पत्र

मुझे भेजती रहती है और टेलीफोन से पूरा सम्पर्क भी बनाये रहती है।

आखिर निजाम ने 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर कर दिये थे। सरदार पटेल ने एक सुन्दर वक्तव्य दिया था, जिसमे चर्चाओ के दोरान मे माउन्टबेटन द्वारा दिये गए निर्णायक सहयोग की पूरी-पूरी प्रशसा की गई थी। इसमे कोई शक नही कि बूढे निजाम के साथ चर्चा करना बडे धीरज का काम था, क्योकि वह परम्परागत पूर्वी कूटनीति के कट्टर उपासक है। बाहरी दुनिया की हलचलो से अनभिज्ञ निजाम अपने-आपको अपने ही षड्यन्त्रो के जाल मे फसाये बिना कोई निर्णय नही ले पाते।

अन्त तक ये चर्चाए बडे ओछे ढग से चली। जब प्रतिनिधिमडल की मगलवार को माउन्टबेटन के साथ आखिरी मुलाकात हुई तो उसने निहायत मामूली शाब्दिक परिवर्तनो के लिए हठ करना शुरू किया। यह बात इस सीमा तक जा पहुची कि सिर्फ अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए और इस दावे को पक्का करने के लिए कि भारत सरकार उस मसविदे मे परिवर्तन करने को तैयार हो गई थी, जो उनके पूर्वगामियो ने तैयार किया था, उन्होने अल्प विराम की जगह अर्द्ध विराम लगाने तक के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। इसलिए माउन्टबेटन ने भी यही समझाने की कोशिश की कि वह एक अल्प विराम तक मे परिवर्तन नही करेगे। नत्थी-पत्रो मे कुछेक आवश्यक मामूली सशोधन स्वीकार कर लिये गए, लेकिन यहा भी भारत सरकार अपन इस निश्चय पर अटल रही कि हैदराबाद को विदेश मे अपने अलग कूटनीतिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नही होगा।

इत्तिहाद और उसके उग्र नेता कासिम रिजवी, जो सयोगवश चर्चा के अन्तिम दौरे के समय दिल्ली मे मौजूद थे, इससे अधिक कोई दावा नही कर सकते कि 'यथास्थिति समझौता' विशुद्ध हैदराबादी प्रतिनिधि-मडल के हाथो हुआ था, लेकिन उनकी नाक रखनेका यह काम भी काफी कीमत चुकाने पर हो गया। इस सब के बावजूद निजाम और उनके इरादो से पटेल का विश्वास उठ गया। यथास्थिति समझौते ने एक साल की मोहलत दी थी, जिसमे दिमाग बडे हो सके और दिल उदार।

नेहरू ने फिर एक सुन्दर भाषण दिया —विस्थापितो की समस्या पर। इसमे उन्होने प्रतिहिसा और प्रतिकार की भावनाओ का कडा विरोध किया और पूरी समस्या का बडा सतुलित चित्र पेश किया। गोपालस्वामी आयगर ने ऐलान किया कि दोनो देशो के बीच महत्वपूर्ण प्रश्नो पर भारत-पाक चर्चा पहले सेक्रेटरियो के बीच होगी और फिर मत्रियो के बीच। इसका अर्थ यह हुआ कि आपसी सम्बन्ध कामचलाऊ ढग से सुधारने के लिए हार्दिक प्रयास किया जायगा। पटेल न लियाकत के साथ हुई अपनी चर्चा को "सोहार्दपूर्ण" वतलाया और जिन्ना से सलाह करने के लिए लियाकत दिल्ली से रवाना हो गए। सयुक्त सुरक्षा-कौंसिल को जिन्दा रखा

जायगा और अगली बैठक लाहौर मे ६ दिसम्बर को होगी।

शिमला, सोमवार, १ दिसम्बर १९४७

ऐसा लगता था कि काश्मीर की समस्या भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ देगी। नेताओ की समझ मे यह बात आने लगी थी कि रियासत को भारत सघ मे रखने के लिए तीस लाख काश्मीरी मुसलमानो को हजम करना और खुश रखना जरूरी होगा। इसलिए शेख अब्दुल्ला जनमत-सग्रह के पक्ष मे होते जा रहे थे, जिसका भारत वादा कर चुका था। इस प्रश्न पर हिन्दू महासभा के खिलाफ गान्धी-नेहरू-अब्दुल्ला का सयुक्त मोर्चा बनने के आसार नजर आ रहे थे। काग्रेस के अन्दर की साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी विचारधाराओ के बीच सघर्ष के लक्षण दिखलाई दे रहे थे। वे काग्रेसी, जो हिन्दू-राष्ट्र के पक्ष मे थे, काश्मीर के इच्छुक नही थे। लेकिन सरकार द्वारा काश्मीर मे उठाये गए कदम ने उनका मुह बन्द कर दिया था।

यह गहरा और नाजुक सघर्ष काश्मीर की समस्या तक ही सीमित नही था। इसका रूप काफी व्यापक था। हिन्दू महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के विस्थापितो विषयक प्रस्ताव की निन्दा की थी। काग्रेस के इस प्रस्ताव मे कहा गया था कि काग्रेस उन मुसलमानो को यहा से जाने के लिए प्रोत्साहन देने का इरादा नही रखती जो यहा रुकने के इच्छुक थे। प्रस्ताव मे स्पष्ट रूप से यह सलाह दी गई थी कि विस्थापितो को अपने-अपने घरो को लौट जाना चाहिए। इसमे महासभा और काग्रेस के बीच भारी सघर्ष के बीज निहित थे, और दोनो प्रस्तावो की कडी शब्दावली निकट भविष्य मे विस्फोट का सकेत करती थी।

हैदराबाद के साथ 'यथास्थिति समझौते' का पहला फल यह निकला कि निजाम ने काग्रेस के स्थानीय राजनीतिक बदियो को छोडने का निश्चय किया। राज्य-काग्रेस के अध्यक्ष श्री रामानन्द तीर्थ सहित अधिकाश महत्वपूर्ण नेता चर्चाओ के दौरान मे जेल मे थे।

शिमला, शनिवार, ६ दिसम्बर, १९४७

व्यवस्थापिका सभा मे नेहरू ने विदेशनीति पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। यह एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमे उनके दिमाग को खुलकर काम करने का अवसर मिलता था। मुझे लगता है कि अपनी सरकार मे विदेशमत्री के पद पर काम करने से उन्हे हार्दिक सतोष प्राप्त होता था। वह भारत को बडी शक्तियो के गुत्थम-गुत्थे से अलग रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बडी नाराजी से नेहरू इस बात का विरोध करते थे कि उनका लक्ष्य तटस्थता है। लेकिन इसमे शक नही कि उनकी

नीति का असर इससे भिन्न नही होगा। वह संयुक्त-राष्ट्र अमरीका और रूस
के साथ सहयोग का आह्वान करते थे और ब्रिटेन अथवा राष्ट्रमडल के बारे मे
इससे ज्यादा कुछ नही कहते कि उन्हे आशा है कि राष्ट्रमडल के कुछ सदस्यो के
साथ भारत के सम्बन्धो मे सुधार होगा। यह दक्षिण अफ्रीका पर परोक्ष आक्रमण
जैसा प्रतीत होता था।

फिलस्तीन के विभाजन के विषय मे सयुक्त राष्ट्र के निर्णय के विषय मे बोलते
हुए नेहरू ने भारत के इस सुझाव पर आग्रह किया कि एक सघ के अन्तर्गत दो स्वायत्त
राष्ट्रो की स्थापना की जाय। उन्होने कहा कि यह सुझाव राष्ट्र सघ मे विभाजन से
ज्यादा बुद्धिमानी पूर्ण माना जा रहा है, क्योकि विभाजन से काफी सकट पैदा हो
चुके थे और आगे भी काफी होगे। उन्होने यह भी कहा कि विश्व की बडी समस्याओ
पर स्वतत्र मत व्यक्त करने से भारत का मान बढेगा। एक बडे मार्के की बात
उन्होने कही राजनैतिक रूप से विदेशनीति देश के अन्दर चलने वाली आर्थिक
नीति पर निर्भर करती है। भारत की आर्थिक नीति अभी तक निश्चित नही हो
पाई। तात्कालिक आतरिक सकट ने उसे भटकने पर मजबूर कर दिया है।

उधर, सयुक्त-राज्य अमरीका मे नेहरू के प्रथम राजदूत, आसफअली,
वाशिगटन मे अमरीकी आर्थिक सहायता के लिए हाथ-पैर मार रहे थे। उनका
कहना था कि भारत की देनदारी की स्थिति दृढ है और वह एक अच्छी मडी है।
भारत-पाक सम्बन्धो के विषय मे प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने उत्तर दिया कि उनको
आशा है कि ये सम्बन्ध सुधरेगे—कम-से-कम आर्थिक स्तर पर।

नई दिल्ली, गुरुवार, ११ दिसम्बर १९४७

विभिन्न दस्तावेजो के अध्ययन और माउन्टबेटन के साथ अपनी लम्बी बातचीत
की सहायता से मै काश्मीर मे गत पखवारे के नाटकीय परिवर्तनो का इतिहास
समझने की चेष्टा कर रहा था। इस पखवारे मे इतनी कूटनीतिक हलचले हुई, जितनी
प्राय एक वर्ष मे भी नही हुआ करती। दोनो देशो के बीच खाई को पाटने और पूरे
प्रायद्वीप को छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिए माउन्टबेटन ने निसन्देह बडे साहस
का काम किया था।

इस्मे ने भी शान्ति-स्थापना के काम मे महत्वपूर्ण योग दिया—लियाकत और
नेहरू के बीच नवम्बर के प्रारम्भ और गत सप्ताह दिल्ली मे हुई, "सौहार्दपूर्ण"
बातचीत मे महत्वपूर्ण भूमिका खेलकर। दोनो नेताओ को एक-दूसरे से मिलाने मे
माउन्टबेटन को फिर से काफी कठिनाई का सामना करना पडा था,, क्योकि
लियाकत ने बैठक के जरा पहले ही एक ऐसा तार भेजा, जो नेहरू को उत्तेजित करने
के लिए काफी था। उन्होने फिर शेख अब्दुल्ला को "देशद्रोही" कहा और भारत

सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह रियासत की पूरी मुसलमान आबादी का नाश करना चाहती है। अपनी यह माग भी उन्होने दोहराई थी कि अविलम्ब एक निष्पक्ष और स्वतत्र शासन की स्थापना की जाय।

सौभाग्य-वश नेहरू ऐसे व्यक्ति नही है जो अपने उचित रोष को झूठे अभिमान का रूप लेन दे। इसलिए माउन्टबेटन उन्हे और लियाकत को काश्मीर के बारे मे पहली बार स्पष्ट तौर से बातचीत करने के लिए राजी कर सके। नेहरू द्वारा मामले को विस्तार से पेश किये जाने के बाद लियाकत ने, जो अपनी हाल की बीमारी के बाद बहुत शिथिल और कमजोर दिखलाई पडते थे, कई प्रासगिक सवाल पूछे और कुछ प्रस्ताव रखे, जिन पर विचार करने का नेहरू ने वादा किया। इस्मे उच्च-स्तर के प्रस्तावो के मसविदे बनाने मे बडे निपुण थे। दोनो सरकारो की ओर से वी पी मेनन और मोहम्मदअली के सहयोग से उन्होने तुरन्त इन प्रस्तावो को औपचारिक स्वरूप दे दिया। यही प्रस्ताव आगामी दोनो दिनो की चर्चा का आधार बने।

सक्षेप मे प्रस्ताव ये थे पाकिस्तान विद्रोही 'आजाद काश्मीर' सेनाओ को युद्ध रोकने तथा कबाइलियो और अन्य हमलावरो को यथाशीघ्र काश्मीर की भूमि से लौटाने तथा उनके द्वारा फिर से हमला न होने देने मे अपने सारे बल का प्रयोग करे। भारत अपनी सेना का अधिकाश भाग लौटा ले। केवल गडबडी को दबाने के लिए छोटी टुकडियाँ भर रखे। सयुक्त-राष्ट्र-सघ से कहा जाय कि वह काश्मीर मे जनमत-सग्रह के लिए एक कमीशन भेजे और उसके पहले वह भारत-पाकिस्तान और काश्मीर से सिफारिश करे कि वे जनमत-सग्रह को सच्चा और निर्विघ्न बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कार्यवाहिया करने का विचार है, जैसे राजनैतिक कैदियो की रिहाई और विस्थापितो की वापसी, उनकी तुरन्त घोषणा कर दी जाय।

इस्मे की सहायता से बातचीत के अन्त मे स्थिति यह रही कि हालाकि कोई निश्चित समझौता नही हो सका लेकिन नेहरू की आलोचना वस्तुस्थिति के विस्तार तक ही सीमित रही। लियाकत तीन शर्तो का आग्रह करने दिल्ली आये थे—दोनो पक्षो की काश्मीर से वापसी, जनमत-सग्रह के पूर्व एक निष्पक्ष शासन-व्यवस्था और निष्पक्ष जनमत-सग्रह। वह केवल अपनी तीसरी शर्त ही पूरी तौर पर मनवा सके और दूसरी शर्त आशिक रूप मे। इस प्रकार वह सैद्धातिक रियायत देने मे भी पीछे नही रहे। इस्मे को पूरा विश्वास था कि राजनीतिक और शासनिक दोनो दृष्टियो से उक्त प्रस्ताव एक ऐसा हल प्रस्तुत करते है, जो कार्यान्वित हो सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि समस्या के हल के लिए ऐसे प्रस्ताव पहली बार ही पेश किये गए है। ऐसा मालूम हो रहा था कि नीव सचमुच अच्छे ढग से रखी जा चुकी है। किन्तु समझौता कराना हमेशा दिल तोडने वाला काम होता है।

दो दिन पहले माउन्टबेटन को एक ऐसी बैठक का सभापतित्व करना पडा

जिसको उन्होने अपने जीवन की सबसे निराशाजनक बैठक बताया। सुरक्षासमिति के समक्ष पटेल और बलदेवसिह द्वारा तबाही की खबर लेकर उपस्थित हुए। वे लोग मोर्चे पर से अभी-अभी लौटे थे। जो खबर वे लाये थे और जो सूचनाए नेहरू के पास स्वतत्र रूप मे पहुची थी, उनके कारण मत्रिमडल का रुख सख्त हो गया और वह तात्कालिक जनमत-सग्रह और फिलहाल समझौता-चर्चा चलाने के भी विरुद्ध हो गए। उनकी तीन शिकायते थी। एक तो पश्चिमी पजाब मे कबाइलियो और हमलावरो की बडी सख्या मे जमा होने की खबरे, दूसरे दिल्ली से लौटने के तुरन्त बाद ही लियाकत का हमलावरो को काश्मीर पर धावा बोलने के लिए उकसाने मे सारी शक्ति लगा देना, , तथा तीसरे, गैर-मुसलमानो की सामूहिक हत्या, काश्मीरी लडकियो की बिक्री तथा अन्य क्रूरताओ की लगातार लोमहर्षक कहानिया।

दोनों के बीच फिर सम्पर्क-स्थापन का काम माउन्टबेटन द्वारा लियाकत को दिये इसी सुझाव से सभव हो सका कि समझौता-वार्ता पुन चालू करने की तारीख की सूचना लियाकत तार द्वारा नेहरू को दे दे। लियाकत ने ऐसा ही किया और साथ ही यह भी आग्रह किया कि खून खराबी को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि दोनों सरकारो के प्रतिनिधि मिलते-जुलते रहे। नेहरू ने तुरन्त इस सन्देश की भावना को स्वीकार कर लिया और वह पिछले सोमवार को सयुक्त-सुरक्षा-कौंसिल की बैठक मे शरीक होने के लिए माउन्टबेटन के साथ लाहौर गये।

बीच मे भोजन के समय को निकालकर काश्मीर पर विचार-विनिमय ३ बजे से लेकर आधीरात तक, कुल ७ घटे, चलता रहा। यह बैठक सामान्यत मैत्रीपूर्ण वातावरण मे हुई और उत्तेजना की बाते केवल यदाकदा ही कही गई। फिर भी माउन्टबेटन को, जिन्होने विरोधी विचारो को सुलझाने का भरसक प्रयास किया, यह पक्का भरोसा हो गया कि गतिरोध इतना पूर्ण था, तथा बाहरी और अन्दरूनी राजनैतिक दबाव इतना गहरा था कि अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार रखनेवाला कोई तीसरा दल ही स्वेच्छा से बीच-बचाव करने मे समर्थ हो सकता है।

इस मौके पर माउन्टबेटन ने सुझाव दिया कि सयुक्त राष्ट्र सघ को तीसरे दल के रूप मे बुलाया जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि इससे हमलावरो को रोकने मे उन्हे बल मिलेगा। उन्होने जिन्ना के इस कथन का समर्थन नही किया कि कराची के हुक्म मात्र से ही ये हमलावर लौटाए जा सकते है। नेहरू जानना चाहते थे कि सयुक्त राष्ट्र सघ के विधान की किस धारा के अनुसार अपील की जा सकती है। चूंकि अब आधी रात हो गई थी इसलिए माउन्टबेटन ने सुझाया कि इस विषय को और बारीकी से देखना चाहिए। थकावट के मारे नेहरू ने स्वीकृति-सूचक गर्दन हिलाई और बैठक समाप्त हो गई।

दिल्ली लौटने के बाद माउन्टबेटन गांधीजी और मेनन से मिल चुके थे। दोनों सयुक्त राष्ट्र सघ की मध्यस्थता के पक्ष मे थे। आज उन्होने नेहरू से और बाते की।

प्रस्ताव के पक्ष मे उनका रुख अब उतना नकारात्मक नही था।

नई दिल्ली, गुरुवार, १८ दिसम्बर १९४७

क्षितिज पर फिर काली घटाए घिर आई हैं और जैसा कि अक्सर गर्म देशो की आबहवा मे हुआ करता है, सूरज छिपने के पहले ही तूफान हमारे सिरो पर आ फटा। सरकारी भवन मे पहुचने वाली खबरो से पता चलता था कि काश्मीर का सकट और भी गहरा होता जा रहा है। युद्ध की ओर झुकाव बढ गया था। ऐसा लगता था कि पटेल ने कडा हुक्म दिया था कि जब तक पाकिस्तान हमलावरो को सहायता देना बन्द नही करता तब तक पाकिस्तान के साथ हुए किसी भी वित्त-सम्बन्धी समझौते पर अमल नही किया जायगा। सवाल पचपन करोड रुपयो का था और व्यापक राजनैतिक तथा नैतिक नतीजो के अलावा पाकिस्तान के लिए इसका आर्थिक परिणाम काफी गम्भीर होगा। पाकिस्तान के पास सिल्लक मे केवल दो करोड रुपये थे, और उसे ऋण बहुत से चुकाने थे। इस बारे मे सिर्फ यही तर्क दिया जायगा "अपने सिपाहियो की हत्या करने को हथियार खरीदने के लिए हम उन्हे रुपया क्यो दे ?" और यह तर्क मत्रिमडल के सामने पेश किया जाने पर शायद ही उसका विरोध किया जाय।

अपने स्वतत्र सूत्रो से भी भारतीय नेताओ को काश्मीर पर हमले मे पाकिस्तान के सहयोग के अधिकाधिक सबूत प्राप्त हो रहे थे। उनके रुख मे कडाई आने का यही प्रधान कारण था। कुछ लोगो का खयाल था कि काश्मीर की घटना एक बडे और व्यापक षडयत्र का छोटा अश मात्र है। उनका कहना था कि भारतीय सेनाओ को काश्मीर मे फसाने के बाद पाकिस्तान हैदराबाद मे सकट खडा करेगा और फिर पजाब की सीमाए पार कर स्वय दिल्ली पर चढ दौडेगा।

एक दूसरा मत यह भी था, जो कम उन्मादपूर्ण होने पर भी कही अधिक खतरनाक था। वह यह कि अगर पाकिस्तान हमलावरो को प्रवेश करने से रोकने मे असमर्थ था, तो यह काम स्वय भारत को करना पडेगा। लेकिन यह काम भारतीय फौजो को पाकिस्तानी सीमा से उस पार भेजने पर ही किया जा सकेगा। अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो छिपे युद्ध से खुला युद्ध कही श्रेयस्कर होगा। जहा तक इसके लिए उचित समय का सवाल था वे मेकबेथ[1] के इस सिद्धात का समर्थन करते थे कि "अगर इसे करना ही है तो, जल्दी-से-जल्दी करना ज्यादा अच्छा होगा।" सरकारी क्षेत्रो मे इस बारे मे बडी चिन्ता फैली हुई थी कि सिखो की समस्या पर काश्मीर का कसा असर पडेगा। उनका अनुमान था कि काश्मीर की

---

१. शेक्सपियर के प्रसिद्ध दुखान्त नाटक 'मेकबेथ' के नायक।

तनातनी और युद्ध जितना अधिक चलता रहेगा, सिखो पर नियत्रण रखना भी भारत सरकार के लिए उतना ही कठिन होता जायगा। ऐसा लगता था कि अगर लियाकत उचित राजनैतिक सुझाव पेश नही करेगे, जिन्हे निगलना शायद उनके देश और उनके साथियो के लिए कठिन होगा, तो स्थिति निरन्तर खतरनाक होती जायगी।

जनता का सारा ध्यान काश्मीर पर केन्द्रित था। इस बीच पटेल उडीसा और मध्यप्रदेश से महत्वपूर्ण काम करके दिल्ली लौट आये थे। वी पी मेनन के सहयोग से वह उडीसा और छत्तीसगढ की पूर्वी रियासतो (जिनकी सख्या कुल नौ है, क्षेत्रफल छप्पन हजार वर्ग मील और आबादी सत्तर लाख) को इस बात के लिए राजी कर सके थे कि सघ-प्रवेश से एक कदम आगे बढकर अपने को दोनो पडोसी राज्यो मे विलीन कर दे। नई शर्तो के अनुसार हालाकि सारे अधिकार नये सघ के अधीन चले जायगे लेकिन राजाओ की व्यक्तिगत सम्पत्ति, खिताब और उत्तराधिकार के अधिकार आदि ज्यो-के-त्यो कायम रहेगे।

इससे सारे छो े और बडे राजाओ के लिए एक नई परम्परा का निर्माण हो गया था, जो अब उनको और भी ज्यादा बल से केन्द्रीय सरकार की ओर घसीटेगी। प्रसगवश, यह याद दिलाना उचित होगा कि उडीसा की रियासतो को उडीसा प्रान्त के शासकीय सम्पर्क मे लाने का पहला सुझाव करीब बीस वर्ष पहले साइमन-कमीशन की एक उपसमिति ने दिया था, जिसके अध्यक्ष थे साइमन के एक छोटे और ख्यातिहीन साथी मि सी आर एटली।

नई दिल्ली, सोमवार, २२ दिसम्बर १९४७

भारतीय मत्रिमडल ने आखिर शनिवार को यह फैसला कर डाला कि हमलावरो को मदद देने के आरोप मे पाकिस्तान के खिलाफ सयुक्त राष्ट्र सघ मे अपील की जाय। लियाकत और मुहम्मदअली कल शाम से दिल्ली मे थे, लेनिक कल और आज की चर्चाओ का ऐसा कोई नतीजा नही निकला जिससे इस गम्भीर निर्णय को रद्द किया या टाला जा सके। अधिकाश समय अत्याचार के आरोपो और प्रत्यारोपो मे ही निकल गया। शिकायत का औपचारिक पत्र आज नेहरू ने लियाकत को दे दिया। मामले को राष्ट्र सघ के समक्ष पेश करने की यह आवश्यक भूमिका थी। लियाकतने जल्दी उत्तर देने का वादा किया। इस प्रकार काश्मीर के ऊपर होने वाले राजनैतिक और कूटनीतिक सघर्ष का पहला दौर समाप्त हुआ।

नई दिल्ली, बुधवार, ३१ दिसम्बर १९४७

१९४७ का वर्ष सामान्यत भारत-पाकिस्तान सम्बन्धो और विशेषत काश्मीर

के भविष्य के लिए अपशकुन के साथ समाप्त हो रहा था। अलिप्त होकर भारत मे व्यतीत नो प्रयासपूर्ण महीनो का लेखा-जोखा करना कठिन था। तात्कालिक परिस्थितिया हमेशा हमारे विचारो और मन पर हावी रहती है।

कम-से-कम काश्मीर के सम्बन्ध मे तो हम इस सकट की कुछ स्पष्ट कल्पना के साथ १९४८ मे प्रवेश कर रहे थे। जैसा कि माउन्टबेटन का अनुमान था, एटली ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उनका विचार था कि सामान्य समझौता कराने वाले की भूमिका खेलने के अतिरिक्त वह कोई निश्चित काम नहीं कर सकेगे। वह सयुक्त राष्ट्र सघ के "उचित माध्यम" पर निर्भर करना अधिक पसन्द करते थे। फिर भी, सावधानी से काम लेने पर जोर देते हुए उन्होने नेहरू को एक बडा सुन्दर सन्देश भेजा था।

मि एटली का उत्तर मिल जाने पर लियाकत के उत्तर के लिए अधिक न ठहर कर सरकार ने सयुक्त राष्ट्र सघ से अपील की दिशा मे आगे बढने का निश्चय कर लिया था। शिकायत की वाक्यावली नरम थी, और उसका मसविदा तब तैयार किया गया जब माउन्टबेटन ग्वालियर मे थे। उसमे चिन्ताजनक वाक्य केवल एक था, वह यह कि परिस्थिति का तकादा होने पर सरकार को सैनिक कार्यवाही करने का हक होगा। माउन्टबेटन ने स्पष्ट कह दिया था कि धमकी या धमकी के सकेत के प्रति सुरक्षा परिषद् की प्रतिक्रिया अनुकूल नही हो सकती।

माउन्टबेटन ने नेहरू को समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि पाकिस्तानी धरती पर आक्रमण करने का, विशेषत जब भारत की शिकायत (सयुक्त राष्ट्र सघ के) विचाराधीन थी, क्या अर्थ होगा। विश्व के लोकमत पर तो इसका विघातक प्रभाव पडेगा ही, साथ ही दोनो उपनिवेशो मे काम करनेवाले ब्रिटिश अफसरो को भी वापस चला जाना होगा। मेरे खयाल से, यह भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के तात्कालिक हितो के अधिक विपरीत होगा। परन्तु नेहरू भली-भाति जानते थे कि इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही से भारत मे माउन्टबेटन की सेवाओ का अन्त हो जायगा।

सयुक्त राष्ट्र सघ के पास भारत की अपील रवाना हो जाने के बाद ही लियाकत का उत्तर प्राप्त हो गया। वह प्रत्यारोपो का एक लम्बा सूचीपत्र ही था। प्रत्यारोपो को जानबूझकर काश्मीर तक सीमित नही रखा गया, वरन् इस सामान्य प्रकरण तक फैला दिया गया था कि भारत ने विभाजन मानने से इन्कार किया और वह पाकिस्तान को नष्ट कर देने के लिए कमर कसे था। लियाकत जूनागढ से लेकर अब तक के सब काडो मे सयुक्त राष्ट्र सघ का हस्तक्षेप चाहते थे, "जिससे सारे विचाराधीन मतभेदो को मिटाया जा सके।" इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ की पृष्ठ-भूमि मे यह समाचार उत्साहजनक है कि उरी पर कोई आक्रमण नही किया गया और वहा की भारतीय सेना की विरोधी सेना से कोई मुठभेड नही हो पाई। माउन्टबेटन का अनुमान है

था, जो लोग दिल्ली मे घटना-स्थल पर मौजूद नही थे, उन्हें मेरे लिए यह समझाना कठिन था कि अपने रोब और सम्मान के बावजूद माउन्टबेटन वैधानिक गवर्नर-जनरल मात्र हैं। भारत सरकार स्वय अपने समाचार-पत्र-सम्बन्धी कष्टो से पीडित थी। काश्मीर के झगडे को सयुक्त राष्ट्र सघ के सम्मुख भेजे जाने के निर्णय के असमय बाहर फूट निकलने से नेहरू बडे सकट मे पड गए थे। यह समाचार मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति द्वारा ही बाहर पहुच सकता था।

माउन्टबेटन द्वारा गत बैठक मे नेहरू को दिये गए सुझाव के अनुसार कर्नल कौल मेरे घर पर मुझे मिलने आये। कर्नल कौल गोपाला स्वामी आयगार और शेख अब्दुल्ला के साथ जा रहे थे, जो लेक सक्सेस मे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा काम था कर्नल कौल को उनके सामने आने वाली जनसम्पर्क की कुछ समस्याओ के बारे मे सलाह देना। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि शेख अब्दुल्ला का रगीन व्यक्तित्व सहज ही लुटिया डुबो दे सकता है। दूसरी ओर आयगार, जिनके कन्धों पर मुख्यत भारत का मामला पेश करने का भार रहेगा, अज्ञात व्यक्ति हैं। इसलिए लक्ष्य यह रहना चाहिए कि इस सतुलन को सुधारने के लिए आयगार को आगे रखा जाय और अब्दुल्ला को पीछे। जैसी प्रेस-कान्फ्रेंसे शेख अब्दुल्ला श्रीनगर मे देते आये थे, वैसी लेक सक्सेस मे सफल नहीं होंगी। मैंने चेतावनी दी कि मामले के बल को जरा भी कमजोर नही होने दिया जाय, क्योकि परिषद् मे पेश किये जाने के पूर्व ही वह प्रेस कान्फ्रेंस द्वारा सबकी निगाह मे आ जायगा।

नई दिल्ली, बुधवार, ७ जनवरी १९४८

रियासती विभाग के मत्री सरदार पटेल की हार्दिक सहमति से माउन्टबेटन इस सप्ताह बडे और छोटे राजाओ मे दो अलग-अलग दलो मे सरकारी भवन मे भेंट कर रहे थे। वह पुन उनमे वह जीवन-शक्ति भरने का प्रयास कर रहे थे, जिसका राजाओ मे स्वत अभाव प्रतीत होता था। उन्होने आज बडे राजाओ को समझाया कि उनके राजकीय मामलो का नियत्रण करने के लिए विशेषाधिकार समितियो की स्थापना करने का क्या महत्व था।

इस पर जो आम चर्चा हुई उसमे केवल अलवर-नरेश ने ही आपत्ति करने की जरूरत समझी। बडे जोश और झगडालू स्वर मे उन्होने कहा, "अगर जनता नर्क मे रहना पसन्द करे, तो उसे स्वर्ग मे रहने के लिए मजबूर नही किया जाना चाहिए।" जब माउन्टबेटन बडे धैर्य के साथ बतला रहे थे कि राजाओ और राजपरिवार के लोगो द्वारा भारत सरकार की कूटनीतिक सेवा मे शामिल होने के लाभ क्या होंगे, तो अलवर-नरेश ने उनकी बात काट कर कहा, "इसमे अहसान की कौन-सी बात हुई! अगर मेनन रियासती विभाग के सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो महाराजा बीकानेर

आरोप लगाया । साफ जाहिर था कि उन्हे काबू मे रखना टेढी खीर थी । अगर यह उस नीति का पूर्वाभास था कि जो वह अमरीका मे अपनाने जा रहे थे, तब तो भारत के हित को आगे बढाने का काम खतरे मे ही था ।

नई दिल्ली, सोमवार, १२ जनवरी १९४८

दिल्ली जिमखाना क्लब मे पत्रकारो की एक दावत मे मुझे इस बात की पहली खबर मिली कि गाधीजी फिर आमरण अनशन शुरू करनेवाले है । उनके इस निश्चय की घोषणा प्रार्थना-सभा मे इतनी अनायास हुई कि हम सभी स्तब्ध रह गए । मुझे तो और भी ज्यादा अचरज हुआ । इस घटना के कुछ ही पहले वर्नोन के साथ 'स्क्वेश'[1] खेलकर लौटते समय माउन्टबेटन के बैठक की खिडकियो के सामने से गुजरते हुए मैने उन्हे गाधीजी के साथ बातचीत करते देखा था । मुझे मालूम था कि मुलाकात जल्दी मे तय की गई थी, लेकिन यह कल्पना नही थी कि इसका कोई विशेष महत्व भी हो सकता है ।

वास्तव मे वह अपनी प्रार्थना-सभा के बाद ही माउन्टबेटन से मिलने आये थे । इस प्रार्थना-सभा मे उन्होने कहा था कि यह उपवास तभी टूटेगा "जब मुझे विश्वास हो जायगा कि सब सम्प्रदाय के लोगो मे हार्दिक मेल हो गया है । और यह किसी बाहरी दबाव से न होकर कर्त्तव्य की आतरिक चेतना मात्र से हुआ है   भगवान ही मेरा सर्वोच्च और एकमात्र पथ-प्रदर्शक है, इसलिए मैने यह महसूस किया कि यह निश्चय तो मुझे किसी और सलाहकार की सलाह के बिना ही लेना चाहिए ।" प्रार्थना-सभा के पहले उनका मौन-दिवस खुला था । फलस्वरूप नेहरू और पटेल तक को उनके प्रस्तावित निश्चय का पहले से कोई पता न चल सका । फिर उन्होने दिल्ली की दयनीय साम्प्रदायिक स्थिति के बारे मे अपनी गहरी पीडा की बात कही । उन्होने कहा कि ऐसा लगता है कि यह साम्प्रदायिकता जीवन के हर अग मे समा गई है । उन्होने कहा कि वह स्वय इसका प्रायश्चित्त करेगे ।

माउन्टबेटन के साथ अपनी बातचीत मे गाधीजी ने माउन्टबेटन से पूछा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को नकद सिल्लक मे से पचपन करोड रुपये देने से इकार करने के बारे मे उनका क्या मत था । माउन्टबेटन ने नि सकोच उत्तर दिया कि वह इस निश्चय को निहायत अराजनीतिज्ञ और अक्लमदी से दूर समझते हैं । गाधीजी ने कहा कि इस विषय मे वह नेहरू और पटेल से बात करेगे । उन्होने कहा कि वह उन्हे स्पष्ट कर देगे कि इस पूछताछ [illegible] उन्होने ही किया था और उन्होने ही इस विषय मे माउन्टबेटन की राय

---

१. एक अग्रेजी खेल ।

आरोप लगाया। साफ जाहिर था कि उन्हे काबू मे रखना टेढी खीर थी। अगर यह उस नीति का पूर्वाभास था कि जो वह अमरीका मे अपनाने जा रहे थे, तब तो भारत के हित को आगे बढाने का काम खतरे मे ही था।

नई दिल्ली, सोमवार, १२ जनवरी १९४८

दिल्ली जिमखाना क्लब मे पत्रकारो की एक दावत मे मुझे इस बात की पहली खबर मिली कि गाधीजी फिर आमरण अनशन शुरू करनेवाले है। उनके इस निश्चय की घोषणा प्रार्थना-सभा मे इतनी अनायास हुई कि हम सभी स्तब्ध रह गए। मुझे तो और भी ज्यादा अचरज हुआ। इस घटना के कुछ ही पहले वर्नोन के साथ 'स्क्वेश'[1] खेलकर लौटते समय माउन्टबेटन के बैठक की खिडकियो के सामने से गुजरते हुए मैने उन्हे गाधीजी के साथ बातचीत करते देखा था। मुझे मालूम था कि मुलाकात जल्दी मे तय की गई थी, लेकिन यह कल्पना नही थी कि इसका कोई विशेष महत्व भी हो सकता है।

वास्तव मे वह अपनी प्रार्थना-सभा के बाद ही माउन्टबेटन से मिलने आये थे इस प्रार्थना-सभा मे उन्होने कहा था कि यह उपवास तभी टूटेगा "जब मुझे विश्वास हो जायगा कि सब सम्प्रदाय के लोगो मे हार्दिक मेल हो गया है। और यह किसी बाहरी दबाव से न होकर कर्त्तव्य की आतरिक चेतना मात्र से हुआ है भगवान ही मेरा सर्वोच्चि और एकमात्र पथ-प्रदर्शक है, इसलिए मैने यह महसूस किया कि यह निश्चय तो मुझे किसी और सलाहकार की सलाह के बिना ही लेना चाहिए।" प्रार्थना-सभा के पहले उनका मौन-दिवस खुला था। फलस्वरूप नेहरू और पटेल तक को उनके प्रस्तावित निश्चय का पहले से कोई पता न चल सका। फिर उन्होने दिल्ली की दयनीय साम्प्रदायिक स्थिति के बारे मे अपनी गहरी पीडा की बात कही। उन्होने कहा कि ऐसा लगता है कि यह साम्प्रदायिकता जीवन के हर अग मे समा गई है। उन्होने कहा कि वह स्वय इसका प्रायश्चित्त करेगे।

माउन्टबेटन के साथ अपनी बातचीत मे गाधीजी ने माउन्टबेटन से पूछा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को नकद सिल्लक मे से पचपन करोड रुपये देने से इकार करने के बारे मे उनका क्या मत था। माउन्टबेटन ने नि सकोच उत्तर दिया कि वह इस निश्चय को निहायत अराजनीतिज्ञ और अक्लमदी से दूर समझते हैं। गाधीजी ने कहा कि इस विषय मे वह नेहरू और पटेल से बात करेगे। उन्होने कहा कि वह उन्हे स्पष्ट कर देगे कि इस पूछताछ का प्रारम्भ उन्होने ही किया था और उन्होने ही इस विषय मे माउन्टबेटन की राय जाननी चाही थी।

---

१. एक अग्रेजी खेल।

दबाव और आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है। इस उपवास से ऐसी शक्ति पैदा हुई कि सब लोग-अप -अपने कामो को छोडकर उसकी ओर खिचे चले आ रहे थे और उस वेदनामय कर्त्तव्य मे हाथ बटा रहे थे, जिसकी कोई भी इन्सान पूरी तौर से उपेक्षा नही कर सकता ।

बीकानेर, बुधवार, १४ जनवरी १९४८

गाधीजी के उपवासके वावजूद निश्चय किया गया कि माउन्टबेटन की चिर-प्रतीक्षित बीकानेर-यात्रा स्थगित न की जाय। लेकिन महात्माजी के प्रति सम्मान-स्वरूप शाही-भोज अवश्य नही होगा ।

हमारे जाने के थोडे समय पूर्व पटेल और नेहरू अलग-अलग माउन्टबेटन से मिलने आये। गाधीजी के निर्णय के बारे मे उनकी प्रतिक्रियाए इस बात की सबसे अच्छी समीक्षा है कि इस समय दोनो के विचारो और दृष्टिकोणो मे कितना अन्तर था। पटेल ने कहा कि उपवास का समय बहुत गलत चुना गया है और उसका असर गाधीजी के इच्छित प्रभाव के बिल्कुल विपरीत होगा। दूसरी ओर नेहरू गाधीजी के निश्चय के प्रति अपनी खुशी और सराहना की भावना को छिपाने मे असमर्थ थे ।

लालगढ़ महल, बीकानेर, शुक्रवार, १६ जनवरी १९४८

आज पणिक्कर के साथ, जो अब भी महाराज के दीवान-पद पर थे, मेरी रोचक बातचीत हुई। वह गाधीजी के उपवास के बारे मे बहुत आशावान थे। उनके विचार से यह उपवास पटेल के खिलाफ लक्ष्य करके किया गया था। उन्होने कहा कि तीन महीने पहले जब गाधीजी दिल्ली आये थे तो पटेल और गाधी मे सघर्ष की नौबत आ गई थी। तब गाधीजी ने कहा था, "वल्लभभाई, मै तो हमेशा समझता आया था कि तुम और हम एक हैं। लेकिन देखता हू कि हम दो है।" बापू की इस गलतफहमी से पटेल की आखे भर आई थी।

दोनो के सबधो के बारे मे पणिक्कर की समीक्षा इस प्रकार थी हालांकि पटेल का काग्रेस-सगठन पर पूरा नियत्रण था पर वह जानते थे कि गाधीजी अब भी जनता के सर्वस्व हैं, और अगर वह चाहे तब भी महात्माजी के प्रभाव को तोड़ नही सकते। उधर गाधीजी नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन ऐसा करने मे वह पटेल को तोडना नहीं, सिर्फ झुकाना चाहते थे।

इसके बाद पणिक्कर ने गाधीजी के राजनैतिक विवेक की प्रशसा की। उन्होने कहा कि लगभग बीस वर्ष के बाद वह हाल मे गाधीजी से मिले, और इस मुलाकात मे उन्होने गाधीजी से विनय की कि रियासतो मे वैधानिक सुधार के काम मे धीरे-धीरे आगे बढने की नीति अपनाये। गाधीजी ने विरोध प्रकट करते हुए कह

दबाव और आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है। इस उपवास से ऐसी शक्ति पैदा हुई कि सब लोग-अपने-अपने कामो को छोडकर उसकी ओर खिचे चले आ रहे थे और उस वेदनामय कर्त्तव्य मे हाथ बटा रहे थे, जिसकी कोई भी इन्सान पूरी तौर से उपेक्षा नही कर सकता।

बीकानेर, बुधवार, १४ जनवरी १९४८

गाधीजी के उपवासके बावजूद निश्चय किया गया कि माउन्टबेटन की चिर-प्रतीक्षित बीकानेर-यात्रा स्थगित न की जाय। लेकिन महात्माजी के प्रति सम्मान-स्वरूप शाही-भोज अवश्य नही होगा।

हमारे जाने के थोडे समय पूर्व पटेल और नेहरू अलग-अलग माउन्टबेटन से मिलने आये। गाधीजी के निर्णय के बारे मे उनकी प्रतिक्रियाए इस बात की सबसे अच्छी समीक्षा है कि इस समय दोनो के विचारो और दृष्टिकोणो मे कितना अन्तर था। पटेल ने कहा कि उपवास का समय बहुत गलत चुना गया है और उसका असर गाधीजी के इच्छित प्रभाव के बिल्कुल विपरीत होगा। दूसरी ओर नेहरू गाधीजी के निश्चय के प्रति अपनी खुशी और सराहना की भावना को छिपाने मे असमर्थ थे।

लालगढ़ महल, बीकानेर, शुक्रवार, १६ जनवरी १९४८

आज पणिक्कर के साथ, जो अब भी महाराज के दीवान-पद पर थे, मेरी रोचक बातचीत हुई। वह गाधीजी के उपवास के बारे मे बहुत आशावान थे। उनके विचार से यह उपवास पटेल के खिलाफ लक्ष्य करके किया गया था। उन्होने कहा कि तीन महीने पहले जब गाधीजी दिल्ली आये थे तो पटेल और गाधी मे सघर्ष की नौबत आ गई थी। तब गाधीजी ने कहा था, "वल्लभभाई, मै तो हमेशा समझता आया था कि तुम और हम एक हैं। लेकिन देखता हू कि हम दो है।" बापू की इस गलतफहमी से पटेल की आखे भर आई थी।

दोनो के सबधो के बारे मे पणिक्कर की समीक्षा इस प्रकार थी हालाकि पटेल का काग्रेस-सगठन पर पूरा नियत्रण था पर वह जानते थे कि गाधीजी अब भी जनता के सर्वस्व हैं, और अगर वह चाहे तब भी महात्माजी के प्रभाव को तोड नही सकते। उधर गाधीजी नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन ऐसा करने मे वह पटेल को तोडना नही, सिर्फ झुकाना चाहते थे।

इसके बाद पणिक्कर ने गाधीजी के राजनैतिक विवेक की प्रशसा की। उन्होने कहा कि लगभग बीस वर्ष के बाद वह हाल मे गाधीजी से मिले, और इस मुलाकात मे उन्होने गाधीजी से विनय की कि रियासतो मे वैधानिक सुधार के काम मे धीरे-धीरे आगे बढने की नीति अपनाये। गाधीजी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा

"आप चाहते है कि मै प्रतिक्रियावादियो को पैर जमाने दूँ।" पणिक्कर ने कहा, "इसका मेरे पास कोई उत्तर न था।" बात सही भी थी। फिर पणिक्कर ने कहा कि गाधीजी अपने श्रोताओ की भाषा बोलते थे। इसीलिए उनकी प्रार्थना-सभा जैसे अवसर अपनी सादगी के कारण भ्रम पैदा कर देते थे। व्यक्तिगत चर्चा मे वह ज्यादा तीखेपन से काम लेते थे। उन्होने जोर देकर कहा कि गाधीजी का "गुप्तचर" विभाग भी बडा सुव्यवस्थित था। सारे देश से उनके पास व्यक्तिगत पत्र आते रहते थे, जिनसे उन्हे देश की स्थिति के समाचार मिलते रहते थे।

आज तीसरे पहर हमने सुना कि सद्भावना के प्रतीकस्वरूप मत्रिमडल ने पाकिस्तान को पचपन करोड रुपये देना स्वीकार कर लिया है। फिल्म शो के बाद माउन्टबेटन ने कहा कि पिछले तीन महीनो की यह सर्वश्रेष्ठ घटना है। लेकिन पणिक्कर ने चिन्ता प्रगट करते हुए कहा कि पटेल पर इस फैसले की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी।

नई दिल्ली, शनिवार, १७ जनवरी १९४८

सवेरा होते ही हम दिल्ली के लिए चल पडे। शाही अतिथि-सत्कार की छाप हम अपने साथ लेकर चले थे। बीकानेर परम्परा और सुधार का सुन्दर मिश्रण था और अपनी जनता की सामाजिक एकता और नए राष्ट्र के प्रति राजनैतिक निष्ठा के मामले मे अपने नरेश-बन्धुओ के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा था।

हमारे लौटने के थोडी ही देर बाद माउन्टबेटन-दम्पति गाधीजी से मिलने बिडलाभवन गये। गाधीजी काफी कमजोर हो गए थे। उन्होने स्वागत करते हुए कहा, "आपको यहा बुलाने के लिए उपवास की जरूरत पडती है।" फिर उन्होने इसे समाप्त करने के बारे मे चर्चा की। गाधीजी ने कहा कि उन्होने सात शर्ते रखी थी। इन सबका सम्बन्ध दिल्ली और समूचे भारत मे रहनेवाले मुसलमानो की बुनियादी सुरक्षा और नागरिक अधिकारो से था। उनके पूरे होने पर ही वह उपवास समाप्त करने का विचार कर सकते थे।

: २१ :

गांधी का बलिदान

नई दिल्ली, रविवार, १८ जनवरी १९४८

पचपन करोड के बारे मे मत्रिमडल का फैसला होते ही राजबाबू और मौलाना आजाद के निर्देशन मे एक अन्तर-साम्प्रदायिक-शातिकमेटी की स्थापना

की गई। इस कमेटी ने बडे सराहनीय उत्साह से काम किया, और आज सवेरे महात्माजी को यह विश्वास दिलाने मे सफल हुई कि दिल्ली मे आवश्यक हृदय-परिवर्तन हो गया है और अब उन्हे अपना उपवास तोड देना चाहिए। उपवास को शुरू हुए एक सौ इक्कीस घटे से ज्यादा हो चुके थे, जिससे गाधीजी के कृश शरीर की सचित-शक्ति पर भारी जोर पडा था।

उपवास ने मुसलमानो का मनोबल बढाने मे निसदेह भारी योग दिया था। लेकिन सिख लोग अवश्य अडे हुए थे। "गाधी को मरने दो" के नारे लगाते हुए और हाथ मे काले झडे लिये सिखो के जलूस बिडला-भवन के सामने से निकाले गए। लेकिन सिख-प्रतिनिधियो ने अन्तर-साम्प्रदायिक कमेटी मे भाग लेने से इकार नहीं किया।

अपनी प्रार्थना-सभा को आज शाम भेजे गए एक सन्देश मे गाधीजी ने कहा कि अगर उनका प्रण पूरा हो गया तो वह "दुगने बल से भगवान से प्रार्थना और कामना करेगे कि वह पूर्णायु होकर आखिरी क्षणतक मानवता की सेवा करते रहे।" कुछ विद्वान पूर्णायु का अर्थ कम-से-कम एक सौ पच्चीस साल मानते हैं और कुछ एक सौ तैंतीस।

नई दिल्ली, मंगलवार, २० जनवरी १९४८

गान्धीजी के उपवास की समाप्ति के उपलक्ष मे होने वाली खुशिया बिडला-भवन के बागीचे मे हुए बम्ब-काड से फीकी पड गई, यह हाथ का बना बम उपवास के बाद की पहली प्रार्थना-सभा मे फूटा, जिसमे गान्धीजी उपस्थित थे। विस्फोट का सारा जोर एक दीवाल पर पडा, जो थोडी-सी ढरक गई थी। किसी के कोई चोट नही पहुची, न कोई भगदड ही मची। गान्धीजी का प्रवचन ऐसे चलता रहा मानो कोई अनिष्टकारी घटना घटी ही न हो। लेडी माउन्टबेटन ने समाचार सुनते ही वहा पहुचने पर उन्हे बिलकुल अनुद्विग्न पाया। उन्होने लेडी माउन्टबेटन से कहा, "मै समझा कि कही नजदीक मे सैनिक-अभ्यास चल रहे हैं।"

नई दिल्ली, शुक्रवार, ३० जनवरी १९४८

माउन्टबेटन आज मद्रास से वापस आ गए। वहा जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

शाम को ६ बजने मे १० मिनट के लगभग मै जार्ज निकोल्स के कमरे मे गया। उन्होने बताया कि गाधीजी की हत्या का प्रयत्न किया गया था और उन्हे तीन गोलिया लगी हैं। आध घटे बाद मैने माउन्टबेटन के ड्राइवर पियर्स से सुना कि गाधीजी नहीं रहे। उसने मोटर मे लगे हुए रेडियो मे यह समाचार सुना था। उसने बताया कि माउन्टबेटन तत्काल सीधे बिडला-भवन जा रहे हैं।

मै मोटर के पास ही खडा था कि माउन्टबेटन बाहर आये। उन्होने मुझे हाथ के इशारे से अपने साथ चलने को कहा। वह बहुत व्यग्र थे और छोटे-छोटे अधूरे वाक्यो मे बोल रहे थे। उन्होने बताया कि राजगोपालाचारी ने कलकत्ता से फोन किया था कि नहरू की रक्षा के अधिक-से-अधिक प्रबन्ध की आवश्यकता है। केवल दो दिन पूर्व ही जब नेहरू अमृतसर की एक सभा मे भाषण दे रहे थे तो दो व्यक्तियो को हयगोलो सहित गिरफ्तार किया गया था।

माउन्टबेटन का खयाल था कि यह घटना अत्यन्त गम्भीर है। इससे नेहरू बिलकुल एकाकी रह गए है और राजनैतिक रूप से बे-सहारे-से है। अब सब-कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उनमे आगामी कुछ घटो की स्थिति पर नियत्रण रखने की कितनी क्षमता है। उनका शीघ्र-से-शीघ्र राष्ट्र को स देश देना आवश्यक है, परन्तु उन्हे जो कुछ कहना है, उसपर पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योकि देश उनके कहे पर चलेगा।

हमारे बिडला-भवन पहुचने के समय तक वहा भारी भीड जमा हो चुकी थी। चारो ओर गडबडी थी। नौजवानो की भीड भवन की खिडकियो पर टूटी पड रही थी। अन्दर लगभग सभी मत्री और प्रमुख काग्रेसजन शोक से स्तब्ध खडे थे। हम गाधीजी के शयन-कक्ष मे गये। वहा धूप की सुगन्ध आ रही थी। कमरे मे लगभग ४० व्यक्ति मौजूद थे, जिनमे नेहरू और पटेल भी थे। हर एक की आखों से आसू बह रहे थे। कमरे के बाहर असख्य जूते रख थे, जिन्हे लोगो ने अन्दर आने के पहले उतार दिया था।

सुदूर कोने मे गाधीजी का निष्प्राण शरीर प्रतिष्ठित था। पहले मैंने समझा कि उसे किसी बडे कम्बल से ढक दिया गया है, परन्तु बाद मे मैंने देखा कि उनके आसपास लगभग एक दर्जन महिलाए बैठी थी और आर्त्त स्वर मे प्रार्थना कर रही थी। उनमे से एक महिला उनके सिर को सम्भाले हुए थी।

गाधीजी की मुद्रा शान्त थी और तीव्र प्रकाश मे कुछ पीली दिखलाई पडती थी। उनका लोहे के फ्रेम का चश्मा, जो उनकी छवि का अविच्छिन्न अग बन गया था, उतार लिया गया था। धूप की सुगन्ध, महिलाओ के भजन का स्वर, छोटा-सा दु र्बल शरीर, सोती हुई-सी मुख-मुद्रा और मूक-दर्शक—कदाचित ये मेरे जीवन के सबसे अधिक सनसनीपूर्ण क्षण थे। वहा खडा-खडा मै भविष्य के बारे मे व्याकुल हो रहा था, इस दुष्कृत्य पर चकरा रहा था। परन्तु पराजय के स्थान पर विजय की अनुभूति भी कर रहा था। मै महसूस करता था कि इस छोटे-से पुरुष के आदर्शो की शक्ति हत्यारे की गोलियो और उनमे निहित विचार-धारा को दबाने के लिए काफी प्रबल सिद्ध होगी।

कुछ देर तक मौन श्रद्धाजलि देने के बाद हम बडे कमरे मे आ गए। बाहर जन-समुदाय बढता ही जा रहा था और खिडकियो के काचो पर लगातार हाथ पीटे

जा रहे थे। मत्रिमडल के सदस्य दूसरे कमरे मे थे। अतएव माउन्टबेटन उनसे बात करने के लिए वहा चले गए।

मैंने माउन्टबेटन को कहते हुए सुना कि गाधीजी ने उनसे अन्तिम भेंट मे कहा था, "मेरी सबसे बडी इच्छा नेहरू और पटेल मे हार्दिक मेल कराने की है।" यह सुनकर दोनो ने नाटकीय ढग से एक-दूसरे का आलिगन किया। कुछ देर बाद माउन्टबेटन बाहर निकल आये। उन्होने कहा, "पर मैंने पटेल को नेहरू के साथ आज रेडियो पर बोलने को सहमत कर लिया है।" वह इसे बडी विजय समझते थे—और इसमे तथ्य भी था। उन्होने फिर कहा कि सब कुछ नेहरू द्वारा स्थिति को तुरन्त सम्भाल लेने पर निर्भर करता है।

तनातनी इतनी अधिक थी कि कोई भी असावधानी भरा शब्द या अफवाह दावानल के समान फैल जायगी। माउन्टबेटन के आते ही किसी आतक फैलाने वाले ने उनका इन शब्दो से स्वागत किया था, "हत्यारा मुसलमान था!" उस समय तक हत्यारे के धर्म और नाम का हमे कोई पता नही था। परन्तु माउन्टबेटन ने यह समझ कर कि यदि वह मुसल्मान था तो ससार की कोई शक्ति नितान्त विनाशक गृह-युद्ध को टाल नही सकती, अन्त प्रेरणा से तुरन्त उत्तर दिया, "मूर्ख, तुम्हे पता नही कि वह हिन्दू था!"

कुछ मिनट बाद मुझे वी पी मेनन से पता चला कि हत्यारा एक मराठा है। जैसे ही गाधीजी अपनी प्रार्थना-सभा मे जाने के लिए निकले उसने बिलकुल निकट से उनपर तीन गोलिया चलाई। मैंने डाक्टर से भी बात की, जो अन्तिम समय से गाधीजी के पास था। उसने कहा कि मकान मे एक भी दवा नही थी, लेकिन अगर होती भी तो कोई फायदा न होता। गान्धीजी ने जरा-सा पानी पिया और फिर उनकी चेतना जाती रही, जो कभी नही लौटी। अन्त्येष्टि के सम्बन्ध मे काफी चर्चा हुई। गाधीजी का स्पष्ट आदेश था कि उनके शरीर को सुरक्षित न रखा जाय, "बल्कि हिन्दू-पद्धति के अनुसार शीघ्र-से-शीघ्र जला दिया जाय।" माउन्टबेटन चाहते थे कि दाह-सस्कार कम-से-कम २४ घटे बाद हो, ताकि उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। परन्तु स्पष्ट दिखलाई पड रहा था कि वह कल प्रात काल किया जायगा। अतएव प्रबन्ध का भार मत्रालय को सौंप देने का निश्चय किया गया। माउन्टबेटन ने अपनी अग-रक्षक टुकडी को भी मदद के लिए भेज दिया था। समय के साथ भीड बढती ही गई। मौलाना आजाद जैसे कुछ लोग नीरव चिन्ता मे निरत थे, श्री मुशी जैसे कुछ अन्य व्यक्ति स्वेच्छा से व्यवस्था करने मे व्यस्त थे। बाहर भीड बढती जा रही थी और गाधीजी के शरीर के दर्शनो के लिए आग्रह कर रही थी। चारो तरफ से सैकडो आखे भवन पर लगी हुई थी और लगता था कि शीशो की खिडकिया शायद ही जन-समूह के दबाव के भार को सभाल पायगी।

मैंने नेहरू को इस सामूहिक हमले के खतरे के प्रति सचेत किया। नेहरू अवर्णनीय

मे दब गए। अर्थी की गाडी को काग्रेस के झण्डो और फूलो से सजा कर तैयार किया गया था, जिसे नौसेना के सैनिक खीचेगे। अर्थी के निकट स्थान पाने के लिए मत्री और जनरलो को सामान्य नागरिको से कन्धे-से-कन्धे मिलाना पड रहे थे—यह गाधी जी के मन की चीज थी।

काग्रेस के चार आना सदस्य, जो उनकी कितनी ही लडाइयो के सैनिक रहे थे, पूरे जोश के साथ वहा उपस्थित थे। शरीर को छत से लाकर अर्थी पर रख दिया गया।

जब शव को अर्थी पर प्रतिष्ठित किया गया, तो एक बार फिर मुझ पर उस शान्त-मुद्रा का गम्भीर असर पडा। आसपास गाधीजी के पुत्र और पौत्रिया बैठी थी। बालिकाए अब भी रो रही थी और धीरे-धीरे उनके सिर पर थपकिया दे रही थी। पटेल भी पास ही निश्चल भाव से सामने देखते बैठे हुए थे। वह पीले पड गए थे और ग्ण दिखलाई पडते थे। यह व्यवस्था के उन कठिन कामो मे कोई भाग नही ले रहे थे, जिनमे नेहरू और माउन्टबेटन जुटे हुए थे।

गई रात नेहरू और पटेल दोनो के ही भाषण बहुत मर्मस्पर्शी थे। पहले से तैयार न किये जाने के कारण वे ज्यादा प्रभावशील बन पडे थे। गाधीजी के निधन से पटेल की व्यक्तिगत क्षति तो हुई ही, साथ ही उन्हे गृह-मत्री की हैसियत से भी एक भारी धक्का पहुचा। यह सच था कि गाधीजी ने सरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करने से इकार कर दिया था परन्तु यह भी उतना ही सच था कि दस दिन पूर्व के बम-विस्फोट और कल के जघन्य-कार्य मे सम्बन्ध था और पुलिस इतने दिनो तक उसकी टोह पाने मे असफल रही थी।

गोलिया खाकर गिरने से पूर्व गाधीजी पटेल से ही बाते कर रहे थे और उन्हे बातचीत के कारण कुछ विलम्ब भी हो गया था। पटेल ने अर्थी के पूरे जलूस मे शामिल होकर इसका पूर्ण प्रायश्चित्त किया, क्योकि उनकी ७२ वर्ष की अवस्था और गिरा हुआ स्वास्थ्य इसके योग्य नही था।

अत मे उस अपार मानव-सागर से अपना रास्ता निकालता हुआ अर्थी का जलूस आगे बढ चला। इस समय लगभग ग्यारह बजे थे और सारे रास्ते विशाल जन-समूह एकत्रित था। उनकी सख्या इतनी थी कि पुलिस और सेना उसे काबू मे नही रख सकती थी। उनके भारी दबाव के कारण अर्थी की चाल एक मील प्रति घटा से अधिक नही बैठ सकी। जलूस के आगे बढने की गति इतनी धीमी होने के कारण लोगो ने जलूस के साथ चलना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोडी देर मे अर्थी के पीछे चलने वाले समूह की सख्या इतनी ही विशाल हो गई जितनी कि आगे मौजूद लोगो की थी।

सरकारी भवन मे लौटने पर हमने दरबार भवन के गुबद के ऊपर चढकर देखा। जलूस 'किंग्जवे' के खुले मैदान पर मानो रुक गया था। भीड ने अर्थी के आस-... एकत्र होकर आगे बढना असभव बना दिया था।

मे दब गए। अर्थी की गाडी को काग्रेस के झण्डो और फूलो से सजा कर तैयार किया गया था, जिसे नौसेना के सैनिक खीचेगे। अर्थी के निकट स्थान पाने के लिए मंत्री और जनरलो को सामान्य नागरिको से कन्धे-से-कन्धे मिलाना पड रहे थे—यह गाधी जी के मन की चीज थी।

काग्रेस के चार आना सदस्य, जो उनकी कितनी ही लडाइयो के सैनिक रहे थे, पूरे जोश के साथ वहा उपस्थित थे। शरीर को छत से लाकर अर्थी पर रख दिया गया।

जब शव को अर्थी पर प्रतिष्ठित किया गया, तो एक बार फिर मुझ पर उस शान्त-मुद्रा का गम्भीर असर पडा। आसपास गाधीजी के पुत्र और पौत्रिया बैठी थी। बालिकाए अब भी रो रही थी और धीरे-धीरे उनके सिर पर थपकिया दे रही थी। पटेल भी पास ही निश्चल भाव से सामने देखते बैठे हुए थे। वह पीले पड गए थे और ग्ण दिखलाई पडते थे। यह व्यवस्था के उन कठिन कामो मे कोई भाग नही ले रहे थे, जिनमे नेहरू और माउन्टबेटन जुटे हुए थे।

गई रात नेहरू और पटेल दोनो के ही भाषण बहुत मर्मस्पर्शी थे। पहले से तैयार न किये जाने के कारण वे ज्यादा प्रभावशील बन पडे थे। गाधीजी के निधन से पटेल की व्यक्तिगत क्षति तो हुई ही, साथ ही उन्हे गृह-मत्री की हैसियत से भी एक भारी धक्का पहुचा। यह सच था कि गाधीजी ने सरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करने से इकार कर दिया था परन्तु यह भी उतना ही सच था कि दस दिन पूर्व के बम-विस्फोट और कल के जघन्य-कार्य मे सम्बन्ध था और पुलिस इतने दिनो तक उसकी टोह पाने मे असफल रही थी।

गोलिया खाकर गिरने से पूर्व गाधीजी पटेल से ही बाते कर रहे थे और उन्हे बातचीत के कारण कुछ विलम्ब भी हो गया था। पटेल ने अर्थी के पूरे जलूस मे शामिल होकर इसका पूर्ण प्रायश्चित्त किया, क्योकि उनकी ७२ वर्ष की अवस्था और गिरा हुआ स्वास्थ्य इसके योग्य नही था।

अत मे उस अपार मानव-सागर से अपना रास्ता निकालता हुआ अर्थी का जलूस आगे बढ चला। इस समय लगभग ग्यारह बजे थे और सारे रास्ते विशाल जन-समूह एकत्रित था। उनकी सख्या इतनी थी कि पुलिस और सेना उसे काबू मे नही रख सकती थी। उनके भारी दबाव के कारण अर्थी की चाल एक मील प्रति घटा से अधिक नही बैठ सकी। जलूस के आगे बढने की गति इतनी धीमी होने के कारण लोगो ने जलूस के साथ चलना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोडी देर मे अर्थी के पीछे चलने वाले समूह की सख्या इतनी ही विशाल हो गई जितनी कि आगे मौजूद लोगो की थी।

सरकारी भवन मे लौटने पर हमने दरबार भवन के गुबद के ऊपर चढकर देखा। जलूस 'किग्जवे' के खुले मैदान पर मानो रुक गया था। भीड ने अर्थी के आस-पास एकत्र होकर आगे बढना असभव बना दिया था।

"हमे अब चलना चाहिए।" इतना कह कर वह चल दिय और हम बहुत से लोगों ने भी उनका अनुकरण किया। इसका अच्छा परिणाम हुआ। बहुत से लोगो का रुख बदल गया।

जैसे-जैसे हम भीड से बाहर जा रहे थे चिता की ज्वालाए और धुआं आकाश की ओर उठता जा रहा था।

नई दिल्ली, मंगलवार, ३ फरवरी १९४८

गाधीजी की मृत्यु पर विश्व मे इतनी प्रतिक्रिया हुई, जिसकी मुझे कल्पना नही थी। दुनिया के कोने-से-कोने से श्रद्धाजलि और प्रशसा के सन्देशो का ताता लगा हुआ था, जिनसे पता चलता था कि उनका प्रभाव भारत की सीमा के बाहर बहुत-दूर-दूर तक फैला हुआ था। हो सकता था कि उनके जीवन का पूरा दर्शन बहुत से लोगो के पल्ले न पडा हो, लेकिन उसका रहस्य तो स्वीकार किया ही जाता था। जैसा कि किंग्सले मार्टिन ने, जो इस तमाम घटना मे मेरे साथ थे, मुझसे कहा था, "भौतिकवाद और राजनैतिक बल-प्रयोग दुनिया मे ज्यादा सफलता पान मे कामयाब नही हुआ। दुनिया स्वीकार करती है कि गाधीजी का उद्दश्य इन दोनो से भिन्न था। नैतिक मूल्यो पर उनके आग्रह से लगता है कि उनके उद्देश्य शायद बेहतर भी थे। इसीलिए वह मानवता के मानस पर अमिट छाप छोड गए थे।"

'न्यूयाक टाइम्स' के शब्दो मे,"जसे अन्य लोग सत्ता और सम्पत्ति के लिए हाथ-पैर मारते थे, वैसे ही उन्होने पूणता के लिए प्रयास किया उनका राजनैतिक प्रभाव जैसे-जसे कम होता गया उनकी सौहार्द-भावना वसे-ही-वैसे बढती गई। 'नये टस्टामेन्ट' की भावना के अनुरूप उन्होंने अपने शत्रुओ को प्रेम करने का प्रयास किया और उनकी भलाई करने की कोशिश की कि जो उनके साथ द्वेष का बरताव करते थे। वह अमर हो गए।" 'दि क्रिश्चियन सायस मानीटर' न उन्हे "प्रस्तुत युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिवादी" के रूप मे देखा। इस प्रकार वह भारतीय राष्ट्रीयता के नेता मात्र नही थे, वह समस्त विश्व के प्रतीक थे। इस पत्र ने फिर एक बडे मार्के की बात कही थी, जो उनके उद्द्श्यो और "द्विमुखी" व्यक्तित्व के बारे मे भ्रम का असली कारण था। लेख मे कहा गया था, "उनका यह विश्वास कि नैतिक प्रेरणा से व्यक्ति पहाड तक को उठा सकता है उसमे पश्चिमी विचारको की एक बडी देन, कानून के प्रति आदर की भावना से विहीन था।" लुई फिशर ने कहा था, "अधिकाश लोगो के लिए राजनीति का अर्थ था सरकार, गाधीजी के लिए इसका अर्थ था मानव-जाति। लेकिन सरकार के अभाव मे मनुष्य अपने उद्द्श्यो को नापन मे असमर्थ रहता है। इसीलिए दुनिया न गाधीजी मे चतुर राजनीतिज्ञ और अकलुष और अटल साधुत्व का मिश्रण पाया। उन्होने अकेले व्यक्ति के नतिक बल को प्रमाणित कर दिखाया।"

हो कर गाय कि अगर गाधीजी होते तो आशीर्वाद दिये बिना न रहते।

उपसहार के रूप मे आज रेडियो पर माउन्टबटन ने गाधीजी को अपनी अन्तिम श्रद्धाजलि दी। यह गाधीजी की स्मृति मे श्रद्धाजलि-भाषणो की आखिरी कडी थी, जिसका प्रारम्भ ३० जनवरी को नेहरू और पटेल के भाषणो से हुआ था, जिसमे उन्होने एकता और प्रायश्चित्त का दृढ आह्वान किया था। करीब-करीब सभी काग्रेसी-नेताओ ने भाषण दिये थे। कई के भाषण बडे मार्मिक थे और उन्होने अग्रेजी गद्य पर—असाधारण अधिकार का परिचय दिया। जो शब्द और विचार मेरे दिमाग मे बचे रह गए, उनमे सरोजिनी नायडू के शब्द भी है, "इसलिए यह उचित ही था कि वह राजाओ की नगरी मे मरे।" और फिर उनका नाटकीय आह्वान, "मेरे पिता, चैन मत लेना। न हमे लेने देना। हमे हमारे पथ पर अटल बनाये रखना।"

राजन्द्रप्रसाद ने कहा, "असली त्याग का समय तो अब आया है, जब हमे त्याग करने के लिए बुलाया जा रहा है।" राजाजी ने बडे पैने ढग से कहा, "दमन और बल-प्रयोग के बिना इस अपूर्ण ससार मे काम नहीं चल सकता, लेकिन हमे हमेशा के लिए यह जान ले कि बिना सद्भाव के सद्भाव पदा नही किया जा सकता।"

: २३ :

फिर वही संघर्ष

नई दिल्ली, रविवार, २२ फरवरी १९४८

वाल्टर माकटन एक सप्ताह हैदराबाद मे रहने के पश्चात् अभी-अभी यहा आय थे। हमे मालूम था कि वह फरवरी के मध्य मे निजाम से मिलने वाले है। अतएव माउन्टबेटन ने निजाम को लिखा था कि वह भारत के साथ सामान्य समझौता करने की दृष्टि से माकटन की यात्रा का लाभ उठाये।

निजाम न माउन्टबेटन की सलाह एकदम स्वीकार कर ली, यह माउन्टबटन के के लिए किंचित् आश्चर्य की वात थी। मै 'आश्चर्य' इसलिए कहता हूँ कि निजाम ने इन दिनो माउन्टबेटन के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत रूप से जो विचार व्यक्त किये थे, वे प्रशसापूर्ण नही थे। हमे मालम था कि वह माउन्टबटन को हैदराबाद का मित्र नही वताते थे। उन्हे अधिकार-हीन वताते थे और कहते थे कि माउन्टबेटन का भावी वार्ताओ मे सहायता करन या न करन से कोई अन्तर नही पडता। परन्तु अब

उन्होने यह आशा व्यक्त करते हुए उत्तर दिया कि माउन्टबेटन "इग्लैड के शाही-परिवार के सदस्य की हैसियत से, दीर्घ-कालीन समझौता कराने मे, जो दुनिया की नजर मे हैदराबाद की ऊची स्थिति के अनुरूप हो, हैदराबाद को अपनी बहुमूल्य सहायता और समर्थन प्रदान करे।" मजे की बात थी कि वह सदा ही माउन्टबेटन के शाही सम्बन्ध की दुहाई देते थे, मानो उससे माउन्टबेटन को हैदराबाद के साथ चर्चा करने के लिए कोई विशेष अधिकार या दर्जा प्राप्त हो गया हो।

'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर होने के बाद एक मास तक करीब-करीब पूरी शाति रही। परन्तु नववर्ष के कुछ ही बाद एक घटना घटी, जिससे ज्ञात होता था कि शाति धोखे की टट्टी थी। भारत के नव-नियुक्त एजेट-जनरल के एम मुशी को निवास-स्थान देने के बारे मे झगडा उठ खडा हुआ। वह था तो बहुत छोटा, लेकिन बिलकुल अर्थहीन नही। जो भवन उनके लिए निर्धारित हुआ था वह तैयार नही था। इसलिए यह सुझाव पेश किया गया कि वह ग्यारह दिनो के अन्तरिम-काल मे किसी एक रिक्त रेसीडेसी मे रहे। निजाम ने तुरन्त इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्हे इसमे सर्वोच्च सत्ता को पुनरुज्जीवित करने की दुरभिसधि दिखलाई पडी। भारत की ओर से यह सीधा-सादा उत्तर दिया गया कि मुशी को समुचित और उपयुक्त निवास-स्थान नही दिये जाने पर उन्हे या किसी अन्य एजेट-जनरल को भेजा ही नही जायगा। इस मौके पर माउन्टबेटन की याद की गई और पत्रो तथा तारो के तेज आदान-प्रदान के बाद निजाम हठ छोडने के लिए राजी हुए। मुशी ५ जनवरी को अपना कार्य-भार सभालने के लिए रवाना हो गए।

इस महीने के अत तक हैदराबाद और भारत का सम्बन्ध इतना खराब हो गया कि दोनो ओर से 'यथास्थिति समझौते' के भंग कर दिये जाने की आशका दिखलाई पडने लगी। सीमा के पास घटनाओ की सख्या मे भयानक वृद्धि हो गई। छोटी-छोटी बातो मे परेशान करने की नीति अपनाये जाने के कारण उत्तेजना फैलती जा रही थी। हैदराबाद-सरकार ने इस नीति का आरम्भ राज्य से कुछ धातुओ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा कर किया। बाद मे साधारण व्यापार के लिए भारतीय मुद्रा पर से मान्यता उठा ली।

इन दोनो से अधिक उत्तेजनात्मक कार्रवाई यह थी कि पाकिस्तान को २० करोड रुपयो का ऋण दे दिया गया। इस सौदे की परिस्थितिया गुप्त और अशान्तिकारक थी। माउन्टबेटन ने इस मामले का बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया और उन्हे जो प्रमाण मिले उनसे इस निष्कर्ष को टालना कठिन था कि यह सौदा वर्तमान विदेश-मत्री मोइन नवाज जग ने उस समय किया था, जब वह 'यथास्थिति समझौता-वार्ता' करने वाले प्रतिनिधि-मडल के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही उस समय की गई जब भारत-सरकार पाकिस्तान को ५५ करोड रुपये न देने का विचार कर रही थी। हैदराबाद की ओर से भी आर्थिक नाकेबदी की विस्तृत

शिकायतें आ रही थी।

गांधीजी के दाह-संस्कार के दिन माउन्टबेटन ने हैदराबाद के नये इत्तिहादी प्रधान मंत्री मीर लायकअली से पहली बार भेंट की। माउन्टबेटन ने उन्हें साफ़ साफ़ शब्दों में सलाह दी कि उनकी सरकार को अपना रवैया सुधारना चाहिए और आमतौर से भारत के साथ दोस्ताने ढंग से काम करने की कोशिश करना चाहिए, तथापि माउन्टबेटन को विश्वास नहीं था कि उनकी बात का कोई गहरा असर हुआ होगा। मीर लायकअली के विनम्र बाहरी व्यवहार के पीछे उन्होंने धर्मान्धता तथा चालबाजी का वह रुख देखा, जिसे हम इत्तिहाद तथा उसके नेताओं का प्रमुख चिह्न मानने के लिए बाध्य हो गए थे। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि मांकटन निजाम को किस हद तक रचनात्मक नीति अंगीकार करने को समझा सकते है, और माउन्टबेटन पटेल तथा भारत-सरकार का धैर्य कायम रखने में कहां तक सफल हो सकते हैं।

नई दिल्ली, सोमवार, २३ फरवरी १९४८

आज सवेरे माउन्टबेटन ने अपने कर्मचारी-मंडल की जो अनौपचारिक बैठक की उसमें वाल्टर मांकटन और वी० पी० मेनन भी अतिथि के रूप मे उपस्थित थे। हम अपने कार्यक्रम की सीमा तोड़कर काश्मीर के संघविलय सम्बन्धी स्मरण-पत्रों और राष्ट्र-मंडल की नागरिकता पर अटकलबाजियों मे लग गए। काश्मीर के विषय मे मांकटन ने कहा, "साफ बात यह है कि इस महादेश के बाहर इस प्रश्न को समझा ही नहीं गया।" वी० पी० मेनन ने जोर देकर कहा कि वास्तव मे सत्ता-हस्तांतरण के पूर्व भावी पाकिस्तान सरकार की संघ-विलय नीति के विषय में अब्दुर्रबनिश्तर की सहमति प्राप्त कर ली गई थी। बाद मे पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकार भी किया था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान मे मिलना मूलतः समझौते के खिलाफ था। काक जुलाई मे दिल्ली आये थे और उन्होंने पटेल से भेंट की थी। पटेल ने उनसे कहा था कि हम जनता की इच्छा के विरुद्ध काश्मीर को भारत मे शामिल करना नहीं चाहते। उस समय माउन्टबेटन की मदद से उन्होंने जिन्ना से भी भेंट की थी।

वैदेशिक मामलों मे नेहरू के सुयोग्य सचिव सर गिरिजाशंकर बाजपेयी के साथ लम्बी बातचीत मे गार्डन वाकर ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि रूस के साथ मैत्री केवल पराधीनता के मूल्य पर खरीदी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत मे रूस का कोई बुनियादी हित नहीं है। संयोग मे मैंने यह भी सुना था कि बाजपेयी ने अमरीकी राजदूत ग्रेडी के साथ कोरिया के प्रश्न पर बातचीत आरम्भ की है। अड़तीसवी अक्षांश रेखा से रूसी तथा अमरीकी असरवाले क्षेत्रों को विभाजित कर देने के कारण उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की स्थिति बहुत-

कुछ पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी की स्थिति के समान हो गई थी। वाजपेयी का तर्क यह था कि यदि अमरीकी सेना कोरिया से नही हटाई जाती तो भारतीय सेना को काश्मीर से हटने के लिए क्यो कहा जाना चाहिए ?

आज सवेरे को बैठक मे मैने जोर दिया कि गार्डन वाकर मे २९ फरवरी तक, जब कि लियाकत के आने की सभावना थी, ठहर जाने का आग्रह किया जाय। मेरी दृढ धारणा थी कि लियाकत और नेहरू के बीच आगामी बातचीत मे एक ब्रिटिश-मत्री का उपस्थित रहना सौहार्द तथा समझौते का प्रेरक होगा। अबतक उचित स्थान और उचित समय पर कभी भी कोई योग्य मध्यस्थ उपस्थित नही रह सका।

माउन्टबेटन ने मुझे आदेश दिया कि सयुक्तराष्ट्र सघ के द्वारा विश्वलोकमत को प्रभावित करने मे भारतीय पक्ष को जो असफलता मिली, उसका सपर्यवेक्षण करू। मैने कहा कि भारतीय पक्ष मे गुण-दोष कोई भी हो, इतना तो सही था कि उसे नितान्त अयोग्य ढग से पेश किया गया है। जन-सपर्क के प्राय प्रत्येक नियम की उपेक्षा की गई इसके अतिरिक्त, मेरा खयाल था कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आरोपो—विशेषत अब्दुल्ला के द्वारा महाराजा को आत्मसमर्पण कराने के कथित "षड्यत्र"—का उत्तर देने की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया। इस प्रकार के आरोपो की उपेक्षा मात्र कर देना समझदारी की बात नही थी।

नई दिल्ली गुरुवार, ४ मार्च १९४८

हैदराबाद का नया प्रतिनिधि-मडल, जिसमे मीर लायक अली, मोइन नवाज जग (मीर लायक अली के महत्वाकाक्षी और शक्तिशाली सम्बन्धी) और मॉकटन थे, दिल्ली आये हुए है। प्रतिनिधि-मडल ने मगलवार को और आज माउन्टबेटन से भेट की। मेनन भी दोनो बैठको मे उपस्थित थे।

कल मीर लायकअली कराची गये थे और माउन्टबेटन के सुझाव पर उन्होने लियाकत से कहा कि वह हैदराबाद के २० करोड रुपयो के ऋण को यथास्थिति समझौते के काल मे बैक से न निकालने का वादा कर दे। वह इस बारे मे लियाकत का मौखिक वादा लेकर लौटे थे।

दोनो ओर से शिकायतो के लम्बे गान गाये गये है। वी पी ने पाकिस्तान को ऋण दिये जाने और भारतीय मुद्रा को अवैध घोषित करने वाले आर्डिनेन्स की कहानी कही। मीर लायक अली ने हैदराबाद के विरुद्ध पूरी आर्थिक नाकेबन्दी का ब्योरा दिया। माउन्टबेटन ने बताया कि भारत मे साम्प्रदायिक सेनाए भग कर दी गई है और हैदराबाद को भी साकेतिक रूप मे इत्तिहाद की सैनिक शाखा, रजाकार सगठन को, जिस के अत्याचारो की गम्भीर कहानिया सुनाई दे रही थी, भग कर देना चाहिए। उन्होने हैदराबाद मे शीघ्र उत्तरदायी शासन स्थापित करने की

आवश्यकता भी समझाई ।

यहा समय और कार्य-पद्धति सम्बन्धी पुराना गतिरोध, जिसकी तह मे सत्ता के सघर्ष छिपा हुआ था, फिर शुरू हो गया। पटेल महसूस करते थे कि जबतक 'यथा-स्थिति समझौता' उचित रूप से अमल मे नही आता, तब तक दीर्घकालीन समझौते की बाते करना बेकार थी। और 'यथास्थिति समझौते' के कार्यान्वित होने की आशा तबतक नही की जा सकती जबतक कि किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना न हो जाय। उसकी प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप मे पटेल इस सुझाव का समर्थन करने को तैयार नही थे कि बराबर सख्या मे हिन्दुओ और मुसलमानो की अतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाय। दूसरी ओर, मीर लायकअली अपने को दीर्घ-कालीन समझौता होने के पूर्व हिन्दू-बहुल सरकार कायम करने मे असमर्थ समझते थे। वह समान सख्या के सुझाव से आगे जाने को तैयार नही थे। फिर भी उनका खयाल था कि दीर्घकालीन समझौता और हिन्दू बहुमत सरकार की स्थापना, दोनो बाते एक साथ हो सकती थी।

बैठक के बाद एक विज्ञप्ति निकालने के प्रश्न पर अच्छा-खासा तूफान उठ खडा हुआ। पटेल ने उसमे किसी भी ऐसी बात को शामिल करने से इकार कर दिया, जिससे सकेत मिलता हो कि भारत ने 'यथास्थिति समझौते' को भग किया है। जहातक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध था, यहा पटेल का आधार दृढ था। उपद्रवो का स्तर प्रादेशिक था और उनके लिए स्थानिक अधिकारी जिम्मेदार थे। शासकीय बोझ और अनुभवहीनता की वर्तमान अवस्था मे आदेश दे देना, उनके कार्यान्वित होने की व्यवस्था करने से कही सरल था। पटेल विज्ञप्ति मे यह कहने को भी तैयार नही थे कि हैदराबाद को जाने वाला माल, जिसे रोका गया बताया जाता है, छोड दिया जाना चाहिए। शायद इसकी तह मे यह शका थी कि यदि इस बात को स्वीकार किया गया तो यह अर्थ लगाया जायगा कि उन्होने व्यापक क्षेत्र मे हैदराबाद के आरोप स्वीकार कर लिये है। माकटन बहुत परेशान थे। माउन्टबेटन ने एक भोज से लौटने के बाद टेलीफोन पर उनसे बाते करके कल इस विषय को फिर उठाने का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली शुक्रवार, ५ मार्च १९४८

माकटन आज तडके हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और माउन्टबेटन ने उनकी अनुपस्थिति मे विज्ञप्ति के सम्बन्ध मे पूछताछ की। उन्होने नेहरू से बाते की। उनका रुख बहुत उचित और सहानुभूतिपूर्ण था। परन्तु वह उत्सुक थे कि इस प्रश्न का हल पटेल के साथ ही किया जाना चाहिए, जो रियासती मत्री की हैसियत से हैदराबाद के मामले के लिए उत्तरदायी है। आज तीसरे पहर माउन्ट-बेटन पटेल से मिलने वाले थे, परन्तु भोजन करते समय पटेल को हृदय का दौरा

हो गया और उनकी हालत खराब हो गई। अब उन्होंने खाट पकड ली और उनके डाक्टर ने अनिश्चित समय के लिए किसी प्रकार का भी काम करने पर पाबन्दी लगा दी। पाबन्दी का यह समय हमारे यहा से जाने के पहले खत्म होता नही दीखता।

मेरा खयाल था कि गाधीजी की मृत्यु के बाद पूरे छ घटे अर्थी के साथ चलकर उन्होने अपने स्वास्थ्य को चोपट कर लिया था। जब मैने उन्हे राजघाट पर देखा था, तब वह बहुत दुबले और बीमार मालूम होते थे। ऐसा लगता था मानो वह मूर्छा मे हो। सारी दुखान्त घटना ने उन पर भारी आघात किया था और, निस्सन्देह उन्हे गृहमन्त्री की हैसियत से गाधीजी की समुचित रक्षा का प्रयन्न न कर सकने पर आलोचनाओ का उचित से अधिक प्रहार सहना पडा। इस राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सकट के समय उनकी बीमारी सरकार के लिए एक भारी चोट थी। इससे जाहिर होता था कि शासन-यत्र अपने दो नेताओ का किस कद्र मोहताज था।

जहा तक हैदराबाद के तात्कालिक प्रश्न विज्ञप्ति, का सम्बन्ध था, ऐसा कोई व्यक्ति नही, जो उनके अन्तिम निर्णय को बदलने की जिम्मेदारी ओढ सके। अतएव, माउन्टबेटन माकटन को लिख देने के लिए विवश हो गए कि फिलहाल कोई प्रेस वक्तव्य नही निकाला जाना चाहिए।

नई दिल्ली, शनिवार, ६ मार्च १९४८

माउन्टबेटन ने हैदराबाद स्थित भारतीय एजट जनरल के एम मुशी से भेट की। मुशी काफी उत्साही, ध्येयवादी, और मै समझता हू, महत्वाकाक्षी व्यक्ति है। यद्यपि उनके पास ब्रिटिश राज की खिलाफत मे कारावास जाने का काग्रेसी सर्टीफिकेट नही है, फिर भी वह काग्रेस के शासकीय आकाश मे ऊपर उठ रहे थे। इससे उनकी राष्ट्रीयता मे उग्रता आना कोई आश्चर्य की बात नही है।

महात्मा जी के सम्बन्ध मे अपने सस्मरण प्रसारित करते हुए उन्होंने अपने-आपको अहिसा का विद्यार्थी बताया था। वह इस आधार पर गाधीजी से झगडने को तैयार थे कि "१९४२ का सत्याग्रह आन्दोलन असफल रहा था। वह अहिसा की कसौटी पर खरा नही उतरा था क्योकि उसमे शत्रु के प्रति प्रेम की बजाय क्रोध की सृष्टि हुई थी।" आज उन्होंने माउन्टबेटन से जो कुछ कहा उससे स्पष्ट था कि वह हैदराबाद के साथ बर्ताव करने मे अहिसा पर ज्यादा भरोसा नही कर रहे थे। उनकी सलाह थी कि यदि रजाकारो की प्रवृत्तियो को तुरन्त रोका नही जाता तो भारतीय पुलिस को भेज कर उन्हे रोकना चाहिए। 'यथास्थिति समझौते' की उनकी कानूनी व्याख्या के अनुसार ऐसा करना उसकी शर्तो के अनुकूल होगा। उनका विश्वास दृढ था कि रजाकारों को वर्तमान शासन न तो रोक सकता था और न रोकना चाहता था।

माउन्टबेटन ने दृढता के साथ कहा कि भारत को हैदराबाद के प्रति नैतिक

तथा उचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसे विश्व के लोकमत के सामने उचित ठहराया जा सके। बातचीत की वर्तमान अवस्था मे मुशी का पुलिस-कार्यवाही का सुझाव बिलकुल गलत था। मीर लायकअली को रजाकारो से निबटने, 'यथास्थिति समझौते' को कार्यान्वित करने और किसी हद तक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

बाद को माउन्टबेटन ने मुझ से कहा कि हालाकि उन्हे मुशी की तत्परता और योग्यता के बारे मे कोई सशय नही था, लेकिन वह नही समझते कि मुशी का स्वभाव और राजनैतिक दृष्टिकोण इस नाजुक दौर मे निजाम से निबटने के लिए उपयुक्त है। इस समय तो असाधारण कूटनीतिक धैर्य और साम्प्रदायिकताहीन वस्तुनिष्ठ की आवश्यकता थी।

माकटन हैदराबाद से लन्दन के लिए रवाना हो गए है। हमे डर था कि कही यह समझकर कि इस सप्ताह जैसी बातचीत केवल समय बर्बाद करना था, वह पूरे मामले से भी हाथ न धो बैठे। माकटन के बिना माउन्टबेटन द्वारा पहल करने की सभावना काफी कम हो जायगी।

: २४ :

परिभाषा और अनुसंधान

नई दिल्ली, शुक्रवार, १९ मार्च १९४८

हम ८ मार्च को कलकत्ता, उडीसा, बरमा और आसाम की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। सब मिलाकर नौ दिन की यात्रा के बाद हम फिर दिल्ली आ गए थे और काम मे जुट गए। दो महीने बाद आज लियाकत और नेहरू मिले। सयुक्त सुरक्षा कौसिल के तत्वावधान मे उन दोनो की भेट कराने मे माउन्टबेटन को काफी कठिनाई हुई। उन्होने निश्चय किया कि सयुक्त सुरक्षा कौसिल की यह अन्तिम औपचारिक बैठक होगी। वैसे वह किसी भी हालत मे १ अप्रैल को समाप्त हो ही रही थी, लेकिन माउन्टबेटन चाहते थे कि वह अपने मौजूदा रूप मे (उनके जाने तक उनकी अध्यक्षता मे, और फिर जिस देश मे बैठक हो उसके प्रधान मत्री की अध्यक्षता मे) एक वर्ष और कायम रहे, जिसमे आगे चलकर इसका कार्यक्षेत्र बढाकर वित्त सबधी और आर्थिक मामले, सचारसाधन और विदेशी मामले भी इसमे शामिल कर लिये जाय। हालाकि यह इरादा दोनो मे से किसी भी पक्ष को पस—

नही आया, फिर भी दोनो प्रधान-मत्रियो ने एक हदतक व्यक्तिगत सपर्क के साधन के रूप मे सयुक्त सुरक्षा कौसिल के महत्व को मान लिया। सामान्य रुचि के विषयो पर चर्चा करने के लिए उन्होने हर महीने बाद मिलना स्वीकार कर लिया।

कटुता और दुराशा भरे पिछले छ महीनो की एक विशेष बात यह रही थी कि नेहरू और लियाकत ने अपनी सौम्यता को कायम रखा था। ऐसा लगता था कि यदि इन दोनो को सारे फैसले करने के लिए अकेला छोड दिया जाय, और उनपर निरन्तर डाले जाने वाले दबाव और बोझ हटा लिये जाय तो सारे मतभेदो के बारे मे दृढ समझौता होने मे देर नही लगेगी।

आज की बैठक मे गौण विषयो पर सौहार्द पूर्ण समझौता हो जाने पर भी काश्मीर का कोई जिक्र नही किया गया। इसका कारण यह नही था कि इस बारे मे बात करने की कोई नई बात नही थी बल्कि सुरक्षा परिषद् के वर्त्तमान अध्यक्ष, चीनी प्रतिनिधि डा सियाग ने स्वत निजी प्रेरणा मे कुछ सुझाव रखे थे जो बुनियादी तौर पर भारत के मन माफिक थे। लेकिन अभाग्यवश डा सियाग ने अपनी योजना के लिए ज्यादा व्यापक समर्थन पाने की चेष्टा नही की। इसका नतीजा यह होगा कि इससे कटुता ही बढेगी और सद्भावना की रही-सही सभावना भी नष्ट हो जायगी। इससे अनुमान होता था कि लेक सक्सेस के काम करने के ढग मे कोई भारी दोष था।

सयुक्त राष्ट्र सघ मे काश्मीर विषयक प्रचार की शायद सब मे अनिष्टकारी, हालाकि अप्रत्याशित नही, घटना यह थी कि जफरुल्ला खा ने भारत की शिकायत के जवाब मे पाकिस्तान की ओर से आरोपो का क्षेत्र काफी व्यापक बना दिया था और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह ऐसे प्रचार पर उतर आये थे, जिसे अमरीकी लोग "चारित्रिक हत्या" कहते थे। ऐसे मौके पर उन्होने माउन्टबेटन का नाम बीच मे घसीटा, जब अपनी वैधानिक स्थिति के कारण माउन्टबेटन सार्वजनिक रूप से कोई उत्तर देने मे असमर्थ थे।

कर्मचारी मडल की बैठक मे इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई और बडी बुद्धिमानी से माउन्टबेटन ने निश्चय किया कि पाकिस्तानी आरोपो के उत्तर में उनके वक्तव्य को आवश्यक प्रमाणो सहित सयुक्तसुरक्षा कौसिल के भग होने के पूर्व उसकी कार्यवाही मे शामिल कर लिया जाय। इससे उनके उत्तर, भारत और पाकिस्तान, दोनो सरकारो के समक्ष आ सकेगे। इस बारे मे उन्होने ब्रिटिश सरकार को भी पूरी जानकारी देने का फैसला किया, क्योकि वाइसराय के रूप मे उन पर होने वाले हमलो से ब्रिटिश सरकार भी अछूती नही बच सकती थी।

जफरुल्ला के दो मुख्य आरोप थे वाइसराय के नाते माउन्टबेटन को जुलाई के प्रारम्भ से सिखो की योजना का पता था। यह जानते हुए भी उन्होने नेताओ को गिरफ्तार करने और उपद्रवी तत्त्वो को कुचलने के लिए कोई सक्रिय कदम नही उठाया, हालाकि ऐसा करने का वादा वह कर चुके थे।

अपने स्मरणपत्र मे माउन्टबेटन ने यह स्पष्ट किया था; हालांकि सरकार के ऊचे पदो पर काम करने वाले लोग सिखो की समस्या के बारे में किसी प्रकार के भ्रम मे नही थे और उसे सुलझाने की आवश्यकता महसूस करते थे, किन्तु किसी विशेष 'सिख योजना' का उन्हे या किसी और को कोई पता नही था। ५ अगस्त को ब्रिटिश खुफिया अधिकारी से मुलाकात के पूर्व इसका कोई सकेत तक नही था। इस मुलाकात मे भी 'योजना' के आकार-प्रकार और काम करने के ढग के बारे मे कोई सतोषजनक जानकारी नही मिल सकी थी। माउन्टबेटन ने अपने तर्क का आधार जेनकिन्स के ९ अगस्त के पत्र को बनाया था। इसमे जेनकिन्स ने पजाब के तीनों गवर्नरों, खुद अपना और अपने उत्तराधिकारी मनोनीत गवर्नरो का मत प्रेषित करते हुए लिखा था कि तीनो एकमत थे कि सत्ता-हस्तातरण के पहले सिखो की गिरफ्तारी की योजना तैयार करने मे अधिक कुछ नही किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान ने एक और भी आरोप लगाया था - सीमा आयोग के निर्णय के प्रकाशित होने के पूर्व वाइसराय भवन के दबाव पर उसे पाकिस्तान के खिलाफ बदल दिया गया था। इसके सबूत मे पेश किया गया एबेल का जेनकिन्स के नाम लिखा ८ अगस्त का पत्र था, जिसमे कहा गया था कि सीमा आयोग का निर्णय ११ अगस्त को प्रकाशित करने का विचार है। इसमे प्रस्तावित निर्णय की एक रूपरेखा भी योजित थी, जिसमे फिरोजपुर और जीरा तहसीलो को पाकिस्तान के अन्तर्गत दिखाया गया था।

बात दरअसल यह थी कि रेडक्लिफ के सेक्रेटरी ने अन्तरिम निर्णय की एक रूप-रेखा एबेल को दी थी। यह रूपरेखा एबेल ने जेनकिन्स को भेज दी, जिन्होने कुछ दिन पूर्व माग की थी कि पहले से इस विषय मे कोई सूचना मिलने से उन्हे पुलिस और सेना तैनात करने मे सहूलियत होगी। यह पूर्वसूचना "दो तहसील" और "दोदिन" के विषय मे गलत निकली। बस वास्तविकता तो इतनी ही थी।

नई दिल्ली, रविवार, २१ मार्च १९४८

चीनी-योजना की भारत के पत्रो मे प्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' इसे "झगडे को युक्तिपूर्ण और व्यवहारिक ढग से निबटाने का पहला उचित प्रयास" मानता था। उसका कहना था "मुख्य सुझाव ऐसे हैं कि कोई भी स्वाभिमानी और शांति-प्रिय राष्ट्र उसे स्वीकार कर सकता है।" लेकिन डान ने आशा प्रकट की, "सुरक्षा परिषद् पहले जैसे यथार्थवाद का परिचय देगी और "समझौते" के लिए प्रस्तुत चीनी सुझावो को, जो एक पक्ष को सब कुछ देने को तैयार थे, और दूसरे को कुछ भी नही, पहले जैसी रोशनी मे देखेगी।' पाकिस्तान का तर्क अब भी यही था कि शासकीय व्यवस्था का प्रश्न काश्मीरी जनता के स्वतन्त्र और

निडर मतदान के बाद ही निबटाया जाना चाहिए, पहले नही।

इस निराशाजनक बहस मे एक मात्र नई चीज थी २० मार्च के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" मे प्रकाशित सुझाव। देवदास गाधी और जी डी बिडला के ऊचे सबधो को देखते हुए, इस पत्र के सुझावो पर हमेशा विचार करना पडता था। जनमत सग्रह मे काश्मीरी जनता के मिलने वाले विकल्पो की चर्चा करते हुए पत्र ने लिखा था, "हमारा मत है कि उनसे केवल इस या उस राष्ट्र मे शामिल होने के लिए मत देने की माग करना गलत और अनुचित होगा। उनको इस बात का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए कि दोनो मे से चाहे जिस राष्ट्र मे शामिल हो या स्वतन्त्र रहे।"

नई दिल्ली, बुधवार, ७ अप्रैल १९४८

हमारे बरमा से लौटने पर माउन्टबेटन के नाम निजाम का एक पत्र आया हुआ था। चूंकि माउन्टबेटन फिर दिल्ली से बाहर जाने वाले थे और इस विवाद से पीछा छुडाना चाहते थे, इसलिए अपने वैधानिक अधिकारो के अनुसार उन्होने रियासती सचिवालय से उसका उत्तर भेज देने को कहा। इस आशय की सूचना उन्होने निजाम को भी भेज दी। रियासती सचिवालय का यह पत्र पहले लिखा गया वी पी मेनन द्वारा, पटेल ने उसमे गरमी भरी, नेहरू ने ठडा किया। माउन्टबेटन ने इसकी प्रति मूल-पत्र चले जाने के बाद देखी और पत्र उन्हे काफी कडा और धमकी भरा लगा। पत्र मे खुले तौर पर निजाम के ऊपर 'यथास्थिति समझौता' भग करने का आरोप लगाया गया था और माग की गई थी कि उसका पालन किया जाय और इत्तिहाद तथा रजाकारो पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

माकटन ने पहले भी इस आशय का विचार प्रकट किया था कि वह इस झमेले से अपने को दूर रखना पसन्द करेगे। अब वह पुन मैदान मे लौट आये है। २८ मार्च को वह हैदराबाद आ गए थे। रियासती सचिवालय के पत्र और रियासत की आम स्थिति का उनपर बडा गहरा असर हुआ। सामान्यत शात और खुशदिल रहने वाले माकटन सबसे लोहा लेने के इरादे से कमर कसकर कल रात दिल्ली आये। निजाम का उत्तर वह अपने साथ लाए थे। यह पत्र बडी चतुराई के साथ लिखा गया था और भारतीय पत्र को कई जगह नीचा दिखलाने वाला था। पत्र पर उनकी प्रतिभा की साफ-साफ मुहर अंकित थी।

दोनो के बीच दृढ दोस्ती और एक दूसरे को भली प्रकार समझने के आधार पर उनमे खुलकर चर्चा हुई। माउन्टबेटन माकटन को यह विश्वास दिलाने मे सफल हुए कि भारत सरकार का अन्तिमेत्थम देने का कोई इरादा नही, और हैदराबाद की नाकेबंदी के लिए वह जिम्मेदार नही। थोडी देर बाद नेहरू ने भी आकर इसी बात की पुष्टि की।

भारत के कई पत्रो मे एक जिहादी भाषण छपा है, जो धर्मान्ध इत्तिहाद नेता, कासिम रिजवी ने ३१ मार्च को "हैदराबाद शस्त्र-दिवस" के उद्घाटन अवसर पर दिया कहा जाता था। इसने एक नई खलबली मचा दी थी। छपी सूचना के अनुसार रिजवी ने हैदराबाद के मुसलमानो को ललकारा था कि जबतक इस्लाम की विजय का लक्ष्य पूरा न हो जाय, तबतक अपनी तलवारो को म्यान मे न रखे। उसके भाषण के सबसे कुत्सित शब्द थे "भारत सघ मे रहने वाले ,हमारे मुसलमान भाई हमारा पाचवा दस्ता होगे।" इस प्रकार की भाषा का उद्देश्य पूरे दक्षिण भारत मे साम्प्रदायिक आग भडकाना था, जो ईश्वर की कृपा से अभी तक उत्तर भारत मे फैले घातक प्रभाव से बचा हुआ था।

नई दिल्ली, रविवार, ११ अप्रैल १९४८

रिजवी का मामला और भी तूल पकडता जा रहा था। माकटन कल हैदराबाद लौट गए। उनको दृढ विश्वास हो गया था कि निजाम को शीघ्र ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। वह निजाम को शीघ्र रिजवी की गिरफ्तारी करने का परामर्श भी देगे। परन्तु आज माकटन के पास से एक तार आया था। उसमे माउन्टबेटन को सूचित किया गया था कि हैदराबाद सरकार को सतोष था कि ३१ मार्च का कथित जिहादी भाषण कभी किया ही नही गया और इससे लगता था कि मैत्रीपूर्ण सबधो की स्थापना मे अडगा डालने का यह सोच-विचार कर रचा गया षडयत्र था।

माउन्टबेटन ने तुरन्त मुझे बुलाया और मुझसे उपलब्ध तथ्यो की शीघ्र छानबीन करने को कहा। इसलिए अब मै जासूस बनकर "रिजवी के वक्तव्य के रहस्य" की छानबीन करने मे निमग्न हू। यदि इस घटना को आच्छादित किये हुए परस्पर-विरोधी और अनिर्णायिक प्रमाणो मे से ही सही मार्ग निकालना था तो मुझे शर्लाक होम्स की सारी तर्क-शक्ति की जरूरत पडेगी। वर्त्तमान स्थिति मे तो मै डा वाट्स की उलझन का ही भागी हू। पहला विचित्र पहलू तो यह था कि भाषण भारतीय पत्रो मे एक सप्ताह के साधारण विलम्ब से प्रकाशित हुआ। उसका बहुत-सा भाग प्रत्यक्ष भाषण के रूप मे था और उसमे श्रोताओ के उत्साहपूर्ण उद्गार भी दिये गए थे।

दो दिन पूर्व भारतीय ससद (लेजिस्लेटिव असेम्बली) मे नेहरू ने उसे हिंसा तथा हत्याओ को प्रत्यक्ष उत्तेजना देने वाला भाषण बताते हुए कहा कि वह "रिजवी के अनेक उत्तेजनात्मक भाषणो मे से एक" है। कल इसकी पुष्टि मे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा अन्य पत्रो ने रिजवी के इसी प्रकार के अन्य भाषणो के उद्धरण प्रकाशित किये, जो बहुत सावधानी के साथ सकलित किये गए थे। इनमे से कुछ

मैने पहले नही देखे थे। किन्तु बताया गया था कि यह सब सितम्बर के बाद के है। अब, असोशियेटेड प्रस के एक प्रामाणिक समाचार के अनुसार रिजवी ने एक और जवानी हिसा कर डाली थी, जो उससे भी बेहूदा थी और जिसकी मैं छानबीन कर रहा हू। कहा जाता है कि उसन मद्रास मे मिलाये गए प्रदेश को वापिस मागने का साहस किया और मुगल सम्राट् के समान दभ से कहा, "वह दिन दूर नही जब बगाल की खाडी की लहरे हमारे शहशाह के कदमो को चूमेगी।"

नई दिल्ली, शुक्रवार, १६ अप्रैल १९४८

मीर लायकअली और रिजवी ने सफाई मे यह कहा था कि ३१ मार्च को न कोई रैली हुई थी और न कोई 'हैदराबाद शस्त्र दिवस' कि जिसमे उक्त भाषण दिया बताया जाता है। लेकिन यह सही नही था। 'टाइम्स' के दिल्ली स्थित सवाददाता एरिक ब्रिटर वहा मौजूद थे। जहा तक उनकी जानकारी थी, उतने तथ्यो का मैंने पता लगा लिया था। उनका कहना था कि ३१ मार्च को ८ और १० बजे के बीच सवेरे हुई परेड मे वह उपस्थित थे। लगभग चार-पाच हजार रजाकारो द्वारा उन्होने रिजवी को सलामी दिये जाते देखा। लेकिन उनकी उपस्थिति मे कोई भाषण नही दिया गया। उन्होने परेड समाप्त होते देखी और उसके बाद बीस मिनट तक वहा खडे रहे। उसके बाद वे बरामदे वाले एक मकान मे लोट आये, जहा बीस-तीस और लोग भी मौजूद थे। चाय और केक के दौर चल रहे थे और मामूली चीजो के बारे मे चर्चा हो रही थी। ब्रिटर का कहना था कि रिजवी उन्हे विदा करने दरवाजे तक साथ आया था। लेकिन वह यह कहने की स्थिति मे नही कि बाद मे रिजवी ने कोई सभा की या नही। इस प्रकार, रहस्य का पर्दा फाश नही हो सका।

दूसरे जरियो से मैने जो जानकारी एकत्रित की थी, उससे लगता था कि रिजवी की आम और खानगी सभाओ मे मुशी और निजाम दोनो के ही खफिया नियमित रूप से मौजूद रहते थे। मेरा विश्वास है कि रिजवी एक ऐसे राजनैतिक आन्दोलन मे व्यस्त था, जिसकी सफलता का अर्थ हो सकता था रक्तपात कि जिसे वह निरन्तर उकसाया करता था, और भारत तथा हैदराबाद के बीच हमेशा के लिए सबध-विच्छेद।

इस समय माउन्टबेटन इस खतरनाक गतिरोध को भग करने का रास्ता निकालने के लिए बैठको मे लग हुए है। माकटन बुधवार को यहा आ गए थे और मीर लायकअली कल। आज सरकारी भवन के शात-सरोवर के एकाकीपन मे मीर लायकअली ने माउन्टबेटन के साथ दोपहर का भोजन किया। वह कुल मिलाकर दो घटे साथ रहे और माउन्टबेटन का अनुमान था कि मीर लायकअली के अडियल व्यक्तित्व और पेचीदा दृष्टिकोण पर उनकी बात का थोडा-थोडा असर हो चला है।

लेकिन,माउन्टबेटन का यह विश्वास अब भी दृढ था कि आगे आने वाले कठिन दिनो के लिए वह उपयुक्त प्रधान-मत्री नही थे। अगर उनका अडियलपन यो ही चलता रहा तो बातचीत हमेशा के लिए टूट जायगी।

यह सभवत निर्णायक क्षण था। पटेल का स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया था और अब वह सरकारी वार्ताओ मे हिस्सा ले सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि निजाम को छोडकर बाकी सब मुख्य पात्र बातचीत मे भाग ले रहे थे। माउन्टबेटन उसमे एक व्यक्ति "सद्भावना आयोग" के रूप मे भाग ले रहे थे।

नई दिल्ली, शनिवार, १७ अप्रैल १९४८

तीन दिन की सरगर्म वार्त्ताओ के बाद एक चार-सूत्री कार्यक्रम का सिद्धात स्वीकार हो गया। इसके लिए माउन्टबेटन मीरलायकअली के साथ औपचारिक बैठक मे सर्वसम्मत नीति पर चलने के लिए रोज सवेरे नेहरू, वी पी मेनन और माकटन से चर्चा कर लेते थे। वी पी उसे लेकर पटेल के पास मसूरी गये थे, जहा पटेल स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। माउन्टबेटन की खुशी और अचरज का ठिकाना न रहा कि पटेल ने पूर्ण सघ विलय के अलावा किसी योजना को ठुकराने का अपना आग्रह छोड दिया था और योजना को अपना अमूल्य समर्थन दे दिया था।

निजाम की स्वीकृति के लिए ये चार सूत्र तय हुए थे —

१ रिजवी पर नियत्रण करने के लिए अविलब कार्रवाई, जिसका आरम्भ रजाकारो के जलूमो, सार्वजनिक प्रदर्शनो, सभाओ तथा भाषणो पर प्रतिबध लगा कर किया जाय।

२ राज्य के काग्रेस-जनो की रिहाई, जिसका आरम्भ नेताओ को अविलम्ब रिहा करके किया जाय।

३ वर्त्तमान सरकार का सच्चा और अविलम्ब पुनर्निर्माण, जिससे वह दोनो सम्प्रदायो की प्रतिनिधि हो सके।

४ उत्तरदायी शासन की शीघ्र स्थापना और वर्ष के अन्त तक सविधान-सभा का निर्माण।

माकटन ने माउन्टबेटन से कहा कि वह निजाम को सलाह देगे कि वह अपने प्रधानमत्री को बदलकर इन सूत्रो की पुष्टि करे। वह महसूस करते थे कि मीर लायकअली पर यहा किसी को रत्ती भर भी विश्वास नही रह गया। किसी और चीज से निजाम के इरादो के बारे मे इतना विश्वास पैदा नही होगा, जितना हैदराबाद के दिल्ली-स्थित एजेंट-जनरल, जैन यार जग के समान योग्यता और सभ्यता वाले व्यक्ति की इस पर पद नियुक्ति से। निजाम के प्रति उनकी निष्ठा सदेह से परे थी और सदेह से परे था उनका दृढ यथार्थवाद। उन्होने भारत सरकार, खासकर वी पी मेनन, पर गहरी छाप छोडी थी।

: २५ :

गतिरोध

नई दिल्ली, शनिवार, २४ अप्रैल १९४८

माकटन १९ को लन्दन के लिए रवाना हो गए। कराची से एक पत्र लिखकर उन्होने निजाम के साथ हुई अपनी बातचीत की सूचना माउन्टबेटन को दी। उन्होने चेतावनी दी थी कि दिल्ली मे जिन चार सूत्रो पर समझौता हुआ था, उसमे से सबमे कष्टकर और समस्या को सुलझाने के मार्ग मे आडे आने वाला सूत्र वह होगा, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए शासन-यत्र की रचना से सबध रखता था। सामान्य आबादी के आधार पर निर्मित विधान सभा, जिसमे एक सप्ताह के अन्दर हिन्दुओ का भारी बहुमत हो जायगा, निजाम के गले नही उतरेगी। लेकिन माकटन ने यह आग्रह अवश्य किया था कि निजाम अपनी सरकार का पुर्ननिर्माण करे, जिसमे वह सब सम्प्रदायो की प्रतिनिधि सरकार का रूप ले सके। निजाम चाहते थे कि माकटन रुके। लेकिन उन्होने यह कहकर रुकने से इकार कर दिया कि नई सरकार की स्थापना न होने की स्थिति मे उनका वहा रुके रहना उनके स्वाभिमान के अनुकूल नही था।

आशा यह की जाती थी कि अपने फरमान के द्वारा निजाम चार-सूत्री योजना को अमली रूप दे देगे। सदा की तरह कल फरमान जारी हुआ था, और हमेशा की तरह सारी उम्मीदो पर पानी फिर गया। चार सूत्रो को स्वीकार करके प्रदत्त व्यावहारिक रियायतो से पैदा होने वाले मनोवैज्ञानिक लाभ को एक ही वाक्य मे साफ कर दिया गया। फरमान मे पहले यह आशा प्रगट की गई कि "वे राजनैतिक दल,जो हैदराबाद के वर्त्तमान अन्तरिम शासन मे शामिल नही है,शीघ्र ही उसमे हाथ बटायेगे और सरकार का भार सभाल लेगे।" फिर फरमान ने अन्तिम वचन के रूप मे कहा, "मुझे डर है कि किसी और जगह की सरकार की नकल मात्र करने से हमारे देश का वातावरण कही अधिक विषाक्त न हो जाय, जैसा कि अन्य स्थानो पर हो रहा है।" छोटी-सी विजय प्राप्त करने को इतना भारी मूल्य चुकाने के लिए तत्पर होना, निश्चय ही चकित करने वाली बात थी।

नई दिल्ली, शुक्रवार, ३० अप्रैल १९४८

हैदराबाद के प्रश्न पर तनातनी बढती जा रही थी। सीमावर्ती घटनाओ मे वृद्धि हो रही थी, जिससे गरम दिमाग और भी गरम हो रहे थे। नेहरू ने अखिल

भारतीय काग्रेस कमेटी के सामने गत शनिवार को बबई मे एक भाषण दिया था। इस भाषण मे उन्होने यह कहा बताया गया था "अब हैदराबाद के सामने दो ही रास्ते हैं—युद्ध या सघ-प्रवेश।" इससे राजनैतिक तापमान उबाल पर पहुच गया था।

माउन्टबेटन ने यात्रावास मे दूसरे दिन समाचारपत्रो मे यह शीर्षक पढा "सघ-प्रवेश या युद्ध।" पढकर वह स्तम्भित रह गए। दिल्ली लौटकर उन्होने तुरन्त नेहरू से सपर्क किया। नेहरू को भी कम विस्मय नही था। उन्होने बतलाया कि रिपोर्ट गलत छपी है, क्योकि उन्होने न तो युद्ध का कोई जिक्र किया था न सघ-प्रवेश का। गलती का कारण शायद यह रहा हो कि भाषण हिन्दी मे दिया गया था, जिसे लिखा था एक मद्रासी-भाषी स्टेनोग्राफर ने।

नेहरू कल प्रेस कान्फेंस मे इस गलती को सुधार देगे। लेकिन एक हफ्ता बीत चुका था और प्रचार का यह स्वय-सिद्ध सिद्धात है कि तुरन्त किये जाने वाले सुधार या खडन का भी, पहले छपी झूठी रिपोर्ट के असर का, दशाश से अधिक असर नही होता। उधर हैदराबाद मे मीर लायकअली ने हैदराबाद व्यवस्थापिका सभा के सामने एक लम्बा-चौडा भाषण दिया जिसमे चारो मे से एक-सूत्र का भी जिक्र नहीं किया गया था। इससे निजाम के फरमान मे निहित सद्भावना के प्रति दिल्ली का बचाखुचा विश्वास भी जाता रहा।

नई दिल्ली, मंगलवार, ४ मई १९४८

हैदराबाद के गतिरोध से माउन्टबेटन बहुत चिंतित थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक, दोनो कारणो से वह चाहते थे कि मामला जल्दी खुशी-खुशी निबट जाय। लगभग छ सप्ताह बाद वह गवर्नर-जनरल पदका भार राजाजी को सौपने वाले थे, और उनका अनुमान था कि यदि इस छोटे से अर्से का ठीक से उपयोग किया जाय तो दोनो पक्षो को अपने मतभेद दूर करने की प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन यह कहना कोई मामूली काम नही था कि माकटन की अनुपस्थिति मे कब और कैसे उनके प्रभाव का पूरा-पूरा फायदा उठाया जा सकेगा।

माउन्टबेटन ने सुझाव दिया कि अब निजाम को आखिरी चेतावनी का पत्र भेजा जाना चाहिए। इसका मजमून भी बडी तत्परता से तैयार किया जा रहा था। लेकिन मैने इसका विरोध किया। मैने आग्रह किया कि अन्य सब इलाज बेकार हो जाने पर ही यह रास्ता अपनाया जाना चाहिए। मेरा कहना था कि पत्र का यह मजमून मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है।

आज सवेरे दस बजे हुई बैठक मे, जिसमे वी पी मेनन, बरनोन और मै थे, माउन्टबेटन मेरे मत से सहमत हो गए।

इसके बाद रियासतो की स्थिति पर चर्चा छिड गई। राज्यो के विलीनीकरण

का जो काम उडीसा और बिहार राज्यो के साथ प्रारम्भ हुआ था, और जिसे पटेल की ओर से वी पी ने अत्यन्त तत्परता के साथ आगे बढाया था, अब ऐसे स्थान पर पहुच गया था कि आगे बढने की गुजाइश नही रह गई थी।

सबसे बडे राज्य-सघ के मसौदे पर २२ अप्रैल को हस्ताक्षर हुए। इसका नाम था मालव-सघ, जो ग्वालियर-इदौर-मालवा-क्षेत्र के बीस राज्यो से मिलकर बना था। इसका क्षेत्रफल सैतालिस हजार वर्गमील और जनसख्या सत्तर लाख से ऊपर है। राजप्रमुख (या सघ के वैधानिक अध्यक्ष) का नाम तय करने का काम बडा नाजुक था। यह पद ग्वालियर नरेश को मिलने वाला था, जिन्हे इक्कीस तोपो की सलामी मिलती है। राजधानी का प्रश्न और भी कठिन था। इस बारे मे यह समझौता हुआ कि ग्वालियर जाडो की राजधानी रहे और इदौर गर्मियो की। भोपाल ने मालव-सघ के बाहर बने रहने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन सरकार के साथ उन्होने दोस्ती कर ली थी और राज्य मे उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ करने की घोषणा की थी।

एक और किस्म का विलीनीकरण भी आज हो रहा था। कच्छ राज्य सीधा भारत सरकार मे मिलाया जा रहा था। यह कच्छ-राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए किया जा रहा था। विलीनीकरण का काम अलग-अलग स्वरूप धारण कर रहा था। दक्षिणी रियासतो और गुजरात के ठिकानेदार, जिनकी सख्या लगभग सौ है—अलग समझौतो द्वारा बबई प्रात मे विलीन हो गए थे। पूर्वी पजाब और मद्रास ने भी पडोसी राज्यो से ऐसे ही समझौते कर लिये थे। सबसे आत्म-निर्भर-सघ बना था सौराष्ट्र सघ, जिसमे काठियावाड के दो सौ सत्तर राज्य शामिल हुए थे। इसके राजप्रमुख नवानगर के जामसाहब थे जो बडे उत्साह से नई व्यवस्था मे शरीक हुए थे। आशा है कि वह केन्द्रीय राजनीति मे महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेगे। इन सघो का शासन लोकप्रिय सरकार चलाएगी।

प्रारम्भ छोटे राज्यो के विलीनीकरण से हुआ। फिर, उदयपुर द्वारा उसमे शामिल होने का निश्चय कर लेने पर उसने ज्यादा ठोस रूप ग्रहण कर लिया। जब माउन्टबेटन उदयपुर गये थे, तब महाराणा ने उनसे कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी जनता के हितो को ध्यान मे रखते हुए किया था। उदयपुर का राजवश भारत के सबमे सम्मानित राजकुलो मे से है और संघ मे उनके शामिल होने का राजपूताने के अन्य बडे राज्यो पर अच्छा प्रभाव पडेगा। यह अन्य बडे राज्य आत्मनिर्भर है और केन्द्रीय विधान परिषद् मे उनके अपने-अपने प्रतिनिधि हैं। इस अधिकार का उपयोग करनेवाली उन्नीस रियासतो मे से सात रियासते किसी-न-किसी सघ मे शामिल हो गई थी।

सफल कूटनीति यही थी कि क्रातिकारी परिवर्तनो को भी परम्परागत परिपाटियो का जामा पहने रहने दिया जाय। वी पी मेनन ने आज कहा कि बाप के पापो का फल बेटो के सिर पडा है। पटियाला और बीकानेर के भूतपूर्व नरेशो ने १९३५ की सघीय-योजना (फेडरल प्लान) को अस्वीकार कर दिया था, जिससे पूरे भारत के ढाचे को भारी धक्का लगा था। ऐन मौके पर माउन्टबेटन द्वारा सघ-प्रवेश की योजना हाथ मे लेने से स्थिति काबू मे आ गई थी और वर्तमान पटियाला तथा बीकानेर नरेशो को नये सबध दृढ करने का अवसर मिल गया था।

माउन्टबेटन ने खुले रूप से स्वीकार किया कि गत वर्ष जब उन्होने सघ-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम हाथ मे लिया था, तब उन्हे कल्पना तक नही थी कि उन विषयो मे वृद्धि की माग इतनी जल्दी की जायगी या उसे स्वीकार कर लिया जायगा। इस सिलसिले मे उन्होने नाइ की राय का उल्लेख किया। नाइ का कहना था कि रियासती समस्या की गभीरता भारत के बाहर बिल्कुल नही समझी गई। वास्तव मे काग्रेस, मुसलिम लीग अथवा सिखो से निबटने की अपेक्षा यह कही गभीर विषय था। नाइ ने कहा कि राजाओ से किसी प्रकार के मैत्रीपूर्ण समझौते की उम्मीद ही उन्होने छोड दी थी। पन्द्रह अगस्त के बाद उन्हे भारी पैमाने पर गभीर उपद्रवो की आशका थी। मई १९४८ तक जो प्रगति हुई, उस तक पहुचने मे अगर एक पीढी का समय भी लग जाता तो उन्हे कोई अचरज न होता। उनका मत था कि इस सफलता को इतिहास मे अभूतपूर्व माना जायगा।

सारी फिजा ही कितनी बदल गई थी। इसका आभास धौलपुर नरेश द्वारा नई योजना मे सम्मिलित होने से मिलता था। गत वर्ष उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि एकीकरण से अधिक किसी प्रकार का विलय उन्हे सर्वथा अस्वीकार होता। आज वह यहा मौजूद थे—मत्स्य राज्यसघ के राजप्रमुख के रूप मे।

नई दिल्ली, सोमवार, १० मई १९४८

मुझे और वरनोन को लगता है कि हमे निजाम की स्थिति के बारे मे पर्याप्त ज्ञान नही है। ऐसी हालत मे हम माउन्टबेटन को किसी उचित कार्यवाही की सलाह नही दे पायगे। दोनो पक्षो के बीच जो अन्तिम पत्र-व्यवहार हुआ है उससे एक नया गतिरोध उत्पन्न हो गया है। दिल्ली न आने के बारे मे निजाम ने जो दुराग्रह किया है, उसके कारण अब यह आशा बिलकुल ही नही रही, कि भारत सरकार माउन्टबेटन को हैदराबाद जाने की सम्मति देगी।

हम महसूस करते है कि यदि माउन्टबेटन के किसी सहायक कर्मचारी को 'राजा' का दूत बनाकर निजाम के पास भेजा जाय तो कुछ व्यक्तिगत सपर्क तथा विश्वास स्थापित हो सकेगा और वर्त्तमान भयानक गतिरोध को मिटाने मे सहायता मिलेगी, हमने माउन्टबेटन से यह बात कही। उन्होने इसे बहुत पसन्द किया और मुझे ही 'राजा के दूत' का काम करने का आदेश दिया। वह नेहरू, वी पी मेनन और जर्डन से इस विषय मे बात करेगे।

नई दिल्ली, बुधवार, १२ मई १९४८

सब ने स्वीकार कर लिया है कि मै शीघ्र निजाम से मिलने के लिए हैदराबाद जाऊ। व्यक्तिगत रूप से स्थिति का अध्ययन करने के साथ-साथ निजाम तथा उनके सलाहकारो को माउन्टबेटन के बचे हुए थोडे से कार्यकाल का सर्वोत्तम उपयोग करने और पुन वार्त्ताए आरम्भ करने के लिए समझाऊ। मुझे यह भी समझाना है कि कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक की जानी चाहिए। आज सवेरे कर्मचारी मडल की बैठक मे वी पी मेनन उपस्थित थे। उन्होने बताया कि इस बात के काफी प्रमाण मिल गए है कि अब कम्युनिस्टो तथा रजाकारो ने आपस मे गठबन्धन कर लिया है। परन्तु अब तक इस पहलू पर पर्याप्त जोर नही दिया जा रहा था। माउन्टबेटन को इस गठबधन पर विश्वास नही होता। किन्तु मेनन को इस पर दृढ विश्वास है और वह इसे परिस्थिति का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू मानते है।

माउन्टबेटन ने बैठक का आरम्भ पटेल के स्वास्थ्य के बारे मे पूछ-ताछ से किया। वी पी मेनन ने बताया कि उनकी नाडी अनियमित है और यह अनियमितता बढती जाती है। इससे चिन्ता उत्पन्न हो रही है।

नई दिल्ली, गुरुवार, १३ मई १९४८

कल माउन्टबेटन ने मेरी उपस्थिति मे नेहरू से पुष्टि करवा दी कि वह चाहते है कि मै हैदराबाद जाऊ। यदि निजाम सघप्रवेश के लिए राजी हो गए तो वह उन्हे पूर्ण वैयक्तिक सरक्षण देगे। मेरे काम के बारे मे मुझे आदेश दिये जाते समय यह

सभावना भी नजरन्दाज नही की गई कि शायद निजाम अपने घर के मालिक नहीं रहे है और किसी प्रकार की गुप्त राजमहली क्रान्ति या तो हो गई हैं या होने वाली है।

सुरक्षा-समिति की बैठक के बाद मै फिर नेहरू से मिला और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने उनके साथ हो लिया। उन्होने कहा कि मेरी यात्रा के बारे मे वह कुछ खास बात कहना चाहते है। उनका मत है कि सकट को टालने की कोशिश करना अक्सर उसे निमन्त्रण देने का सबसे पक्का ढग होता है।

हैदराबाद की सीमा पर प्रतिदिन जो गडबडी और गोलाबारी होती रहती है उसको चुपचाप देखते रहना सभव नही है।

जब मै लौटा उस समय भी मेनन माउन्टबेटन के साथ बाते कर रहे थे। वह सुरक्षा-समिति के कार्य से सतुष्ट दिखलाई पडे। उससे सैनिक तथा अ-सैनिक अधिकारियो को एक-दूसरे को अधिक निकट से जानने का अवसर मिला था।

माउन्टबेटन मेरी यात्रा के बारे मे बडे आशावान है। तय हुआ कि मै हैदराबाद सरकार की व्यवस्था के अन्तर्गत यात्रा करू। ५ बजे मै जईन और उनके पुत्र अलीखा से मिलने हैदराबाद भवन गया। जईन ने कहा "यदि भारत सरकार ने बहुत अधिक दबाव न डाला तो सारी बात हल हो जायगी।"

नई दिल्ली, शुक्रवार, १४ मई १९४८

मैने फिर जईन के साथ बातचीत की। मै मीर लायकअली का अतिथि रहूँगा। मेरी यात्रा की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई। यह मुझे मौके पर तय करने की आजादी है। मेरे हैदराबाद छोडने के पहले जईन भी वहा पहुच जाने की आशा करते है।

मै जो पत्र ले जा रहा हू उसमे निजाम के उत्तर पर निराशा व्यक्त की गई है और बताया गया है कि कार्यभार बहुत होने और कार्यकाल के बहुत थोडा रह जाने के कारण माउन्टबेटन का हैदराबाद आना सभव नही। तथापि माउन्टबेटन ने लिखा है "मै बहुत उत्सुक हू कि भारत छोडने के पहले आपके साथ कुछ व्यक्तिगत सबध स्थापित कर सकू।" बाद मे, मुझे अपने सहायक मण्डल का सबसे पुराना सदस्य बताकर उन्होने कहा है, "यह मेरे विचारो को भलीभाति जानते है और इन पर मेरा पूरा विश्वास है।"

अन्त मे उन्होने कहा है, "हैदराबाद से कम्युनिस्ट और साम्प्रदायिक स्थिति के जो समाचार आ रहे हैं, उन्होने मुझे बेचैन कर दिया है। उनका आपकी स्थिति पर जो असर हो रहा है वह विशेषरूप से चिन्ताजनक है। अतएव, मुझे विश्वास है कि आप श्री कैम्पबेल जान्सन को सामान्य तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से स्थिति

का स्पष्ट परिचय कराने मे सकोच न करेगे। मैं चाहता हू कि मेरा सदेश अकेले मे ही आपको दिया जाय, आपके सिवा किसी दूसरे को नही। मुझे आशा है कि श्री कैम्पबैल जान्सन आपके साथ मेरा व्यक्तिगत सपर्क स्थापित कर सकेगे। दूसरो की उपस्थिति से यह सबध दूषित हो सकता है।"

सो कल मै रवाना हो जाऊगा। केवल एक बात निश्चित है कि आगामी ४८ घटो मे मुझे माउन्टबेटन तथा भारत सरकार के सपर्क मे कटा रहना पडेगा। माउन्टबेटन के साथ छ वर्ष की सेवा मे मुझे सबसे कठिन काम यही मिला है। फिर भी मै उनके पास काफी समय तक रह चुका हू और उनकी स्फूर्त्ति का कुछ अश तो मुझे भी मिल गया है।

: २६ :

निजाम से भेंट

हैदराबाद, शनिवार, १५ मई १९४८

मे नाश्ते के बाद विलिगडन हवाई अड्डे से रवाना होकर, भोपाल मे थोडा ठहरता हुआ, भोजन के पहले हैदराबाद पहुच गया। हवाई अड्डे पर मीर लायक अली की ओर से कैप्टेन बेग और मुशी की ओर से कम-से-कम तीन व्यक्ति मेरा स्वागत करने के लिए आये थे। तीन मिनट के अन्दर ही मुझे अपना कूटनीतिक कार्य प्रारम्भ कर देना पडा, क्योकि मुशी के प्रतिनिधियो ने मुझे उनका आग्रह भरा न्योता दिया कि मै पहले उनसे मिलू और उनके साथ ही खाना भी खाऊ। मुझे उत्तर देना पडा कि मै लायकअली का अतिथि हू और उनकी योजना को जाने बिना कोई कार्यक्रम नही बना सकता। फिर भी मै मुशी से मिलूंगा अवश्य।

मुशी मेरे आने का समाचार पाकर विशेष रूप से बगलोर से आ गए थे। मेरी जो यात्रा गुप्त रूप से होनी थी उसपर अब प्रचड प्रकाश पड गया था, क्योकि मुशी ने मेरे आने और अपनी वापसी की सूचना सम्वाददाताओ को दे दी थी।

इससे निबटने के बाद हमने सिकन्दराबाद और हैदराबाद नगरो को पार करते हुए १० मील का मार्ग तय किया। मार्ग मे बहुत लोग दिखलाई नही पडे। जो दिखलाई पडे वे आराम से चलते-फिरते अपने कामो मे लगे हुए थे।

प्रधान मत्री के निवासस्थान 'शाहमजिल' मे पहुचते ही मुझे एकदम मीर लायक-अली के पास पहुचाया गया। वह कुछ बीमार थे। उन्होने कहा कि मैने आपके

लिए भोजन की विशेष व्यवस्था नही की है इसलिए मुशी का आमत्रण स्वीकार कर लेना उचित होगा। उन्होने यह इस खयाल से भी कहा कि मुशी कल वापस बगलोर जाने वाले है। उन्होने कहा कि वह सब विचारो के नेताओ के साथ मेरी भेट कराने का प्रबध कर रहे हैं। मुझे इच्छानुसार घूमने-फिरने और जहा चाहू वहा जाने की स्वतन्त्रता है। उन्होने मुख्य बात यह कही कि आर्थिक नाकेबदी मे अब भी ढील नही की गई है, जिससे हमे पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन नही मिल रहा है। उन्होने कुछ बसे मगाई है, जो बबई मे जग खा रही थी। मैने कहा कि निश्चय ही इन शिकायतो को अधिक व्यापक समझौते के द्वारा दूर किया जा सकता है।

देर से भोजन करने के बाद मुझे बताया गया कि निजाम ५ बजे मुझसे मिलेगे। मुझे समय पर उनके निवास-स्थान "किग कोठी" पहुचा दिया गया। प्रधान मत्री कोई १० मिनट पहले ही वहा पहुच चुके थे। मुझे मामूली सजावट वाले एक कमरे मे ले जाया गया। धुधले प्रकाश मे मैने देखा कि कमरा विक्टोरिया के काल की साज-सज्जा से सुशोभित था और एक ओर पचमजार्ज का चित्र टगा हुआ था।

मीर लायकअली ने आगे बढकर निजाम से, जो एक कुर्सी पर अदृश्यप्राय बैठे थे, मेरा परिचय कराया। एक क्षण के लिये मै चकित रह गया। किन्तु बाद मे शीघ्र ही मैने अपनी सुध-बुध बटोरकर यथोचित शिष्टता के साथ उनका अभिवादन किया। वह निहायत भद्दे कपडे पहने हुए थे—एक सफेद सूती शेरवानी और सफेद पाजामा, परो मे भूरी स्लीपरे थी और हलके भूरे मौजे टखने पर बेतरतीब फैले हुए थे। सिर पर बादामी रग की तुर्की टोपी थी जो सिर के पिछले भाग पर रखी हुई थी। उनकी कमर झुकी हुई थी और दातो का खराब हाल था। उनके हाथ काप रहे थे और बात करते समय उनके घुटने इस बुरी तरह आपस मे टकरा रहे थे मानो वे मृगीरोग से पीडित हो। उनके व्यक्तित्व का सबमे सबल अग है उनकी अभिव्यक्ति का पैनापन और स्वर की कर्कशता।

मै निश्चय नही कर सका कि मीर लायकअली बैठे रहेगे, या चले जायगे, परन्तु जब मैने निजाम को माउन्टबेटन का पत्र दिया, और वह उसे धीरे-धीरे पढने लगे, उस समय वह चाहते तो मुझसे एकात मे बाते कर सकते थे। परन्तु उन्होने इस मौके को नही अपनाया। मीर लायकअली वही डटे रहे। पत्र पढने के बाद निजाम बडे भयानक ढग से मेरी ओर मुडे। उन्होने कहा कि मै लार्ड माउन्टबेटन के सीमित समय तथा अधिकारो को खूब जानता हू। "वह एक महीने मे क्या कर सकते हैं?" उन्होने कहा, "मुझे विश्वास है कि लार्ड माउन्टबेटन अच्छी तरह समझते हैं कि मेरा हैदराबाद छोडना बिल्कुल असभव है। यदि लार्ड माउण्टबेटन को यहा आने और मुझसे मिलने की फुरसत नही है, तो फिर (उन्होने विदाई का इशारा किया) मुझे अफसोस है। उन्हे मेरा सलाम है, और खुदा हाफिज!"

निजाम ने कहा, जहा तक भारत सरकार के साथ हमारे सबधो का प्रश्न है,

मीर लायकअली ने बातचीत को राष्ट्रमडल के प्रश्न पर टाल दिया। निज़ाम जानना चाहते थे कि भारत के राष्ट्रमडल मे बने रहने की क्या सभावना है। मैने बताया कि इस प्रश्न पर बहुत जोरो से विचार हो रहा है और बहुत-से प्रभावशाली लोग भारत के राष्ट्रमडल मे बने रहने के समर्थक हैं। मैंने यह भी कहा कि मै एक बात कहना चाहता हू जिसका वाइसराय के कर्मचारी मडल का सदस्य होने से कोई सबध नही है। वह यह कि भारत राष्ट्र-मडल मे रहे या न रहे, वर्तमान ब्रिटिश लोकमत केवल इसी आधार पर भारत के एक भाग के साथ अधिक अनुकूल और दूसरे भाग के साथ कम अनुकूल व्यवहार का समर्थन नही करेगा। यदि इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जायगा तो वह भ्रामक होगा। मेरा खयाल है कि मेरी इस बात का असर हुआ।

इसके बाद विश्व की सकटापन्न स्थिति पर कुछ बाते हुई। अन्त मे निजाम ने माउन्टबेटन के प्रति शुभकामनाए व्यक्त की और बातचीत समाप्त हो गई।

निजाम के प्रतिकूल रुख के कारण एक घटे की यह भेट सरल तो नही रही, किन्तु उससे उनके व्यक्तित्व और मानस के अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। निजाम का शरीर भले ही बूढा गया हो, उनका मस्तिष्क सतर्क है और अपनी बुद्धि पर उनका पूर्ण नियत्रण है। मुझ पर यह छाप पडी, मानो मुझसे किसी वृद्ध, सनकी प्रोफेसर ने अपने विशेष विषय पर बातचीत की हो। निजाम पुराने ढग के राजा हैं—अहकारी और सकुचित विचारो के, परन्तु अपने निजी क्षेत्र मे अजेय। सारी बातचीत मे उनका रुख घोर भाग्यवादी था।

मुझे कोई चिह्न दिखलाई नही पडा कि निजाम बदी है। कोठी के सामने भारी सख्या मे पुलिस तैनात है, किन्तु निजाम की हत्या का जो प्रयत्न किया गया था, उसे दृष्टि मे रखते हुए उसमे कोई असाधारण बात दिखलाई नही पडती। राजमहल मुख्य-मार्ग से बहुत दूर भी नही है, दिल्ली के साधारण मकान भी सडक से उतनी ही दूरी पर है। मेरे विदा लेने के बाद मीर लायकअली वही ठहरे रहे।

मीर लायकअली के मकान मे मोइन मुझसे मिलने आये। स्पष्ट था कि वह जानना चाहते थे कि निजाम की बातो पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है। मैने केवल इतना कहा कि बातचीत सामान्य ढग की थी और उससे कोई प्रोत्साहन प्राप्त नही हुआ।

हमने सधि या सघ-प्रवेश पर बाते की। उन्होने कहा कि हमे भय है कि तीन विषयो मे सघ-प्रवेश बाद को तीस विषयो मे सघ-प्रवेश बना दिया जायगा। उसमे कानूनो की मान्यता स्थापित करने तथा आतरिक स्वतन्त्रता खोने का भी प्रश्न उठेगा, जिसे निजाम कभी स्वीकार न करेगे।

इसके बाद मै मुशी के साथ भोजन करने के लिए चला गया। वहा पहुचने मे तेज मोटर पर मुझे लगभग ४० मिनट लगे। उनका निवासस्थान सिकदराबाद के एक छोर पर हवाई अड्डे के समीप है। मुशी यहा रहते हुए नगर के जीवन से

बिलकुल पृथक् है और उनकी भेट केवल उन लोगो से हो सकती है, जिनके पास समय और पेट्रोल है या जिन्हे उनसे मिलने की राजनैतिक आवश्यकता है।

मैने उन्हे कुछ खिन्न और परेशान पाया ; उन्होने कहा कि लायकअली ने उनके साथ हुई भेट की एक बिलकुल झूठी रिपोर्ट दी है, जिसके कारण उन पर से उनका विश्वास बिलकुल उठ गया है। उन्होने यह भी बताया कि मोइन और लायकअली के बीच की स्थिति बडी अस्पष्ट है। यद्यपि वे दोनो साले-बहनोई है पर उन दोनो मे मतभेद है। जहा तक निजाम पर प्रभाव का प्रश्न है, लायकअली का तारा इस समय बुलन्द है।

मुशी ने कहा कि निजाम उत्तरदायी शासन या 'सघ-प्रवेश' के सबध मे कोई ठोस कार्रवाई नही करना चाहते। परन्तु वह मेरे इस विचार से सहमत है कि राजनैतिक स्थिति की बागडोर निजाम के ही हाथो मे है।

मैने उन्हे विश्वास दिलाया कि मेरी यात्रा व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक है और मैं प्रधान मत्री तथा वी पी मेनन की पूर्ण सहमति से आया हू।

वह कल बगलोर वापस जाने के बारे मे बिलकुल प्रसन्न दिखलाई पडे। उन्होने कहा कि उनकी पत्नी अब यहा रहना पसन्द नही करती और सरकार के साथ उनका सबध इतना बिगड गया है कि कोई सपर्क ही बाकी नही रह गया।

हैदराबाद, रविवार, १६ मई १९४८

दिन भर काम मे बहुत व्यस्त रहा। बातचीत से जरा भी फुरसत न मिली। मैने मीर लायकअली से कहा कि मै कासिम रिजवी से खानगी तौर पर मिलना पसन्द करूगा बशर्ते कि इस भेट के बारे मे कोई प्रचार न हो और यह समझ लिया जाय कि मै केवल उन्ही लोगो से मिल रहा हू जिनसे आप मुझे विशेष रूप से मिलाना चाहते है। उन्होने उत्तर दिया कि वह निश्चित रूप से चाहते है कि मै रिजवी से मिलूं। उन्होने कहा कि रिजवी मेरे दौरे पर रवाना होने के पूर्व मुझ से भेट करने आयगा। उन्होने मुझे सलाह दी कि उसी वक्त मै भी बातचीत मे शामिल हो जाऊ।

मैने ऐसा ही किया। कुछ मिनटो की मामूली बातचीत के बाद प्रधान मत्री मुझको रिजवी के साथ छोड कर चले गए। बातचीत की शुरुआत मैने इस प्रकार की घटनाए जिस प्रकार करवट ले रही है उससे मुझे मायूसी हो रही है। उसने खट से उत्तर दिया कि वह तो जरा भी मायूस नही है। अगर है तो उन्मादपूर्ण। उसने मुझसे कहा कि मै यह अच्छी तरह समझ लू कि उसका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानो की रक्षा है और उसकी भारी वफादारी उन्ही के प्रति है। मैने उससे पूछा कि क्या इस समाचार मे कोई सचाई है कि कम्युनिस्ट रजाकारो से कह रहे है कि दोनो को

मिलकर सम्मिलित कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर रिजवी ने बहुत गरम हो कर जवाब दिया, "जब आप रजाकारो का जिक्र करते है तो उसका मतलब मुझसे है। मै आपको बता दूं कि यहा मुसलमाननो की हालत ऐसी है कि वे खुदबखुद बडी तेजी से कम्युनिस्ट बन रहे हैं। मैने उन्हे (रिजवी ने ठीक निर्देश नही किया कि उनसे उसका क्या अभिप्राय था) चेतावनी दे दी है कि ऐसा होना संभव है।"

फिर उसने दृढतापूर्वक कहा कि वह कम्युनिप्टो के साथ मिलकर काम करने को बिलकुल तैयार है और इस दशा मे उसने प्रारम्भिक कार्यवाही भी कर ली है। इस बात को बिलकुल पक्का करने के लिए कि मैने उसके विचारो को गलत रूप मे नही समझा, मैने कहा कि मेरा खयाल है कि कम्युनिश्टो द्वारा स्वय निजाम को दी गई सीधी चुनौती रजाकारो के मार्ग मे एक बाधा सिद्ध होगी। चुनौती से मेरा मतलब कम्युनिस्टो की वह चेतावनी है, जिसमे उन्होन कहा है, "निजाम के साथ कोई वास्ता नही होगा।" मेरे इम कथन को सुनकर रिजवो एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला कि यह कठिनाई वह भी महसूस करता है। लेकिन बाद मे जब मैने फिर इस विषय की चर्चा की तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि मुसलमानो को हताश होने से बचाने के लिए कम्युनिस्ट ही एकमात्र साथी मिद्ध हुए तो सरकार तथा राजवश दोनों ही उसके लिए गौण वस्तुए बन जायगी। "यदि भारत हमे दो वर्ष तक चुपचाप स्वेच्छा से चलने दे तो मै वचन देता हू कि एक ऐमी चीज का निर्माण कर दूँगा जिससे सब ईर्ष्या करने लगेंगे। हिन्दू अभी से रजाकारो मे शामिल हो रहे है।" मैने पूछा कि क्या राजनैतिक समझौते के बिना दो वर्ष बाद फिर वैसा ही सकट उत्पन्न नही हो सकता? इसका उसने समर्थन किया लेकिन साथ ही अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि भारतीय सघ दो वर्ष से अधिक नही टिकेगा।

उसने कहा कि समस्या के शातिपूर्ण हल की उसे रत्ती भर भी उम्मीद नही। हिन्दुओ के प्रश्न पर चर्चा के समय उसकी बातो से स्पष्ट प्रकट हो गया कि उसका हृदय जातीय घृणा की भावना से सराबोर है। उसकी नजर मे गाधीजी की मृत्यु उनके व्यवहार का प्रतीक है। उसने कहा कि हिन्दू सदा अपने देवताओ को महादेव बनाने के लिए उनको मार डालते है। मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या उसे यह ध्यान नही है कि कम्युनिस्टो के वर्तमान सगठन मे हिन्दुओ की ही प्रधानता है। रिजवी ने उत्तर दिया कि यह बात सही है, लेकिन वे दूसरे दलो की अपेक्षा कम साम्प्रदायिकतावादी है।

मैने कहा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि रिजवी ही राज्य मे वास्तविक शक्तिसपन्न व्यक्ति है, इसके बारे मे उसकी क्या राय है? इस पर रिजवी ने उत्तर दिया, "आप मेरे बारे मे इस प्रकार की निन्दात्मक बातो मे विश्वास न करे कि मैं षड्यत्रकारी हूं और सरकारे गढा करता हू। मै तो एक अदना-सा शख्स हू। मैं

केवल मुसलमानो के हितो का रक्षक और उनका सेवक हू ओर उनके हितो की रक्षा मे कोई कसर मै उठा न रखूंगा। सरकार कभी-कभी मेरे विचार जानने के लिए मुझे बुलाती है और मै बिलकुल स्पष्ट रूप मे उन्हे व्यक्त कर देता हू।" उसने मुझ से कहा कि मुसलमानो को मौत से बचाने तथा मुसलमान स्त्रियो के सतीत्व की रक्षा करने के लिए वह अपनी जान न्योछावर करने को तैयार है। उसने कहा कि हैदराबाद के कांग्रेसी प्रतिनिधि मिट्टी के माधो है। फिर पहली बार मुसकराते हुए वह बोला, "हिन्दुओ की देख-रेख का भार मुझ पर छोड दीजिए।"

रिजवी पूरी तरह धर्मांध है। वह ऐसी आखो से घूरता है जो आप के चुभने लगती है। यदि उसके व्यक्तित्व पर बेहदापन ओर छल-कपट की तह नही होती तो उसकी नजर उसके दोस्तो ओर दुश्मनो के दिल दहला देती है। यही कारण है कि जब वह जोर-जोर से बकवास करता है तो उसकी कलई खुल जाती है और उसकी बातो को गम्भीर मानना कठिन हो जाता है। उसकी बकवास से यही लगता है कि उसकी नाटकीयता उसकी शक्ति से कही अधिक है। देखने मे वह ठिगना और मोटा है। उसकी दाढी की लम्बाई-चोडाई विशाल है और सिर पर तुर्की टोपी को वह ऐसे बाके ढग से पहनता है कि धूर्तता टपकती है। तेज कदमो से बाहर जाते समय वह चार्ली चैपलिन ओर किसी छोटे पैगबर का प्रतिरूप जान पडता था।

हैदराबाद, सोमवार, १७ मई, १९४८

आज रात को आठ बजे प्रधान मत्री से मेरी आखिरी बातचीत हुई। मैंने लायकअली से कहा कि मै यह निश्चित रूप मे जानना चाहता हू कि निजाम इसलिए तो दिल्ली जाने से नही डरते कि उन्हे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति कोई खतरा लगता है। लायकअली ने बताया कि हो सकता है कि ऐसी आशका निजाम के मन मे रही हो, लेकिन मुख्य ओर निर्णयात्मक कारण यह था कि यदि वह दिल्ली जाते तो रियासत मे इस बारे मे बडी गलतफहमी फैल जाती। मैने लायकअली को बताया कि ब्रिटेन के विरोधी दल के समर्थन पर यहा जो भरोसा किया जा रहा है उससे स्पष्ट ही मुझे चिन्ता है। मैने कहा कि यह भारी भ्रम साबित होगा। ब्रिटिश लोक सभा मे हैदराबाद अगर दलीय प्रश्न बन भी जायगा तो भी इससे रियासत की कोई भलाई नही होगी। लायकअली ने कहा कि वह मेरी इस बात से सहमत है। वह एटली के बडे प्रशसक है ओर नही चाहते कि हैदराबाद कही भी दलीय वाद-विवाद का विषय बने।

जब मैं जैन यारजग के पुत्र और खूबसूरत पुत्रवधू के साथ सुन्दर वातावरण मे भोजन कर चुका तो जैन ने खुद, जो उसी दिन दोपहर को आ गए थे, मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की और मैं रात के ११ बजे उनके मकान पर गया। उन्होंने

बताया कि वह निजाम से एकान्त मे मिले थे। निजाम फिर बहुत गर्म हो रहे थे। जईन ने कहा, 'लेकिन, वह तो हमेशा ऐसे ही रहते है।'' निजाम वैधानिक प्रभुसत्ता के प्रश्न पर टस-से-मस होने को तैयार नही है। किन्तु, जईन ने उन्हें बताया कि एक ऐसी नई सरकार बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है, जिसका आधार मौजूदा सरकार की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो। उन्होंने मुझे ऐसा आभास दिया कि निजाम और लायकअली आखिर ऐसा करने के लिए राजी हो गए हैं। निजाम ने, मेरे दौरे की चर्चा भी उठाई थी और यह कहा कि उन्होने बिना किसी हिचक के जो-कुछ भी उनके मन मे था, मुझसे कह दिया। निजाम को विश्वास है कि माउन्टबेटन के खुद आने की अब भी दस प्रतिशत सम्भावना है और जईन से पूछा कि उनका क्या खयाल है। जईन ने बताया कि यह बात कुछ हद तक इसपर निर्भर करती है कि मैं कैसी रिपोर्ट भेजता हू। तब निजाम ने मेरे बारे मे प्रश्न पूछने शुरू किये—मैं कौन हू, मेरी नीति क्या है, आदि।

जईन का खयाल है कि अगर वैधानिक प्रभुसत्ता की माग को मान लिया जाय तो समस्या का हल सम्भव है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि ऐसा होने पर फिर भारत सघ मे 'प्रवेश' शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। निजाम ने जईन से दो-एक दिन बाद कुछ और बातचीत करने के लिए कहा है और वह मगल व बुध को, जब निजाम से बातें करेंगे तो इसे स्वीकार कराने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि वह केवल तीन विषयो तक सीमित रहे। जईन ने बताया कि वह अल इद्रूस से, जो कि रजाकारो को फौजी सहायता देते बताये जाते है, साफ बात करने की सोच रहे है। यह चीज दिल्ली मे काफी ʻचैनी का कारण बनी हुई है।

हैदराबाद—नई दिल्ली, मंगलवार, १८ मई १९४८

दिल्ली लौटते ही मै सीधा वी पी मेनन से मिलने गया। अपने हैदराबाद के सिरदर्द के अलावा उनपर रियासतो के विलीनीकरण की नीति का भी पूरा-पूरा दायित्व है और वह काम के बोझ से बुरी तरह दबे हुए है। उनकी साफ राय है कि मरी यात्रा उपयोगी रही है। लेकिन वह हैदराबाद विधान सभा की प्रभुसत्ता के प्रश्न पर चर्चा करने को तैयार नही थे। मेरा अनुमान है कि मेरी गैर-मौजूदगी मे हैदराबाद की ओर उनका रुख कडा हो गया है। लेकिन मैंने उन्हें कल जईन के लौटने तक इस विषय मे कोई राय कायम न करने के लिए तो राजी कर ही लिया। वी पी ने आखिरी शर्तो की बात छेडी, लेकिन मै शारारिक और दिमागी थकावट की ऐसी सीमा पर पहुच चुका था कि मेरे लिए उनकी बात समझना मुश्किल हो रहा था।

: २६ :

विदाई के दिन

नई दिल्ली, गुरुवार २०, मई १९४८

कल सारी दुनिया से नाता तोड कर मैंने अपना सारा दिन रिपोर्ट पूरी करने की जी तोड कोशिश मे लगाया। मै चाहता हू कि मेरे शिमला पहुचने के एक दिन पूर्व ही यह रिपोर्ट माउन्टबेटन के हाथ मे पहुच जाय।

आज शाम मेरी नेहरू के साथ एक घटे तक वातचीत हुई। मैंने अपने नतीजों के बारे मे उनसे चर्चा की। उनका मत है कि शायद निजाम मुझे डराने के लिए जानबूझ कर नाराजी का अभिनय कर रहे थे। चूँकि वह किसी नये दल के साथ चर्चा करने से इन्कार कर रहे थे इसलिए उनका गोलमोल बातें करना समझा जा सकता है। वह इस बात मे मुझसे सहमत है कि रजाकारो के असली जन्मदाता दीनयारजंग मे रजाकारो के भग किये जाने की प्रतिक्रियाओ का सामना करने का बूता है।

प्रधान मत्री ने कहा कि हैदराबाद का इतिहास कभी गौरवपूर्ण नही रहा। उन्होंने हमेशा बल के आगे घुटने टेके है। मराठो के सामने उनका ढेर हो जाना इसका उदाहरण है।

नेहरू महसूस करते है कि निजाम अपनी दोलत और व्यक्तिगत अधिकारो के वारे मे सचमुच चितित हो सकते है। इनके विषय मे वह आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सघ-प्रवेश के द्वारा वह भारतीयविधान हैदराबाद पर लादना नही चाहते। अतिरिक्त विषयो पर अलग से समझौता किया जा सकता है। ओर न वह हैदराबाद की सेना को ही हडप कर जाना चाहते है।

निजाम के धार्मिक-विचारो की चर्चा करते हुए नेहरू ने कहा कि मेरे साथ बातचीत के दौरान मे उनका मोहर्रम की चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योकि यह उस घटना की यादगार है जब मुसलमान जाति शिया और सुन्नी फिरको मे बट गई थी। हैदराबादी मुसलमान सुन्नी है लेकिन निजाम के बारे मे अनुमान किया जाता है कि वह छिपे तौर से शिया है।

मैंने कहा मुझे आशा है कि मेरे हैदराबाद के दोरे को जो प्रकाशन मिला उससे वह अधिक परेशान नही हुए होगे और यह सफाई दी कि इसका मुख्य कारण मुशी के कर्मचारी-मडल का उत्साह था। मने अपनी तरफ से उसे नियत्रण मे रखने की पूरी कोशिश की थी। (मुझे पता चला था कि मत्रि-मंडल के एक-दो सदस्यो ने इस बारे मे कुछ आलोचना की थी, लेकिन नेहरू या पटेल ने कुछ नही कहा था

और वे इस बारे मे बिलकुल परेशान नही थे)। नेहरू ने आज फिर कहा कि उसकी कोई बात नही और मेरे दौरे के महत्त्व पर उसका कोई असर नही पडता।

नेहरू ने कहा कि निजाम का रुख उनकी समझ मे नही आता क्योकि वह नही समझते कि निजाम किसी प्रकार की वीरतापूर्ण भूमिका खेलने के लिए बने हैं।

कुछ देर तक यह अनिश्चित रहा कि जईन और मेनन आपस मे मिलेंगे या नही, लेकिन बाद मे जईन रात को ९ बजे मेनन के घर पहुचे और मैं भी कुछ देर बाद उनमे शामिल हो गया। सीमावर्त्ती तनाव को देखते हुए मेनन का यह दृढ मत है कि वर्तमान अनिश्चितता को चलते नही रहने दिया जा सकता। एक-दो प्रस्तावित कार्य-क्रमो पर विचार करने और उनके ठुकराए जाने के बाद बैठकों का एक पेचीदा सिलसिला तैयार किया गया, जिसके अनुसार मीर लायकअली २२ तारीख को दिल्ली बुलाये जायगे, नेहरू और मेनन पटेल से मिलने के लिए मसूरी जायगे और बातचीत के दौरान मे फैसले का मौका आने पर, कोई दृढ निश्चय करने से पहले, माउन्टबेटन को भी आमन्त्रित कर लिया जायगा।

बातचीत कुछ असम्बद्ध और अनावश्यक रूप से लम्बी होने पर भी स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण थी। सीमावर्त्ती काडो और सरदार के विचारो को मद्दे नजर रखते हुए स्थिति की गम्भीरता महसूस की गई। किसी भी मुख्य विचाराधीन विषय पर जईन ने निजाम के रुख का कोई सकेत नही मिलने दिया। लेकिन मेनन ने उन्हे आश्वासन दिया कि सघ-प्रवेश तीन विषयो तक ही सीमित रहेगा—अन्य विषय अलग चर्चा का विषय होगे। जैसे हैदराबाद की सेना का स्वरूप और निजाम के वैधानिक अधिकार। (अन्तिम मामला सबसे पेचीदा वैधानिक और राजनैतिक प्रश्न है, जिस पर हमे सावधानी से तयारी करनी होगी।) लायकअली की स्थिति और सरकार के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया गया। जईन ने कहा कि लायकअली के लिए यह कठिन होगा कि खुद छोडकर शेष सारे मन्त्रिमडल को भग कर दे और फिर उसकी रचना करे। लेकिन इस प्रश्न पर आगामी बैठक मे खुल कर चर्चा की जायगी।

इस सभावना पर भी विचार किया गया कि जईन स्वय सरकार मे शामिल हो। जईन ने कहा कि वह खुद प्रधान मन्त्री न होकर किसी दूसरे के मन्त्रिमडल मे कार्य करना अधिक पसद करेगे। लेकिन वह सहयोग देने को तैयार है बशर्ते की नियुक्ति सीधी निजाम की ओर से हो न कि भारत सरकार के दबाव के फलस्वरूप।

जईन यह महसूस करते है कि इन सब विषयो पर मेनन के प्रस्ताव पहले की अपेक्षा अब अधिक रुचिकर हैं। किन्तु जहा तक मै जानता हू भारत के दृष्टिकोण मे कोई बुनियादी परिवर्तन नही हुआ। फिर भी मेनन ने जईन के प्रति अपनी सराहना और समझौते की अपनी इच्छा को बडी भावुकता और हार्दिकता से व्यक्त किया है। इन दो व्यक्तियो के बीच मौजूद सद्भावना उत्साह बढाने वाली

है। स्थिति का अधिकाश दारोमदार अब मसूरी मे पटेल के साथ होने वाली मुलाकात पर और इस बात पर निर्भर करता है कि इस बैठक से मेनन को खुद फैसला करने की कितनी आजादी मिलती है। मेनन यह मुठभेड आसान नही समझते है।

वी पी. और जर्डन दोनो ने मेरी हैदराबाद-यात्रा को उपयोगी बतलाने की सहृदयता दिखाई।

नई दिल्ली, मंगलवार, २५ मई १९४८

शिमला मे छत्तीस घटे बिताने के बाद मै रविवार को सवेरे वरनोन के साथ वहा से चल पडा। यात्रा करते-करते मै ऊब गया हू। पिछले सप्ताह मैने जो दौड धूप की वह रचनात्मक और सम्बद्ध चिंतन को सीधी चुनौती थी। माउन्टबेटन के अगाऊ दस्ते के रूप मे हम दिल्ली के 'भाड' मे लौट आये है। पिछले चौबीस घंटे उन्होने पटियाला मे बिताये। उनके यहा पहुचने पर हम उन्हे यह बताने की स्थिति मे थे कि मीर लायकअली, जो रविवार को ही यहा आ गए थे बडी गलत भावना लेकर आये थे। वह वास्तविकता से इतनी दूर थे कि सकट अब टल गया है। इसलिए आज माउन्टबेटन ने लायकअली से बहुत माथापच्ची की। मेरे खयाल मे अपने मिशन के दौरान मे माउन्टबेटन ने जो विभिन्न लोगो से मुलाकाते की है, यह उन सबसे लबी थी और ५ घटे तक चली।

इस मुलाकात, और मेरे हैदराबाद दौरे, की पृष्ठभूमि यह थी कि सीमावर्ती मुठभेडो पर काबू पाने के लिए हैदराबाद की सीमा के पास भारतीय सेनाओ का काफी बडी सख्या मे जमाव हो गया है। अतिम और सबसे गभीर घटना गगापुर रेलगाडी की थी, जिसमे दो गैर-मुसलमान लापता और घायलो की सख्या भी काफी थी। इस घटना से भारतीय जनमत बहुत उत्तेजित हो उठा था। मेरे हैदराबाद जाने से दो दिन पहले सुरक्षा-समिति की एक बैठक मे यह निश्चय किया गया था कि फौजी तैयारिया अवश्य चलती रहनी चाहिए। लेकिन आक्रमण करने के लिए सेना को दस दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होगा। नेहरू से माउन्टबेटन को जो आश्वासन प्राप्त हुए थे उनसे उन्हे तसल्ली हो गई कि बहुत बडा सकट पैदा हुए बिना, जैसे हिन्दुओ का कत्लेआम, आक्रमण नही किया जायगा। वह अब निश्चित हो गए है कि उनके भारत छोडने से पहले या शायद उससे भी बाद तक, वर्षा के आरम्भ से पूर्व ऐसा कोई कदम नही उठाया जायगा।

इस तरह शातिपूर्वक समझौता कराने के लिए बहुत थोडा ही समय शेष रह गया था। अत बहुत सख्त कदम उठा कर लायकअली की आखे खोलनी थी कि खतरा कितना निकट है और उन्हे समझा देना था कि अब चालबाजी से काम लेना उनके और उनके राज्य के लिए भारी खतरा सिद्ध होगा। मैने माउन्टबेटन को शिमले मे बता दिया था कि मुझे तो मीर लायकअली का रुख 'बुद्धिमान मूर्ख'

के समान लगता है—सारे गलत काम करने के लिए वह सारे सही तर्क जुटा सकते हैं।

माउन्टबेटन ने बातचीत के आरम्भ मे ही बिना किसी लाग-लपेट के लायकअली के सामने उन सम्भावित घटनाओ का चित्र रखा जो कोई समझौता न होने पर, और हैदराबाद मे हिन्दुओ की खून-खराबी होने पर होगी। यदि उनके भारत से चले जाने के कुछ सप्ताह बाद भारत सैनिक हस्तक्षेप का निश्चय करे तो हैदराबाद की फौज क्या कर लेगी ? लायकअली ने कहा कि वह फौजी स्थिति को पूरी तरह समझते है, लेकिन वह सघ-प्रवेश को सर्व-प्रभुसत्ता की अपेक्षा दसगुना बदतर मानते हैं। उन्होने सफाई दी कि व्यक्तिगत रूप से वह तो जनतंत्री व्यवस्था के पक्ष मे है, लेकिन हैदराबाद मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना का विरोध वह केवल इसलिए करते है कि बिना किसी शक के वह सघ-प्रवेश का कारण बनेगा। जब वी पी कमरे मे दाखिल हुए तो तीनो केन्द्रीय विषयो के बारे मे लायकअली ने पाच या दस वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन समझौते का सुझाव सामने रखा।

नई दिल्ली, बुधवार, २६ मई १९४८

मेनन और लायकअली के बीच एकान्त वार्त्ता बहुत रात गये तक चलती रही। मेनन ने मसौदे तैयार करने और हल खोज निकालने की अपनी विलक्षण शक्ति का उपयोग करके "समझौते के मुख्य मुद्दो" की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली थी। उसको दो भागो मे विभाजित किया गया था। मुख्य मुद्दे कुल ११ हैं। पहले भाग मे हैदराबाद और भारत के बुनियादी सबधो की व्याख्या थी और दूसरे भाग मे प्रथम भाग को कार्यान्वित करने के लिए अन्तरिम व्यवस्था का उल्लेख। 'मुख्य मुद्दो की सूची' से लायकअली के इस अनुरोध की रक्षा हो गई थी कि सघ-प्रवेश के अलावा तीसरा विकल्प और जनमत-सग्रह का सुझाव भी वह निजाम के सामने पेश करना चाहते है। इस तीसरे विकल्प का सवाल वैसे अब कोई मतलब नही रखता।

माउन्टबेटन की खुद यह दृढ राय थी कि जनमत सग्रह सबसे अच्छा हल रहेगा क्योकि "समझौते के मुख्य मुद्दो" की सूची से विस्तार के बारे मे लम्बी और थकाने वाली सौदेबाजी का एक और दरवाजा खुल जायगा। लायकअली की व्यक्तिगत राय भी ऐसी ही मालूम देती थी क्योकि उन्होने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत-सग्रह से "दोनो पक्षो की बात रह जायगी।" भारतीय क्षेत्रो मे जनमत-सग्रह का समर्थन किया जा रहा था, विशेषत पटेल की ओरसे, जिनका आशीर्वाद अनिवार्य था। साथ ही यह मान लिया गया था कि उससे अपने आप सघ-प्रवेश नही हो जायगा।

नई दिल्ली, शनिवार, २९ मई १९४८

हैदराबाद की परेशान करने वाली चर्चाओ का यह सब मे नाजुक दौर है। वी पी, मसूरी जाकर पटेल से मिल आये थे और उनका रचनात्मक और कडे शब्दो वाला सन्देश साथ लाये थे। पटेल ने फिर जनमत-सग्रह का सुझाव दोहराया था। जहा तक समझौते के मुख्य मुद्दो का प्रश्न था, उन्होने पहले भाग मे वर्णित बुनियादी सम्बन्ध तो बिना किसी फेरबदल के स्वीकार कर लिये थे। किन्तु वह दूसरे भाग मे दी गई अन्तरिम-व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करना चाहते थे जिसमे नियत्रण का ज्यादा भार गैर-मुसलमानो के हाथ मे रहे। पटेल के सन्देश का अन्तिम भाग स्वय उन्ही के हाथ का लिखा हुआ था और उसमे उन्होने कहा था कि अगर लायक-अली काम की बात करना चाहते है तो उन्हे निजाम से पूरे अधिकार लेकर यहा आना चाहिए। उन्होने लिखा था, "ऐसे व्यक्ति से चर्चा करने से क्या फायदा जिसे हर बार आदेश प्राप्त करने के लिए वापिस लौटना पडता है।"

वह चाहते है कि चौबीस घटे की मोहलत देते हुए एक तार भेजा जाय। इसमे लिखा जाय कि यदि लायकअली इस अवधि के भीतर पूरे अधिकार और बुनियादी चीजो पर सहमति सहित यहा नही आ सकते तो भारत सरकार यह निष्कर्ष निकालेगी कि हैदराबाद-चर्चाए जारी रखने के लिए उत्सुक नही है—केवल समय गवाना चाहता है। उनके आखिरी शब्द थे "एक सप्ताह के अन्दर फैसला करो।" नेहरू ने लायकअली के प्रति गहरा अविश्वास प्रगट किया था। उनकी हलचलो के बारे मे प्राप्त खुफिया जानकारी से पता चलता था कि हमारा सामना बहुत ही चाल-बाज व्यक्ति से है। लेकिन उनके या निजाम के उत्तर को अब ज्यादा रोका नही जा सकता।

आशा की बात केवल यह थी कि माकटन ने फिर भारत आने का फैसला किया था। माउन्टबेटन ने इस समाचार के प्रति अपनी हार्दिक खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके आने तक वह स्थिति को सभाले रखने की कोशिश करेगे।

लेकिन माकटन ३ जून के पहले भारत आने वाले नही थे। और इसी दिन म अपने परिवार के साथ समुद्री रास्ते से घर जाने के लिए बम्बई से प्रस्थान करूगा।

आज शाम सरकारी भवन मे फे और मुझे विदाई देने के लिए एक दावत दी गई। वैमे हम जा तो मगलवार को सवेरे रहे है, लेकिन माउन्टबेटन-दम्पति को फिर समय नही मिलेगा, और दावत मे शरीक होने के लिए वह उत्सुक है। दावत मे बिलकुल पारिवारिक वातावरण था। मुझे दु ख है कि आखिरी पटाक्षेप होने के पहले ही मै भारत छोड रहा था।

बाद मे माउन्टबेटन ने मुझे एक चादी का सिगरेट-केस भेट किया जिस पर उन्होने बडी उदारता से अपना सन्देश भी खुदवा दिया था। विश्वास, प्रशसा और

दोस्ती के इन प्रतीको ने मुझे विभोर कर दिया। लेकिन सबसे बडा पुरस्कार मै अपने इस सौभाग्य को मानता हू कि कि एक महान् मिशन पर मुझे एक महान् व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिला।

नई दिल्ली, रविवार, ३० मई १९४८

आज शाम हम एक स्वागत समारोह मे शामिल हुए, जिसका आयोजन मेनन ने दिल्ली जीमखाना क्लब मे किया था। दिल्ली का करीब-करीब हर खास व्यक्ति वहा दिखाई दे रहा था। माउन्टबेटन-दम्पति को आगामी तीन सप्ताहो मे जो अनेक विदाई-भोज दिये जायगे, उनमे यह सब से पहला है। इस भीडभाड मे एक सदेश-वाहक निजाम के तीन पत्र लाया, जिनको पढने मे मेजबान, प्रमुख अतिथि और प्रधान-मत्री तीनो रम गए। भारतीय और विदेशी समाचारपत्रो के अधिकाश प्रतिनिधि वहा उपस्थित थे। ज्योहीमाउन्टबेटन, नेहरू और मेनन एक कोने मे जाकर खडे हुए और चिन्ता पूर्ण धीमे स्वरो मे बातचीत करने लगे तो दूर से ताडने वाले इन प्रेसवालो को यह समझने देर नही लगी कि कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल समाचार आया है।

सरसरी नजर से देखने पर लगता था कि माउन्टबेटन के तत्वावधान मे समझौते की आशाओ पर पानी फिर गया है। पहले पत्र मे, "समझौते के मुख्य मुद्दो" पर निजाम की बस यह प्रतिक्रिया है कि वह माकटन के आगमन की प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नही कर सकते। दूसरे पत्र मे इस समझदारी भरे सुझाव पर निजाम ने "दो टूक नही" लिख दी थी कि वह एक नये और अधिक समर्थनीय प्रधान मत्री की नियुक्ति पर विचार करे। ध्यान देने की बात थी कि खुद लायक-अली ने कहा था कि यदि इस सुझाव से सद्भावना बढाने मे मदद मिलती हो तो वह खुद यह सुझाव रखने को तैयार है। उनके सुझाव मे कितनी ईमानदारी थी, वह ही जाने। तीसरा पत्र फिर से एक निमत्रण मात्र है, माउन्टबेटन को हैदराबाद बुलाने के लिए। यह निमत्रण भी सौहार्द अथवा शिष्टाचार से शून्य था।

माउन्टबेटन ने निश्चय किया—जो मेरे विचार मे बुद्धिमानीपूर्ण था—कि केवल पहले पत्र का उत्तर दिया जाय जिसमे और अधिक विलम्ब पर खेद प्रकट करते हुए यह आशा प्रकट की जाय कि लायकअली जब अगली बार दिल्ली आवे तो उन्हे समझौताकरने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होगे।

निजाम के इन शोचनीय नकारात्मक पत्रो के अतिरिक्त लायकअली ने मामले को और तूल दे दिया था। उनकी माउन्टबेटन, नेहरू तथा मेनन से २६ तारीख को जो बाते हुई थी, उनकी वरनोन द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के ठीक होने से उन्होने इकार कर दिया था और कहा था कि वह कभी इस बात पर राजी नही हुए कि तीन केन्द्रीय विषयो पर भारत वैधानिक अधिकारो के अतिक्रमण की घोषणा कर सकेगा।

लेकिन जो भी लोग उस समय कमरे मे उपस्थित थे, उनको पूरा विश्वास है कि लायकअली इस बात पर राजी हो गए थे। यह पत्र नेहरू की इस चेतावनी की पुष्टि करता था कि लायकअली भरोसे के लायक व्यक्ति नही है और उनका एक मात्र उद्देश्य टालमटोल करना था। माकटन का हस्तक्षेप प्रतिपल भारी महत्व ग्रहण करता जा रहा था।

मौजूदा तनाव के बावजूद जईन यारजग हैदराबाद भवन मे पार्टिया देकर शाति और विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। जाने से पहले हमारा प्राय. अन्तिम कार्यक्रम उनके तथा उनके परिवार और सगी-साथियो के साथ भोजन करना था। भोजन के बाद जब हम बागीचे मे बैठे थे तो हैदराबादी महिलाओ मे से एक ने शाइस्ता गुफ्तगू करते हुए 'यथास्थिति समझौतो', सघ-प्रवेश के निर्देश-पत्रो तथा प्रभु सत्ता—से तुच्छ मामलो को ठिकाने लगा दिया। इन महिलाओ ने आह भर कर कहा, "दिल्ली अब पहले वाली दिल्ली नही रही। अब मुगल बादशाह नही रहे।"

एम. वी. केलडोनियो, गुरुवार, ३ जून १९४८

जब मै यह लिख रहा हूँ, मै भारत से इगलैड जाने वाले 'एम वी केलडोनियो' नामक जहाज के राजसी कमरे मे बैठा हू। हम सब पाच है—फे, मे और मेरी पत्नी तथा दो छोटे बच्चे। मगलवार सुबह हम बबई के लिए रवाना हुए थे, जो ८०० मील और २६ घटे की यात्रा है।

आज सवेरे मैने माकटन से साता क्रुज के हवाई अड्डे पर मुलाकात की। वह एक खास हवाई जहाज से यहा पहुचे है।

जहाज पर सवार होने से पहले मैने आखिरी सरकारी कर्त्तव्य के नाते माउन्टबेटन को तार द्वारा सूचित किया। जब मै माकटन से मिला तो वह स्पष्टतया सदिग्ध और निराश थे, और वह इस बात से बेखबर थे कि घटनाओ को अनुकूलता-पूर्वक वहा ले जाने मे उनकी सलाह क्या महत्त्व रखती है। मैने राजनैतिक तनाव की वास्तविकता और समय-तत्त्व की अनिवार्यता पर बल दिया है और मै कह सकता हूँ कि माकटन मेरी मुलाकात के बाद अधिक आशावान नजर आते थे।

आज दोपहर बाद जब जहाज समुद्र-तट से रवाना हुआ तो मुझे लग रहा है कि मै दबा-दबा जा रहा हूँ। निश्चय ही अत्यधिक व्यस्तता के बाद यह एकाएक बेकाम हो जाना ही इसका कारण था। ज्योही हमने अरब सागर मे प्रवेश किया, बम्बई की दूरस्थ बत्तियाँ टिमटिमाती नजर आ रही थी, सब ओर अनत शान्ति थी। लेकिन हमे चेतावनी दी गई कि भारी तूफान का सामना होनेवाला है।

लन्दन, बुधवार, २३ जून १९४८

बीस दिन की समुद्री यात्रा के बाद हम कल लिवरपूल पहुंचे। बम्बई से डेढ़ सौ मील चलने पर हमारी तूफान से टक्कर हुई, जिसने अदन तक हमारा पीछा नही छोडा। माउन्टबेटन और उनके दल के नार्थोल्ट हवाई अड्डे पर उतरने के समय मैं वहा पहुच गया। इतनी ही यात्रा मे उन्हे हवाई जहाज से केवल अडतालीस घटे लगे थे।

उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर एडिनबरा के ड्यूक और एटली दोनों मौजूद थे। इससे उनके आगमन का महत्व असाधारण बन गया। इसके पहले शायद ही किसी और वाइसराय अथवा गवर्नर-जनरल ने अपने स्वागत के लिए एक शाही ड्यूक ओर प्रधान मत्री को उनकी वापिसी पर स्वागत के लिए खडे पाया होगा। अन्य मत्री लोग, ऊचे और वरिष्ठ अधिकारी, बी बी सी न्यूज रील और समाचार पत्रो के प्रतिनिधि तथा फोटोग्राफर भी बडी सख्या मे वहा उपस्थित थे। भारत के नये युद्धपोत "दिल्ली" के सौ नाविको ने उन्हे सलामी दी।

एटली की उपस्थिति बिलकुल मौजूं थी, क्योंकि भारत मे सत्ताहस्तातरण प्रधान मत्रीपद का सबसे ऐतिहासिक निर्णय था। उसके स्वरूप और अमल का भारी उत्तरदायित्व हमेशा उन्ही के कन्धो पर रहा इसलिए इतिहास मार्ले और मिन्टो, माटेग्यू और चेम्सफोर्ड की भाति एटली और माउन्टबेटन के नाम भी साथ लिया करेगा।

लन्दन, सोमवार, २८ जून १९४८

हैदराबाद वार्त्तालाप भग हो गया है। इसका केवल सक्षिप्त समाचार जहाज के रेडियो पर सुना था। इसके साथ ही माउन्टबेटन के विदाई प्रबंधी समाचार भी सुने थे। माउन्टबेटन के विदा होने के समय पर १५ अगस्त के समान ही हार्दिक-उत्साह प्रगट किया गया था। कई दृष्टियो से तो यह हार्दिक-विदाई उससे कही अधिक उल्लेखनीय थी, क्योंकि अब तो माउन्टबेटन के प्रति यह व्यक्तिगत कृतज्ञता की भावनाओ की मात्र अभिव्यक्ति थी।

जब से माउन्टबेटन-दल लौटा है, मैंने रोनी और वरनोन के साथ लंबी चर्चाएं की हैं और इसी बीच एक या दो बार स्वत माउन्टबेटन से भी बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त अपनी विदाई के समय तक उन्होने अनेक सूचनाए एकत्र की थी। इन सब आधारो से पता चलता है कि माकटन के साथ मेरी मुलाकात के बाद का घटनाक्रम सक्षेप मे इस प्रकार रहा-

माकटन हैदराबाद मे तीन दिन रुके और लायकअली के साथ दिल्ली आ गए। पहले तो वार्तालाप मे बहुत गरमा-गरमी रही और कई बार लगा कि बातचीत का सिलसिला हमेशा के लिए टूट जायगा। नेहरू ने लायकअली से मिलने से इंकार

कर दिया और माकटन ने लदन लौट जाने की धमकी दी। एक बार तो माउन्टबटन ने नेहरू को फोन पर यह कह उस दिन का सकट टाल दिया कि उन्हे पक्का विश्वास है कि वह सतोषजनक हल खोज लेगे, जबकि तथ्य यह था कि उनके सामने ऐसा कोई हल था ही नही। लेकिन ज्यो-त्यो बातचीत को जारी रखा गया। नेहरू ने ८ जून को एक भाषण दिया, जो सहायक सिद्ध हुआ। अपने भाषण मे उन्होने अपने आलोचको को इस बात का उत्तर दिया कि भारतीय फौजो ने अबतक हैदराबाद मे क्यो प्रवेश नही किया। उन्होने कहा कि जब भी कभी बल का प्रयोग हुआ है, उससे निराकरण के बजाय अधिक समस्याए उत्पन्न हो गई है।

माकटन का ख्याल था कि परिस्थिति पर काबू पाने के लिए दीर्घकालीन जन-मत-सग्रह से कुछ बढकर होना चाहिए। अपनी रुग्ण-शैया से पटेल अब भी बिना शर्त-सघ-प्रवेश चाहते थे। उनका कहना था कि भारतीय पक्ष की ओर से अब और हल पेश नही किये जाने चाहिये। माकटन को यह मान्य था और उसने दो दस्तावेज उपस्थित किये—१९४९ के आरभ मे उत्तरदायी सरकार जारी करने तथा विधानसभा स्थापित करने का फरमान, और वर्तमान सरकार का तात्कालिक पुनर्निर्माण। दूसरा दस्तावेज पूरी तरह से वी० पी० मेनन के समझोते की शर्तो का प्रथम भाग था। लायकअली ने यह कह कर एक बार फिर चाल चली कि वह निजाम के साथ सलाह करने जाना चाहते है। ९ जून को दिल्ली मे यह अफवाह उडी कि हैदराबाद मे पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि आया हुआ है, लेकिन लायकअली ने कसम खा कर इससे इकार किया और तय पाया कि वह सलाह-मशविरे के लिए हैदराबाद जाय।

१२ जून को माकटन ने सूचना दी कि वैधानिक अतिक्रमण और विधान-सभा के निर्माण-सबधी दो मामलो के सिवा सब तजवीजो पर प्रबन्ध-परिषद की मार्फत निजाम से नजर डलवा ली गई है। इससे पहले तो दिल्ली मे माउन्टबेटन, माकटन और नेहरू के बीच मसूरी मे बातचीत मे अधिक कठिनाई पैदा हुई और उसके बाद मसूरी मे पटेल के साथ एक मुलाकात मे और माउन्टबेटन की मोजूदगी मे मत्रि-मडल की अधिकाश बैठको मे भी इसका सामना करना पडा। लेकिन इन तजवीजो को निजाम द्वारा सशोधित रूप से इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि असैंबली के निर्माण मे साम्यता का कोई सीधा उल्लेख न हो, और उसकी जगह हैदराबाद मे "मुख्य राजनैतिक दलो के नेताओ से परामर्श के साथ" इन शब्दो को रखा जाय।

१३ जून को माकटन ने लायकअली से बहुत जोर दे कर कहा कि इस बार वह पूर्ण-निर्णायक अधिकारो के साथ आवे, लेकिन अपनी निर्णायक इच्छा का उपयोग करने मे इस बार भी वह परिषद् और स्वत निजाम द्वारा बधे थे। १४ जून को लायकअली ने "समझोता-शीर्षको" मे चार नये सशोधन करने के लिए कहा। वे ये थे पहला, भारत सरकार हैदराबाद से प्रार्थना करेगी कि वह भारत मे प्रचलित

व्यवस्था के अनुरूप ही एक कानून स्वीकार करे और वह खास तौर पर हैदराबाद के लिए न हो, दूसरा, हैदराबाद को आठ हजार अनियमित सैनिक रखने की मंजूरी दी जाय, तीसरा, रजाकारो का धीरे-धीरे अत किया जायगा, एकाएक नही, चौथा, जिस सकट-अवस्था के अधीन भारत हैदराबाद मे सेनाएं रखना चाहता है उसकी गवर्नमेंट आव् इडिया एक्ट मे व्याख्या की जाय। माउन्टबेटन का ख्याल था कि भारत सरकार इन अतिरिक्त मामलो पर विचार नही करेगी, लेकिन जब नेहरू भी मानने को तैयार हो गए तो उन्हे बेहद खुशी ओर आश्चर्य हुआ।

१५ जून को माउन्टबेटन ने हैदराबाद प्रतिनिधि मडल से मुलाकात की और इस अप्रत्याशित सफलता की सूचना दी। इस पर लायकअली ने तत्काल दो नये मामले उपस्थित कर दिये। वह चाहते थे कि आर्थिक और तट-कर सबधी स्वतत्रता के ऐलानो को भी शामिल कर लिया जाय। भारत सरकार एक बार पुन सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को सहमत हो गई ओर उसने तजवीज भी की कि एक नत्थी-पत्र मे इस विषय पर बल दिया जा सकता है। माउन्टबेटन ने कहा कि इस मामले पर नेहरू इस हदतक बढ गए कि वह नत्थी-पत्र मे हैदराबाद के आर्थिक विकास मे सयुक्त-सहकारिता की शर्त को भी शामिल कर देगे। साथ जाहिर था कि लायकअली उनके इस आशय को नही समझे ओर उन्होने इस शर्त को तत्काल निकाल देने के लिए कहा। लेकिन जब माकटन ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि हैदराबाद के लिए इस रियायत को दरगुजर करना अत्यधिक मूर्खता होगी, और माउन्टबेटन ने भी स्पष्ट किया कि अबतक हमेशा ही इसके साथ पूर्ण सघ-प्रवेश की शर्त रही है तो लायकअली ने अपनी माग को वापिस ले लिया। इस प्रकार सद्भावना की यह एक और मिसाल पेश की गई। लेकिन, जैसा कि माउन्टबेटन ने कहा है, इस समय पर लायकअली की यह मूर्खता क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना थी।

लायकअली आखिरी दस्तावेज ओर सब सशोधनो को लेकर हैदराबाद रवाना हो गए। माकटन ने जोर देकर उनसे कहा कि या तो पूरी तरह मजूर करो अथवा पूरी तरह इकार। उसी शाम को ७-३० बजे तक उत्तर की प्रतीक्षा की गई, लेकिन, आखिर ९-४० पर यह जवाब मिला कि निजाम अपनी मत्रि-परिषद् की सलाह के बिना कोई अतिम निर्णय करने मे असमर्थ है। व्यावहारिक रूप मे यह आगामी दिन तक सभव नही था। फलत इस विलब को दिल्ली ने मजर कर लिया।

सोलह को दोपहर के समय माउन्टबेटन और माकटन को सूचना मिली कि चार नय प्रश्नो के आधार पर निजाम को सिफारिश की गई है कि वह इन तजवीजो को स्वीकार न करे। इन आधारो को माउन्टबेटन और यहा तक कि माकटन ने भी अत्यधिक अन्याय पूर्ण और बेहूदा बताया। उपरात निश्चय हुआ कि माकटन रात ही को हैदराबाद जाय।

उनका सब से बडा एतराज विधान-सभा स्थापित करने सम्बन्धी फरमान

कि एक उप-पैरे मे से "इस आधार पर, जिस पर मै बाद मे विचार करूगा" शब्दो को निकाल देने के बारे मे था। लेकिन उनका प्रतिनिधि मडल इन शब्दो को निकालने की मजूरी पहले ही दे चुका था, इसलिए इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नही माना जा सकता था। एक दूसरा एतराज यह था कि वह नत्थी-पत्र के निर्णय द्वारा आर्थिक समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नही (और भारत ने तो बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही यह रियायत पेश की थी)। अब वह इसे मूल-समझौतो मे शामिल कराना चाहते थे।

सत्रह को दोपहर के वक्त माकटन ने फोन से "बस अत" यही शब्द कहे। उसी शाम को निजाम ने बिल्कुल एक नया प्रश्न खडा कर दिया और इससे पहले उसका उल्लेख कभी नही किया गया था। यह प्रश्न सकट काल मे फौज तैनात करने के भारतीय अधिकार के बारे मे था। उन्होने बातचीत को जारी रखने के लिए भी कहा। इधर नेहरू और वी॰ पी॰ मेनन माकटन के इतजार मे थे। उनके आ जाने पर एक प्रेस-कान्फ्रेस की गई, जिसमे निजाम को दी हुई शर्ते प्रकट कर दी गई।

इतना सब होने पर भी नेहरू ने वचन दिया कि वह स्वीकृति के लिए इस समझौते को खुला छोडते है और समय की पाबदी नही लगाते। माकटन ने माउन्टबेटन को बताया कि लायकअली के इस व्यवहार से तो उन्हे बहुत ही निराशा हुई है कि निजाम तक के मुलाकात करने के पहले उसने रिजवी के साथ तीन घटे बातचीत की। माकटन ने हैदराबाद की कथित नाकेबदी के विषय मे भी एक अनौपचारिक प्रेस-कान्फ्रेंस मे अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि केन्द्रीय सरकार और किसी भी प्रान्तीय शासन ने इसे लागू नही किया, बल्कि छोटे दर्जे के अफसरों की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओ का ही यह परिणाम है।

माकटन के बातचीत-सम्बन्धी महान् चातुर्य को समझने की योग्यता होती तो परिणाम अनुकूल हो सकता था।

अपने पद-काल के आखिरी दो सप्ताहो मे हैदराबाद की लंबी बातचीत और उसके दबाव के कारण माउन्टबेटन के लिए यह असभव हो गया कि वह काश्मीर-विषयक मध्यस्थता का कोई अ तिम यत्न कर सके। मार्च मे उन्होने दोनो प्रधान-म त्रियो का समझौता कराया था कि वे लगभग प्रतिमास मिला करेगे। लेकिन दो मास से ऐसा कोई यत्न नही हुआ। माउन्टबेटन ने नेहरू को सुझाव दिया कि वह लियाकत को दिल्ली मे मिलने के लिए लिखे, जिससे लियाकत माउन्टबेटन को भारत छोडने से पूर्व विदाई-नमस्कार कर सके। लेकिन इस कोशिश को पहले तो हैदराबाद के कारण स्थगित करना पडा और उसके बाद लियाकत की बीमारी के कारण।

विभिन्न हलो पर विस्तार मे बातचीत करने की सारी पष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। यद्यपि भारतीय म त्रि-म डल नियमित पाकिस्तानी सेना के काश्मीर-युद्ध मे भाग लेने के प्रति अत्यत कठोर था, तथापि समझौते के लिए काफी गुजाइश थी। जब नेहरू ने पाकिस्तानी सेना के युद्ध मे भाग लेने के प्रमाण भेजे, तो लियाकत ने साफ तौर पर इसका प्रतिपादन नही किया, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा के भय पर ही जोर दिया। उन्होने लिखा, "ज्यो-ज्यो भारतीय फौजे उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर पहुचती जाती है, कबाइलियो को सीधा खतरा महसूस होने लगा है।" माउन्ट-बेटन की राय है कि दोनो मुख्य व्यक्तियो का इस खास मौके पर परस्पर न मिल सकना राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप मे अत्यन्त अभाग्यपूर्ण था।

लेकिन भारतीय जनता के हृदय पर माउन्टबेटन ने जो निश्चित विजय प्राप्त की थी, उसके मुकाबिले निजाम और काश्मीर की असफलताए तो आकस्मिक-सी जान पडती थी। भारत मे माउन्टबेटन का आखिरी दिन, जैसाकि मुझे सबको जबानी मालूम हुआ है, कल्पनातीत विजय का था। अत्यधिक बल के साथ माउन्टबेटन दल यह मान गया था कि भारत के लोगो और सरकार ने उनके मिशन के आशय और उनके यत्नो की सचाई को स्वीकार कर लिया है और वे उन्हे मित्रो तथा आजाद करने वालो के रूप मे विदाई दे रहे है।

पहला विदाई-अभिनदन-पत्र दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की ओर से दिया गया था। यह मान-पुत्र पाने के लिए वह पुरानी दिल्ली के शाही मार्ग चादनी चौक से होकर निकले थे। चादनी चौक मे ठसाठस भीड थी। १९११ मे जब लार्ड हार्डिज की हत्या की चेष्टा की गई थी, तब से लेकर कोई भी वाइसराय इस मार्ग से नही निकला था। गाधी-ग्राउड तक उनके चारो ओर भीड का समुद्र था, जो जय-जय के नारे लगा रही थी और उन्हे फूल मालाए पहना रही थी। गाधीग्राउड मे लगभग ढाई लाख आदमी जमा थे और ढाई लाख की और भीड उसमे दाखिल होने की चेष्टा

कर रही थी।

महान शाही भोजो[1] मे सबसे आखिरी इस बार मत्रि-मडल की ओर से शाम को दिया गया था। इस अवसर पर नेहरू ने चिरस्मरणीय शब्दो मे माउन्टबेटन-परिवार को हार्दिक श्रद्धाजलि भेट की। उन्होने कहा "श्रीमान्, बहुत ऊची ख्याति के साथ आप यहा आये थे, लेकिन भारत मे कइयो की ख्याति का लोप हो गया। आप यहा महान् कठिनाई और सकट के काल मे रहे और इतने पर भी आपकी ख्याति का लोप नही हुआ। यह एक आश्चर्यजनक शक्ति का परिचायक है।"

लेडी माउन्टबेटन के विपय मे आगे उन्होने कहा, "आपके हाथ मे जादू है। जहा कही भी आप गई, आपने सान्त्वना प्रदान की, आपने आशा और उत्साह उत्पन्न किया। इसलिए, इसमे क्या आश्चर्य है कि भारत के लोग आपसे प्रेम करे और आपको भी अपने मे से ही एक समझे तथा आप के जाने पर उन्हे दु ख का अनुभव हो।"

चार घटे पूर्व दिल्ली की सामान्य जनता द्वारा मित्रता और प्रेम के आश्चर्य-जनक प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए नेहरू ने कहा, "मै नही कह सकता कि लार्ड और लेडी माउन्टबेटन को उस अवसर पर कैसा लगा होगा, लेकिन इन विशाल प्रदर्शनो का आदी होते हुए भी मै तो अत्यन्त प्रभावित हुआ हू। मुझे इस वात की हैरानी है कि एक अगरेज और एक अग्रेज-महिला किस प्रकार भारत मे इस थोडे से काल मे इतने ज्यादा लोक-प्रिय वन गए। निश्चय ही यह एक ऐसा काल है, जिसमे किसी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दु ख और विनाश का भी यह काल था। आपको अनेक उपहार और भेट प्राप्त होगी, लेकिन लोगो के प्रेम और आत्मीयता से वढ कर वास्तविक या मूल्यवान क्या हो सकता है?"

१. माउन्टबेटन-दंपति ने भारत मे अपने १५ मास के आवास मे अत्यधिक व्यस्त कार्य-कलापो के बावजूद सरकारी भवन मे सदिच्छा और मैत्री-भावना की वृद्धि की दृष्टि से जो भोज दिये उनका विवरण इस प्रकार है: दिन के भोजन पर उन्होने ७६०५, रात्रि-भोज पर ८३१३ और चाय-पान आदि के लिए २५२८ व्यक्तियो को आमंत्रित किया।

परिशिष्ट

: १ :

ब्रिटिश सरकार की जिस घोषणा के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो उपनिवेशो को सत्ता-हस्तातरण की गई, वह सामान्यतया '३ जून की योजना' के नाम से प्रख्यात है। इस घोषणा का मूल पाठ निम्न है

ब्रिटिश-सरकार का वक्तव्य

नई दिल्ली, मगलवार, ३ जून १९४७

प्रस्तावना

१ २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह जून १९४८ तक भारत मे ब्रिटिश-सत्ता को भारतीयो के हाथो सौप देना चाहती है। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि १६ मई १९४६ की मन्त्रि-मडल मिशन-योजना को सफल बनाने मे मुख्य दलो के लिए सहयोग करना और भारत के लिए ऐसा विधान तैयार करना सभव होगा, जो सब सबधित दलो को मान्य हो। यह आशा पूर्ण नही हुई।

२ मदरास, बबई, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रात और बरार, आसाम, उडीसा और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रात के प्रतिनिधियो तथा दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा और कुर्ग के प्रतिनिधियो की बहु-सख्या नया सविधान बनाने की दिशा मे पहले ही पर्याप्त प्रगति कर चुकी है। दूसरी ओर मुस्लिम लीगी दल ने, जिसमे बगाल, पजाब, सिध तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधियो की बहुसख्या शामिल है, विधान-सभा मे भाग न लेने का फैसला किया है।

३ ब्रिटिश-सरकार की सदा यह इच्छा रही है कि सत्ता-हस्तातरण स्वत भारतीयो की इच्छानुसार ही हो। भारतीय राजनैतिक दलो मे परस्पर समझौता होने की दशा मे यह कार्य अत्यन्त सुगम हो जाता। फलत, ऐसे किसी समझौते की अनुपस्थिति मे भारतीयो की इच्छाओ का निश्चय करने का काम ब्रिटिश-सरकार पर आ पडा है। भारत के राजनैतिक नेताओ के साथ पूर्ण विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के लिए नीचे दी हुई योजना को अपनाने का फैसला किया

है। ब्रिटिश सरकार यह साफ जाहिर कर देना चाहती है कि वह भारत के लिए भी किसी भी प्रकार का सविधान बनाने की इच्छा नही रखती, क्योकि यह तो स्वत भारतीयो का ही मामला है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत योजना मे सयुक्त भारत के लिए विभिन्न सप्रदायो के बीच वार्तालाप मे बाधा बनने वाली भी कोई बात नही है।

निर्णायक प्रश्न

४ ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नही है कि वर्तमान विधान-सभा के कार्य मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। नीचे लिखे कुछ प्रातो के लिए अब व्यवस्था कर दी गई है, और ब्रिटिश सरकार को विश्वास है कि इस घोषणा के फलस्वरूप उन प्रातो के मुस्लिम-लीगी प्रतिनिधि भी इसके कार्य मे अपना उचित योग-प्रदान करेगे, जिनके प्रतिनिधियो की बहुसख्या पहले से ही उसमे भाग ले रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस विधान-सभा द्वारा जो भी सविधान तैयार किया जायगा वह देश के उन भागो पर लागू नही हो सकता, जो उसे स्वीकार करने के इच्छुक न हो। ब्रिटिश सरकार इस बात से सतुष्ट है कि जो विधि नीचे दी गई है, उसमे उन क्षेत्रो के लोगो की यह इच्छा जानने की सर्वोत्तम व्यावहारिक विधि निहित है कि उनका सविधान ।

(अ) वर्तमान विधान-सभा मे बने, या

(ब) उन इलाको के प्रतिनिधियो की नई और अलग विधान सभा मे, जिन्होने वर्तमान विधान-सभा मे भाग न लेने का निर्णय किया है ।

जब यह हो चुकेगा तो यह निश्चय करना सभव हो जायगा कि किस अधिकारी या अधिकारियो को सत्ता-हस्तातरण किया जाना चाहिए ।

बगाल और पजाब

५ फलत, पजाब और बगाल की प्रातीय व्यवस्थापिका सभाओ मे प्रत्येक को (यूरोपीय सदस्यो को छोड कर) दो भागो मे बैठने के लिए कहा जायगा —एक वह, जिसमे मुस्लिम-बहुल-जिलो का प्रतिनिधित्व होगा और दूसरे, जिसमे शेष प्रात का । जिलो की जन-सख्या का निश्चय करने के लिए १९४१ की जनगणना के आकडो को अधिकृत माना जायगा । इन दोनो प्रातो के मुस्लिम-बहुल जिले इस घोषणा के अन्त मे दिये गए है ।

६ प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा के दो भागो के सदस्यो को अलग-अलग बैठको मे इस मतदान का अधिकार होगा कि उस प्रात का विभाजन किया जाय या नही। यदि दोनो मे से कोई भी भाग विभाजन का समर्थन करता है तो विभाजन होगा और तदनुसार प्रबध किये जायगे ।

७ विभाजन के प्रश्न का निर्णय होने से पहले, प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियो

को अग्रिम रूप मे मालूम होना चाहिए कि दोनो भाग यदि अतत सयुक्त रहने का ही निर्णय करते है तो समग्र रूप मे वह प्रात किस विधान-सभा मे शामिल होगा। इसलिए, यदि दोनो व्यवस्थापिका सभाओ का कोई भी सदस्य यह जानना चाहेगा, तो व्यवस्थापिका सभा के सब सदस्यो (यूरोपियनो के सिवा) की बैठक होगी और उसमे इस प्रश्न का निर्णय किया जायगा कि इन दोनो भागो के सयुक्त बने रहने के निर्णय की दशा मे वह प्रात समग्र रूप मे किस विधान-सभा मे शामिल होगा।

८ विभाजन का निर्णय हो जाने की अवस्था मे व्यवस्थापिका सभा का प्रत्येक भाग अपने प्रतिनिधित्व के हल्को की ओर से उक्त पैरा ४ मे दिये विकल्पो मे से किसी एक को ग्रहण करने का निर्णय करेगा।

९ विभाजन के प्रश्न का निर्णय करने के तात्कालिक मुद्दे के लिए बगाल और पजाब की व्यवस्थापिका सभाओ के सदस्य मुस्लिम-बहुल जिलो (अन्त मे लिखे अनुसार) और गैर-मुस्लिम-बहुल जिलो के अनुसार दो भागो मे बैठेंगे। यह विधि तो केवल नितात अस्थायी स्वरूप की प्रारभिक कार्यवाही है, क्योकि यह तो साफ जाहिर है कि इन प्रातो के आखिरी विभाजन के लिए सीमा-सबधी प्रश्नो की विस्तृत खोज करनी आवश्यक होगी, और, जैसे ही दोनो मे किसी भी प्रात के विभाजन का निर्णय हो जायगा, गवर्नर-जनरल एक सीमा-आयोग की स्थापना करेंगे, जिसकी सदस्यता और अधिकार-क्षेत्र का निश्चय सबधित लोगो के परामर्श से किया जायगा। उसे मुस्लिमो और गैर-मुस्लिमो के आसपास के बहुल इलाको का निश्चय करने के आधार पर पजाब के दो भागो की सीमा-रेखाए बनाने का आदेश दिया जायगा। उसे अन्य तत्वो को भी दृष्टि मे रखने की हिदायत की जायगी। इसी तरह की हिदायतें बगाल सीमा-आयोग को भी दी जायगी। जब तक सीमा-आयोग की सूचना सक्रिय रूप मे लागू नही हो जाती, तब तक परिशिष्ट मे लिखित अस्थायी सीमाओ का प्रयोग किया जायगा।

सिंध

१० सिंध की व्यवस्थापिका सभा भी यूरोपीय सदस्यो के सिवा उक्त पैरा ४ के विकल्पो के आधार पर अपने विशिष्ट अधिवेशन मे अपना निजी निर्णय करेगी।

उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रात

११ उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात की स्थिति सबसे अलग है। इस प्रात के तीन प्रतिनिधियो मे से दो पहले से ही मौजूदा विधान-सभा मे भाग ले रहे हैं। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति तथा अन्य विचारो को दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि सारा या पजाब का कोई भाग मौजूदा विधान-सभा मे शामिल न होने का निश्चय करता है, तो उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात को अपनी स्थिति पर पुन-

विचार करने का अवसर देना आवश्यक होगा। ऐसी अवस्था मे उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचको का जन-मत सग्रह होगा, जो पैरा ४ विकल्पो मे से जिसे ग्रहण करना चाहते है, चुनेगे। यह जनमत-सग्रह प्रातीय सरकार के परामर्श के साथ गवर्नर-जनरल की देख-रेख मे होगा।

ब्रिटिश-बलूचिस्तान

१२ ब्रिटिश-बलूचिस्तान ने एक सदस्य चुना है, लेकिन वह मौजूदा विधान-सभा मे शामिल नही हुआ। इसकी भौगोलिक स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए, इस प्रात को भी अपनी स्थिति पर पुन विचार करने और यह चुनने का अवसर दिया जायगा कि वह पैरा ४ के विकल्पो मे किसे ग्रहण करना चाहता है। यह किस प्रकार समुचित ढग से किया जा सकताहै, इस बारे मे गवर्नर-जनरल विचार कर रहे है।

आसाम

१३ यद्यपि आसाम प्रबल रूप मे गैर-मुस्लिम प्रात है, तथापि सिल्हट का जिला, जो बगाल के साथ जुडा हुआ है, प्रबल रूप मे मुस्लिम है। यह माग की गई है कि बगाल का विभाजन होने की दशा मे सिल्हट को बगाल के मुस्लिम-भाग मे शामिल किया जाय। तदनुसार यह फैसला किया गया है कि यदि बगाल का विभाजन हो तो आसाम की प्रातीय सरकार की सलाह से गवर्नर-जनरल की देख-रेख मे सिल्हट जिले मे इस आशय से जन-मत-सग्रह किया जायगा कि सिल्हट का जिला आसाम प्रात का भाग बना रहे या पूर्वी बगाल के नये प्रात मे शामिल कर लिया जाय, बशर्ते कि वह प्रात उसे शामिल करने के लिए सहमत हो, यदि जनमत-सग्रह का परिणाम पूर्वी-बगाल मे शामिल होने के पक्ष मे हो,तो पजाब और बगाल जैसा ही सीमा-आयोग बनाया जायगा, जो सिल्हट जिले के मुस्लिम-बहुल इलाको और आसपास के जिलो के निकटस्थ मुस्लिम-बहुल इलाको की सीमा-रेखा नियत करेगा। इसके बाद उन्हे पूर्वी बगाल के हवाले कर दिया जायगा। शेष आसाम प्रात मोजूदा विधान-सभा की कार्यवाही मे भाग लेता रहेगा।

विधान-सभाओ का प्रतिनिधित्व

१४ यदि बगाल और पजाब के विभाजन का निर्णय हो जाता है तो १६ मई १९४६ की मत्रि-मडलीय योजना मे निहित सिद्धात के अनुसार प्रत्येक दस लाख जनसख्या पीछे एक प्रतिनिधि चुनने के लिए नये चुनाव करने आवश्यक होगे। इसी तरह के चुनाव सिल्हट मे भी करने होगे, अगर वह पूर्वी बगाल मे शामिल होने का निर्णय करता है। प्रत्येक इलाके मे प्रतिनिधियो की सख्या इस प्रकार होगी.

प्रात	सामान्य	मुस्लिम	सिख	योग
सिल्हट जिला	१	२	—	३
पश्चिमी बगाल	१५	४	—	१९
पूर्वी बगाल	१२	२९	—	४१
पश्चिमी पजाब	३	१२	२	१७
पूर्वी पजाब	६	४	२	१२

१५ विभिन्न इलाको के प्रतिनिधि प्रदत्त आदेशो के अनुसार या तो मौजूदा-विधान-सभा मे शामिल होगे या नई विधान-सभा बनायगे ।

प्रशासनिक मामले

१६ यदि किसी विभाजन का निर्णय हो जायगा तो प्रशासनिक नतीजो पर यथाशीघ्र वार्त्तालाप आरभ किया जायगा ।

(अ) यह वार्त्तालाप यथाक्रम उत्तराधिकारी शक्तियो के प्रतिनिधियो के बीच सुरक्षा, अर्थ और सचरण सहित उन सब विषयो के बारे मे होगा, जो वर्तमान मे केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

(ब) सत्ता-हस्तातरण से उत्पन्न मामलो के विषय मे सधियो के लिए विभिन्न उत्तराधिकारियो और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्त्तालाप होगे ।

(स) जिन प्रातो का विभाजन होगा, उनकी सपत्तियो और देनदारियो, पुलिस और अन्य नौकरियो, हाइकोर्टो, प्रातीय सरकारी सस्थाओ जैसे सभी प्रातीय विषयो के प्रशासनिक मामलो पर वार्त्तालाप होगा ।

उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के कबीले

१७ भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात के कबीलो के साथ समुचित उत्तराधिकार शक्तिया समझौते करेगी ।

रियासते

१८ ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उक्त निर्णयो की घोषणा का सबध केवल ब्रिटिश भारत के साथ है और भारतीय रियासतो के प्रति उसकी नीति १२ मई १९४६ की मत्रि-मडलीय घोषणा मे निहित है, जिसमे कोई फर-बदल नही किया गया है ।

गतिशीलता की आवश्यकता

१९ उत्तराधिकारी शक्तियो को सत्ता ग्रहण करने के लिए तैयारी का समय मिल सके, इसके लिए अत्यावश्यक है कि ऊपर लिखी हुई सब विधियो को यथाशीघ्र

पूरा कर लिया जाय। देरी से बचने के लिए विभिन्न प्रात या प्रातो के भाग इस योजना की शर्तो के अनुरूप यथासभव स्वतत्रता-पूर्वक भी कार्य करेगे। मौजूदा विधान-सभा और नई विधान सभा (यदि बनी) अपने-अपने इलाको के लिए विधान बनाने का कार्य करती रहेगी।

तात्कालिक सत्ता-हस्तातरण

२० प्रमुख राजनैतिक दलो ने बारबार इस बात पर जोर दिया है कि जितना भी जल्दी सभव हो, भारत मे सत्ता-हस्तातरण हो जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार इस विचार के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है और वह जून १९४८ तक या उससे भी पहले स्वतत्र भारतीय सरकार या सरकारे बना कर सत्ता-हस्तातरण कर देने की इच्छुक है। इस घोषणा के फलरूप जो निर्णय होगे उसके अनुसार औपनिवेशिक स्तर के आधार पर एक या दो उत्तराधिकारी शक्तियो को सत्ता-हस्तातरण करने के लिए वह मौजूदा अधिवेशन मे एक विधान भी पेश करना चाहती है। भारतीय विधान सभाओ को समयान्तर यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश-राष्ट्र-मडल मे रहना चाहते है या नही।

१९४१ की जनगणना के अनुसार पजाब और बगाल के मुस्लिम-बहुल जिले:

१ पजाब

लाहौर डिवीजन—गुजरावाला, गुरुदासपुर, लाहौर, शेखूपुरा, स्यालकोट।

रावलपिडी डिवीजन—अटक, गुजरात, जेहलम, मियावाली, रावलपिंडी, शाहपुर।

मुलतान डिवीजन—डेरागाजीखा, झग, लायलपुर, मिन्टगुमरी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ।

२. बगाल

चटगाव डिवीजन—चटगाव, नोआखाली, तिपरा।

ढाका डिवीजन—बकरगज, ढाका, फरीदपुर, मैमनसिह।

प्रैसीडैसी डिवीजन—जेस्सोर, मुर्शिदाबाद, नदिया।

राजाशाही डिवीजन—बोगरा, दीनाजपुर, मालदा, पबना, राजाशाही, रगपुर।

: २ :

प्रमुख व्यक्तियों के परिचय

भारत-विभाजन और सत्ता-हस्तातरण की इस लम्बी कहानी मे लगभग २५ से अधिक व्यक्तियो के नामो का उल्लेख हुआ है। हिन्दी के पाठको के लाभ के लिए इनमे से कुछ का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है

अब्दुल्ला, शेख : काश्मीर के प्रतिनिधि राष्ट्रीय दल 'नेशनल काफ्रेस' के तत्कालीन नेता, काश्मीर के भारत मे शामिल होने पर तत्कालीन प्रधान-मत्री।

अमृतकौर, राजकुमारी . महात्मा गाधी की सचिव, भारत सरकार की भूतपूर्व स्वास्थ्य-मत्री।

अली, मीर लायक नवम्बर १९४७ से निजाम हैदराबाद की परिषद् के प्रधान

अर्सकिन क्रम, लैफ्टीनेंट कर्नल वी एफ : वाइसराय और भारत के गवर्नर जनरल के काफ्रेस-सचिव ।

आचिन्लेक, फील्ड मार्शल सर क्लाड : १५ अगस्त तक भारत मे कमाडर इन-चीफ, ३० नवम्बर १९४७ तक भारतीय सेनाओ के विभाजन की देखरेख के लिए सुप्रीम कमाडर।

आयंगर, गोपालस्वामी : (स्व०) भारत-सरकार के मत्री, जनवरी १९४८ मे सयुक्त-राष्ट्र-सघ मे जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मडल के नेता।

इस्मे, लार्ड . वाइसराय के स्टाफ, और दिसम्बर १९४७ तक भारत के गवर्नर जनरल के स्टाफ के मुखिया।

एबेल, जी ई बी. (बाद में सर जार्ज) : वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी।

कृपालानी, आचार्य जे. बी. : काग्रस के तत्कालीन प्रधान।

छतारी, नवाब मई १९४७ से नवम्बर १९४७ तक निजाम हैदराबाद की परिषद के प्रधान।

जिन्ना, मुहम्मद अली : (कायदे-आजम) (स्व०) मुस्लिम लीग के प्रधान, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल।

जैनकिन्स, सर इवान · १५ अगस्त १९४७ तक पजाब के गवर्नर।

त्रिवेदी, सर चन्दूलाल : उडीसा के गवर्नर, १५ अगस्त १९४७ से पूर्वी पजाब के तत्कालीन गवर्नर।

देवदास गाधी : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रबन्ध-सपादक, महात्माजी के सुपुत्र

~~सेना~~ के कमाडर, सितम्बर से दिसम्बर १९४७ तक भारत के गवर्नर-जनरल के सनिक सकट-कालीन मंडल के नता।

लाकहार्ट, लफ्टिनेंट-जनरल सर राव.: जून से १५ अगस्त १९४७ तक उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रात के गवर्नर, १५ अगस्त १९४७ से जनवरी १९४८ तक भारत उपनिवेश की सेना के कमाडर-इन-चीफ।

लियाकत अली खा: (स्व०) मुस्लिम लीग के प्रधान मत्री, अतरिम सरकार मे अर्थ सदस्य, पाकिस्तान उपनिवेश के प्रधान मत्री, उपरात मारे गए।

स्काट, आई डा. वाइसराय के डिप्टी सक्रेटरी।

अनुक्रमणिका

●